

मेहनत यह बात पक्की कर लेना चाहते थे कि कांग्रेस का वामपक्ष मजदूर हो जाये और इसलिए वे • डी • माधवीय और स्वर्गीय डा • बागिया आदि के सहयोग से उन्होंने कांग्रेस तथा देश के वामपक्षी तत्वों को संगठित करने का अभियान शुरू किया था ।

मेहनत का विचार था कि मैजिस्ट्रेट हेडक्वार्टर में उनका गुट और उनके चढ़ते कौन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घट पट घासल होना उनकी इन नयी महत्वा-कांक्षाओं को पूर्ण करने तथा किसी भी मजदूर पारिवर्षिक को सम्हालने में सहायक होगा । यह किसी का नहीं मानूस था कि नेहरू के धाद बदा होगा । ऐसी हालत में सेना को हाथ में रखना आवश्यक था ।

लेकिन सत्य यह था कि स्वयं कौल न दावे पक्ष में अनुयायी थे, न बायें पक्ष के । वह मूलतः दिसाप्रेमी और राष्ट्रवादी थे और बर्मा तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में मैजिस्ट्रेट दामन स्थापित होने के कारण उनके अन्दर अशान्तिजनक राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ जाग्रत हो चुकी थीं ।

उनके मन में भी यह सवाल बार-बार उठता था कि नेहरू के साथ क्या ? क्या सारा देश विप्लव और अराजकता में डूब जायेगा ? ऐसी परिस्थिति में उनका और सेना का क्या कर्तव्य होगा ? कौल के मन में उत्तर निश्चिन्त था । उनका यह विश्वास था कि देश को एक एकजिन्तामी और संगठित सरकार की आवश्यकता है और आर्थिक गति-विधि, प्रयोग्यता और सारे देश में सन्तानक रोग को तरह फैली हुई बर्झमानों को दमकर दूर रख कर चुने थे कि लोकतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था में इनकी समझा नहीं है कि वह इन सारी बुराइयों को दूर कर सके ।

आने वाले अनिश्चित समय को देखते हुए कौल ने यह ठीक समझ था कि कृष्ण मेहनत जैसे गत्यात्मक नेता से दनाजर रली जाये । इसके अन्तर्गत प्रधान सेनापति का पद प्राप्त करने के लिए भी मेहनत का प्रयत्न आवश्यक था ।

चाकर जैसे नर्म स्वभाव के व्यक्ति के प्रधान सेनारवि होने के कारण, कौल ही सेना के वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे युवक भ्रष्टमरों का गुट पैदा कर लिया था जो उनके प्रणमक थे और किसी दिशा में भी उनके पीछे चलने को तैयार थे । भविष्य में एक विशेष भूमिका भ्रष्ट करने के लिए कौल पूरी तैयारी कर रहे थे ।

कृष्ण मेहनत के साथ कौल के सम्बन्ध 'प्रेम-पूणा' के विरोधाभास पर आधारित थे जबकि मेहनत कौल के प्रति पूर्णतः सहनशील थे जैसे एक स्नेहशील पिता अपने साहने बिन्दु अमयन पुत्र की हर बात बर्दाश्त कर लेता है । यही १९६३ तक मेहनत कौल की बहुत प्रशंसा करते रहे थे हानाकि कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि कौल उनकी बुराई करते हैं । वास्तव में

मेनन ने इन शफराहों में विश्वास करने से इनकार किया है और कहा है ।”  
“वह सामान्यतः सारे ही राजनीतिज्ञों की बुराई करते होंगे ।”

लेकिन सही बात यह है कि कौल मुक्त रूप से दूसरों से मेनन की कम-जोरियों के बारे में बातें करते थे और अपने रक्षा मंत्री के आदेशों तथा इच्छाओं को बिना संशय पाये काटते रहे थे । इसका एक उदाहरण है कि मेनन के स्पष्ट आदेशों के खिलाफ कौल ने एक सोवियत हेलिकॉप्टर में सैन्य की और सोवियत विमानों को रद्द करवा दिया जबकि मेनन ने अमरीकी विमानों की तुलना में रूसी विमानों को ज्यादा प्रशंसित किया था और उन्हें मंगाने के लिए आर्डर भी दे दिया था । मेनन कौल की इस हरकत पर बहुत ज्यादा क्रुद्ध हुए थे लेकिन जब संसद में विरोधी पक्ष ने इसके खिलाफ आवाज उठायी थी तो मेनन ने कौल के इस काम का समर्थन किया था ।

अपने रक्षामंत्री को बताये या उनसे पूछे वगैर कौल सीधे अमरीकी राजदूत से भारत की प्रतिरक्षा समस्याओं के बारे में बात करते थे । डेलेस हूगन के अनुसार अमरीकी राजनयिकों और जवरलों के साथ वार्ता करने में कौल मेनन की बड़ी सिकायत करते थे और उन्होंने अमरीकीनों से कहा था कि वे भरसक भारतीय सेना के साथ सम्बन्ध रखें ।

डेलेस हूगन ने तो यह तक कहा है कि सन् ६२ में, मेनन के विरोध के बावजूद, कौल ने श्री नेहरू को इस बात पर राखी कर लिया था कि वे अमरीकी तथा पश्चिमी अस्त्रों की माँग करें ।

वास्तव में कौल ने अनाधिकार रूप से काफी कुछ अपने सिर पर ले लिया और ऐसा करने पर भी वे साफ झूठ जाते थे । इसके पहले कि श्री नेहरू संकटकाल में पश्चिम को सहायता माँगने का निर्णय करते, कौल ने अपनी तरफ से भारत की सैनिक आवश्यकताओं की एक पेश्रिस्त अमरीकी राजदूत श्री गालब्रेथ को दे दी थी ।

उन्होंने इस बात का भी चिन्मा ले लिया था कि अपने साथी अधिकारियों के अनधिकृत बुरे बलन के खिलाफ रक्षा मंत्री को सूचना दें । उदाहरणार्थ कौल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ही मेनन को यह बताया था कि जनरल मानेकशॉ ने विधिसम्मत अधिकारों का उल्लंघन किया है । रक्षा मंत्री ने तीन सदस्यों की एक जांच समिति स्थापित की लेकिन इस समिति ने भागेकशॉ के खिलाफ लगाये गये सारे आरोपों को रद्द कर दिया ।

एक बार मेनन ने कौल को, उन्हें बताये वगैर सीधे प्रधान मंत्री से प्रतिरक्षा समस्याओं के बारे में बातें करने के लिए आड़े हाथ लिया । कौल ने खरा जवाब दे दिया । यदि मेनन को यह अच्छा नहीं लगा तो उन्हें चाहिए कि वे सीधे प्रधान मंत्री से सिकायत करें क्योंकि प्रधान मंत्री ने स्वयं इस विषय पर उनसे (कौल से) बातचीत की थी ।

१९६१ में जब प्रेसिडेंट बेनेडी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में चेस्टर बाउल्स भारत आये तो उन्होंने कौन से मिलने की इच्छा प्रगट की यह बात मेनन को अच्छी नहीं लगी लेकिन उन्होंने कौन को भी बाउल्स से मिलने से नहीं रोका क्योंकि मुनाकात की इच्छा थी बाउल्स ने प्रगट की थी

१९६१ में नैका मोर्चे पर भारत की पराजय के बारे में मुमने बात करते हुए मेनन ने घपरा सामरिक नीति का बिक्रि किया। उनकी योजना के अनुसार बीमरीला तक बराबर और नियंत्रित रूप में प्रेषण करता था और उसके बाद चीनियों को घेर कर बिनास देमाने पर उन पर आक्रमण करना था। लेकिन, उन्होंने कहा, कि प्रधान मंत्री और जनता दोनों का साहस छल हो चुका था और ऐसी हालत में पराजय करना असम्भव था। "हम चीनियों को चुनौती देकर उनके अपने छुड़ा मरन से क्योंकि भारतीय सैनिकों तक उत्तर देने के कारण वे स्वयं मरने को सज्ज म फसा रहे थे, मेनन ने कहा, लेकिन नेहरू ब्रह्मा उठे थे और देश का माहस नब्बों से सारम हो रहा था। ऐसे समय पर हमारे देश में व्यक्ति जैसा व्यक्ति नहीं था। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसका मतलब होता कि मैं नेहरू पर दोष लगा रहा हूँ।'

मेनन से मैंने थोराट योजना के बारे में प्रश्न किया। यह योजना जनरल थोराट ने फरवरी १९५६ में बनायी थी जब वे पूर्वी बर्मा के सनापति थे। मेनन ने कहा कि उन्होंने ऐसी किसी योजना के बारे में सुना तक नहीं था।

परिस्थिति का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके, जनरल थोराट ने एक 'प्रति-रक्षा रक्षा' निश्चित की थी। इसके अनुसार भारतीय सेना को नेका में घाघी दूर तक पीछे हटना था और उसके बाद लेना के बजाय बीमरीला में दाब से डट कर मुड़ करना था। इस योजना के आधार पर मार्च १९६० में पूर्वी बर्मा में 'लान जिना' नामक एक मरक छ दिन तक की थी। यह मरक यह मान कर की गयी थी कि चीन तथा पाकिस्तान दोनों ने पूर्वी प्रदेश में आक्रमण किया है। इस मरक के फलस्वरूप जनरल थोराट ने यह भी आशा या हि निजते सैनिकों, घस्रो, वाहनों तथा पशुओं की आवश्यकता थी।

लेकिन थोराट योजना को नेका की प्रतिरक्षा सम्मिया का धरन्द बुरात तथा आधुनिकतम परिवोध थी, रक्षा मन्त्रालय की दरजों में धून धा रही थी और सैनिक हेडक्वार्टर में ऐसे लोग अक्षरवरी सामरिक योजनाएँ बना रहे थे जो न नेका के भू-देश तथा रण परिस्थितियों के बारे में कुछ जानते थे और न जिन्होंने सीमान्त के पार पशु के सैनिक के अधिकार तथा नैयारी के सम्बन्ध में हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को ठीक तरह धीमा और समझ था।

जहाँ तक धातु सेना का सम्बन्ध था, सब से बुरी बात यह थी कि हमारे पाँच प्रिन्स देशों में बीच प्रकार के विमान मँगाने पड़ रहे थे जिसकी वजह से

मानकीकरण असम्भव था, देख-भाल करना खर्चीला था और हर प्रकार के विमान के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक था।

उच्चतर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए इंजीनियरों तथा तकनीकियों को अनुचित रूप से ब्रिटिश लाइसेन्स पर एव्रो टर्बोजेट यातायात विमानों के उत्पादन में लगाकर मेनन ने वायु सेना की परेशानियों तथा कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया था।

इस प्रकार सेना के अनुशासन तथा हौसले से खिलवाड़ करके मेनन ने ऊपर से नीचे तक सेना में अव्यवस्था और संगठनहीनता फैला दी थी। इसके कारण स्वाभाविक रूप से कमान्डरों तथा मोर्चे पर युद्ध करने वाले जवानों का हौसला खत्म हो गया था और यही वजह थी कि नेफ़ा में भारतीय सेना चीनियों के सामने जरा भी नहीं ठहर सकी थी।

ऐसे समय पर जब उत्तरी सीमान्त पर चीनी संकट के बादल धीरे-धीरे एकट्ठे हो रहे थे तो मेनन को केवल यह चिन्ता थी कि कैसे सैनिक हेडक्वार्टर में एक बफ़ादार गुट संगठित करें। ऐसे समय पर उनका कर्तव्य था कि अपनी सारी मानसिक शक्ति देश की प्रतिरक्षा पर केन्द्रित करते और महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य अफसरों की नियुक्ति करते। मेनन अपने बचाव में यह भी नहीं कह सकते कि चीन ने उन्हें अपने आक्रमणशील इरादों का पूर्वाभास नहीं दिया था।

यही कारण था कि मेनन के शत्रु खुली तौर से उन पर यह आरोप लगाते थे कि वे बाद में राज्य विप्लव करने के लिए देश के प्रतिरक्षा संगठन का इस्तेमाल कर रहे थे।

## असम्भववादी सैनिक हेडक्वार्टर

नयी दिल्ली के सामान्य वातावरण के अनुकूल १९५४ के बाद से सैनिक हेडक्वार्टर की बहाली बाहिली और निश्चलता की बहानी है।

देश की सुरक्षा के अचूक प्रहरी होने और प्रतिरक्षा सम्बन्धी हर सम्स्या का हल ढूँढने के बजाय, हमारे सैनिक अक्सर उत्तरी सीमान्त के प्रतिरक्षा से सम्बन्धित हर प्रस्तावित हम में कोई न कोई कठिनाई और निराशा देने दे।

हम बारे में उन्होंने कई कहाने प्रस्तुत किये थे कि निम्नत सीमा पर चौकियाँ स्थापित करने तथा सैनिक दल भेजने के विषय पर प्रधान मंत्री के आदेशों की कौन कौन सी बाधाएँ नतीजा बिया जा सकता था। उस प्रदेश की दुर्गमता, हमारे सम्बन्धी कठिनाइयाँ और प्रस्तावित स्थानों का कुछ नीतिक दृष्टि कोण से बेकार होना—यह विषय कहाने थे।

अगस्त १९५० में चीन द्वारा निम्नत के 'मुक्त' हो जाने के बाद भारत सरकार के विदेश तथा रक्षा मंत्रालयों में खबरदस्त सरगमी शुरू हो गयी थी।

अक्टूबर १९५० में विदेश मंत्रालय के एनिहासित विभाग ने एक नोट तैयार किया था जिसमें तिब्बत पर चीन के अधिकार जमा होने का महत्व बताया गया था और नेत्रा सीमान्त की और विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था। उक्त नोट में सहाय की और बात ध्यान नहीं दिया गया था।

१२ नवम्बर १९५० को सैनिक हेडक्वार्टर ने उत्तर पूर्वी सीमान्त की प्रतिरक्षा का निरीक्षण किया था और भारतीय सीमान्त के विवादपूर्ण स्थानों पर चीनियों के कब्जा करने की सम्भावनाओं तथा इन सम्भावित अतिवृत्तियों को पहले से ही रोकने के लिए मामाम राइफल्स की चौकियों को घाते ठक स्थापित करने के औचित्य का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

साथ ही विदेश, रक्षा तथा गृह मंत्रालयों की एक अन्तर विभागीय समिति ने यह प्रस्तावित किया था कि नेफा की भारत-तिब्बत सीमा पर २१ चेक-चौकियां फौरन से फौरन स्थापित की जायें।

लेकिन इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए शायद ही कोई कदम उठाया गया था क्योंकि यह आशा थी कि चीन-तिब्बत सीमा समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है।

दिसम्बर १९५० में प्रधान मंत्री ने लोक सभा में यह घोषणा की थी कि मैकमहॉन रेखा को किसी हालत में भंग नहीं होने दिया जायेगा।

इस के फलस्वरूप आत्मान के पूर्वी कमान्ड के सेनापति से आग्रहपूर्वक यह कहा था कि प्रधान मंत्री की घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया था कि प्रधान मंत्री की घोषणा से एक नया तत्व प्रकाश में आया था और भारत के मुख्य द्वारों पर फौरन अपनी सेना तैनात करना आवश्यक था। राज्यपाल ने यह सुझाव दिया था कि हमारी चौकियां ठीक मैकमहॉन रेखा तक स्थापित कर दी जायें ताकि हमारी उपस्थिति से सीमान्त पर हमारा दावा सुरक्षित हो जाये।

लेकिन बाद में शितान में हुए एक सम्मेलन में (जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल, सरकार के परामर्शदाता तथा शम्भु वरिष्ठ सैनिक और प्रशासकीय अधिकारी शामिल हुए थे) यह तय पाया गया कि मैकमहॉन रेखा तक चौकियां स्थापित करने से कोई खास जायदा नहीं होगा क्योंकि सम्भव लाभ की तुलना में कहीं बड़ादा प्रयत्न करने पड़ेंगे।

१ दिसम्बर, १९५० को भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसके सभापति मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी थे। इस समिति का काम था उत्तर में लद्दाख से उत्तर पूर्व में भारत बर्मा सीमा तक उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमान्तों की प्रतिरक्षा के पूरे क्षेत्र का पर्यवेक्षण करना और अपने सुझाव पेश करना।

१९५१ में इस समिति ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार सीमा प्रश्न का अध्ययन करे और यह तय करे कि समझौते के आधार के रूप में वह उन क्षेत्रों में जहाँ उसकी स्थिति अनिश्चित या विवाद पूर्ण थी वह किस रेखा पर दावा करेगी। समिति ने कहा कि रेखा निश्चित हो जाने के बाद हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम उस पर सफल रूप से खड़े रहें और चीनी या तिब्बती सैनिकों या अक्रसरों द्वारा उन क्षेत्रों पर एक पक्षी रूप से कब्जा होने से रोक सकें। समिति की रिपोर्ट में आये यह भी कहा गया था कि विवादपूर्ण क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र पुलिस को तैनात करना आवश्यक होगा।

समिति ने आग्रहपूर्वक इस ओर ध्यान दिलाया कि "सिक्किम के संगठित होने और चीन के द्वारा तिब्बत को 'मुक्त' किये जाने के कारण लद्दाख का युद्ध

नीतिक मूल्य ध्वज और भी बढ़ गया है और चेतावनी दी कि महाग से उत्तर प्रदेश तक की सड़क में स्थित कई दरों के कारण "यह सारा क्षेत्र प्रतिभ्रमणों के लिए भय है।"

समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाह्य में बर्फ जम जाने की वजह से किसी हालत में यह नहीं तय मान लेना चाहिए कि यह दरें दुर्मेघ हैं क्योंकि कुछ निरक्षर रगन वाला सभ्र काफी दूर तक प्राकृतिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है।

त्रैकल सिन्धु पर चीन के बगड़ा कर लेन की बात पर उत्तेजना के धीरे-धीरे छरम हान के कारण भारत तिब्बत सीमा को सुगन्धित करने की बात भी पीछे चली गयी। और 'हिंदी चीनी भाई भाई' युग के आरम्भ होने के कारण कम से कम, जनता और पत्रकार सीमा समस्या को बिल्कुल ही भूल गये।

समिति के प्रस्तावों और उमरी आवाजों की तरफ केवल इस सीमा तक ध्यान दिया गया कि १९५१ में यह मन्त्रालय ने महाग में पनामिक वाइपॉक, चुंगुल तथा दमबाक में तीन प्रशासकीय चौकियाँ स्थापित की और १९५३ में एक घटना के बाद, राज्य सरकार ने भारत-तिब्बत सीमा पर गढ़वाल के निर्माण नामक स्थान में दली अपनी चौकी की शक्ति बढ़ायी।

मई, १९५४ में भारत तथा चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद चीन के सम्बन्ध में तेज सरगर्मी का दूसरा दौर शुरू हुआ।

जुलाई, १९५४ में प्रधान मंत्री ने विदेश मन्त्रालय के सेक्रेटरी-जनरल, विदेश सचिव, रक्षा मन्त्रि तथा वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के नाम एक चापल पत्र लिखा।

उक्त चापल-पत्र में श्री नेहरू ने बताया कि यह समझौता चीन तथा तिब्बत के साथ हमारे सम्बन्धों में एक नया मोड़ है और बताया कि हमारी नीति के अन्तर्गत तथा चीन के साथ हमारे समझौते के फलस्वरूप, उत्तरी सीमान्त को निर्दिष्ट और ठोस समझना चाहिए—उसके बारे में किसी से विवाद करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। प्रधान मंत्री ने आदेश दिया कि इस सारे सीमान्त पर चक चौकियाँ स्थापित कर देनी चाहिए, विनियत ऐसे स्थानों पर जिन्हें विवादपूर्ण समझा जाता हो।

प्रधान मंत्री की इस महत्वपूर्ण घोषणा को कार्यान्वित कराने के लिए कोई समन्वित योजना नहीं बनायी गयी।

२६, फरवरी, १९५४ को भारत सरकार ने तिब्बत में तैनात अपने गैरिस्तों को हटा लिया—यह इस बात का सबेरा था कि तिब्बत के भाषनों में भारत न अपना हाथ खींच लिया है। यह गैरिस्त भारत की अंग्रेजी सरकार ने ग्यात्से और यानुग में स्थापित किये थे और लगभग ३० वर्ष से वहाँ थे।

तिब्बत सरकार के लिए उनकी भूमि पर भारतीय गैरिसनों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि भारत सरकार को तिब्बत की स्वतन्त्रता और उसकी बाहरी प्रतिरक्षा में क्रियात्मक दिलचस्पी है।

सितम्बर, १९५४ में विदेश, रक्षा तथा गृह मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में सात स्थानों को विवादपूर्ण स्थितियाँ निश्चित किया गया था। क्योंकि यह समझा गया था कि न गृह मंत्रालय और न राज्य सरकारों में आवश्यक क्षमता है इसलिए इन चीकियों पर सैनिक तैनात करने का उत्तर-दायित्व रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था।

लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में निष्पक्ष प्रगट की और जब उसे बताया गया तो उसने इस बात पर और भी अधिक गौर करने का वायदा किया। प्रत्यक्ष है कि 'बात पर और अधिक गौर करने का' कोई फल नहीं निकला। इन चीकियों पर सैनिक तैनात नहीं किये गये और बाह में चीनी, अपनी इच्छा के अनुसार, इन खाली चीकियों पर कब्जा करते और उन्हें छोड़ते रहे। सन् १९५४ तक लद्दाख में चीकियों की संख्या तीन से बढ़ कर पाँच हो गयी थी।

सितम्बर, १९५६ में हिमाचल-तिब्बत सीमा पर शिपकीला की घटना के बाद, प्रधान मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निम्नलिखित आदेश दिये :

१. हमारी सेना को शिपकीला से जितना निकट सम्भव हो तैनात रहना चाहिए।
२. हमारी सेना को अपनी वर्तमान स्थिति से आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चीनियों के साथ संघर्ष होने की सम्भावना है।
३. यदि चीनी हमारी भूमि पर आगे बढ़ें तो उन्हें रोकना चाहिए। रोकने का काम हाथ में ले लेने से पहले चीनी कमान्डर को बता देना चाहिए कि हमारी आका के बिना उनके शिपकीला दरें को पार करने को हम अग्र-संघर्ष समझेंगे, अतः उन्हें वापस लौट जाना चाहिए।
४. हम चीनियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और यदि वे पीछे नहीं हटेंगे तो हम इस दिशा में आगे कदम उठावेंगे। हमारे कमान्डर को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह अभी आगे-कदम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि यह बात दिल्ली और पेकिंग तक पहुँचा दी गयी है और इसलिए भी कि दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं लेकिन यदि इसके बाद भी अग्रसंघर्ष हुआ तो संघर्ष अनिवार्य हो जायेगा।

५. हम यह चाहते हैं कि यदि हमारी इत च. ही की सैनिक संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हो तो आप फौरन वहाँ कुछ अतिरिक्त सैनिक या सीमा सुरक्षा पुलिस के सिपाही भेज दें।



६ हम चीनी दूतावास से एक बार आपत्ति प्रगट कर चुके हैं और हम यहाँ भी और पेकिंग में अपने राजदूत तथा स्टाफ में अपने कॉन्सल जनरल के द्वारा फिर से आपत्ति प्रगट करेंगे।

नेविन पंचशील सम्झौते का नया अभी तक सरकार और देश पर छाया हुआ था। और व तस्वीर के इस विरोधी रण को देखने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत चीन सीमा पर सकट खड़ा हो सकता है।

भक्तान्न चिन में चीन के अधिकरण के प्रकाश में घाने के पतनस्वरूप १९५८ में दिल्ली में सरणियों का तीसरा दौर शुरू हुआ। यह दौर और भी तीव्र हो गया था क्योंकि अगले वर्ष अप्रैल में दलाई लामा ने भारत में सरण ले ली थी।

भक्तान्न चिन में चीनी सड़क बंद करने के बाद दिसम्बर १९५८ में सैनिक हेडक्वार्टर ने रक्षा मन्त्रालय के सामने यह सुझाव रखा था कि कराकोरम दर्रे के पास एक भारतीय चेक चौकी स्थापित कर दी जाये ताकि दर्रे में से किसी चीनी अधिकरण की पूछ बेचना मिल सके।

वास्तव में १९५८ तक कोई भारतीय अधिकारी भक्तान्न चिन नहीं पहुँचा था—उसके बाद ही हमारे दस्तों इस इलाके में गश्त लगाने के लिए पहली दफा भेजे गये थे।

८ जनवरी, १९५९ को नयी दिल्ली में हुई एक मीटिंग में यह तय किया गया कि मध्य लद्दाख के साँगन्ग्यान्, घामस लु गपा और शिंगलु ग नामक स्थानों में प्रशासकीय चौकियाँ स्थापित की जायें। यह भी निर्दिष्ट किया गया कि एक प्रशासकीय टोह दल लानक ला भेजा जाये ताकि पूरी टोह लेने के बाद हम मांग पर सीमा से निकटतम स्थान पर एक चेक चौकी स्थापित की जा सके।

२८ जुलाई को चीनियों ने खुाँक दुर्ग को भेजे गये हमारे एक प्रशासकीय गश्ती दल को गिरफ्तार कर लिया। २० दिन बाद उन्हें चुंगुल में स्थान हमारी चेक चौकी पर रिहा किया गया।

उसी वर्ष भारत में चीनियों ने स्पानगुर में अपनी एक चौकी स्थापित की—यह स्थान स्पष्टतः भारतीय सीमा के अन्दर था। इस पर सैनिक हेडक्वार्टर ने पश्चिमी बंगाल को आदेश दिया कि चुंगुल में प्रस्तावित चौकी औरन स्थापित कर दी जाये और चुंगुल में स्थित गैरिजन से कहा जाये कि भविष्य में चीनी अधिकरणों को रोकने के लिए वह सारे सीमान्त पर क्रियात्मक रूप से गश्त लगाता रहे।

साथ ही सैनिक हेडक्वार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चीनियों को स्पानगुर से निकालने के लिए कोई आक्रमणशील प्रयत्न न किया जाये।

सैनिक हेडक्वार्टर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-तिब्बत सीमा के लद्दाख इलाके में जम्मू-कश्मीर के मिलीशिया को तैनात करने के पीछे यह विचार था कि उस क्षेत्र में परम्परागत सीमा के इस पार भारतीय भूमि पर हमारा व्यावहारिक और क्रियात्मक अधिकार स्थापित हो जाये और बराबर गस्त लगाते रहने से चीनियों तथा अन्य अनधिकृत लोगों के अतिक्रमण रोक दिये जायें।

पश्चिमी कमान्ड को यह आदेश दिया गया कि यदि हमारे इलाकों में चीनियों से मुठभेड़ हो तो भी अस्त्रों का प्रयोग न किया जाये जब तक आत्म-रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो जाये। "ऐसी परिस्थिति में उन्हें हमारी भूमि से हट जाने के लिए राखी करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके ऐसा करने से इनकार करने के बावजूद पूर्व स्थिति कायम रखी जाये और हेड क्वार्टर को इस विषय पर सूचित कर दिया जाये ताकि मामले को राजनयिक तरीकों से हल किया जा सके।"

अक्टूबर में सैनिक हेड क्वार्टर की आंख अचानक खुली और उन्हें यह मात्तूम पड़ा कि लद्दाख में हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था अत्यन्त अपर्याप्त थी और सारी सीमा पर फौजी हुई हमारी थार चौकियों में इतनी एक्ति नहीं थी कि किसी बड़े चीनी आक्रमण को सह सकें। न उस समय यह सम्भव था कि, भू-प्रदेश और दुरी संचार व्यवस्था को देखते हुए, ऐसी सेना सीमा पर तैनात की जा सके जो सफलता से सीमा की रक्षा कर सके। इसलिए सैनिक हेडक्वार्टर ने पश्चिमी कमान्ड से यह कहा कि सम्भावित चीनी अग्रचरण का मुकाबिला करने के लिए एक सामान्य प्रतिरक्षा रेखा प्रस्तावित करे।

इस आत्म-स्वीकृति का इतने विलम्ब से प्रगट करना एक परेशान कर देने वाली बात थी।

पश्चिमी कमान्ड ने एक योजना पेश की जिसमें वह रेखा निर्धारित की गयी थी जहाँ से चीनी आक्रमण की बाढ़ को रोकने का प्रस्ताव रखा गया था। यह कार्य पूरा करने के लिए पश्चिमी कमान्ड ने यह माँग की थी कि १९६० में लद्दाख में चार डिवीजन तैनात कर दिये जायें और उसके साथ कुछ सहायक अस्त्र तथा सेवाएँ भी भेजी जायें। कहा गया था कि फौरन लद्दाख की रक्षा करने के लिए यह अल्पतम सैनिक आवश्यकताएँ थीं इस बात की भी माँग की गयी थी कि १९६१ में एक और डिवीजन लद्दाख पहुँचा दिया जाये।

साथ ही पश्चिमी कमान्ड ने यह भी कहा था कि कार्गिल से लेह तक फौरन एक ऐसी सड़क बना दी जाये जिस पर एक टनी यातायात ले जाया जा सके—इससे लद्दाख में स्थित सेना के हवाई अवपातन पर निर्भर रहने की मजबूरी बहुत कम हो जाती।

उसी महीने प्रधान मंत्री ने सहानुभूति की सुरक्षा तथा गहरी सहायता-निष्पन्न सीमा पर अथवा अत्यधिक सैनिक कारवाही करने की हिम्मेदारी सेना पर दाव दी। इस तरह निम्नलिखित सीमान्त सेना में हमारी सेना का सीधा सम्पर्क हो गया और गहन सहायता आदि का काम पूरी तरह सेना पर आ पड़ा।

सेना इन सब उत्तरदायित्वों के लिए जिस सीमा तक आवश्यक थी यह नयी दिल्ली से ३१ अक्टूबर, १९५६ को भेज गये एमानिटेड प्रेम के न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुए दिसपैच से पता चलता है। उक्त दिसपैच में लिखा गया था "अपने हिमाचल सीमान्त के पास के बड़े-बड़े इलाकों को साम्यवादी चीन से सुरक्षित रखने की आशा भारतीय सेना ने त्याग दी है।" दिसपैच में कहा गया था कि यह सूचना विश्वस्त सूत्र से प्राप्त हुई थी।

यह स्पष्ट है कि नयी दिल्ली में स्थित एमानिटेड प्रेम के सम्पादकाना ने यह दिसपैच अपने मन से नहीं गढ़ी होगी बल्कि यह सूचना उसे सेना के किसी ऊँचे तथा हिम्मेदार अधिकारी से प्राप्त हुई होगी। दिसपैच में कहा गया था 'यदि हमारे वस्तु में निश्चित में निम्न चीनी सेना ने भारत के उन सीमान्तीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयत्न किया किन पर वे दावा करते हैं तो भारतीय युद्ध नीति यह होगी कि लगभग बिना लड़े यह विस्तार क्षेत्र वे दावा को देने चले जायें।' 'राष्ट्र के अपनी भूमि के बाकी अन्दर तक घस घाने के बाद ही वे उससे डट कर मोर्चा लेने की स्थिति में होंगे।'

दिसपैच में आगे यह भी कहा गया था "कहा जाता है कि सेना ने यह फैसला इसलिए किया है कि सड़कों तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण बड़े सैनिक दस्तों का सीमा तक पहुँचाना उसके लिए असम्भव है।"

अक्टूबर, १९५६ में जो परिस्थिति थी उसके बारे में इस दिसपैच ने अत्यन्त बहुत सच व्यक्त किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अक्टूबर १९६२ तक यही स्थिति बनी रही—चीन के तीन वर्षों में निम्न सीमा पर हमारी सेना की सहायता में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

हम यह देखते हैं कि प्रधान मंत्री के स्पष्ट आदेशों और चेतावनियों तथा उच्चतम स्तर पर हमारे अधिकारियों के सौच विचार के बावजूद १९५६ के अन्त में भी सहाय में भारतीय नियंत्रण रेखा वहीं थी जहाँ १९४८ में थी। इसी बीच सहाय में अपनी सैनिक कारवाहियों को पुष्ट करने के लिए चीनियों ने सड़कों का जाल बिछा दिया था—उत्तर पूर्व में अकनाई चिन मार्ग, मध्य क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली लानक्ला-जोगरा ला सहक और जीप मार्ग और पुर उत्तर में तिकपाग-किडिग डिमना-नांगु ग-सुर्मदा को मिलाने वाली सड़क।

नेका में यद्यपि बायो क्षेत्र पर अन्तर्जातीय नियंत्रण स्थापित किया जा चुका था फिर भी सेना वहाँ पर्याप्त रूप से नहीं पहुँची थी।



निकटतम धोकी पर रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि यह बात उच्चतम अधिकारियों तक पहुँचायी जा सके और इस बारे में आदेश प्राप्त किये जा सकें कि घाने क्या करना चाहिए।

२० अगस्त को सैनिक हेडक्वार्टर ने इस विषय पर पश्तुनी बमाड का अन्तिम आदेश दिए। साथ ही, रक्षा मन्त्रालय को लिखे गये एक नोट में, जनरल स्टाफ के तत्कालीन प्रमुख जनरल सेन ने इस आन की चेतावनी दी कि यदि विदेश सचिव के २६ मई के आदेश के अनुसार गलती कार्रवाई की जाय तो विवादपूर्ण स्थानों में भीड़ियाँ व्यापित की जायेंगी इस बात की पूरी सम्भावना है कि चीनियों में इससे विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होगी। उक्त नोट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसी हासन में "इस बात की सम्भावना पैदा हो सकती है कि बहुत दिनों बाद पड़ोसी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सरहर्दी भड़क उठे।"

जनरल सेन ने यह भी स्पष्टाया कि समार सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण उस समय तक सीमा सस्या में ही सैनिकों को सहाय भोजना सम्भव हो सका था। अब उस क्षेत्र में प्राप्त सैनिकों की देखने हुए यह मुश्किल थी कि सेना किसी बड़े भीनी आक्रमण को शेल सके।

जनरल स्टाफ के प्रमुख के इस नोट ने, जो ५ सितम्बर को विदेश सचिव को भी दिलाया गया था, विदेश मन्त्रालय में हलचल मचा दी। उक्त अवसर पर एम० दत्त ने यह कहा था "यह सामान्य की बात है कि मई में जो फैसले लिए जा चुके हैं उन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया।"

विदेश सचिव की इस टिप्पणी के फलस्वरूप रक्षा मन्त्री ने सैनिक हेडक्वार्टर से जवाबतलब किया। उत्तर देते हुए जनरल स्टाफ के प्रमुख ने बताया कि कई समार सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सेना तैयार नहीं थी और सहाय में सरकार के आदेशों को कार्यान्वित करने में असमर्थ थी।

यह देखते हुए कि परिस्थिति इस प्रकार की थी जिसके बारे में तुरन्त कदम उठाना अनिवार्य था, सैनिक हेडक्वार्टर ने क्या कदम उठाये थे तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिसका तरफ जनरल स्टाफ के प्रमुख ने अपने जवाब में सर्वेक्ष किया था? इस बात का कोई खास प्रमाण नहीं है कि उक्त कठिनाइयों को हल करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किये गये थे।

यूँ यह बात अवश्य मान लेनी चाहिए कि जनरल स्टाफ के प्रमुख तथा सैनिक हेडक्वार्टर इस दिशा में सब कुछ नहीं कर सकने थे जब तक मन्त्रिमण्डल इस बात को उच्च प्राथमिकता नहीं देता और सरकार इस बात की छूट नहीं देती कि साल फीते के गोरखवाले को बाट कर काम को गति दी जाये।

फिर भी सैनिक हेडक्वार्टर इस आरोप से नहीं बच सकता कि संकट के प्रति सजग न होने के कारण उसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। देश की बाहरी सुरक्षा के प्रहरी होने की हैसियत से सैनिक हेडक्वार्टर को चाहिए था कि सिर पर संकट आ पहुँचने के पहले ही सरकार को चेतावनी देता और उसे पूर्णरूप से त्रिधाशील होने के लिए विवश करता।

१९६० के बाद, जब संकट मुँह बाये ठीक सामने खड़ा था और प्रस्तुत जिम्मेदारी को पूरा करना अनिवार्य हो गया था तो सेना में तुरन्त-भाव प्रचानक जाग्रत हो गया। लेकिन सरकार अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि चीनी संकट असली है या उसके इतनी जल्दी टूट पड़ने की सम्भावना है। अतः अब सेना की बारी थी कि सरकार के अन्दर तुरन्त-भाव पैदा करे और चीनी आक्रमण का सफलता से सामना करने के लिए सेना को पर्याप्त रूप में साधन सम्पन्न बनाने के महत्त्वपूर्ण काम को जल्दी-से-जल्दी पूरा करने के लिए उसे हर तरीके से उकसाये।

लेकिन यह करना भी आसान नहीं था क्योंकि सरकार तथा सेना को अब तक यह विश्वास था कि चीनी भारत से कोई निर्णयात्मक संघर्ष नहीं करेंगे और यह कि वे केवल लुका-छिपी का खेल खेल रहे थे।

१९६० के अन्त के आस-पास लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र के निकट काफ़ी सीमा चीनी सरगर्मी देखी गयी। इस बात का सन्देश दिया गया कि उत्तर से दक्षिण जाने वाली अक्साइ चिन सड़क को दक्षिण में सामक़ी ला से शुरू होकर कोंगका ला दर्रे से गुज़रने वाले मार्ग से मिलाने वाली एक सड़क बनाने के लिए चीनी उस क्षेत्र का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

यह भावश्यक था कि ऐसी कोई भी सड़क हॉट स्प्रिंग्स होकर या उसके बाजू से गुज़रती—और हॉट स्प्रिंग्स भारत में काफ़ी अन्दर को है। वहाँ एक भारतीय सैनिक चौकी भी स्थित थी। इसलिए यह तय किया गया कि हॉट स्प्रिंग्स में स्थित अपनी चौकी की समित बढ़ा दी जाये और गश्ती दस्ते बराबर उस सीमा तक भेजे जायें जिसका दावा चीनियों ने अपने १९५९ के मानचित्र में किया था।

प्रधान मंत्री ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। ३० दिसम्बर को सैनिक हेडक्वार्टर ने पश्चिमी कमान्ड को यह आदेश दिया कि इस फैसले को कार्यान्वित कर दे। इसके तीन महीने बाद तक यह फैसला केवल शब्दिक रूप में ही था।

२२ मार्च, १९६१ को जनरल स्टाफ़ के नये प्रमुख जनरल कौल ने रक्षा मंत्रालय से यह निवेदन किया कि सरहद्दी सड़कों, हवाई अड्डों के निर्माण, लद्दाख में स्थित सेना को सामग्री पहुँचाने तथा बुरे मौसम की वजह से बहुत कम

ऐसे दिन होने के कारण जिनमें विमान चलाना सम्भव था, सद्दान में इन्तैमान किये जाने वाले विमान दल के लिए, यह सम्भव नहीं हो सका था कि आवश्यक प्रतिरक्षित सेना सहाय पहुँचाता। जनरल स्टाफ के प्रमुख ने कहा कि इस वजह से कम-से-कम कुछ समय के लिए सद्दान में अपनी रक्षा व्यवस्था को इन दो कामों तक ही सीमित करना पड़ेगा - (१) सद्दान के उन इमारतों में भावी प्रतिक्रमण रोकना जिन पर सब तक किसी पर का बन्ना नहीं था, और (२) सेना की रक्षा करना।

जनरल स्टाफ के प्रमुख के इस पत्र से यह स्पष्ट प्रगट होता है कि सैनिक हडकवाट में ऐसे विषय पर सुरक्षित-भाव का पूर्ण अभाव था जो देश के मौमान्य की सुरक्षा में सम्बन्धित था। यह भी जाहिर होता है कि प्रधान मंत्री तक के आदेशों के प्रति सेना कितनी साधारण थी।

१२ अप्रैल, १९६१ को पश्चिमी कमान ने उन प्राप्य सैनिक दलों की अन्तरता के बारे में जनरल स्टाफ के प्रमुख को विना जिन पर सहाय तथा पाकिस्तान के पाम के सरहदारी इलाका की सुरक्षा का भार था। इस पर जनरल स्टाफ के प्रमुख ने सहाय मन्त्रालय को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा।

उक्त पत्र में कौल ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि १५वीं बार के पाम सशस्त्रों की इतनी कमी थी कि वह चीनी अक्षयर्षण को किसी हावत में नहीं रोक सकती थी और इसलिए सद्दान के अग्रिम क्षेत्रों में हमें अपनी प्रारम्भिक पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। कौल ने यह स्वीकार किया इन क्षेत्रों में आवश्यक सख्या में अपने सैनिक न भेज सकने तथा हवाई अवपानन के द्वारा उनका पोषण न कर सकने, सद्दान के अभाव और बिन्दो हवाई भूमा पर पर्याप्त सुविधाएँ न होने, सेना, स्टोर तथा अन्य सामग्री के लिए उचित आश्रय-स्थान की कमी, सैनिकों के अभाव आदि कारणों से ही यह कमी पराजय सहनी पड़ेगी।

अन्त में कौल ने कहा "आज जो स्थिति है उसे देखते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि चीन हमारे बिन्दो चुने हुए इलाकों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करता चाहें तो हम उन्हें किसी तरह नहीं रोक सकेंगे।"

जून १९६१ के मध्य तक भारतीय सेना ने सद्दान में १५ चौकियाँ स्थापित कर दी थीं और इन सबको हवाई अवपानन के द्वारा सामान पहुँचाया जाना था। १० जून को लिखे गये एक पत्र में कौल ने प्रधान सेनापति को चेतावनी दी थी कि यदि उस महीने में वायु सेना ने ३६४ टन निर्माण सप्लाय स्टोर तथा अन्य सामग्री का अवपानन नहीं किया तो हमें इनमें से कुछ चौकियों को त्याग देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पत्र में यह भी कहा गया था कि अनुमान के आधार पर यह निर्दिष्ट था कि वायु सेना इस सामग्री के एक-

तिहाई हिस्से का ही जून में अवपातन कर पायेगी और इसलिए हमें वक्ती तौर पर चार चौकियों को छोड़ देना पड़ेगा ।

इस पूरे दौरान में इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भारतीय सेना ने चीनियों की रण शैली के आदी बनने या ऊँचे, दुर्गम स्थानों पर युद्ध करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिशा में कोई विशेष प्रयत्न किये हों । न इस बात का प्रमाण मिलता है कि सेना ने गम्भीरतापूर्वक चीनियों की सामरिक नीति समझने और उसके लिए जवाबी सामरिक नीति बनाने की कोई खास कोशिश की हो । हमारी सेना की युद्धनीतिक विचार-धारा और सामरिक प्रशिक्षण बराबर ही पाक-अभिस्थापित ही रही ।

यदि लोकतन्त्र में वाद-विवाद से सरकार चलायी जाती है तो उत्तरी सीमान्त पर चीन से सम्भावित खतरे के विषय पर हमारे रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों में जून वहुसे हुई और उसकी सुसना में काम बहुत कम हुआ ।

सीधा, स्पष्ट तथ्य यह है कि सैनिक हेडक्वार्टर ने इस सत्य के प्रति आखिरी मूँद ली थी कि यदि हमारी सेना उत्तरी सीमान्त की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है तो न केवल उस पर यह आरोप लगता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया बल्कि देश उस सीमान्त पर दावा करने का अधिकार खो देता है ।

देश की सरहद की सुरक्षा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि : "ऐसा करना असम्भव है ।" जो असम्भव है उसे भी करना पड़ता है अन्यथा शत्रु को छूट होती है कि बिना खटके आक्रमण करे और हमारी भूमि पर मनचाही सीमा तक अतिक्रमण करे ।

उस समय राजधानी में यह व्यापक दुस्स्थिति थी कि जबकि सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण समस्याओं पर रक्षा मंत्री तथा प्रधान सेनापति के स्तर पर दुर्भाग्यवश बहुत होती थी तो सम्बन्धित समस्याएँ क्राइलों में दब कर कहीं जा जाती थी और संयोग से निकला हुई कोई मामूली-सा मसला महत्वपूर्ण रूप ले लेता था । उच्चतम स्तर पर लिए गये निश्चयों की कार्यान्वित करने में अक्षर महीनों ही क्या कई वर्ष तक लग जाते थे ।



## यह रहा दूसरा गाल

भारत के बारे में उसके अंग्रेज शासकों की एक अत्यन्त स्पष्ट, सुबुद्ध और अप्रदर्शी नीति थी और इस नीति का मूल उद्देश्य था कि भारत के सीमान्तों को कभी किसी प्रकार का खतरा न हो। युद्ध से पूर्व, यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि भारत के सीमान्तों के चारों ओर प्रतिरोधक राज्यों का एक ब्यूह फैला दिया जाये और यह प्रतिरोधक राज्य ऐसे हों जो अंग्रेजी प्रभाव और प्रभुत्व को स्वीकार करते हों।

साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड उस काल का सबसे सशक्त देश था—उसकी एक टेढ़ी चितवन की ओर से भी अन्य कोई देश उदासीन नहीं हो सकता था फिर भी कहीं किसी प्रकार की कमजोरी छोड़ देने में वे विश्वास नहीं रखते थे और इसलिए उन्होंने अपने भारतीय उपनिवेश की प्रतिरक्षा के लिए प्रचूक प्रयत्न कर रखा था। वास्तव में भारत के चारों ओर उन्होंने इतनी चौड़ी सुरक्षा-पेटी खड़ी कर दी थी कि पूर्व में उसका प्रतिरक्षा बंद सिगापुर था और पश्चिम में अदन।

इस नीति के अन्तर्गत यह भी आवश्यक था कि भारत के उत्तर-पूर्वी सीमान्त पर तिब्बत का राज्य स्वतन्त्र और भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण रहे और साथ ही उस पर अंग्रेजी प्रभाव भी हो। अतः, नाम के लिए तिब्बत पर चीनी प्रभुत्व स्वीकार करते हुए भी, अंग्रेजी सरकार ल्हासा की सरकार से सीधा सम्बन्ध रखती थी और, दबे रूप से, इस बात की हर मुमकिन कोशिश करती थी कि तिब्बत हमेशा एक स्वतन्त्र और स्वशासित देश रहे। यह सही है कि यह नीति उसी समय सफल हो सकती थी जब चीनी सरकार में इतनी शक्ति

नहीं थी कि वह अंग्रेजों का विरोध कर सके, यह भी स्पष्ट है कि मात्र समय बदल चुका है और अब यह नीति काम नहीं कर सकती।

उस समय में भागत निम्न सम्प्रदायों के पीछे यह सुलभ प्रेरणा थी कि निम्न का वर्णना पटार—जो भारत की सीमाओं को विस्तृत करता है—जिसी हालत में भी किसी सम्मानित शत्रु—जो प्रगतिशील रूप, उसके बाद साम्यवादी रूप और बाद में आधुनिक धर्म—का हाथ न लग और इस बात के कई प्रमाण हैं कि इस सम्प्रदाय में भागत के अंग्रेजी गणतन्त्र बराबर गलेज और सजा रहे थे तथा इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर योजनाएँ बनाई जाती थी और कूटनीतिक बदल उठाए जाते थे। इनमें से एक बदल था भारत-निम्न की प्रतिनिधित्व सीमा को स्पष्ट और निश्चित रूप से तय करना।

भागत की अंग्रेजी सरकार और निम्न के भारतीय सम्प्रदायों में अंग्रेज बराबर इस धारणा पर काम कर रहे थे कि स्थायी की सरकार जी-जान में यह चाहती है कि वे निम्न में रहे और निम्न में उनकी दृष्टिकोणी काममें रहे ताकि दोबारा चीनी प्रभुत्व स्थापित होने की सम्भावना ही वैश्व में हो सके।

उनकी यह धारणा निश्चित रूप से सही भी बनी। सन् १९५० में १९५६ तक निम्न की सरकार भारत सरकार से यह धारणा करती रही कि वह क्रियात्मक रूप से उसकी सहायता करेगी चीनी आक्रमण और अधिकार से बचने के लिए।

सन् १९१४ में भारत कि अंग्रेजी सरकार ने यह फैसला किया कि भारत तथा निम्न और चीन तथा निम्न के बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से निश्चित कर देना चाहिए। (यह ध्यान देन योग्य बात है कि चीन और निम्न के बीच भी सीमा निश्चित करने का टेका अंग्रेजों के अपने ऊपर से लिया था।) इस उद्देश्य से सिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तीनों सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधि थे। इस कॉन्फ्रेंस ने भारत निम्न तथा निम्न-चीन के बीच की सीमाएँ निश्चित कर दीं और इस फैसले पर तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये।

लेकिन बाद में चीनी सरकार ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हालाँकि उसका प्रतिनिधि इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका था। चीनी सरकार की दलील यह थी कि वे निम्न और चीन के बीच के सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं हैं। इससे यह तो स्पष्ट है ही कि भारत और निम्न के बीच की सीमा से तत्कालीन चीनी सरकार को कोई अपास नहीं थी यद्यपि मात्र पेकिंग के शासन यही सिद्ध करने की वाजिब कर रहे हैं कि भारत तथा निम्न के बीच की सीमाएँ अवैध रूप से निर्धारित की गई हैं।

सन् १९१४ की इस शिमला कॉन्फेंस में निश्चित भारत-तिब्बत सीमा को मैकुमहॉन रेखा कहा जाता है क्योंकि उक्त कॉन्फेंस के समापति, इंग्लैण्ड के प्रतिनिधि, सर ग्रार्थर मैकुमहॉन थे ।

इस सीमा निर्धारण के बावजूद अगले तीस वर्ष तक भारत-तिब्बत सीमा को व्यावहारिक रूप से निश्चित करने के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया । लेकिन सन् १९४३ में, जब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति एक बार फिर भीषण रूप से अस्थिर अवस्था में थी, भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि भगड़े की सम्भावना को खत्म करने के लिए भारत, तिब्बत और चीन के बीच की सीमाओं को ठोस रूप से निर्धारित कर दिया जाये ।

इस निश्चय के अन्तर्गत यह फैसला किया गया कि भारत-तिब्बत सीमा पर कुछ स्थानों पर स्थायी और पक्के रूप से कब्जा कर लिया जाये ताकि तिब्बत के लिए सीमा लक्षणा असम्भव हो जाये (जैसा कि वे नेफा प्रदेश में कुछ समय से रह-रह कर रहे थे) । अतः, सन् १९४४ के प्रारम्भ में लौहित घाटी में शालोंग नामक स्थान पर एक चौकी बना दी गई तथा दो और चौकियाँ सियांग घाटी में रीना और काको नामक स्थानों में स्थापित कर दी गई । स्ते-ला उप-एजेन्सी में रुपा की स्थायी चौकी की सैनिक शक्ति बढ़ाकर एक प्लेटून कर दी गई । इसके अतिरिक्त, दिरांग जंग में भी एक प्लेटून की शक्ति की एक स्थायी चौकी स्थापित कर दी गई ।

सैनिक चौकियों की स्थापना के अलावा भारत सरकार ने राजनैतिक और सुचारुवादी कार्यक्रमों के द्वारा सीमान्त के ग्रास-भास की आदि जातियों में अपना प्रभाव फैलाने का भी प्रयत्न किया । पोलिटिकल एजेण्टों ने उन क्षेत्रों का दौरा किया, जिनमें तब तक बाह्यर के लोग पहुँचे ही नहीं थे और न भाष-चित्रों पर जिनका कोई निश्चित उल्लेख था । उन्होंने वहाँ के आपसी झगड़ों को तय किया और संक्रामक बीमारियों के समय डॉक्टरी मदद भी पहुँचायी ।

भारत सरकार द्वारा स्थापित नई चौकियों के खिलाफ तिब्बत सरकार ने फौरन आपत्ति खड़ी की और यह निवेदन किया कि दोनों राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी समस्या (स्टेट्स-की) कायम रखी जाये । इसके पीछे उनका तर्क यह था कि तिब्बत तथा भारत के बीच मैकुमहॉन रेखा से सम्बन्धित झगड़ों से चीनी सरकार फायदा उठा सकती है ।

भारत की अंग्रेजी सरकार ने निश्चित रूप से तिब्बत की आपत्तियों को रद्द कर दिया और वह स्पष्टतः प्रगट कर दिया कि सीमान्त पर सैनिक चौकियाँ स्थापित करने का उन्हें पूरा अधिकार है । इसके अलावा २९ दिसम्बर, सन् १९४४ को, भारत सरकार ने ल्हासा सरकार को लिखा कि मैकुमहॉन रेखा के दक्षिण क्षेत्रों में उन्हें (भारत सरकार को) पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वे जो

चाहे करें—हाँ, यदि ऐन गीमा पर उन्होंने कोई बंदम उग्राया तो वे इसकी भूचना तिब्बत सरकार को दबाने देंगे। साथ ही इस बात का इन्कार किया गया कि तिब्बत के प्रति उनसे कोई सन्तुष्टता इरादे हैं, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि भारत सरकार हमेशा हर सम्भव सहायता के लिए तैयार है।

भारत सरकार के इस पत्र की प्रतिक्रिया तिब्बत के गामकों पर बड़ी तीव्रता से हुई। स्थापना की राष्ट्र-सभा ने एक प्रस्ताव पान किया जिसमें इस बात पर शक और भ्रमनाय प्रगट किया गया कि भारत सरकार ने भविष्य पक्ष से तिब्बत के कुछ हिस्सों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और इस बात की मांग की गई कि स्वे-सा और बालान धर्मों से भारतीय सेनाओं परीत हटा भी जायें।

हालांकि इस और स उस समय भारत पर आक्रमण करने की कोई सम्भावना नहीं थी फिर भी भारतीय सेना के हवाई बमबोर्डा का यह निर्दिष्ट मन था कि भारत को अपने पूरे प्राकृतिक तथा युद्ध नीति के अनुसार मार्गों के सीमान्त पर नियंत्रण रखने का अधिकार काम में लाना चाहिए क्योंकि इसमें उत्तर-पूर्वी भारत की प्रतिरक्षा और भी टोस होगी।

सैनिक हवाई बमबोर्डा की शाय थी कि अधिकृत के किसी भी युद्ध में उत्तर और उत्तर-पूर्व से हवाई आक्रमण की सम्भावना हो सकती है और इसलिए भारत को अपने इस सीमान्त पर आगे से आगे सैनिक चौकियाँ स्थापित करने का अधिकार हाथ में रखना चाहिए ताकि इन सम्भावित हवाई आक्रमणों की चेतावनी काफी पहले से मिल सके।

सन् १९४६-४६ में भी भारतीय सेना के उच्चतम अधिकारियों का यह मत था कि तिब्बत पर किसी भी राष्ट्र का प्रभुत्व बढ़े-देस का अधिकार भारत की प्रतिरक्षा के लिए सतर्क होना। इसलिए तत्कालीन भारत सरकार की यह मूल नीति थी कि तिब्बत से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखे जायें और उसका स्वायत्त किसी भी उपाय से काममें रखा जाये। इस नीति के अन्तर्गत भारत की ओर से तिब्बत को किसी भी सैनिक सहायता का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि वह किसी भी राष्ट्र-शक्ति को ऐसे राज्यों में अधिकार जमाने से रोके जहाँ से भारत की सुरक्षा को सतर्क पहुँचने की आवश्यकता हो। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह था कि राष्ट्र देश को तिब्बत के उन इलाकों पर बन्ना करने से रोका जाये जहाँ से भारत पर हवाई आक्रमण करना या रॉकेट मिसाइल छोड़ना सम्भव है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि सेप्टिमेंट जनरल सर फ्रांसिस टुकर ने, जिन्होंने कई वर्षों तक भारतीय सेना में काम किया था और स्वतंत्र भारत में पूर्वी बमबोर्डा के सेनापति के पद से पञ्जाब ग्रहण किया

था। भारत की प्रतिरक्षा नीति के बारे में इसी बात पर जोर दिया है। 'व्हाइट पेपर सर्वेस' नामक अपने संस्मरणों में उन्होंने लिखा है :

"शत्रु के दृष्टिकोण से देखते हुए, अब से कुछ वर्षों के बाद तिब्बत ही वह प्रदेश होगा जहाँ से पूर्वी भारत को हवाई आक्रमणों का निशाना बनाना सम्भव होगा। तिब्बत के वह प्रदेश जो दूरस्थ इलाकों की बमबारी के लिए उपयुक्त हैं ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से हवाई आक्रमणकारियों के दस्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार ५० पी०, बिहार और बंगाल पर हवाई आक्रमण और कब्जा करना सुविधाजनक हो सकता है। इसलिए भारत का हित इस बात में है कि वह किसी भी तरीके से तिब्बत के पठार पर चीन का अधिकार न होने दे। और इसको रोकने का एक तरीका यह है कि वह पहले से उस पठार के चुने हुए हिस्सों पर अधिकार कर ले।"

भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद और उसके साथ ही चीन के द्वारा तिब्बत की 'राजनैतिक भुक्ति' की सम्भावनाएँ स्पष्टतर होने के कारण नई दिल्ली में काफ़ी सरगर्मी पैदा हो गई। मूलतः इस सरगर्मी के पीछे यह भय था कि पूरी फैली हुई हिमालय पर्वतमाला में बिखरे हुए अनगिनत दरों से कितने ही साम्यवादी तिब्बत से भारत में घुस सकते हैं।

इसको रोकने का एक उपाय था और वह था ल्हासा की सरकार को शक्तिशाली बनाना और इसके लिए आवश्यक था, (१) ल्हासा में भारतीय सैनिक मिशन की स्थापना, (२) ग्यान्तसे में स्थित भारतीय सैनिक दस्ते की शक्ति को एक कम्पनी से बढ़ाकर एक बटालियन कर देना; (३) तिब्बत को अस्त्र-शस्त्रों की सहायता देना; (४) ग्यान्तसे-गंगटोक मार्ग को ठीक करना; (५) तिब्बती सेना को भारत में प्रशिक्षण देना, और (६) प्रमुख तिब्बती परिवारों को भारत में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देना।

देश की सुरक्षा को कोई खतरा न हो इसके लिए यह भी प्रस्तावित किया गया कि शुम्बी घाटी पर भी, जो भारत के उत्तर-पूर्वी सीमान्त में कटार की तरह घँसी हुई है, अधिकार कर लिया जाये।

भारत सरकार ने राजनैतिक कारणों से ल्हासा में सैनिक मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया। तिब्बत को अस्त्र-शस्त्रों की सहायता देने की बात से भी भारत सरकार किमती और ग्यान्तसे में अपनी चौकी की सैनिक शक्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का साहस भी वह न बटोर पाई। यह सारी चीजें ऐसी थीं जिन्हें दलाइलामा की सरकार जी जान से चाहती थी।

दिया जिसने अनुमति देगी मे चीन की सातव्व सरकार की प्राप्तिप्राप्ति  
होगी या न हो ।

उसी वक, निम्बर ५१ म जब गन फामिली में ५६ राष्ट्र जापान के  
साथ गान्ति-सहि करने के लिए एकत्र हुए थे ता भारत ने उसमें शामिल होने  
से इनकार कर दिया था क्योंकि और कारणों के अलावा चीन की सौवतव  
सरकार का उसके लिए शामिल नहीं दिया गया था । नम्बर तन् १९५१  
की सङ्गत राष्ट्र की बैठक में भारत ने इस बात पर फिर जोर दिया कि चीन  
का प्रतिनिधित्व उसकी नवी सौवतव सरकार ही करे । उसके बाद तन् १९५५  
तक, सातव्व नाम भारतीय प्रतिनिधि मध्य बनी मुम्बई । यही राय प्राप्ति  
रहा ।

मई, तन् १९५५ में थी नेहरू न स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की  
कि कोरिया के बारे में भारत ने जो प्रस्ताव सङ्गत राष्ट्र में रखा है वह पूरी  
तरह कोरियाई युद्ध के बँदियों के मामले में मात्र चीन के दृष्टिकोण का प्रति-  
निधित्व करता है । यह प्रस्ताव बहुत बड़े बहस से स्वीकार किया गया । और  
जब वन में इन बँदियों के विनिमय के लिए सङ्गत राष्ट्रों का एक समीपन  
नियुक्त किया गया तो भारत ने उनका समायोजन स्वीकार कर लिया ।

दिसम्बर, १९५५ म भारत सरकार ने तिब्बत और भारत के सम्बन्धों  
के बारे में पश्चिम म एक वास्तविक मुद्दा दिया । यह कदम भारत सरकार ने  
इस बात और उद्देश्य से उठाया था कि चीन की वर पुनर्प्राप्ति समस्याएँ मुक्त  
जाएँगी और चीन तथा भारत के बीच नवी और सहकारिता के सम्बन्ध दृढ़तर  
हो जाएँगे ।

जब किसी दूसरे देश ने सङ्गत राष्ट्र म तिब्बत के सम्बन्ध में मानकी  
प्रतिकारों का सवाल उठाया तो थी वृण मेनन ने उसके उत्तर में यह दलील  
पेश की थी कि वेतिंग की सरकार सङ्गत राष्ट्र की सदस्य नहीं है इसलिए  
तिब्बत म मानकी प्रतिकारों का मुचलने के लिए सङ्गत राष्ट्र उसे दोषी नहीं  
ठहरा सकता । थी मेनन ने यह नहीं सोचा कि तिब्बत के मामले में सङ्गत  
राष्ट्र के इस प्रस्ताव से 'जाति का पण और भी दृढ़ हो सकता है ।' भारत  
सरकार का यह रज था कि चीन या तिब्बत के धर्मकी मामलों में दखल  
देने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और यह कि उक्त सभ्यता धर्म नीत-मुद्द  
के मुद्दा में उँक गयी है ।

फलो की देखने हुए यही नीति निजलता है कि चीन की सौवतव सर-  
कार की मित्रता और उसका सहयोग प्राप्त करने म भारत पूरी तरह प्रसन्न  
रहा —सात चीन पूर्ण निर्भरता और निम्ब के साथ अपने इस पूर्वनिश्चित  
कार्यक्रम को पूरा करने में लगा रहा कि भारत की हानि प्रदेक्षार भी तीनी

देशों की सीमाओं को 'ठीक तरह से' निर्धारित करे। लेकिन अगले कुछ वर्षों तक, कोरियाई युद्ध में पहुँची हुई सतियों को हमवार करने के लिए, चीन के हित में यही था कि अपने सींग न दिखाये और शांति का नकाव पहिने रहे। इसलिए साँप की फुफकार को दबाकर उसने शांति के कबूतर की तरह गुटरगुट करना शुरू कर दिया।

२६ अप्रैल, १९५४, को चीन और भारत ने सुप्रसिद्ध पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किये—यह समझौता भारत और तिब्बत के बीच व्यावसायिक और आवागमन की सुविधाओं के बारे में था। इसके बाद नयी दिल्ली ने हर मामले में तिब्बत की ओर से हाथ खींच लिया।

जो भूमि सम्बन्धी अधिकार और सुविधाएँ स्वतन्त्र भारत की सरकार को अंग्रेजों से विरासत के रूप में मिली थी उन्हें नयी दिल्ली ने त्याग दिया और यह स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का खंग है। पंचशील समझौते में केवल व्यावसायिक एजेन्सियों का, वाजारों का और यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों का उल्लेख था और आपसी सीमा के आर-पार व्यवसाय तथा आवागमन के नियम निर्धारित किये गये थे।

यही नहीं, नयी दिल्ली ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि वह यातुंग और ग्यांत्से से अपने सैनिक दस्तों को हटा लेगी और तिब्बत में स्थित अपनी डाक, तार और टेलीफोन की चौकियों तथा डाक-बंगलों को चीनी सरकार को सौंप देगी।

इस समझौते के अन्तर्गत २६ अक्टूबर, १९५४, को यातुंग और ग्यांत्से में स्थित भारतीय सैनिक दस्तों को वापस बुला लिया गया।

भारत की सहृदयता के उत्तर में चीन ने उन पाँच सिद्धांतों को स्वीकार किया जिनका उल्लेख पंचशील समझौते में था। यह पाँच सिद्धांत थे : (१) एक-दूसरे के प्रादेशिक संगठन और राज्यसत्ता को मान्यता देना, (२) एक-दूसरे पर आक्रमण न करना, (३) एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करना, (४) साम्य और एक-दूसरे के लाभ का स्वाभाव रखना और (५) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

सन् १९५५ के वांग्दुंग सम्मेलन में श्री नेहरू अपने चहेते चाउ इन-साई को अपने साथ लाये और अफ्रीकी तथा एशियाई नेताओं से उन्होंने उनका परिचय कराया। भारत और चीन का प्रेमवाप इस समय पूरे जोर-शोर से चल रहा था।

लेकिन इसके बावजूद सचार्ई यह भी कि भारत के सामने, उसके उत्तर-पूर्वी सीमान्त पर, एक ऐसी नयी और सतरनाक परिस्थिति भुँह बाये खड़ी थी जिससे शक्तिशाली अंग्रेज साम्राज्यवादी भी डरते थे और जिसे रोकने के लिए वे एक शताब्दी से कड़ा प्रयत्न कर रहे थे।

भारत और चीन के बीच का प्रतिरोधक क्षेत्र खत्म हो चुका था और अपने सीमाना पर भारत का सीधा सम्पर्क एवं आसन्न शांतिवादी, अतिरिक्त नीति के, आक्रमण प्रवृत्त पड़ोसी में था। चीन तथा राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्नतम का पठार सब एक ऐसी सम्भावित शत्रु के हाथ में था जिसने पड़ोसी देशों के बारे में अपनी निम्नतम की वित्तीय क्षमता नहीं रखी थी।

द्विज दिन से चीनी साम्यवादियों ने पेरिंग में शासन की बागडोर सम्हाली थी उसी दिन से उनके विचारों और उनकी नीतियों के दो मुख्य उद्देश्य थे (१) एक स्वतंत्र और महान शक्ति का मोहदा हाथिल करना, और (२) राज्य की सीमाएँ स्थापित और निम्नतम सब पैना देना। अमरीका के सहायक सैनिक प्रतिरक्षण के कारण ताइवान पर विजय प्राप्त करना तो इतना आसान नहीं था लेकिन निम्नतम की आसानी से हृदय तितना था करना था।

चीन के द्वारा निम्नतम पर अपना अधिकार जताने और जमाने में उनका यह निश्चय भी मूलतः आसन्न था कि वे निम्नतम और भारत के बीच की सीमाओं की 'सुधारना' चाहते थे।

यह उद्देश्य सभी पूरा हो गये थे जब चीन सैनिक दृष्टि से अचल सशक्त हो जाए। पेरिंग की साम्य सरकार आरम्भ से इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी सारी शक्ति लगा रही थी।

'यन्त्र की भाँती से शक्ति पैदा होती है' चीनियों के महान पैगम्बर माओ-त्से-तुंग ने कहा था। और माओ का यह विश्वास था कि, 'युद्ध समय का सबसे उच्च रूप है। वेगल इसी के द्वारा, विश्रम के किसी स्तर पर, कर्तव्य, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजनैतिक दलों के बीच के भेद और विरोध खत्म किये जा सकते हैं।'।

दमनिक अपना पूरा आर लगाकर पेरिंग में विश्व की सबसे विनाश केन्द्र गठित की और सारे राष्ट्र की पीसकर, उसको बलि चढ़ाकर मारी राजनैतिक प्रतिभा तथा आर्थिक साधन धन्युक्ति की विकसित करने में लगा दिया।

इस गरीब शक्ति-युद्ध और निर्मम कूटनीति के मुकाबिले में था श्री नेहरू का सरल, बुद्धिमत्ता और आदर्शवाद और 'सत्यमेव जयते' में अद्विग विश्वास— एक ऐसा राजनैतिक दर्शन जो युद्ध की असम्य मान्यता था और वर्तमान धन्यु-युग में युद्ध की एक केन्द्र, दक्षिणावृत्ति और समझता था।

इस अव्यावहारिक दृष्टिकोण का एक ठो उदाहरण है श्री नेहरू का यह वक्तव्य जो उन्होंने भारतीय और चीनी अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल की



रिपोर्ट पर बार्ता करते हुए दिया था। श्री नेहरू ने कहा था :

“केवल यही बात कि हम बिना झुके या पीछे हटे एक सही दृष्टिकोण पर अटल हैं, हमारी शक्ति प्रदर्शित करता है और इससे कुछ निश्चित तथा स्थायी फल अवश्य पैदा होते हैं। आज गले ही यह असम्भव लगे लेकिन मैं हमेशा यह सम्भव समझता हूँ कि हमारे दृष्टिकोण के ओचित्य का और उस पर अटल रहने में प्रदर्शित हमारी शक्ति का एक न एक दिन चीनी सरकार पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। और यदि ऐसा है तो मैं निरन्तर और पूरे जतन से इस बात की कोशिश करूँगा कि वे सत्य के प्रति हमारे इस आग्रह की सराहना करें, उसे समझें और यह स्वीकार करें कि उन्होंने एक गलत काम किया है जिसे उन्हें अब मन्द कर देना चाहिए।”

क्या धृष्ट था यह ‘आध्यात्मिक शक्ति’ और कुटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मुकाबले का ! कौसी आत्म-प्रवंचना थी जो इस गंगे गथापं को देखने से इनकार करती थी कि राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप मूलतः निर्धारित होता है आत्म-लाभ और आत्म-प्रतिष्ठा की अदमनीय आकांक्षाओं से और इसलिए इन राष्ट्रों के दिल इस्पात के बने हैं और उन्हें ‘आध्यात्मिक शक्ति’ तथा उचित-अनुचित के नैतिक मानदण्डों से बदला नहीं जा सकता।

यह बात बड़ी आसानी से मान ली जानेवाली है कि ‘जिसकी लाठी उसी की भैंस’ की नीति, जिस पर अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने १९ वीं सदी के उत्तरार्ध और २० वीं सदी पूर्वार्ध में व्यवहार किया था, द्वितीय महायुद्ध के बाद के युग से काम में नहीं लायी जा सकती थी और यह कि सन् ‘५० या ५६’ में भारत इस स्थिति में नहीं था कि तिब्बत में चीन के आक्रमणशील अतिक्रमण को रोक सकता।

जनतन्त्रात्मक भारत सैनिक होड़ में चीन की उस साम्यवादी तानाशाही से कभी नहीं जीत सकता था जो धी-धूप के स्थान पर बन्दूकों को प्राथमिकता देती थी और जिसने पूरे राष्ट्र को एक सुसंगठित चौकी बना दिया था।

विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि चीन ने अपने सीमान्त के पास के सारे हिमालय प्रदेश को सैनिक रूप से सुसज्ज कर दिया है। सन् १९६२ तक विस्तृत सीमान्त पर लाखों चीनी सैनिक पूरी सैनिक तैयारी के साथ जुटा दिये गये थे। पूरा दक्षिणी तिब्बत एक विशाल छावनी में परिवर्तित कर दिया गया था। जिसका स्पष्ट, एकमात्र उद्देश्य यह था कि वहाँ से आगे के क्षेत्रों पर छापा मारना आसान हो जाता है—इसके अलावा ऐसा करने में चीनियों की कोई नियत हो ही नहीं सकती थी क्योंकि न तो इतनी जबरदस्त तैयारियाँ

तिब्बत को अपने अधिकार में रखने के लिए आवश्यक थीं और न दक्षिण में आक्रमण की कोई सम्भावना थी।

जदरदस्त भाषा में जान और मास व्यव करने चीनियों ने हम दुर्गम इलाक़ में मार्गों के सैनिक भागों का निर्माण किया और इनमें से बहुत सी सड़क ऐसी हैं जिन्हें बड़ी से बड़ी सड़क में एलेमास किया जा सकता है। उन्होंने हवाई घाड़ों का भी निर्माण किया। दुर्गम में दुर्गम प्रदेश में साल भर काम करनेवासी अनेक सैनिक चौकियाँ स्थापित की गयीं और आवागमन के सूत्रों का जाल बिछा दिया गया।

अनुमान यह लगाया जाना है कि बेदत तिब्बत में ही १५ डिभिजन में विभक्त लगभग दो लाख चीनी सैनिक हैं। यह भी सूचना मिली है कि चीनी बराबर अपने हवाई बेशा का जाल फैलाने चले गये हैं—विशेषण लहामा और उनके आसपास के इलाका में—और कई स्थान पर उड़ाने गये राक्षस भी लगा दिये हैं।\*

भूमि, जल और हवाई मेनारों में कुल मिलाकर चीन की मोठ मुक्ति सेना में लगभग २५ लाख सक्रिय सैनिक हैं। भूमि सेना में ढेर ही डिभिजन हैं और हर डिभिजन में १० से १२ हजार तक सैनिक हैं। चीनी भूमि-सेना की व्यवस्था साबितन फ़स की भूमि-सेना की तरह है।

एकै अलावा जल-सुरक्षा सेना में पाँच लाख से ऊपर सैनिक हैं जो सीमान्त प्रतिरक्षण तथा भन्दरनी सुरक्षा के निर्देशर हैं। यही नहीं बल्कि एक अर्धसामयिक सैनिक संगठन भी है जिसके करोड़ों से ज्यादा सदस्य हैं। सन् १९५५ में अनिवार्य सैनिक सेवा कानून पास किया गया था जिसमें अनुमार १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर मर्द फ़ौजी सेवा के लिए बाध्य है।

इसके मुकाबिले में भारत की स्थानी सेना (जल और हवाई सेना को छोड़कर) की संख्या लगभग दस लाख है और यह भी चीनी तथा पाकिस्तानी मोर्चों में विभक्त है।

ऐसी परिस्थिति में तिब्बत में दस-बस के साथ जमे हुए चीन से भारत अपने सीमान्त की रक्षा करने के लिए कर भी क्या सकता था?

पहली भयानक भूल तो यह थी कि लगभग शुरू से ही चीन के दानुता-पूर्ण इरादों का पता होने पर भी अपने प्रतिरक्षा संगठन को छिन्न-भिन्न होने देना और चीन द्वारा मैत्री तथा शांति के दावों में आश्विवास करना। यही एक भोपा भूल उन सारी तक़्तियों की जड़ थी जो सन् १९५६ के बाद भारत के लिए पैदा हुई।

\* १८ अगस्त १९५६ के "न्यूयॉर्क टाइम्स" में इरिस्तेन-सैनिकारी के एक लेख के अनुसार।

‘भाई-भाई’ की सरल और निष्कपट मनोवृत्ति (जो हमारे अन्धविश्वास का परिणाम थी) के कारण भारत ग्यारह वर्ष की चेतावनी के बावजूद चीनी आतंक का मुकाबिला करने के लिए तैयार न हो सका ।

यह कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं था कि सन् १९५० तथा उसके बाद तिब्बत में चीनी उपद्रवों से भारत को चेतावनी नहीं मिली—सारी गड़बड़ इस बात से हुई कि श्री नेहरू ने पूरी तरह केवल कूटनीति पर—अपनी पसन्द की सत्यवादी नीति पर—ही विश्वास किया । चीन से सम्भावित खतरे का मुकाबिला करने के लिए और इसके लिए नीति के परम्परागत अस्त्र-सैनिक-शक्ति को रह कर दिया !

श्री नेहरू अपने इस आदर्शवाद में स्वयं बह गये थे कि आधुनिक युग में युद्ध की नीति—अस्त्र होना अनुचित है और उसकी जगह वैयक्तिक नीति तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में समझौते के साधनों का प्रयोग करना ही उचित है ।

दो

## नक्सोवाजी का दौर

कहानी दरमस्त काफ़ी पढ़ने से शुरू होती है। उस समय भी बहुचर्चित और बहुप्रचलित पंचशील सम्झौते पर—जिसमें दोनों देशों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कसम खायी थी और एक-दूसरे की प्रभुत्व सीमाओं तथा प्रादेशिक प्रसङ्गना का धाँवर करने का दावा किया था—हस्ताक्षर किये जा रहे थे, पकिंग ने इस बात के बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू कर दी थी कि 'सममान क्षेत्र विभाजन को सुधार दिया जाये।' चीनी पाँव ठले धाँस उगने के ज़ायल नहीं थे।

चीनी कार्रवाई ने रूप लिया नक्सोवाजी के युद्ध का। उन्होंने जो मानचित्र बटवाये उनमें २,६०० मील सम्बन्ध भारत तिब्बत सीमा से सगे हुए भारत भूमि के कई हिस्सों को चीन का भग्न दिखाया गया था।

सन् १९५४ में जब श्री नेहरू पकिंग गये तो उन्होंने चाउ-इन-लाई का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। चाउ-इन-लाई ने श्री नेहरू को आश्वासन दिया कि यह नक्शे पिछली बुद्धो-मिनतांग सरकार के बनाये नक्शों की प्रतिलिपियाँ थी जिन्हें ठीक करने का समय नयी सरकार को अब तक नहीं मिला था।

यही नहीं, चाउ इन-लाई ने श्री नेहरू की इस बात का समर्थन किया कि सीमा का मसला गौण है, कि जिन भूमि-खण्डों की स्थिति सन्देहात्मक है वे अधिकतर निजन प्रदेश हैं और इन पर किस देश का अधिकार है यह बात सहृदयता और समझौते में तय की जा सकती है।

लेकिन सन् १९५९ में चीन ने जो नये नक्शे निकाले उनमें न केवल पुराने सन्देहात्मक स्थिति के क्षेत्रों को फिर से चीन का भग्न बताया गया था

वल्कि इस बीच में लद्दाख प्रदेश में चीन ने भारत के जिन हिस्सों को हड़प लिया उन्हें भी चीन का ही अंग बताया गया था । उस वर्ष जब चाउ-इन-लाई भारत आये तो श्री नेहरू ने उनसे फिर इन गलत नक्शों के बारे में बात की ।

चीनी प्रधान मंत्री ने कहा कि यद्यपि उन्हें अंग्रेजी साम्राज्यवादियों द्वारा चीन पर थोपी गयी मैकमहॉन रेखा के सीमा विभाजन से आपत्ति है फिर भी उन्होंने उसके अनुसार चीन और बर्मा के बीच की सीमा स्वीकार कर ली है और भारत के साथ भी उस रेखा के अनुसार सीमा विभाजन को स्वीकार करने का उनका इरादा है ।

साथ ही चीनियों ने अपने ऊपर से दोष हटाने के लिए एक और तरीका निकाल लिया—उन्होंने उल्टे भारत को यह दोष देना शुरू कर दिया कि उसने सीमान्त के पूर्वी भाग में 'गैर कानूनी' मैकमहॉन रेखा के दक्षिण में स्थित चीनी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया है तथा मध्य और पश्चिमी भागों के चीनी इलाकों में भारतीयों ने प्रवेश कर लिया है ।

चीनियों ने अपने गलत मानचित्रों को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया और उन्हीं को प्रचलित रखा । यही नहीं वल्कि मानचित्रों में भारत के जिन इलाकों को उन्होंने चीन का अंग बताया या उन्हें वास्तव में चीन का अंग बनाने के लिए उन्होंने सैनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी ।

पेकिंग सरकार को लिखे गये एक पत्र में श्री नेहरू ने इस बात पर आश्चर्य प्रगट किया कि यदि चीन को मैकमहॉन रेखा द्वारा निर्धारित सीमा विभाजन से कोई आपत्ति थी तो उन्होंने यह प्रश्न उस समय क्यों नहीं उठाया जब सन् १९५४ की संधि के बारे में बातचीत चल रही थी । इसके उत्तर में चाउ-इन-लाई ने मित्रता का नक्काब उतार फेंका और स्पष्ट रूप से यह कहा कि सीमा की बात उस समय केवल इसलिए नहीं उठायी गयी थी कि उस समय तक सीमान्त का फैसला करने के लिए परिस्थिति 'परिपक्व नहीं थी ।'

उसी पत्र में चाउ ने आग्रहपूर्वक यह भी कहा था कि भारत-चीन की सीमा को कभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया था और ऐतिहासिक रूप से चीन और भारत के बीच इस विषय पर कभी कोई संधि या समझौता नहीं हुआ था ।

“इसका सबसे निकटतम उदाहरण है चीनी सिक्कांग का उद्गुर स्वाशासित प्रदेश जो हमेशा से चीन का अंग रहा है ” चाउ ने जोर देकर कहा था । “चीनी सरकार के सीमा प्रहरियों ने हमेशा से इस प्रदेशों में गलत लगायी है और सन् १९५६ में निमित्त सिक्कांग-तिब्बत मार्ग इस प्रदेश में से होकर गुजरता है ।”



दलाई लामा ने इस गड़कती हुई आग में घृताहुति दे दी । २० जून, १९५६ को मसूरी में एक पत्र-सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की कि तिब्बत एक स्वतन्त्र सत्ताधारी राज्य था जब उसने १९५० में चीन से सन्धि की थी और इस बात पर आग्रह किया कि यह सन्धि 'दो स्वतन्त्र सत्ताधारी राज्यों के बीच हुई थी ।'

तिब्बत के देह-राजा ने चीन से आन्दो और खाम नामक इलाकों की, जिन्हें चीन बहुत पहले हड़प करके अपने राज्य में मिला चुका था, वापसी की माँग करके बृहत्तर तिब्बत बनाने का भी दावा किया । उन्होंने यह भी कहा, "हम और हमारे मंत्रीगण जहाँ भी हों, तिब्बत के लोग हमें ही अपना शासक स्वीकार करेंगे ।" और उन्होंने भारत से निवेदन किया कि जो सहानुभूति और सहायता भारत ने अल्जीरिया तथा अन्य एको-एशियाई देशों को उनके स्वतंत्रता-संघर्ष में दी थी, वही भारत को चाहिए कि तिब्बत को भी दे ।

८ सितम्बर, १९५६ को श्री नेहरू को लिखे गये पत्र में चाउ इन-लाई ने पहली बार भारत के उन इलाकों पर खुल कर दावा किया जो अब तक सिक्किम, चीनी मान-चित्रों में चीन का अंग बताये गये थे । इस इलाके का क्षेत्रफल लगभग ५०,००० वर्ग मील था जो इंग्लैण्ड के बराबर है । इसके पहले चाउ इन-लाई ने बराबर यह कहा था कि यह मानाचित्र कुओमिन्तांग सरकार के बनाये हुए हैं और चीन की नयी सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हैं ।

उक्त पत्र में चाउ इन-लाई ने खुल्लमखुल्ला कहा कि "चीन की सरकार मैकमहॉन रेखा को कतई स्वीकार नहीं करती ।" उन्होंने यह भी कहा, "परम-श्रेष्ठ ने अपने पत्र में चीन तथा सिक्किम के बीच की सीमा का भी चित्र उठाया है । चीन और भूटान के बीच की सीमा की तरह इस सीमा का प्रश्न भी हमारी वर्तमान बातचीत का अंग नहीं है ।" यूँ चीन ने भारत को यह चेतावनी भी दी कि वह इन दो पर्वतीय राज्यों के साथ भारत के विशेष सम्बन्धों को स्वीकार नहीं करता ।

इस बीच चीन मान-चित्रों की बहुत छोटकर सक्षिप रूप से मैदानेजंग में उतर आया था । अत्यन्त सुनिश्चित और निर्भय ढंग से उसने सारे सम्बन्धों को छोड़कर गोली-बाखूब से समस्याओं को हल करने का सिलखिला शुरू कर दिया था ।

सन् १९५३ में तिब्बत-भड़वाल सीमा को पार करके चीनियों ने भारत में घुसने का प्रयत्न किया था जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल में नेलांग नामक रापनी चीकी को और भी सशक्त बनाया था ।

जुलाई, १९५४ में—लगभग उस समय जब चीन तथा भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे—चीन ने तिब्बत-उत्तर प्रदेश सीमा के अन्य

क्षेत्र बाराहोती में भारतीय सैनिका की उपस्थिति के खिलाफ आपत्ति की दी & यह पहला मौका था जब चीन ने भारत को यह बताया था कि बाराहोती उसके राज्य का अंग है।

भारत सरकार की एक विज्ञप्ति ने इस बात को दबाने का प्रयत्न किया था और कहा था कि बाराहोती १६,००० फुट की ऊँचाई पर दो वर्गमील की जगह है जिसका प्रतिरक्षा या अन्य किसी दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। "भारत-निबन्धन सीमा पक्के तौर पर निर्धारित है। यह प्रश्न त्रिभुज माथूली का है कि यह छोटा सा प्रदेश सीमान्त के उत्तर में है या दक्षिण में।"

उसने अपने वर्ष जून में चीनी सेना ने बाराहोती में छावनी बनायी और सितम्बर, १९५५ में यह नीली दर्रे से दक्षिण में दग भीम प्रन्दर तब घुस कर हमजान पहुँच गई।

सितम्बर, १९५६ में हिमाचल प्रदेश-निबन्धन सीमा के गिपकी ला प्रदेश में चीनी तथा भारतीय पुलिस दलों के बीच गोमी चलने से तनाव और भी बढ़ गया। २४ सितम्बर के स्मारक-पत्र में भारत सरकार ने चीन को यह सूचना दी कि भारत के सीमान्त प्रतिरक्षण दल को यह आश्वासन दे दी गई है कि 'वे अपनी जगह से किसी हालत में भी न हटें और चीनी दल को तिल भर भी आगे न बढ़ने दें बल्कि ही ऐसा करने के लिए उन्हें धक्का भी उठाने पड़ें। साथ ही भारत सरकार ने चीन को यह चेतावनी दी कि चीन यदि अपनी छिट-मुट छापामारी कारवाइयों को बन्द नहीं करता है तो "दली देशों की सीमा पर सशस्त्र भगड़े हो सकते हैं।" लेकिन चीनी अपनी हकतो में बाध नहीं आये और बाद में भारत की सामोसी से यह सिद्ध हो गया कि भारत द्वारा चीन को दी गई चेतावनी में कोई कम नहीं था।

प्रधान मंत्री श्री नेहरू के कथनानुसार भारत के सीमान्त प्रदेशों में इनके-इन्के चीनी सैनिक दल "छोटे-मोटे छाये मारते रहे।" २८ अगस्त, १९५६ को श्री नेहरू ने लोक सभा में कहा, "यह कोई अनहोनी बात नहीं है क्योंकि सीमा का कोई निश्चित विभाजन नहीं है और दूसरे देश के दल कभी-कभी सीमा को लाँघ सकते हैं। सन् १९५७-५८ में हमने चीन की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और वे पीछे हट गये थे। यह बात वही खत्म हो गयी थी।"

अक्तूबर, १९५७ में चीनियों ने पहली दफा नेफा के लोहित सीमान्त द्विबिन्दु के बालोग नामक स्थान में प्रवेश किया था। सन् '५६ में दलाई लामा के भारत में आ जाने के बाद चीनियों ने नकाब उतार फेंका और सीमान्त के परिषदा तथा पूर्वी इलाकों (विशेषतः कामेन्ग खड में वहाँ से दलाई लामा भारत आये थे) में खुल कर और बार-बार से छाये मारने शुरू कर दिये।



साथ ही तिब्बती शरणार्थियों के भाग कर भारत में आने का कायदा भी चीनियों ने पूरी तरह उठाया। शरणार्थियों के इन दलों के साथ दर्जनों चीनी जासूस भारत में घुस आये। यह गुप्तचर सूत्र-खसल और व्यवहार में सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के लोगों से इतने मिलते-जुलते थे कि उन्हें पहिचानना असम्भव था और इसलिए यह आसानी से पूरे आसाम और नेफा में फैल गये। वे अधिकतर तिब्बती भड़कियों और मजदूरों के वेष में आये थे और गोहाटी, डिब्रूगढ़ तथा सिल्चर के आस-पास बस गये थे। चीन का समर्थन करने वाले भारतीय साम्यवादियों की सहायता से इन्होंने इन इलाकों में एक विस्तृत जासूसी जाल बिछा दिया था।

बोमदी ला के उत्तर में चीनी आक्रमण से दो वर्ष पहले बनी हुई तीबांग तथा नेफा के सैनिक और शासकीय केन्द्र तेजपुर के निकट मिसीमारी को मिलाने वाली नई सड़क के पास एक छोटे से गाँव में एक चीनी जासूस चाय का होटल चलाता रहा। बोमदी ला के दक्षिण में, चाकू नामक गाँव में एक चीनी जासूस भदोठारह महीने तक बैतार से खबर भेजता रहा और उसके बाद वह पकड़ा गया।

सन् '६२ के आक्रमण से पहले के कुछ महीनों में चीनी विमान २५ बार अवैध रूप से नेफा के ऊपर उड़े। स्पष्ट है कि यह उड़ानें हवा से ही तस्वीरें खींचने और जानकारी प्राप्त करने के लिए की गयी थीं।

भारतीय प्रतिरक्षण दल ने बहुत पहले से स्थानीय अधिकारियों को यह सूचना दे दी थी कि उस प्रदेश में चीनियों का जासूसी जाल बढ़ता जा रहा है लेकिन उनको यह शिकायत थी कि अधिकारियों ने उनकी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया था।

जून में चीनी सरकार ने यह झूठा आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने तिब्बत-नेफा सीमा पर मिगाईतुन के पास चीनी इलाके में प्रवेश किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमारी सेनाओं ने तिब्बती विद्रोहियों के साथ मिल कर चीन की लोक सरकार के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई की है।

दिल्ली सरकार ने इन आरोपों से इन्कार किया और इस बात पर आश्चर्य प्रगट किया कि चीन की सरकार ने ऐसी अफवाहों पर विश्वास किया है। भारतीय सैनिक दस्ता जिस स्थान पर था वहाँ से सैनिक भी आगे नहीं बढ़ा था।

जुलाई में भारत सरकार ने बेकिंग से इस बात पर आपत्ति की कि चीनी तिब्बत में भारतीय अधिकारियों और भारतीय व्यापारियों तथा यात्रियों के रास्ते में कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं।

२८ जुलाई को सहाय में लोफुंग-से और झुला-से से २० मील दक्षिण-पूर्व में चीनियों ने छः भारतीय सैनिकों के दस्ते को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पहले

वे स्थागुर में अपनी चौकी पर तथा बाद में रदों से गये। फल में यह छः भारतीय सैनिक १८ अगस्त का स्थागुर में छाड़ दिये गये।

भारत में चीनियों ने चुंगुन के भारतीय एवार्ड ब्रडटे के पास की एक पहाड़ी पर एक पर्यवेक्ष चौकी स्थापित की। २७ भारत की स्थागुर से २२ मील दक्षिण में रेडग मा के पास चीन १ अगस्त ध्वज आरोहित किया। यह स्थान हमारी सीमाओं के तीस मील छन्दर था।

उसी महीन भारतीय सेना के परिधिधी बमाल ने यह सूचना दी कि दक्षिण लगुन के गार्डराग नामक स्थान पर चीनी एक बटापियन से अधिक सैनिक हैं और निम्नत के तांगिगाग नामक स्थान को वहाँ से मिलान के लिए तीन टन की एक माल बनाई जा रही है।

दूसी बीच मफा मार्च पर दो सौ सगस्त चीनिया के एक दस्ते ने ७ अगस्त को लिगमान के पास हमारी सीमा में की। वहाँ पर स्थित भारतीय टुकड़ी चीनियों ने कहा कि वे पीछे हट जायें लेकिन हमने उत्तर में उन दो सौ सगस्त चीनिया में हमारी बारह सैनिकों की टुकड़ी का डोबन साबा के पुन मक पीछे लदेह दिया। किसी तरह के मानकों ने गोपिया नहीं बताई। कुछ समय बाद चीनी पीछे हट गये और हमारी टुकड़ी पुन अपने स्थान पर वापस लौट आई।

लेकिन चीनी दस्ता कुछ दिना बाद फिर वापस लौट आया और उसने माँ की कि हमारी टुकड़ी फौरन अपनी जगह से हट जाये और भारतीय ध्वज नीचे उतार दिया जाये। हमारे सैनिकों ने इन धारणों को मानने में इन्कार कर दिया। श्री नेहरू ने फोच समा को बताया कि चीनी दस्ते ने हमारी टुकड़ी को वहाँ से छेड़ने का फिर प्रयत्न किया लेकिन हमारी टुकड़ी अपने स्थान पर अविकल रही और बाद में वहाँ अन्य कोई घटना नहीं हुई।

अगस्त के अन्त में चीनियों का एक ज्यादा बड़ा दस्ता मिगाईनुन के दक्षिण में, लागजू के पास सुबनचिरी सीमांत डिवीजन में हमारे देश में घुस आया और गोनाबारी शुरू कर दी। २००-३०० चीनी सैनिकों के इस दल ने भासाम राइजिन्स के बारह सैनिकों को घेर कर बँद कर लिया। इनमें ही आठ सैनिक चीनिया के अंगुल से बच कर आग निकले और लागजू में स्थित अपनी चौकी पर वापस लौट आये।

कुछ समय बाद चीनी फिर लौट कर आये और उन्होंने हमारी एक मुख्य चौकी को घेर लिया जिसकी शक्ति ३० सैनिकों की थी। काफी समय तक गोलाबारी चलती रही लेकिन अन्त में, विरोधियों के अत्यन्त सफल होने के कारण, हमारी टुकड़ी को लागजू से हटना पड़ा।

नियमों के अनुसार भारत सरकार ने लांगजू में हुई घटना के खिलाफ चीनी सरकार से आपत्ति प्रकट की। साथ ही, भारत सरकार ने नेफ्रा का इलाका पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में कर दिया।

सितम्बर तक चीनी लड़ाख क्षेत्र में और भी आगे बढ़ आये और उन्होंने चुशुल-रेजांग ला में अपनी एक कम्पनी, तिंगचांद में एक कम्पनी तथा बटा-लियन हूड क्वार्टर और उंबोगुरु के ठीक दक्षिण में खुर्नाक-फोट-मण्डल में एक कम्पनी स्थापित की। कुछ ही दिनों में चीनियों ने अपनी चौकी स्पांगुर भील के उत्तरी छट से हटाकर, चुशुल से नौ मील पूर्व टूला नामक स्थान पर, जो स्पांगुर भील के दक्षिणी छट पर है, स्थापित कर दी।

इस घटना फ्रम से यह स्पष्ट है कि तनाव बराबर बढ़ता जा रहा था और चीनी छलांगे मार-मार कर भारत भूमि पर बढ़ते आ रहे थे।

२० अक्तूबर तक चीनी सेना दक्षिणी लड़ाख की घांघ जेनमो घाटी में चालीस मील अन्दर तक घेस आई थी। रास्ते में कोंगका दर्रे के पास भारतीय पुलिस दल ने उनका मुकाबला किया था लेकिन चीनियों ने जबरदस्त गोला-बारी की और नौ भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। भारतीय दल के दस सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। इनमें से करमसिंह नामक एक वीर अधिकारी भी थे जो इस दल के नेता थे।

इस घटना के बाद लड़ाख क्षेत्र की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी भी, पहली दफा, पूर्णरूप से सेना को सौंप दी गई।

लेकिन इस सबके बावजूद, १६ नवम्बर को, नयी दिल्ली ने, जो अब तक एक शांतिपूर्ण समझौते की इच्छुक थी, प्रस्ताव रखा कि जबती तौर पर, लड़ाख क्षेत्र में, भारतीय सरकार चीन द्वारा निर्धारित सीमा तक अपनी सेनाएँ हटा ले और चीनी सेनाएँ उस सीमान्त के पीछे हट जायें जो परम्परागत रूप से भारतीय मानचित्रों में दिखाया जाता है। भारत सरकार का विचार यह था कि इस प्रकार दोनों दलों के बीच एक फासला हो जाने से सीमान्त के यह झगड़े खत्म हो जायेंगे।

पेकिंग ने शुरुआत इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उल्टे धनसाईं चिन क्षेत्र के पश्चिम तथा दक्षिण में चीनी सेनाएँ और भी आगे बढ़ आयीं और उन्होंने कई और नयी सड़कें बनाना शुरू कर दिया।

फरवरी, '६० में हमारे गुप्त सूचना विभाग ने यह सूचना दी कि चीनियों ने लानक-ला से कोंगका ला तक अपनी सड़क को इतना सुधार लिया है कि उस पर भारी गाड़ियों को चलाया जा सकता है और उत्तर में सिक्किम-किजिजिलगा-

गिमलूग को भिन्नान वाली उनकी मटक इस योग्य है कि उस पर अच्छे मौसम में हल्की गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं।

नेकिन घाँस में, एक हफ्त के लिए, आगामी सप्ताहों में कूटनीतिक रूप से लिया जब चाउ इन-मार्च थी नेहरू से बात करने के लिए नहीं दिल्ली भागे। लेकिन चाउ-नेहरू बातों का कोई फल नहीं निकला और चीनियों ने दोहरे उत्साह से भारत-विजय मोर्चा पर फिर से पकड़ पकड़ का खेल शुरू कर दिया।

जून में, नेहा मोर्चे पर चीनी सैनिकों का एक बहुत बड़ा दस्ता भारत के पाँच मील घाँस, कामग मेस्टर के लोका प्रवेश में उत्तमग गोम्पा नामक गाँव में (जहाँ एक मठ भी था) पहुँच गया। नयी दिल्ली ने फौरन इसके खिलाफ प्रतिक्रिया प्रकट की।

साथ ही भारत सरकार ने चीनी सरकार को यह भी बताया कि मार्च सन् १९६० में तब तक ३२ दहा भारतीय हवाई क्षेत्र को भग दिया था—यह विमान विमान से उड़कर भागे थे। दिसम्बर, १९६० और सितम्बर, १९६० के बीच चीनी विमानों ने १०२ दहा भारतीय हवाई क्षेत्र को भग दिया था।

सितम्बर, १९६०, में चीनियों ने एक नयी दिशा में कार्रवाई शुरू की—उस मार्ग में पहली दहा एक सशस्त्र चीनी दस्ते ने जेता दर्रे के पास सिक्रिम में प्रवेश किया।

अपने वरिष्ठ भी ऐसा मार्ग नहीं बीता जिसमें लड़ाई या नेका क्षेत्रों में चालिया न उठान न मचाया हो या भारत भूमि का कुछ हिस्सा न हड़पा हो। इन घटनाओं के समय अब अधिकतर गोलाबारी भी होने लगी थी।

२४ दिसम्बर १९६१ को भारत सरकार ने सीमा की समस्या पर दोनों देशों के अधिकारियों की रिपोर्टें प्रकाशित की। विस्तृत प्रमाणों के आधार पर लिखी हुई इन रिपोर्टें ने यह स्पष्ट किया कि भारत-चीन के बीच की परम्परागत सीमाएँ वही थी जो भारत अपने मानचित्रों में दिखाता रहा था और यह कि चीन ने सर्वप्रथम रूप में भारत के लगभग ५०,००० वर्ग मील क्षेत्र पर दावा किया था।

काले समय तक चीनी सरकार ने यह भी स्वीकार नहीं किया कि इस तरह की किसी रिपोर्ट का कोई महत्त्व है। मई, १९६२ में उन्होंने दो रिपोर्टें के चीनी भाषा को विकृत तथा सशिष्ट रूप से प्रकाशित किया।

२० अप्रैल को एक चीनी दस्ता फिर जेता दर्रे के पास सिक्रिम में घुस आया। मई में चीनी पश्चिमी विमान में पुनः के विरुद्ध भारतीय भूमि पर चढ़े भागे। जुलाई में एक चीनी अग्रिम दल सीमा पार करके नेका के कामग मेस्टर में घुस आया और चेपोकांगोंना के पश्चिम में एक मील घाँस तक पहुँच गया।

बीच जुलाई में मंगोलिया से लौटते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी जनरल, श्री धार० के० नेहरू, पेकिंग में रहे इस उद्देश्य से कि चीनी नेताओं से मिल कर यह पता लगायें कि दोनों देशों के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर व्यापसी समझौते की दिशा में कोई प्रगति की जा सकती है, या नहीं। चीनियों की ओर से उन्हें इस विषय पर कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। उल्टे, अपने ही महीने चीनी दस्ते लद्दाख में ओर भीतर तक प्रवेश कर गये—उन्होंने  $35^{\circ} 12' 50, 35^{\circ} 15'$  उत्तर में, न्यांगू में और दंबगुल में तीन चौकियाँ स्थापित कीं और इन चौकियों को अपनी पीछे की छावनियों से मिलाने के लिए नयी सड़कें बनायीं।

सितम्बर में, चीनियों ने तीसरी बार जेलेप दर्रे के पास सिकिम में प्रवेश किया।

भारत सरकार ने चीन की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उन्होंने कई बार सीमा भंग करके भारत में प्रवेश किया है, अनधिकृत रूप से भारत भूमि के काफी बड़े हिस्से को कब्जे में कर रखा है, नयी सड़कें बनायीं हैं और सैनिक चौकियों को स्थापित किया है।

सन् १९६२ के आरम्भ होने के साथ २६०० मील लम्बी भारत-तिब्बत सीमा पर चीनियों के उत्पात और भी बढ़ गये।

जनवरी में चीनी अग्रिम दल लद्दाख में बिन्दु  $35^{\circ} 12' 50, 35^{\circ} 15'$  उ० की अपनी चौकी से बारह मील आगे बढ़ गया और मेन्ना में चीन के शासकीय और सैनिक अधिकारियों ने लांगजू के पास भारतीय सीमा को पार किया और वे सुबनसिरि सीमान्त डिवीजन के रॉय नामक गाँव में (जो भारत में आधा मील अन्दर था) पहुँच गये।

२२ फरवरी को भारत सरकार ने चीन की सरकार से लद्दाख क्षेत्र में चीनी अग्रिम दस्तों की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की। इसके कुछ वाद ही भारत ने चीन से फिर यह शिकायत की कि उन्होंने लद्दाख में सुम्बों से छः मील पश्चिम में एक सैनिक चौकी स्थापित की है।

लेकिन इन शिकायतों के बावजूद, अप्रैल और मई भर चीनी अग्रिम दस्ते लद्दाख के विपचाय क्षेत्र में उत्पात मचाते रहे।

वास्तव में ३० अप्रैल को चीनी सरकार ने यह स्पष्ट घोषणा की कि उन्होंने काराकोरम दर्रे से कॉंगका दर्रे तक पूरे प्रदेश में अपने सैनिक दस्तों को गश्त लगाने का आदेश दे दिया है और साथ ही उन्होंने यह भी माँग की कि भारत अपनी उन दो सैनिक चौकियों को हटा ले जो निश्चित रूप से भारतीय सीमा के अन्दर ही थीं। पेकिंग सरकार ने यह धमकी दी कि यदि भारत उसकी माँगों को स्वीकार नहीं करेगा तो वे सारे सीमान्त पर सैनिक गश्त लगाना फिर से शुरू कर देंगे।

इसके तीन दिन के बाद चीनी और पाकिस्तानी सरकारों ने इस घातकी समझौते की घोषणा की कि वे भारत-चीन की मोखा के उस विभाग को, जो काराकोरम के पश्चिम में पाकिस्तान के अन्तर्गत कुन्जुंग में कश्मीर के सह में लगा हुआ है, निर्दिष्ट करके अपनी भूमि में मिला देंगे। भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जम्मू और कश्मीर के पूरे राज्य पर भारत का एकलव्य अधिकार है और कश्मीर की सीमा के किसी एक के बारे में पाकिस्तान से कोई भी समझौता भारत की दृष्टि में निरर्थक होगा।

उसी मास में, अर्थात् मई में, चीनिया में महात्मा ने, भारत के दस सौ पन्द्रह, स्यांग्गु के दक्षिण-पूर्व में एक नयी सैनिक चौकी स्थापित की।

भारत सरकार ने चौकी बार सहाय के विपक्ष में क्षेत्र में चीनियों की सैनिक सरगर्मी के खिलाफ आपत्ति प्रकट की और अपने इस प्रस्ताव को दोहराया कि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय मिलाएँ उन सीमा के पीछे हट जायें जिसका चीन दावा करता है और चीनी सेनाएँ भारत की परम्परागत सीमा के पीछे हट जायें। शांतिपूर्ण समझौते के हक में भारत ने यह भी मानना स्वीकार कर लिया कि असीमित मानवगत के लिए चीनी अधिकारों पर अधिकार होना चाहिए।

उसी महीने में इसी बार और पूर्व पश्चिमी बार, स्यांग्गु के निचले चीनियों के द्वारा एक नयी सैनिक चौकी स्थापित करने के खिलाफ भारत को फिर धिक्काया करनी पड़ी।

२ जून को चीन और भारत के बीच १९५४ के पंचशील समझौते की अवधि खत्म हो गयी—यू भी वह हमेशा ही व्यावहारिक रूप से निरर्थक रही थी। चीन की सरकार ने उसे बार-बार भंग किया था तिब्बत में भारतीय वाणिज्य, व्यापारियों तथा अन्य भारतीय नागरिकों को सजा कर और भारतीय भूमि पर रह-रह कर छाप मार कर।

सहाय में नयी सैनिक चौकियाँ स्थापित करने और नयी सड़कें बनाने के खिलाफ भगने दो महीने में भारत ने चार दफा और आपत्ति प्रकट की। इस प्रकार सन् '६२ के पहिले सान महीने में नयी दिल्ली को जो दफा पक्ष से निराश करने पड़ी थी।

## समस्या की जड़

सन् १९५५ के शुरु में ही चीनियों ने लद्दाख के अक्सार्ड चिन इलाके में (जो भारत का अंग है) एक सड़क बनानी आरम्भ कर दी थी। यह सड़क मध्य एशिया में चीन के सिक्कांग प्रान्त और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध थी।

चीनियों की इस कार्रवाई की सूचना सबसे पहले पेकिंग में स्थित भारतीय सैनिक सहचारी जिग्मेडियर एस० एस्० मलिक ने नवम्बर, १९५५ में अपनी एक रिपोर्ट के द्वारा भारत सरकार को दी थी। नयी दिल्ली में इस सूचना की ओर उस समय कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

पाँच महीने बाद, जिग्मेडियर मलिक ने एक विशेष रिपोर्ट द्वारा फिर से, आग्रहपूर्वक, अक्सार्ड चिन में बनने वाली इस सड़क की ओर ध्यान आकर्षित किया। जिग्मेडियर मलिक के कथनानुसार तत्कालीन भारतीय राजदूत, श्री आर० के० नेहरू ने उनकी इस रिपोर्ट को भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजने में आनाकानी की इसलिए कि कहीं भारतीय प्रधान मंत्री ऐसा करना अनुचित न समझें।

फाफ़ी दवाब डालने के बाद भारतीय राजदूत इस वक्त पर राजी हुए कि जिग्मेडियर मलिक की रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय के चीन विभाग के डायरेक्टर को भेज दिया जाये। साथ ही जिग्मेडियर मलिक ने अपनी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सैनिक हेडक्वार्टर को भी भेज दी। इसके बाद क्या था !—नयी दिल्ली और पेकिंग में भारतीय दूतावास के बीच तेजी से तार दोड़ने लगे।

सन् १९५७ के अन्त में जब चीनियों ने अक्सार्ड चिन से होकर गुजरने-वाली इस सड़क को पूरा कर लिया तो उन्होंने इस मार्ग के आरम्भोत्सव में

शामिल होने के लिए भारतीय राजदूत और उनके सैनिक सहचारी को घामात्रित भी किया। चीनियों की चाल यह थी कि भारतीय दूतावास के सदस्यों के इस उत्सव पर उपस्थित होने से यह सिद्ध हो जायेगा कि भारत ने अपनी भूमि पर बने उनके इस मार्ग का अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन भारतीय राजदूत तथा उनके सैनिक सहचारी ने इस उत्सव में शामिल होने से इन्कार कर दिया।

मन् १९५६ में, जनरल जे० एन० चौधरी के नेतृत्व में एक भारतीय सैनिक प्रतिनिधि मंडल चीन गया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को अत्यन्त नियंत्रित रूप में देश में घुमाया गया।

लेकिन जनरल चौधरी ने चीन की मिग-१७ विमान उड़ान देखा देने की विशेष इच्छा प्रकट की। चीनियों ने बड़े सकोच के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल को यह फँकट्टी दिखाना स्वीकार किया और वह भी इस शर्त पर कि प्रतिनिधि मंडल का कोई भी सदस्य भारत लौटने पर भारतीय नौसेना के अग्रज मनापति को इस फँकट्टी के बारे में कुछ न बताये। इसके विपरीत जब चीनी सैनिक प्रतिनिधि मंडल मन् '५८ में भारत घाया हो उनके उदार हृदय भारतीय मेहबाना ने उनसे कोई रहस्य छिपा कर नहीं रखा—मेहमानों की ज़ारदार छानिर की गयी और उन्हें देश के महत्वपूर्ण सैनिक प्रतिष्ठानों का दौरा कराया गया।

अकस्माई चिन में हमारी भूमि पर बनी हुई चीनी सड़क के बारे में भी नेहरू ने सरकारी तौर पर पहली सूचना २८ अगस्त, १९५६ में दी जबकि भारतीय समाचार पत्रों में बहुत पहले से इस सम्बन्ध में रिपोर्टें छप रही थीं। और उस समय भी यह बात प्रधान मंत्री के मुँह से एक प्रकार से निकाली ही गयी क्योंकि लोह सभा में सहाय में चीनी उत्पादों के बारे में प्रश्नों की बाँछार-सी लग गयी थी।

लोक समामद, श्री एन० जी० गोरे ने पूछा था कि क्या यह सही है कि चीनिया ने गर्तों और यारकन्द के बीच ऐसी सड़क बनायी है जो लद्दाख से होकर गुजरती है और क्या यह सड़क एक वर्ष या उससे भी अधिक समय से बनी हुई है।

सड़क के अस्तित्व की बात स्वीकार करते हुए प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया था "भव में एक या दो वर्ष पहले चीनियों ने गर्तों से यारकन्द (चीनी तुर्किस्तान) तक एक सड़क बनायी थी, यह भी रिपोर्ट थी कि यह सड़क हमारे उत्तर-पूर्वी जहाँसे इनाके के एक कोने से होकर गुजरती है। मेरे कथान से यह सभा इस बात की मानेगी कि यह इनाके अत्यन्त दूरस्थ और



दुर्गम है, यहाँ पहुँचना भी लगभग असम्भव है और यदि पहुँचने का प्रयत्न भी किया जाये तो कई हफ्ते लग सकते हैं।

“एस तिलसिले में हमारा एक प्रारम्भिक भवेलक दल वहाँ भेजा गया था। मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि कब लेकिन मेरे ख्याल से यह दल एक सात से भी पहले भेजा गया था—जागद पिछले साल। वास्तव में दो दल भेजे गये थे—इनमें से एक दल वापिस लौट आया था, दूसरा नहीं लौटा था।”

“जो दल नहीं लौटा वह क्यों?” एक सदस्य ने प्रश्न किया।

“हमने दो-तीन हफ्ते इन्तजार किया,” प्रधान मंत्री ने कहा, “जब वह फिर भी नहीं लौटा तो हमें धक हुआ कि घायद चीनियों ने उसे सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया है। अतः हमने चीन सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया—घटना के लगभग एक महीने बाद हमने यह सवाल उठाया था। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे सैनिकों ने उनकी सीमा भंग की थी, उनकी भूमि पर अनधिकृत रूप से पदार्पण किया था और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन चीन सरकार ने यह लिखा था कि भारत-चीन के सम्बन्धों को देखते हुए वह उन सैनिकों को रिहा करने वाले हैं। और बाद में हमारे सैनिकों को लगभग एक मास हिरासत में रखने के बाद उन्होंने रिहा कर भी दिया।

“यह है उस सड़क के बारे में कुछ बात जिस पर गामनीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। यूँ बात यह है कि इस सारे प्रवेश में कोई निश्चित सीमा विभाजन नहीं है। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हमारे नक्शों में स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया है कि यह इलाका भारतीय राज्य संघ का ही हिस्सा है। हो सकता है कि कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से निर्धारित न हों। लेकिन बाहिर है कि अगर किसी विशेष हिस्से के बारे में कोई मतभेद या झगड़ा है तो उसके बारे में बातचीत की जा सकती है। जिस सीमा की सरफ इशारा है वह पुराने कश्मीर राज्य, तिब्बत और चीनी तुकिस्तान के बीच की सीमा है। उस सीमा को किसी ने निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया है। लेकिन मोटे तौर पर पर्यवेक्षण करके तत्कालीन भारत सरकार ने वह सीमा निर्धारित कर दी थी जिसे हम मानते आ रहे हैं।”

श्री गोरे ने कहा : “क्या इसका मतलब यह है कि हमारे देश के जो भी हिस्से दुर्गम हैं और जहाँ पहुँचना दुश्वार है वहाँ कोई भी दूसरा देश सड़कों

बना सकता है और छावनीयों को हम मारता है ? हम कुछ-कुछ के लिए अपने दल भेजते हैं, चीनी हमारे रक्षा का गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर हमारे आपसी मित्रतापूर्ण सम्बंधों के कारण उन्हें रिहा कर देते हैं—यस इच्छा वाली है ? और मगर अपनी जगह पर है विदेशी हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते ?

"मैं नहीं जानता कि भारतीय संसद मुझे यह आदेश देगी है कि मैं उनकी इन बातों का जवाब दूँ," प्रधान मंत्री ने कहा, "यहाँ पर, दरभंगा, दार्जीलिंग म्यांमार देश होते हैं। यह म्यांमार सीमाना से सम्बंध रखते हैं। सीमाना के कुछ भागों के बारे में तो दोनों में से किसी एक को इस बात पर सहमत या आपत्ति नहीं है कि सीमाना का यह विषय भाग हुआ है। उन प्रदेश पर कब्जा करने का प्रयत्न हमारे लिए एक चुनौती है।

"लेकिन कुछ इनाम ऐसे हैं जहाँ यह निर्दिष्ट रूप से निर्धारित करता सुनिश्चित है कि सीमा रेखा कौन-सी है—न ही इस बारे में भोटा-भोटा जान हो। या नवों पर हम रक्षा को बनाना बहुत सुनिश्चित काम है, यदि बहुत भोटी रेखा सीधी जाये तो तीन चार माल भूमि तो उसी से हो जाती है।

"फिर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी सीमाएँ पढ़ने वाली निर्धारित नहीं की गयी। यह हिस्से यह हैं जिनमें किसी देश को कोई दिल-बासी नहीं थी। इसलिए जब हम म्यांमार में दोनों पक्षाओं को उपस्थित तथा पर गौर करना होगा और यदि सीमाना के बारे में कोई भगवा मारा होगा तो उचित और शान्तिपूर्ण ढंग से उसके बारे में फैसला करना होगा। मैं इस काम में हम चीन से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और हमने यह सुझाव रखा है कि दोनों सरकारें इस समस्या पर विचार करें।"

तीन दिन बाद श्री नेहरू ने राज्य सभा के अग्रणी चिन में हुई घटनाओं के बारे में एक बड़ा सुनभा हुआ वक्तव्य दिया।

मेहबूब-उल-हक (जिसे सिक्कीम निम्नतम मार्ग भी कहते हैं) गिरफ्तार, १९५७ में बन कर पूरा हुआ था। अगले वर्ष अर्थात् १९५८ की गर्मियों में दो भारतीय पर्यटकों को अग्रणी चिन इलाके में यह पता लगाने के लिए भेजे गये कि इस सड़क का भारतीय सीमाना से क्या सम्बंध है और वह भारतीय क्षेत्र में होकर गुजरती है या नहीं।

इनमें से एक दल को चीनिया ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दल ने लौट कर यह रिपोर्ट दी कि यह सड़क दक्षिण में सरीसृप जिले के भील के पास भारतीय इलाके में घुसी है और फिर उत्तर-पश्चिम की ओर सड़क के उत्तर-

पश्चिमी कोने में हाजी खंजर के पास भारतीय इलाक़े को छोड़ती हुई चली गयी हैं।

भारत के आपत्ति-मित्र के उत्तर में चीन सरकार ने १ नवम्बर, १९५८ को यह घोषणा की कि उन्होंने भारतीय पर्यवेक्षक दल को छोड़ दिया है और यह कि सिक्किम-तिब्बत मार्ग केवल चीनी प्रदेश में होकर गुजरा है।

चीनी घोषणा के दूसरे अंग पर (अर्थात् चीन के इस दावे पर कि सिक्किम-तिब्बत मार्ग चीनी प्रदेश से ही गुजरा है) ८ नवम्बर के एक पत्र द्वारा भारत सरकार ने आपत्तिय प्रगट किया लेकिन बार-बार दाव दिलाने के बावजूद चीन से उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अक्साई चिन प्रदेश की सामान्य ऊँचाई १७,००० फ़िट से अधिक है। सन् १८४२ में कश्मीर के महाराजा गुलाबसिंह, तिब्बत के लामा गुरुसाहिब और चीन के सम्राट के प्रतिनिधि के बीच एक सन्धि हुई थी जिसके अनुसार, अक्साई चिन को शामिल करते हुए, लद्दाख का पूरा इलाक़ा जम्मू-कश्मीर राज्य का अंग बन गया था।

उसके उपरान्त यह इलाक़ा बराबर जम्मू-कश्मीर राज्य का ही अंग बना रहा। अंग्रेजों ने उसके बाद कई बार इस बात की कोशिश की कि तिब्बत तथा जम्मू-कश्मीर के बीच की सीमा पुनः निर्धारित की जाये। इस काम में सह-योग देने के लिए चीनी सम्राट से प्रार्थना की गयी कि वे अपना प्रतिनिधि भेजें। चीनियों ने इस कार्रवाई में कोई भाग नहीं लिया। १२ जनवरी, १८४६ को चीनी कमिश्नर ने यह वक्तव्य दिया, "मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त दोनों देशों के बीच की सीमा काफ़ी निश्चित रूप से निर्धारित हो चुकी है और इसलिए सबसे उत्तम बात यह होगी कि परम्परागत सीमाओं को ही माना जाये। इन सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए कोई प्रयत्न न करना ही अब सुविधाजनक होगा।"

अंग्रेजों की भी यही राय थी। हालाँकि भूमि पर कोई वास्तविक सीमा निर्धारण नहीं किया गया था फिर भी नक्शे पुराने रिवाजों और परम्पराओं के आधार पर बनाए गये थे। यह नक्शे भारत में पिछले लगभग ती बर्षों से इस्तेमाल किये जा रहे थे। इनमें अक्साई चिन प्रदेश को लद्दाख का हिस्सा बताया गया था। क्योंकि चीन-तिब्बत के साथ अक्साई चिन की सीमा का भूमि पर निर्धारण नहीं हुआ था इसलिए एक-दो बार इस बारे में प्रश्न खड़े हुए थे। पुराने चीनी मान-चित्रों में अक्साई चिन और तिब्बत तथा चीन के बीच की सीमा दूसरी तरह से दिखायी गयी थी।

श्री डी० पी० सिंह ने यह तबाल उठाया था कि इस मामले में लोक सभा की राय पहले क्यों नहीं ली गयी और उस पर श्री नेहरू ने कहा था : "ऐसी

कोई साम बात नहीं थी जिसके लिए सोव समा को आग्राह किया जाता और उसकी राय भी जानी हमारी जानकारी के बगैर चीनियों ने उस प्रदेश के एक दूरस्थ कान में एक सड़क बना ली है और हम पत्र-व्यवहार द्वारा इस बात में कारवाही कर रहे हैं। एसी परिस्थिति अब तक पैदा नहीं हुई है जिसकी ओर सोव समा का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होगा—हमने सोचा था कि हम इस समस्या का पत्र-व्यवहार द्वारा सुलझा लेंगे और उचित समय पर सोव समा को इस विषय पर पूरी सूचना दे देंगे।”

सन् १९५६ में चीनियों ने निम्बन सिक्काग मार्ग के पश्चिम में एक और सड़क बनायी। इसके अलावा अफगानी रेलवे चीनियों के बीच पातायान की सुविधाएँ सुगमतर करने के लिए उद्धान कई और भी सड़कों का निर्माण किया। इसके विपरीत, सन् १९६० तक, भारत ने उत्तरी सीमान्त के इलाकों में पातायान की सुविधाओं को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जनवरी, १९६०, में सीमान्त मार्ग बिभाग की स्थापना की गयी जिसने तोबाक तथा बोमदीना के बीच केवल १८ महीने में सड़क बना दी।

सीमा सम्बन्धी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए श्री नेहरू ने फिर एक महान प्रयत्न किया और १९६० के शुरू में चाउ इन-साई को दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया। लेकिन भारत में बहुत कम लोगों को यह उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच कोई सन्तोषजनक समझौता हो सकेगा।

१६ अप्रैल, १९६०, को चीनी प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँचे और अगले छः दिनों तक श्री नेहरू से उनकी बातचीत जारी रही। बातचीत के अन्त में दोनों प्रधान मंत्रियों ने घोषणा की कि वे दोनों समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे।

इसके उपरान्त यह तय पाया गया कि दोनों देशों के अधिकारी निम्न और सारे आवश्यक तथा सम्बन्धित प्रमाणों का अध्ययन करके रिपोर्ट दें। साथ ही इस बात का भी फैसला किया गया कि सीमान्तों पर अगलों की रोक-थाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाये।

यह विश्वास किया जाता है कि इन बातचीतों के दौरान में चाउ इन-साई ने एक विशेष प्रकार का विनिमय प्रस्तावित किया था। चीनी प्रधान मंत्री का सुझाव था कि नैत्रा सीमा पर चीन भारत द्वारा निर्धारित सीमा स्वीकार करने और रैकमहॉल रेखा के पीछे हटने को तैयार हो सकता है यदि भारत नद्दास में उस सीमा को स्वीकार कर ले जहाँ तक चीनी सब तक बढ़ चुके थे। चीन के इस प्रस्ताव से यह स्पष्ट था कि अक्सर चीन में बनी हुई सड़क का उनके लिए विशेष महत्व है।

लेकिन उस समय तक भारत में सामान्य जनमत, विशेषतः संसद के विरोधी दल इस विषय पर इतने भड़क उठे थे कि श्री नेहरू के सामने समझौते

के लिए कोई रास्ता नहीं था। चाउ इन-लाई दिल्ली में ही थे जब लोगों ने बड़ी संख्या में श्री नेहरू के निवास स्थान के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और यह मांग की कि चाउ इन-लाई के व्यक्तिगत दबाव से भारत सरकार को डीला नहीं पड़ना चाहिए। श्री नेहरू ने लोगों को आश्वासन दिया कि भारत की तिल भर भूमि भी चीन को नहीं दी जायेगी।

मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि श्री नेहरू को चाउ इन-लाई का यह प्रस्ताव अस्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा जब कि कोई भी मर्यादावादी इस सम्झौते को मान लेता।

इस सम्झौते के अन्तर्गत चीन अक्सर चीन का जो हिस्सा मांग रहा था वह यूं भी सुदृढ़रूप से उसके अधिकार में था और इस बात की कोई सम्भावना नहीं थी कि इस समय या भविष्य में भारत उस इलाके को चीन से वापस ले सके। वास्तव में, चीन हमसे उस प्रदेश को प्राप्त करने की स्वकृति चाहता था जो यूं भी उसके कब्जे में था और उसके बदले में वह मैकमहॉन रेखा को स्वीकार करने को तैयार था।

राजनैतिक मामलों में ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं जब मर्यादावादी लोग मुक़द्दमान सह लेने में सलाह समझते हैं क्योंकि दूसरा कोई उस्ता नहीं होता। भारत सरकार यह अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने इस निश्चय का समर्थन सैनिक शक्ति से नहीं कर सकती और चीन के साथ युद्ध करने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा लगता था कि चीन के साथ झगड़ों में भारत के ऊपर कोई ग्रह लगा हुआ था जिसके कारण बिगड़ी हुई परिस्थिति को सम्हालना उसके लिए असम्भव था।

अक्सर चीन में बनी हुई सड़क का चीन के लिए कितना अवरोध महसूस था और किमी भी हालत में उस पर कब्जा रखने का उनका इरादा कितना दृढ़ था, यह बात २६ दिसम्बर, १९५६ के चीनी सरकार के इस पत्र में स्पष्ट है :

"सिक्किम और पश्चिमी तिब्बत के बीच यही क्षेत्र एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा यातायात सम्भव है क्योंकि उत्तर पूर्व में गोबी का विशाल मरुस्थल है जिसमें होकर तिब्बत पहुँचना लगभग असम्भव है।" इसी पत्र में चीनी सरकार ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि "यह क्षेत्र हमेशा से चीन का अंग रहा है और सिक्किम तथा तिब्बत के बीच यातायात के लिए वे सदा इसी मार्ग को इस्तेमाल करते रहे हैं।" चाउ इन-लाई ने यह भी कहा कि सन् १९५० में चीन की लोक मुक्ति सेना इसी मार्ग से होकर सिक्किम से तिब्बत में घाटी प्रदेश तक गयी थी।\*

\* १५ अक्टूबर, १९६२ को चीन भारत सीमा प्रश्न पर चाउ इन-लाई द्वारा अफ्रीकी और एशियाई नेताओं को लिखे गये पत्र के अनुसार।

श्री नेहरू ने लोक सभा को बताया कि चीन का यह दावा है कि सैकड़ों वर्षों से बाराकोरम पर्वतमाला कोग का दर्रे तक उसका सीमान्त रही है। उनका यह भी दावा था कि इस प्रदेश का उत्तरी हिस्सा तिब्बत का नहीं, सिक्किम का भाग है। उनका कहना था कि यह प्रदेश गोरी मन्स्यल की तरह है—वहाँ कोई प्रशासकीय व्यवस्था नहीं थी, केवल एक दूरस्थ नियंत्रण था। शासन अधिकारी या जरूरी वस्तुएँ बनाने वाला थफसर वहाँ फगो-जमी जाता रहता था। साम सामान्य स्थापित होने के कई वर्ष पहले से इस इलाके पर चीन का वास्तविक अधिकार रहा था।

लेकिन श्री नेहरू ने इस बात को ध्यान दिया कि चीन ने कभी भी, प्रभाग, देशान्तर तथा पर्वतमालाओं को निर्दिष्ट करके, इस क्षेत्र में कुछ सीमा निर्धारण नहीं किया था।

बाउ इन-लाई दिल्ली में विराशा, कटुता और क्रोध से भरपूर वापस गये। राले में काठमाण्डू रुककर, अर्घरात्रि के एक पञ्चवार सम्मेलन में उन्होंने खुल कर अपनी इस मनोस्थिति को प्रगट किया। भारत द्वारा उनके प्रस्ताव को रद्द करने का अर्थ उनके लिए केवल यही था कि अब से चीन भारत के साथ प्यादा सन्धी से पैदा आये।

यह स्पष्ट था कि दोनों पक्षों की मनोवृत्ति ऐसी होने पर बाद में होनेवाली अधिकाधिकारी की बातचीत असफल रहे। इस बातचीत का केवल एक ही लाभ था कि दोनों देशों के बीच खुल तौर पर भगडा घुम् होने की स्थिति कुछ समय के लिए धीरे टल जाये।

यहाँ से भारत चीन सम्बन्धी ने एक धीरे नया धीरे अमानक मोड़ पिया। पकिंग सरकार ने यह इरादा कर लिया कि अत्र क्रौरन खुले तौर पर भारत से भगडा घुम् कर दे। इस निश्चय के अन्तर्गत चीन ने अपने धीरे दबावों को हल्का करना शुरू किया।

सबसे पहले तो चीन ने नेपाल में मित्रता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये। चीन तथा नेपाल के बीच एक आर्थिक सम्झौता हुआ। जिसके अन्तर्गत नेपाल को दम करोड रुपये की सहायता देना तय हुआ। साथ में यह भी निर्दिष्ट हुआ कि चीनी विशेषज्ञों का एक दल पूरी तरह चीन के खर्चे पर नेपाल में तकनीकी विकास कार्यों के लिए आये। चीन ने यह भी उत्तरदायित्व लिया कि वह नेपाली तकनीकी विद्यार्थियों को अपने खर्चे पर चीन में विशेष प्रशिक्षण देगा। इसने असावा यह फैसला किया गया कि चीन तिब्बत और नेपाल को भिलाने के लिए एक सहक वा निर्माण करे।

चीन ने काठमाण्डू में एक विज्ञान दूतावास भी खोला—अब तक नयी दिल्ली में स्थित चीनी राजदूत ही यह काम चलाता रहा था।

चीन ने नेपाल के साथ सीमा सम्बन्धी समझौता भी किया जिसमें उसने ऐवरेस्ट पर्वत पर अपना बहुत दिनों का दावा नञ्चर अन्दाज कर दिया। वास्तव में, जब नेपाली विदेश मंत्री समझौते पर हस्ताक्षर करके पेकिंग से स्वदेश लौटे तो उन्होंने विद्व के उच्चतम स्तर पर नेपाल का अधिकार पुनः घोषित किया और चीन ने उनके इस दावे पर कोई आपत्ति प्रगट नहीं की।

चीन-नेपाल मैत्री का अर्थ यह था कि आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से चीन उस प्रदेश में दाखिल हो गया है जिसे भारत तब तक अपने प्रभाव में सम्भलता रहा था। चीन ने तो यह भी प्रस्ताव रखा था कि वह नेपाल से यह समझौता कर ले कि वे दोनों एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे लेकिन नेपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

कुछ समय पूर्व ही श्री नेहरू ने नेपाल के बारे में यह घोषणा की थी कि नेपाल की सीमा भारत की सीमा है और नेपाल पर किया गया आक्रमण भारत पर आक्रमण समझा जायेगा।

उसी वर्ष चीन ने वर्मा से भी एक सीमा सम्बन्धी समझौता किया जिसमें बड़ी उदारता से, उसने दोनों देशों के बीच मकूमहॉन रेखा को सीमा के रूप में स्वीकार किया। यह प्रयत्न था भारत को चिढ़ाने तथा भारत के समान सीमा के विषय पर वर्मा की आपत्तियों का अन्त करने का।

इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को पटाने का काम शुरू किया और इस बात का प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो भाग है, उसके तथा चीन के बीच की सीमा के बारे में समझौता कर लिया जाये। साथ ही चाउ इन-लाई ने इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और इन्डोनेशिया में रहने वाली चीनी जनसंख्या के प्रति जकार्ता का जो तयकथित दुर्वाचहार था उस बारे में दोनों देशों के बीच बहुत दिनों के मतभेद को खत्म कर दिया।

चीन की इन सारी चालों के पीछे यह लक्ष्य था कि भारत को उसके सारे पड़ोसियों से घलग कर दिया जाये। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, १९६३ के शुरू में पेकिंग सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा कि नेपाल, भूटान, तिब्बत, नेफा और नागा प्रदेश को मिलाकर एक हिमाचल संघ की स्थापना की जाये। साथ ही साथ, ऐशियाई और अफ्रीकी देशों में स्थित चीनी प्रचारतन्त्र ने भारत को बदनाम करने और उसे शलत सिद्ध करने का हर सम्भव प्रयत्न किया।

इसी बीच भारत-चीन सीमा समस्या के सिलसिले में शब्दिक कार्रवाई के बजाय सैनिक मुठबेड़ों का क्रम शुरू हो गया। जैसे-जैसे सशस्त्र भगड़ों की संख्या बढ़ती गयी और चीनी धीरे-धीरे भारत की भूमि हड़पते गये वैसे-वैसे

चीन ने ऐसे नये मान-चित्र प्रकाशित किये जो चीन द्वारा भारत के सीमान्त क्षेत्रों को हड़प करने का समयान्तर करते थे और नये क्षेत्रों पर चीन का दावा प्रतिपादित करते थे ।

इसके पनस्वरूप दोनों पक्षों ने ऐसे क्षेत्रों में अधिकारियों की जासूसी करना और गन्त नगाना शुरू किया जिनकी ओर पहले दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया था । इन कार्रवाइयों की वजह से दोनों पक्षों की प्रचण्ड सैनिक भिड़न होना निश्चित होना जा रहा था ।

नेहरू-बाउ बार्ता के उपरान्त दोनों देशों के अधिकारियों की जासूसी बिल्कुल निर्गन्ध थी । इस जासूसी से चीनियों ने केवल यह लाभ उठाया था कि चनुर प्रदेशों और हमारे अफसरों द्वारा दिये उनके स्पष्ट उत्तरों से उन्होंने हमारे सीमान्त प्रदेशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी ।

रामेय विभाव में हमारे चीनियों के बारे में चीनियों ने बारह प्रश्न किये (बाद में हमी इसाके में उन्होंने सबसे उबरदस्त प्राक्रमण किया) । नेफा प्रदेश के बारे में उन्होंने कुल मिलाकर पच्चीस स्पष्टीकरण माँगे ।

बातचीत के अन्त तक चीनियों ने नेफा के सीमान्त इलाकों के बारे में सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी । दो वय बाद प्राक्रमण करने समय उन्होंने इस जानकारी से पूरा लाभ उठाया था ।

बातचीत के बारे में रिपोर्ट देने समय भारतीय अधिकारियों ने यह शिक्षाया की कि “भारतीय पक्ष द्वारा पूछे गये ११८ प्रश्नों में से चीनियों ने केवल ५६ का उत्तर दिया—इनमें से भी अधिकतर उत्तर अपूर्ण थे—जबकि भारतीय पक्ष ने चीनियों द्वारा पूछे गये सब प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह दिया ।”

रिपोर्ट में आगे कहा, “बातचीत के दौरान में एक बार चीनी पक्ष ने यह मत प्रकट किया कि हमारे द्वारा उनकी निर्धारित की हुई सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न अनावश्यक है और उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष को सीमा के कुछ विषय और निश्चित स्थानों तक ही अपनी पूछ-ताछ सीमित रखनी चाहिए ताकि सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन तक आइटम नंबर एक (सीमा की स्थिति तथा भूमि विवेचनाएँ) पर मारा वाद-विवाद पूरा हो जाये ।

“भारतीय पक्ष ने इस ओर सचेत किया कि आइटम नंबर एक का मूल महत्त्व इसलिए है कि जब दोनों पक्षों को सीमा की स्थिति की पूरी और स्पष्ट जानकारी होगी तभी वे उस क्षेत्रों को अच्छी तरह जान सकेंगे जिनके बारे में मतभेद है और अपनी अपनी सरकारों के दावों के समर्थन में प्रमाण पेश कर सकेंगे ।



“स्वयं चीनी पक्ष ने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न किये थे” और भारतीय पक्ष ने हमेशा पूरी तरह उनके उत्तर दिये थे ।

“बाद में चीनी पक्ष ने अपनी आपत्ति वापस ले ली लेकिन यह जानना चाहता कि क्या भारतीय पक्ष चीन द्वारा निर्धारित सीमा इस लिए जानना चाहता है कि उसके बाद भारतीय सैनिक उस सीमा रेखा को पार नहीं करेंगे ।”

इस बीच में सीमान्त प्रदेशों में चीनी उत्पात बढ़ते जा रहे थे ।

## निर्णय ले लिया गया

सन् १९६१ के अन्त तक उत्तरी घाटान्त में युद्ध के घने, हाते बादल छाये सगे थे। भारत तिब्बत सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा था। और हिंसा भी समय-बिस्फोट की सम्भावना थी।

जैसे-जैसे चीनी सीमान्त के पूर्वी तथा पश्चिमी विभागों में ज्यादा-से-ज्यादा घसने लगे जैसे-जैसे नयी दिल्ली ने मनीनगर की रणरंग में पश्चिम की घातिल-पत्र भेजने शुरू किये—वास्तव में यदि यह घातिलपत्र सिद्धात्त हों तो सारा चीन विध्वस्त हो जाता।

भारत की उत्तेजित जनता यह मान कर रही थी कि सरकार चीन के निन्दाक डाम और मजबूत बार्डबार्ड करे।

सैनिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अभी तक युद्ध के लिए तैयार न होने तथा उस समय तक भी यही विश्वास करने रहने के कारण कि चीन युद्ध नहीं छेड़ेगा, भारत सरकार ने इस विषय पर एक 'अस्थिर नीति' अपनायी जिसमें कोई दम नहीं था। वास्तव में ऐसा लगता था कि यह नीति उत्तरी सीमान्त चीनी सबूट को रोकने के लिए नहीं, भारतीय जनमत को बहुमान के लिए बनाई गयी है।

हमारे जो सैनिक दल सीमान्त पर चीनियों का मुकाबला करने के लिए स्थित थे वे सख्या में बहुत कम थे, संसार तांत्रिक महायुद्धा मिलने की व्यवस्था अत्यन्त धराब थी और रसद तथा साम्राजि प्राप्त करने के लिए वे हवाई यातायात पर निर्भर थे। इनके विपरीत चीनियों की सैनिक सख्या अधिक थी और न केवल उनकी चौकियाँ कम कामना पर स्थित थी बल्कि उन्हें आवश्यक सामग्री पहुँचाने रहने के लिए सुगम मार्गों का जाल बिछा हुआ था।

सन् १९५६ और १९६१ के बीच जब भारत सरकार टालमटोल कर रही थी, मोटियों कर रही थी, फ्राइलें इधर से उधर दौड़ा रही थी, विस्तारपूर्ण आपत्ति-पत्रों का वित्तिमय कर रही थी और कुछ ढीली-ढाली कार्रवाई कर रही थी, उसी समय में चीन अत्यन्त व्यावहारिक रूप से लद्दाख में अपनी 'अग्रिम नीति' कार्यान्वित कर रहा था—नयी सैनिक चौकियाँ स्थापित कर रहा था, भारतीय प्रदेशों में काफी अन्तर उसके दस्ते गड़त कर रहे थे, नई सड़कें बनायी जा रही थीं और वह अधिकाधिक भारतीय भूमि को नियन्त्रित जा रहा था।

जून, १९५६ तक भारतीय पुलिस के गस्ती दस्तों ने पाया कि कोंगका दर्रे पर चीनी अधिकार नहीं है। उस समय चीनी अक्सर चिन मार्ग और लानक ला से आगे नहीं बढ़े थे। लद्दाख प्रदेश में उनकी अग्रिम चौकियाँ स्पांग्गुर तथा खुर्क दुर्ग में ही थीं।

लेकिन २१ अक्टूबर, १९५६ को हमारे गस्ती दस्तों पर चीनियों ने कोंगका ला के पास छिपकर छापा मारा। दिसम्बर, १९५६ तक चीनियों ने मध्य विभाग में लानक ला और कोंगका ला के बीच ऐसी सड़क बना ली जिस पर मोटरों आसानी से आ-जा सकती थीं। उत्तर में, कराराकाश दरिया से लग कर कराराताग से सुन्दो तक तथा उसके आगे शामिल खुंगपो तक भी उन्होंने एक और सड़क बना ली थी। इस प्रकार उन्होंने कराराताग, शामिल खुंगपो तथा लानक ला के बीच नियन्त्रण की एक उत्तर-दक्षिण रेखा स्थापित कर ली थी।

सन् १९६० में चीनियों ने दक्षिण में और भी दूर तक अपनी निगाहें चौड़ायी—उन्होंने चांग चैनमो घाटी तथा पॉन्गांग त्सो में प्रवेश किया और ग्यान्जु तथा डम्बूगुरु में अपनी चौकियाँ स्थापित की। सन् १९६१ में इन चौकियों को खुर्क दुर्ग तथा कोंगका ला से मिलाने वाले एक मार्ग का निर्माण पूरा किया। तिब्बत में स्थित रुदाँक को स्पांग्गुर से मिलाने वाली एक और सड़क भी बनायी गयी।

लद्दाख के मध्य सेक्टर में चांगचैनमो घाटी तथा खुर्क दुर्ग के बीच चीनियों ने १४००-१८०० वर्ग मील भूमि अपने कब्जे में कर ली थी।

१९६१ के अन्त तक हमारे गुप्त सूचना विभाग की रिपोर्टों से यह पता चला कि चीनी स्पांग्गुर में अपनी चौकी को और भी मजबूत बना रहे हैं और उस समय वहाँ उनकी दो सैनिक कम्पनियाँ स्थित हैं।

स्पांग्गुर भारत का अंग था और उस प्रदेश में था जिसके बारे में स्वयं चीनी भी यह कहते थे कि वे वहाँ गड़त नहीं लगाते हैं। उसके और उत्तर में चीनियों ने चिपचाप और सुन्दो में भी अपनी सैनिक चौकियों को और अधिक सुदृढ़ बना लिया था।

इस बात की भी सूचना मिली थी कि नेफ्रा सोमान्त से लगे हुए तिब्बती प्रदेश में भी चीनी अपनी सैनिक स्थिति संगठित कर रहे हैं। नेफ्रा के सियांग

और मोहित द्विबीजनों के मामले समाने क्षेत्र में चीनियों ने अपनी सेनाएं भेज दी और उनके गस्ती दरंग हमारी सरहद तक छापा मारने लगे ।

इस स्थान पर सीमान्त के दरों की ऊँचाई सबसे कम है । वेमाको प्रदेश विंगप रूप में निवटनम तथा घासानी से विवर्धित किया जा सकने वाला मार्ग था मिनाग-ल्हासा सड़क से, सिपाय पाटी स नगे-नगे नेफा जाने के लिए ।

कामेंग सेक्टर के पार लोला दर्रे के निकट और मोहित सेक्टर के पार शेल्ह दर्रे व धाय-धाम नदी चीनी चौकियाँ पायी गयी । चीनी दम्ये सुबन-सिरि सेक्टर के पार यांगला और मोहित सेक्टर के पार सामा तक गस्त लगाने लग । चीनियों ने गयुन दज्या से लुम तक तथा कामेंग सेक्टर के पार मामांग से ले तज मडवे बनाम का काम भी ठीकी से पूरा किया ।

नेफा के आदिवासियों का कई तरीकों से फुलवाने का काम भी चीन ने शुरू कर दिया । हमका एक उदाहरण था कि भारत में प्रचलित करने के बाद सुबनसिरि सीमान्त द्विबीजन की रैगिन जाति के कुछ लोग जब सीमा पार करके भागे तो चीनियों ने उन्हें तिब्बत में बाधय दिया और उनमें से दो को गांव का अधिकारी बना कर राजपुति भी दे दी ।

नवम्बर, १९६१ में प्रधान मंत्री ने लद्दाख और नफा में स्थित सेना को नये आदेश दिए । इसका अनुसार उन्हें धाजा मिल गयी कि अपनी वर्तमान स्थितियों से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक जितनी दूर तक सम्भव हो, वे गस्त लगायें । इस आदेश के पीछे यह इच्छा था कि हम ऐसी नयी चौकियाँ स्थापित करें जो चीनियों को भागे बड़ने से रोकें और उनकी उन चौकियाँ पर अधिकार कर लें जो हमारी भूमि पर बनी हो । गस्ती दस्तों से कहा गया कि जब तक आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक न हो तब तक वे चीनियों से भगडा मोन न लें ।

उत्तर प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर वे कठिनाइयाँ नहीं थी जो लद्दाख में थी । हमारा प्रतिरक्षा बना का इसलिए यह आदेश दे दिया गया कि व जितनी दूर सम्भव हो पहुँच जायें और उस पूरे सीमान्त पर सक्रिय रूप से कर्जा कर लें । प्रतिरक्षा रेखा में कहीं भी खाली स्थान रह जायें तो उन्हें गस्त लगाकर या चौकियाँ स्थापित करके भर देने का आदेश भी था ।

धन, ५ दिसम्बर, १९६१ को सैनिक हेड क्वार्टर ने पूर्वी तथा पश्चिमी कमांडो को आदेश दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की दिशा में जहाँ तक सम्भव हो, हमारे दल गस्त लगायें, चीनियों को भागे बड़ने से रोकने के लिए और सैनिक चौकियाँ स्थापित करें, हमारी भूमि पर बनी हुई चीनी चौकियों पर हावी हो जायें, पूरे सीमान्त पर सक्रिय रूप से कर्जा कर लें, खाली स्थानों को गस्त लगा कर या चौकियाँ स्थापित करके भर दें और अपनी समस्याओं का हिल से भूस्थान कर दें ।

इस आदेश के द्वारा भारत सरकार ने उत्तरी सीमास्त पर अपनी 'अग्रिम नीति' को कार्यान्वित किया। निर्णय की कुन्तुभी वजह उठी थी।

६ मई, १९६२ को जनरल थापर ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया था कि यदि चीनियों ने अक्साई चिन प्रदेश में हमारी चौकियों पर आक्रमण किया तो प्रत्युत्तर में हम उनकी स्थागुर में स्थित चौकी पर कब्जा कर लेंगे क्योंकि चुशूल क्षेत्र में हमारी सैनिक संख्या चीनियों से अधिक थी। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि चुशूल से स्थानीय आक्रमण की सूरत में वहाँ की सैनिक शक्ति बढ़ाना आवश्यक होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

४ मई को सैनिक हेड क्वार्टर ने पश्चिमी कमान्ड को चेतावनी दी कि उत्तरी लद्दाख में चिपचाप नदी के मोर्चे पर स्थित हमारी चौकियों के खिलाफ चीनियों में तीव्र प्रतिक्रिया है और इस बात की सम्भावना है कि वे हमारी चौकियों को उखाड़ने का प्रयत्न करें। १५ मई तक उक्त चौकियों की सैनिक संख्या बढ़ाने के लिए आदेश दे दिये गये। साथ ही पूर्वी कमान्ड से कहा गया कि नेफा-तिब्बत सीमा पर हमारी चौकियाँ जल्द से जल्द, २० मई से पहले तैयार हों जायें।

पश्चिमी कमान्ड को दिये गये आदेशों के साथ सी० जी० एस० ने इस बात पर भी जोर डाला कि अपनी 'अग्रिम नीति' को सक्रिय और जोरदार रूप से प्रदर्शित करने तथा लद्दाख, विशेषतः उत्तरी इलाकों में स्थित अपने सैनिकों में शण-प्रवृत्ति कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि शशस्त्र रूप से शस्त्रे लगायी जायें भले ही चौकियों की सैनिक संख्या कम हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखने का आदेश दिया गया कि यह शस्त्रे सिर्फ सवर्क्षण कार्य के लिए हों और केवल आत्म-रक्षा के लिए ही शस्त्रों का प्रयोग किया जाये।

भारत सरकार की 'अग्रिम नीति' के जोर पकड़ने के साथ अब चीन की धारों थी आपत्ति-पत्र भेजने की। चीनियों ने बार-बार यह शिकायत की कि भारतीय सैनिक दस्ते रह-रह कर उनकी सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं और घमकी दी कि यदि भारत ने अपनी सैनिक सज्जामें नहीं रोकी तो उसका नतीजा बुरा होगा।

दोनों देशों की 'अग्रिम नीतियों' के जोर-शोर से क्रियाशील होने के कारण लद्दाख, विशेषतः अक्साई चिन पठार रंगमंच बन गया एक-दूसरे को धोला देने के छतरनाक खेल को खेलने के लिए। चीनी और भारतीय चौकियाँ इस अंधा-धुन्ध तरोत्रे से बननी शुरू हो गयीं कि उनकी एक मुँथी हुई सी मृलला बन गयी जिसके कारण रह-रह कर आपस में अगड़े होना और स्थायी तनाव रहना आवश्यक हो गया।

वाल्व मे हमारे गुप्त सूचना विभाग ने घर हम बान की सम्भावना देनी कि चीनी हम बान का प्रयत्न करेंगे कि हर मुमकिन जगह पर भारतीय सीमा के धीरे धीरे घस कर तथा दक्षिण लद्दाख में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मे लगी हुई हमारी दुर्ब प्रतिरक्षा रक्षा को तोड़कर पिछले कुछ महीना मे स्थापित की गयी भारतीय चौकिया का खूब भग कर दें।

X

X

X

‘नऊनी युद्ध’ का अध्याय अब समाप्त हो गया।

२३ मई, १९६२, को पश्चिमी कमांड के एक मदेश ने बताया कि लद्दाख में हमारी चौकिया के सामने चीनी सरगमों धीरे धीरे बढ़ गयी है तथा हम बान की सम्भावना है कि दौनव बेग धोखी और स्वागुर में अपनी अग्रिम चौकियो तक सड़क बनाने के बाय की मुराशिन् रणन के लिए चीनी हमारी भूमि पर नयी चौकियो की स्थापना करें।

चीनियो न कराकोरम दर्रे तथा वागवा ला के बीच स्थित अपने दस्तों को आदेश दे दिया कि वे घागे के प्रदसों मे गस्त लगाना फिर से शुरू कर दें। माय ही चीन ने घमकी दी कि यदि भारत न लद्दाख मे गस्ती बारवाई बन्द नही करे तो न बाकी सीमान्त पर गस्त लगाता शुरू कर देंगे।

चीन ने अपने आपत्ति-पत्रो मे हम बात की नी चेतावनी दी कि यदि भारतीय सैनिक लद्दाख के खानो हिस्स मे नयी चौकिया स्थापित करने का काम बन्द नही करेंगे तो उठ आत्म रक्षा के लिए मजबूर हाना पड़ेगा। प्रत्युत्तर मे चीनी सैनिको ने बेसी मरुता मे चिश्वाप घाटी मे बनी हुई नयी भारतीय चौकियो का घेर लिया।

माय ही, चीनी उस सीमान्त की धीरे घागे बढ़ने लगे जिसका दावा उन्होंने १९६० मे किया था और उन्होंने ३० नयी चौकिया स्थापित की जबकि १९६२ मे हमने कुल मिलाकर ३५ चौकिया स्थापित की थीं।

इनके अतिरिक्त चीनिया ने तीन नयी सड़को का निर्माण शुरू किया (१) सामजु गलिंग स, गसवान नदी के किनारे-किनारे, हमारी एक चौकी के निकट तक, (२) खुनक दुर्ग से मिरिबाग के पास तक और (३) स्वागुर मील के दक्षिणी किनारे से लगकर स्वागुर से चिनबाग तक।

२५-२६ जून को लद्दाख का दौरा करने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल कौल ने सेनापति को दी गयी रिपोर्ट में लिखा

“हम लोगों के लिए यही उत्तर होगा कि लद्दाख मे जितनी चौकिया स्थापित कर सके करें। यह चौकिया भले ही अत्यन्त छोटे मुकामों पर हो लेकिन हमे किसी हानन मे इस बात का इन्तजार नही करना चाहिए कि इस इलाके मे विशाल सैनिक संगठन स्थापित हो। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि चीनी हमारी चौकियो पर हमला नही करेंगे भले ही वे उनकी चौकियो से कमजोर हों।”

यह अत्यन्त दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि २६ जून तक जनरल कोल को यह भ्रम था कि "चीन हमारी चौकियों पर हमला नहीं करेंगे" और यह कि उस इलाक़े की सारी चीनी सरणियों मान एक घुड़की है। जुलाई के पहले दस दिनों में नयी दिल्ली और पेरिस के बीच ३७८ आपत्तिपत्रों का विनिमय हुआ।

गलवान घाटी में काफ़ी नीचे तक चीनी प्रदेश से तथा वहाँ पर स्थित हमारी चौकी के तीन ओर से ४०० चीनी सैनिकों द्वारा घिर जाने से लद्दाख़ की परिस्थिति और भी खराब हो गयी।

अगले महीने चीनी लद्दाख़ के मध्य सेक्टर की ओर मुड़े और उन्होंने पांगोंग झील के क्षेत्र में यूसा में स्थित भारतीय चौकी को हर तरफ़ से काट दिया। यूसा और सिरिजाप पर पांगोंग झील में तैरती हुई नौकाओं से नियंत्रण रखा जा रहा था।

१७ अगस्त को पहली दफ़ा हमारे सैनिकों को घाज़ा दी गयी कि यदि चीन लद्दाख़ में हमारी चौकियों को घेरें तो उन पर गोली चलायी जाये।

पश्चिमी कमान्ड के सेनापति को यह आदेश दिया गया कि "हमारी चौकियों के पीछे चौकियाँ बनाने से चीनियों को किसी भी तरह रोका जाये। यदि चीनी अपनी स्थितियों से न हटे और हमारी चौकियों को घेरने का काम जारी रखें तो हमारे सैनिकों को यह आज्ञा है कि वे गोली चलायें और चीनियों के घेरे को तोड़ दें।"

चीनियों की नीति अब यह हो गयी थी कि हमारे अवपातन प्रदेशों पर क़ब्ज़ा कर ले ताकि हमारी चौकियों को हवाई यातायात द्वारा रसद आदि मिलना बन्द हो जाये। इसलिए हमारी चौकियों को यह आदेश दिया गया कि चीनी प्रयत्नों को विफल करने के लिए वह इन अवपातन प्रदेशों की रक्षा सशस्त्र रूप से करें। आदेश के शब्द थे: "अवपातन प्रदेशों पर क़ब्ज़ा करने के लिए चीनी प्रयत्नों को हमारी चौकियों पर प्रहार करने का प्रयत्न समझा जायेगा और उसे सशस्त्र रूप से विफल किया जायेगा।"

यूँ आखिर चुनौती दे दी गयी—भारत ने भी चीन को ललकारा।

×

×

×

लेकिन अगस्त, १९६२ के बीच में पश्चिमी कमान्ड के सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल दौलतसिंह के एक नोट से यह प्रत्यक्ष होता है कि इस प्रतिरक्षा व्यवस्था में क्या फ़ोल थी। उन्होंने बड़ी कटुता से इस बात की शिकायत की थी कि लद्दाख़ में हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था इतनी संगठित नहीं है कि बड़े चीनी आक्रमण के सामने ठहर सके। दौलतसिंह ने यह आरोप लगाया था कि लद्दाख़

की रक्षा के लिए कम से कम एक डिवीजन की माँग को भी सैनिक हेडक्वार्टर न पूरा नहीं किया था।

इसका पता यह था (जैसा जनरल दोननसिंह ने बताया) कि सहाय में स्थित सीमिन सेना को हम तरीके से इन्फेल्स करना पड़ रहा था कि अपने प्रदेशों का सामरिक रूप से नहीं, केवल भंडे दिताकर ही कब्जे में रखना सम्भव था। जनरल सिंह की राय थी कि अपनी 'पश्चिम नीति' को कार्यान्वित करने के कारण परिस्थिति और भी खिड़ गयी थी क्योंकि उसके खिलाफ चीनियों की प्रतिक्रिया बहुत ही सकल थी। महात्मा ने उस समय चीनियों का एक पुरा मैनिफेस्टो डिवीजन था जबकि हमारे सिर्फ दो नियमित और दो मिलीशिया बटालियन थे।

जनरल सिंह ने यह बतावनी भी दी कि यदि चीकियाँ स्थापित करने की स्पर्धा जारी रही तो हर सेक्टर में और हर स्थिति में चीनी हमारे ऊपर छा जायेंगे। वास्तव में, दोनों पक्षों के सैनिक साठसो और सत्तरसो की उस समय का हालत था उनके अनुसार यह बात चीनियों के हित में थी कि हम चीकियाँ स्थापित करने का काम जारी रखें। सहाय में अपनी सैनिक स्थिति को बिनाप पैमाने पर सगठित करने की क्षमता चीनियों ने हमसे कई गुणा बढ़ा दी थी क्योंकि आरम्भ से ही वे भयानकता में हमसे चीनूने थे।

जनरल सिंह ने बताया कि इस समस्या को सुलझाने में सामरिक तर्क का प्रयोग किया जाय क्योंकि अब तक राजनैतिक घावपचरनाओं के अनुपात में सैनिक तैयारी और भाषण व्यत्यस्त अपर्याप्त रहे थे। उन्हें इस बात की भी गिफायत थी कि सहाय में हमारी अग्रिम चीकियाँ बहो भी सामरिक दृष्टि से उचित स्थानों पर नहीं थी जबकि चीनियों ने हर जगह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान घेर लिये थे। हमारी चीकियाँ पूरी तरह अवपाकन प्रदेशों पर निर्भर थी और सामरिक दृष्टि से, ऊँचाई पर बना हुई चीनी चीकियाँ उन पर पूरी तरह हावी थी।

जनरल सिंह के अनुसार उक्त प्रदेश में हमारा सैनिक फैलाव 'कड़ा दिवाने' की राजनैतिक चाल में निष्पत्ति था, सामरिक दृष्टिकोण से नहीं। इसके विपरीत चीनी सैनिक फैलाव से यह भाष्ट था कि वह एक सुनिश्चित सामरिक योजना पर आधारित है और किसी विरोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया गया है।

जनरल दोननसिंह की राय थी कि सहाय में स्थित भारतीय सेना के सामने कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था और यदि था तो उसके लिए पर्याप्त सैनिक तैयारी नहीं थी। उनके विचार से चीनियों में अपनी सैनिक क्षमता थी कि सहाय में वे अपनी ही निर्धारित सीमा के हुई १९६० की सीमा के भागे के



प्रदेशों पर भी कब्जा कर सकते थे। और यदि वे ऐसा करने का निश्चय कर लेते तो भारतीय सेना में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन्हें रोक सकती।

अपने नोट के अन्त में जनरल सिंह ने लिखा :

“मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा यदि मैं इस और ध्यान आकर्षित न करूँ कि सम्भाव्य संकट का रूप क्या है, वह कितना विशाल है और उसे टालने के लिए किन साधनों की आवश्यकता है... अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मुसला ऐसा है जिसके बारे में उच्च-तम राष्ट्रीय स्तर पर तुरन्त निर्णय करना आवश्यक है और डील-बाल करने की गुंजाइश कतई नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिन अति-रिक्त सैनिक साधनों की माँग की गयी है उनकी मात्रा काफी अधिक है लेकिन यदि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में देखा जाये तो यह माँग बड़ी या अनुचित नहीं है। इससे कम साधनों से अपने उद्देश्य पूर्ण करना असम्भव होगा।”

जनरल सिंह के पत्र और उनके सुझावों पर जनरल थापर के सभापतित्व में सैनिक हेडक्वार्टर की एक विशेष बैठक में विस्तार में बहस हुई। वीलस सिंह स्वयं इस बैठक में उपस्थित थे। लेकिन बात-चीत के दौरान मे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का वही आग्रह रखा था कि हर हल में कोई न कोई पक्ष निकाली जाये; हर अधिकारी कोई चतुर बात कह कर वाक्पटुता में वाजी मारना चाहता था। नतीजा यह निकला कि सर्व सम्मति से यह सिद्ध कर दिया गया कि जनरल सिंह के प्रस्ताव अनुचित और अव्यावहारिक हैं।

बाद में बैठक के फैसलों को औपचारिक रूप से व्यक्त करते हुए, सी०जी० एस० जनरल कौल ने पश्चिमी कमान्ड के सेनापति का ध्यान उनके इन प्रस्तावों की ओर आकर्षित किया कि सितम्बर १९६३ तक तीन ब्रिगेड युपों का एक पर्वतीय डिप्टीजन लड़ाख भेज दिया जाये और सन् १९६४ तक लड़ाख में भेजने के लिए एक और ब्रिगेड पूरी तैयारी में रखा जाये तथा कहा कि सितम्बर, १९६३ तक तीन ब्रिगेड युपों का एक पर्वतीय डिप्टीजन लड़ाख भेजना असम्भव है।

जहाँ तक लड़ाख में हमारे सैनिक उद्देश्यों का प्रश्न था, जहाँ जनरल कौल ने पुनः यह बात कही कि चीनियों को आगे बढ़ने से रोकना और लेह की रक्षा करना हमारे उद्देश्य हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक हेडक्वार्टर ने सरकार को आगाह कर दिया है कि तत्कालीन साधनों को देखते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति की गारंटी देना असम्भव है। और चूँकि सरकार को सीमित सैनिक साधनों का ज्ञान था इसलिए उसने इस स्थिति पर सन्तोष कर लिया।

## नकली युद्ध का अन्त

'नकली युद्ध' का अन्त १० अक्टूबर, १९६२ को अचानक आत्म हो गया। अब तक दोनों पक्ष केवल सेंचें भरने का दिलचस्प खेल खेलते रहे थे।

भारतीय सेना के एव वरिष्ठ अधिकारी ने सहाय में इन सरगर्मियों का वर्णन इस प्रकार किया है "एक प्रकार का खेल सा था वह। वहीं बट (चीनी) चौकी बना लेते थे, वहीं हम। हमें यह विश्वास था कि बात इसके आगे नहीं बढ़ेगी।"

लेकिन एव पक्ष ने सेंचें भरने के इन खेल में कुछ ज्यादाती कर दी। गजीआ यह हुआ कि नैफा के बामेग सेक्टर के डोला क्षेत्र में स्थित ले जाग नामक स्थान पर चीनी तथा भारतीय दस्तों में संघर्ष भगड़ा हो गया। यह वह चिनगारी थी जिससे युद्ध की आग भटक उठी।

वास्तव में इस घटना के अठारह दिन पहले से चिनगारी फूस के ढेर के आग-दम भेड़ता रही थी जिसके फलस्वरूप मधी दिल्ली में भीषण रूप से सरगर्मियाँ शुरू हो गयी थी।

८ सितम्बर को सैनिक हेड क्वार्टर में प्राप्त हुए एक सिग्नल से ज्ञात हुआ कि उस दिन १४-३० मिनट पर एक चीनी सैनिक दस्ते ने सीमा पार कर ली है और नामका नु मदी और बागला के दक्षिण में डोला में स्थित हमारी चौकी को घेर लिया है।

उका चौकी केवल तीन महीने पहले, जून में ही, हमारी सक्रिय 'अग्रिम-नीति' के अन्तर्गत स्थापित की गयी थी।

भारत सरकार चीनियों की ओर से इतनी तेज प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। और न भारत सरकार के लिए अब यह सम्भव था कि चीनी उत्पादों का मुहताब जवाब देने की माँग करने वाले जर्मन को टाल सके।

सैनिक हेड क्वार्टर ने तुरन्त एबे पंजाब बटालियन को डोला पहुँचने का आदेश दिया। इसके ठीक बाद ही उस प्रदेश में एक पूरे ब्रिगेड को केन्द्रित करने की योजना थी। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के कार्यालय में हुई एक बैठक में पूर्वी कमान्ड के सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल एल० पी० सेन ने बताया कि डोला में ६०० चीनी सैनिक हैं। उनका अनुमान था कि इस चीनी दस्ते को वहाँ से खदेड़ने के लिए उन्हें पैदल सेना के एक ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ेगी और इस ब्रिगेड को डोला पहुँचाने में दस दिन लगेंगे।\*

१२ सितम्बर को सरकार ने आदेश दिया कि चीनियों को डोला से निकाल दिया जाये। ३३वें फ़ोर कमान्डर लेफ्टिनेंट जनरल उमरावसिंह और ४थे डिवीज़न कमान्डर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने कहा कि जो सैनिक साधन उनके पास हैं उन्हें देखते हुए यह काम पूरा करना असम्भव है। उन्होंने कहा कि जबकि चीनी पूरे तरीके से तैयार थे, उनके सामने सभार-तान्त्रिक कठिनाइयाँ थीं, रसद तथा अन्य सैनिक सामग्रियों का अभाव था और फ़ायर समर्थन अपर्याप्त था।

वास्तव में, उमरावसिंह की राय थी कि ऐसा कोई क्रम सिर्फ़ जल्दबाजी का काम होगा। उनका मत था कि डोला से पीछे हट जाया जाये और तोबांग की रक्षा के लिए साधन केन्द्रित किये जायें। तोबांग, जहाँ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, सामरिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण था और उसकी स्थिति अच्छी थी।

लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी थी कि उसके आदेश का पालन किया जाये।

साथ ही, मज़ाक यह था कि यह नौवस्त पहुँचने पर भी जब एबे पंजाब बटालियन के कमान्डिंग ऑफ़िसर, लेफ्टिनेंट कर्नल मिश्रा ने इस बात पर त्वष्ठीकरण माँगा कि डोला जाते समय चीनियों से मुठभेड़ होने की स्थिति में क्या किया जाये तो उनसे कहा गया कि वे चीनियों को पीछे हटने के लिए राजी करने की कोशिश करें और अस्त्रों का प्रयोग केवल तभी किया जाये जब ऐसा करना आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक हो और वह भी तब जब चीनी ५० गज से कम फ़ासले पर हों।

\*इस अध्याय में दिये गये मूल तथ्यों को लेखक ने अधिकतर जनरल कौल की पुस्तक 'भनकही कहानी' से लिया है।

१४ सितम्बर को सभा सत्रासय प्र हुन एव सभ्येनन मे मुख्य मेनापनि जनरल मापर ने सरकार को नेपा प्रदेश म सैनिक कारवाई के लिये फाता किया क्यकि उस प्रदेश म कई घपपान्तिगाए थी ।

पश्चिमी बमाल के सनारनि जनरल दोनर्नामह ने जारन थापर के मत का अनुमोदन किया और स्पष्ट रूप मे यह कहा कि यदि सहाय म चीनियों ने घातमण किया ता उस प्रदेश की सभा करने वाली हमारी सेना को वे विम्वुन नष्ट कर देंगे ।

पूर्वी बमाल ने मेनापनि जनरल मेन मे भी नफा में स्पिन भारतीय सेना की कमजारी के बारे म स्पष्ट मत प्रगट किया ।

सक्ति भाग्न सरकार दब किमी भी सौमन पर मुठ करने के लिए तुनी हुई थी—जनमन के दबाव स 'उने यह स्पिन घपमाने पर विवग होना पहा था ।

इस प्रकार लगभग आधिवरी बका पर, पक्ष की चिन्ता किये और, सरकार सेना से सक्रिय होने की मांग कर रही थी और सेना के बरिष्ठ अधिकारी सरकार को यह सन्नाह दे रहे थे कि सैनिक कारवाई मे जल्दबाजी करना देश के लिए घातक होगा ।

उसी दिन नयी दिल्ली मे प्रकाशित एक सरकारी पत्र मे घोषणा की "भारतीय सनिक सभ्य-सभ के साथ घातता पहारी की तरफ बढ़ गये हैं । नेत्रा (दाता) म स्पिन हमारी चौकी को सनस्त कर दिया गया है और स्थिति से सफमता मे निवटन के लिए पूर्वी बमाल बराबर प्रयत्नात्त है ।" यहाँ तीबांग के उम त्रिगेड की ओर मनेत है जो डोला प्रदेश की ओर बढ़ रहा था लेकिन जो बासल मे २४ सितम्बर तक डोला मही पटुचा था ।

१८ सितम्बर का एक सरकारी प्रवक्ता ने एक पत्रकार सभ्येनन में यह घोषणा की कि सेना को यह आदेश दे दिया गया है कि डोला क्षेत्र मे चीनियों को निवास करें । (उम समय प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री तथा अन्य मंत्री तीनों देश से बाहर थे) ।

त्रिगडियर जे० पी० दलवी २० सितम्बर को डोला पटुके और उन्होंने सेपिटनेट कनन मिथा से इस विषय पर मसवरा किया कि सरकारी आदेश का पालन कैसे किया जाये । हमारे बमालर अभी इस समस्या पर विचार विमग कर ही रहे थे कि उसी दिन आधी रात को एक चीनी दस्ते ने हमारे एक बरर में एक ड्रेनड पंका जिसमे तीन सैनिक जहमी हो गये । दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी शुरू हो गयी जिसमे दो चीनी सैनिक मरे और दो जहमी हुए । इसके बाद कार्पाण बन्द हो गयो ।

इस बीच भारतीय सैनिकों की तरफ मुठे हुए लाउडस्पीकरों के द्वारा चीनी दरावर यह नारे लगाते रहे ! "हिन्दी-चीनी भाई-भाई ! यह जमीन हमारी है ।—तुम वापस जाओ ।"

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग होती रही ।

२२ सितम्बर की एक निर्णायक मीटिंग में, जिसका सभापतित्व उपरक्षा मंत्री के रघुरमैया ने किया था (श्री मेनन संयुक्त राष्ट्र की सभा में शामिल होने के लिए गये हुए थे), सरकार ने आग्रहपूर्वक कहा कि राजनैतिक कारणों से इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि चीनियों को डोला क्षेत्र से निकाल दिया जाये । इस पर मुख्य सेनापति जनरल थापर ने कहा कि यह आदेश उन्हें लिखित रूप में दिया जाये । रक्षा मंत्रालय के सहायक सचिव श्री एच० जी० सरीन के हस्ताक्षर होने के बाद यह आदेश औपचारिक रूप से मुख्य सेनापति को दे दिया गया ।

२५ सितम्बर को डोला क्षेत्र के पुल नं० २ पर चीनियों ने स्वचालित फायरिंग की जिसके फलस्वरूप तीन भारतीय सैनिक जखमी हुए । अगले दिन, पहली बार, भारतीयों ने ३ इंच मॉर्टर के चार राउंड फायर किये ।

३० सितम्बर को रक्षा मंत्रालय की एक बैठक में (जनरल कौल के अनुसार) कृष्ण मेनन ने सैनिक अधिकारियों को यह बताया कि सरकार की नीति यह थी कि सड़ियों के मौसम के कारण सरगमियाँ ठंडी होने से पहले नेफ्रा में चीनियों पर एक तगड़ा सैनिक प्रहार डाला जाये ।

अतः ३ अक्टूबर को एक विशेष ४थी कोर बनायी गयी और जनरल कौल को उसका कमान्डर नियुक्त किया गया । उनको यह काम सौंपा गया कि चीनियों को नेफ्रा के भारतीय इलाकों से निकाल दिया जाये ।

४थी कोर का कमान्डर पद सम्हालने के लिए नेफ्रा जाने से पहले एक मुलाकात में श्री नेहरू ने जनरल कौल से कहा कि उन्हें "विश्वास था कि चीनियों को अक्रान्त आ जायेगी और वे डोला से हट जायेंगे । लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हम उन्हें उन प्रदेशों से निकाल दें या कम से कम भरसक ऐसा करने की कोशिश करें । यदि हमने ऐसा नहीं किया तो, श्री नेहरू ने कहा, "सरकार में जनता का विश्वास बिल्कुल खत्म हो जायेगा ।"

४थी कोर का कमान्डर पद सम्हालते ही जनरल कौल परिस्थिति का स्थानीय अध्ययन करने के लिए फौरन डोला के लिए रवाना हो गये । तीन दिन तक हेलिकॉप्टर में उड़ने और पैदल चलने के बाद वह डोला की ऊँचाई पर पहुँच पाये ।

इस एक महीने में, मदी के दोना तरफ मगटिन चीनी और भारतीय सेनाएं नमका खु के मुकाबिले में ठनी हुई थी ।

८ अक्तूबर को जनरल कौर स्थानीय कमांडर के साथ बात-चीत कर ही रहे थे कि ४०० यज की दूरी से चीनियों ने स्वचालित राइफल का एक दौर फायर किया । भारतीय पक्ष ने इसका बार्ड उत्तर नहीं दिया और घटना जहाँ की वहाँ ठनी पड़ गयी ।

घसली घटना दो दिन बाद घटी । १० अक्तूबर की प्रातः कात ५०० चीनी सैनिकों के एक दस्त ने नमका खु के उत्तर में स्ले जांग में स्थित हमारी चौकी पर आक्रमण किया । यह चौकी एक दिन पहले ही स्थापित की गयी थी और उस समय चीनियों ने बार्ड विरोध प्रगट नहीं किया था ।

अब तक दोनों पक्षा को यह नाहि रही थी कि यदि एक पक्ष कोई चौकी स्थापित करता था तो दूसरा पक्ष उन स्वीकार कर लेना था—केवल प्रत्युत्तर में किसी और स्थान पर अपनी चौकी पड़ी कर लेता था । इसलिए हमें यह आशा थी कि एक बार बार्ड हम स्ले जांग पर बहका कर लेंगे तो चीनी उसका विरोध नहीं करेंगे । लेकिन हम यह भी समझते थे कि यदि चीनी हमारी इस ५० सैनिकों की छाटी-सी टुकड़ी को छेद देने का निश्चय कर लेंगे तो न हम इस बात को रोक सके और न अपने सैनिकों को सहायता पहुँचा सकेंगे ।

फिर भी आक्रमण होने पर, स्ले जांग की हमारी सैनिक चौकी में (जो सुदृढ़ और अच्छी जगह पर स्थित थी) बड़ी बहादुरी से और दृढ़कर मुकाबिला किया । ६वें पञ्जाब घटालियन का एक और दस्ता सहायता के लिए आ गया और एक ऊँचे स्थान से उसने शत्रु पर गोलाबारी शुरू कर दी । चीनियों को हार खाकर वापस लौटना पड़ा और उनके काज्जी लोग बाम भागे ।

बाद में, चीनियों ने दूसरी बार और बड़े पैमाने पर तीन तरफ से आक्रमण किया । इस बार शत्रु के बहुत बड़ी संख्या में होने के कारण हमारे सैनिकों को अपना स्थान छोड़कर नदी के दक्षिण की तरफ हटना पड़ा ।

इन दोनों मुठभेड़ों का नतीजा था कि भारतीय पक्ष के छ आदमी मरे, ११ जख्मी हुए और ५ लापता हो गये । पैकिंग, टैडियो के अनुसार उनके १०० आदमी मरे ।

भारत और चीन के बीच यह पहली सशस्त्र मुठभेड़ थी । इससे यह बान भी स्पष्ट थी कि परिस्थिति गम्भीरतर रूप लेती जायेगी । यह भी जाहिर हो गया था कि अब चीनी इस बात की आशा नहीं देंगे कि भारतीय सैनिक उन सीमान्त इलाका में अपनी चौकियाँ स्थापित करें जिन्हें वे अपना कहते थे ।

इस मुठभेड़ का एक महत्व यह भी था कि भारत ने चुनौती स्वीकार कर ली थी ।

लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि ढोला ऐसा उचित स्थान नहीं था जहाँ पर जमाकर भारतीय सेना शत्रु से टक्कर लेती। जबकि सामने के शिखरों पर समुद्र बड़ा बँटा था तो हमारी सेनाओं का तनहटी में स्थापित होना सामरिक दृष्टि से कोई माने नहीं रखता था। चीनी बागला पहाड़ी पर १४,५०० फिट की ऊँचाई पर ये ओर ढोला में स्थित हमारी सेना, उनकी आँखों के ठीक नीचे १२,००० फिट की ऊँचाई पर। यदि हमें इस क्षेत्र में लड़ना आवश्यक था, तो हमें वहाँ से हटकर लुम्पू की ऊँची भूमि पर स्थापित होना चाहिए था।

इस समय नेकला के लगभग ३०० मील लम्बे सीमान्त की रक्षा करने के लिए हमारे केवल दो ब्रिगेड थे—तोवांग में स्थित ७वाँ ब्रिगेड और सुबनसिदि, सियांग तथा लोहित सेक्टरों में बँटा हुआ ५वाँ ब्रिगेड। [डिवीजन का तीसरा ब्रिगेड वहाँ से बहुत दूर इम्फाल (मनीपुर) में स्थित था।]

बात दरअसल यह थी कि हमारी सेना गलती से ढोला में फँस गयी थी और उसके बाद राजनैतिक कारणों से सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि यह छोटा-सा दस्ता अपनी जगह पर अटल रहे हालाँकि सैनिक अधिकारी इस निर्णय के विरुद्ध थे।

ढोला में फँस हुए हमारे एक ब्रिगेड के मुकाबिले में चीनियों का पूरा डिवीजन वहाँ स्थित था। जब कि चीनी सेना को, यातायात के अत्यन्त उत्तम साधन और सुविधाएँ होने के कारण, रसद और शस्त्र सैनिक सामग्री प्रचुर मात्रा में मिल रही थी, हमारा निकटतम रोडहेड ६० मील दूर तोवांग में था और हमारे सैनिकों को रसद की, अस्त्र-शस्त्रों की, गोला-बारूद की, जूतों की और कढ़ी सदियों के लिए आवश्यक वस्त्रों की कमी थी। ढोला में चीनियों से मुठभेड़ होने से ठीक पहले हमारे दो बटालियनों—२रा राजपूत और १/६ गुरखा—के पास केवल तीन दिन की रसद और छोटे अस्त्रों के गोला-बारूद के सिर्फ ५० राउण्ड थे। मॉर्टर तथा अन्य प्रकार के बम सभी लुम्पू से ढोला की तरफ आ ही रहे थे। और उन ऊँचाइयों पर स्थित हमारे सैनिक अभी तक जहाँ बंदियों में थे जो केवल गर्मियों के लिए उपयुक्त होती है।

ढोला में स्थित हमारी सेना पूरी तरह निर्भर थी हवाई यातायात द्वारा सामान गिराये जाने पर लेकिन यह तरीका कठिन भी था और अनुचित भी। हवा से गिराया हुआ सामान अक्सर गहरी खाइयों में गिर पड़ता था और उसे वहाँ से लाना असम्भव था। एक बार तो ऐसा हुआ कि त्सांगदर पर हवाई तौर पर गिराई हुई तोपें, जिनकी बहुत ही सख्त जरूरत थी, पराशूटों के बल पर न खुलने के कारण भूमि पर गिरने के बाद टुकड़े-टुकड़े हो गयीं।

सारी स्थिति को वहाँ पर अच्छी तरह देख लेने के बाद, नयी कोर के कमान्डर जनरल कौल डिवीजनल कमान्डर निरंजन प्रसाद और ब्रिगेड

कमांडर बनवो में पूरी तरह सहमत हुए कि ढोला क्षत्र से सन्तु को निकालने के लिए सरकारी आना अभ्यासहारिक है ।

११ अक्तूबर को जनरल कौन नयी दिल्ली वापस पहुँचे और उन्होंने एक बैठक में (जिसमें रक्षा मंत्री और मुख्य सेनापति भी थे) श्री नेहरू को ढोला की आँव देवी स्थिति बताया ।

जनरल कौन ने इस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि ढोला में प्रतिकूल स्थिति में पड़ी हुई, छोटी-सी और साधनहीन सेना के लिए यह भ्रमम्भ है कि वह सरकारी आदेश का पालन करे । उन्होंने आग्रहपूर्वक यह कहा कि ढोला में हमारी सेना की स्थिति पूरी तरह अनुचित है, कि वह ऐसी तनहटी में पड़ी हुई है जहाँ से किसी भी प्रकार का युक्तिवादन असम्भव है और इसके ऊपर चीनी एक ऊँची, अनुकूल स्थिति में बटे हुए हैं । सामरिक और मभार तांत्रिक दृष्टि में चीनी ज्यादा अच्छी स्थिति में थे और मुठभेड़ होने पर उनकी जीत होनी निश्चित थी । वास्तव में, जनरल कौन की राय थी कि हमारी सेना को वहाँ से हट कर सामरिक दृष्टि से किसी ज्यादा अनुकूल स्थान पर पर जमाने चाहिए ।

काफी वादविवाद के बाद श्री नेहरू इस बात पर तैयार हुए कि 'चीनियों को निकालने' का आदेश बंद कर यह आदेश दिया जाये कि ढोला में स्थित हमारी सेना भीतिया के विरोध के बावजूद अपने स्थान पर बड़ी रहे । यह बदला हुआ आदेश ढोला भेज दिया गया ।

आदेश में इस परिवर्तन को देखते हुए हमारे अग्रिम मोर्चे के कमांडर अचानक चकित हुए होते जब १३ अक्तूबर को उन्होंने रेडियो पर पत्रकारों को दिया गया श्री नेहरू का अफसोस सुना होगा ।

उस दिन सुबह, पालम हवाई अड्डे पर, कोलम्बो जाने समय श्री नेहरू ने पत्रकारी से कहा कि इस बात के लिए आदेश जारी कर दिए गये हैं कि चीनियों को नेत्रा में 'हमारी भूमि' से निकाल दिया जाये । स्पष्टीकरण के लिए पूछे गये एक अतिरिक्त प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा, "इसकी निधि मैं निर्दिष्ट नहीं कर सकता । इस बात का फैसला करना पूरी तरह सेना के हाथ में है ।"

श्री नेहरू के इस कथन से, उस समय, देश-विदेश में भीषण वाद विवाद सदा हो गया । और जनरल कौन ने अपनी पुस्तक 'अनकही कहानी' में पाँच वर्ष बाद वाद विवाद की अपटो की फिर से अडका दिया ।

श्री नेहरू पर यह आरोप लगाया गया कि अपने इस कथन में उन्होंने झूठ माना था । आरोप लगाने वालों ने उनके १३ अक्तूबर की पत्रकारों को दिये गए कथन का सीधा सम्बंध उस नियम से लगाया जो ११ अक्तूबर की



अद्वारा की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में चीनियों को ढोला से बाहर निकालने के मूल आदेश को बदल दिया गया था और नया सरकारी आदेश यह था कि ढोला में स्थित भारतीय सेना चीनी विरोध के बावजूद अपने स्थान पर बटी रहे।

मेरे विचार से प्रधानमंत्री के १३ अक्टूबर के कथन को ११ अक्टूबर के निर्णय के आधार पर झूठ कहना अनुचित है क्योंकि श्री नेहरू का शेष कथन भी ध्यान में रखना चाहिए : “इसकी तिथि में निश्चित नहीं कर सकता। इस बात का फैसला करना पूरी तरह सेना के हाथ में है।”

प्रत्यक्ष है कि यदि उनके मन में ढोला की सीमित समस्या होती (जिसके बारे में ११ अक्टूबर को वृत्त हो चुकी थी) तो वे अनिश्चित रूप से यह नहीं कहते कि चीनियों को बाहर निकालने की तिथि को निश्चित करने की बात सेना के हाथ में है। यहाँ यह बात समझ लेना आवश्यक है कि ११ अक्टूबर का निर्णय केवल ढोला में स्थित हमारी सेना के सामने उपस्थित समस्या के बारे में था। और हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि पत्रकारों के सामने १३ अक्टूबर को दिया गया श्री नेहरू का कथन मात्र एक राजनैतिक कथन था जो इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसके द्वारा भारत सरकार ने पहली बार (मले ही आतुर जनमत के दबाव के धरा) यह घोषित किया था कि अब से वह अपनी भूमि पर चीनी अतिक्रमणों को सहन नहीं करेगी और सशस्त्र रूप से शत्रु का मुकाबला करेगी।

क्योंकि १३ अक्टूबर के सामान्य कथन का ११ अक्टूबर के निर्णय से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिए कथन में कोई झूठ नहीं था। यूँ ११ अक्टूबर का बदला हुआ आदेश—कि हमारी सेना ढोला में बटी रहे या यदि सामरिक कारणों से आवश्यक हो तो वहाँ से हट भी जाये—समस्या को बढ़ती तौर पर राजनैतिक ढंग से हल करने का तरीका भी हो सकता था जो भारत सरकार की इस नीति का अंग था कि अब से वह चीनियों का मुकाबला करेगी।

श्री नेहरू के कथन की संदिग्धता वास्तव में संदिग्ध है विशेषतः ऐसे समय पर जब राज्य के प्रमुख के कथनों में स्पष्टता तथा साधवानी की विशेष आवश्यकता थी। लेकिन मैं इस आरोप का समर्थन कदाई नहीं कर सकता कि श्री नेहरू ने जान-बूझकर झूठ बोला। श्री नेहरू में कम से कम इतना विवेक अवश्य था कि ऐसा कोई वक्तव्य न दें जो घटनाओं से झूठ साबित हो जाये।

श्री नेहरू ने जानबूझकर एक संदिग्ध वक्तव्य दिया था और इसके पीछे उनके दो उद्देश्य थे : एक तो आतुर जनमत को बहलाना; दूसरे, चीनियों को जतला देना कि भारत सरकार की नीति बदल गयी है और यदि वे अपने अतिक्रमणों में बाध न आये तो आगे से भारत उनका सशस्त्र रूप से विरोध करेगा।

हो सकता है कि अपने सहज स्वभाव के कारण श्री नेहरू ने यह समझा हो कि इस घाम घोषणा द्वारा प्रगट भारत सरकार के इस सैन्यवादी दृष्टिकोण से चीन प्रभावित हो जायेगा और हमारे सीमान्त पर अपने उद्भावों को बन्द कर देगा ।

यह धारणा इस बात को देखने हुए सही हो सकती है कि श्री नेहरू को धन्य तब यह विद्वान् था कि चीनी बेवकूफ बन्दर-मुडकी की नीति का प्रयोग कर रहे हैं और सीमान्त की समस्याओं को हल करने के लिए व कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे । वास्तव में यह विचार किया जाता है कि कुछ ही महीने पहले भारत के रक्षा मंत्री और चीनी प्रधान मंत्री जेनेवा में मिले थे तो चांग इन साई ने श्री नेहरू को (कृष्ण मेनन द्वारा) यह पारवामन दिया था कि चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा ।

यह आरोप लगाना भी गलत होगा कि श्री नेहरू के १३ अक्तूबर के बयान के कारण ही चीनिया ने २० अक्तूबर को भारत के उत्तरी सीमान्त पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था । क्योंकि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि चीनी काफी समय से २,६०० मील सम्भे भारत-निम्न सीमान्त पर शक्ति संचित कर रहे थे, इस उद्देश्य से कि वे एक दिन भारत पर आक्रमण करेंगे । चीनी समाजवादी के और व जानते थे कि उनकी स्पष्ट विस्तारवादी नीति के फल-स्वरूप भगडा होना निश्चित है ।

सन् १९५५ से सीमा त के तिब्बत वाले भाग में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के बनाने का काम शुरू हो गया था । उस समय नयी दिल्ली और पकिंग में यह भारा बुलन्द था “हिन्दी चीनी भाई-भाई” । मैक्महॉन रेखा के तनिक उत्तर में उन्होंने एक उत्तम ३-टनी सड़क बना ली थी और इसके मलावा उससे मिलने वाली सहायक-सड़कों का जाल बिछा दिया था । नेपा के कामेंग मण्डिवीडन और भटान के काफी निकट बूम ला से ५० मील दूर मरापुमत्सो में उन्होंने एक हवाई धड्डा भी बना लिया था ।

अक्तूबर १९६२ तक केवल नेपा के सामने ही चीनियों के चार डिवाइजन स्थित थे । इसके विपरीत उस इलाके में हमारा निक एक डिवाइजन था—और उसने भी एर बिगेड कम था । मन् १९५६ में चीन के बराबर बढ़ते हुए उत्पातों से यह स्पष्ट था कि भारत के प्रति चीन की नियत खराब है ।

कई वर्षों से सदास में चीन की स्पष्टतः यह नीति थी कि निश्चित रूप से हमारी भूमि पर आतिश्रमण करते हुए स्वयं निर्धारित सीमा तक बढ़ने जाये । और चीनिया द्वारा निर्धारित यह सीमा रेखा उनके हर नये मानचित्र के साथ हमारी भूमि पर आगे खिसकती ही जाता थी ।

सन् १९६२ के मध्य तक हमारी निश्चेष्टता के कारण चीन की ‘अग्रिम’ नीति शान्तिपूर्ण ढंग से काम कर रही थी और उन्होंने कभी भी शत्रुओं का

प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझा। लेकिन जून १९६२ में भारत ने भी अपनी सक्रिय 'अग्निम नीति' भालू कर दी थी और इसके फलस्वरूप सशस्त्र झगड़ा होना निश्चित था—इसके लिए चीनी काफ़ी समय से तैयार थे।

गुप्त सूचना विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर १९६२ के छुले सशस्त्र झगड़े से पहले चीनियों ने छः और बटासियन भारत-तिब्बत सीमा पर पहुँचा दिये थे। पूरे तिब्बत में चीनियों के आठ डििवीजन थे। इनमें से लगभग सात डििवीजन दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिमी सीमान्त इलाकों में स्थित थे।

इसके अतिरिक्त सिनयांग के दो रेजिमेंट (४००० सैनिक) उत्तरी लद्दाख के सामने स्थित थे। दक्षिण लद्दाख तथा पंजाब-हिमाचल प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा पर चीनियों के सात बटासियन डटे हुए थे।

२० अक्टूबर के विद्युत् चीनी आक्रमण के लगभग एक सप्ताह पहले से थागला क्षेत्र में चीनियों ने तेज सरगर्मी शुरू कर दी थी। पशुओं पर लादकर वे अपनी तोपें उस क्षेत्र में ले आये और डोला में स्थित हमारी सेना की तरफ़ उनका वज्र करके उन्हें स्थापित कर दिया। उस समय हमारी सेना के पास एक भी तोप नहीं थी।

जिस समय चीनियों ने, विशाल पैमाने पर, लद्दाख और नेफ़ा पर एक साथ आक्रमण शुरू किया उस समय भारतीय सैनिक अधिकारी मोर्चा लेने के बजाय, इस बात पर बहस कर रहे थे कि संख्या में अधिक, साधनों में उत्तम शत्रु का मुकाबिला करने की माँग करने वाले सरकारी आदेश का पालन कैसे किया जाये। और अपनी सैनिक संख्या की कमी तथा अस्त्रों और साधनों की तात्कालिक अपर्याप्तता को देखते हुए उन्होंने एकमत होकर यह कह दिया था कि शत्रु का सामना करना असम्भव है।

## असीम अपमान

सितम्बर १९६२ के बाद अघा घादयी भी यह देण सहता था कि चीन आक्रमण करने पर आमादा है और कुछ म पुण मफरना प्रान्न करने को तैयारी कर रहा है ।

१३ सितम्बर को एक चीनी पत्र ने बड़े तीर पर यह माँग की कि १३ अक्तूबर को दोना देगा म समझौते को खान हा और दोना देगा की मेनाएँ सीमान्त पर २० किलोमीटर पीछे हट जायें ताकि ताव कम हो जायें । इन पत्र मे भारत पर यह आरोप लगाया गया कि वह झूठे समझौते और मन्त्र भगडों की डिपुन्नी नीति मे काम से रहा है और भारत सरकार सीमा समस्या को धानिपूर्ण ढंग से नहीं मुनझाना चाहती है बल्कि 'समझौते की घाट मे चीनी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहती है और सीमा की यथापूर्व स्थिति को भग करना चाहती है ।"

पेकिंग द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग अजीब था हात्ताकि अपने राजनयिक पत्र व्यवहार मे व हमेगा ही अनियन्त्रित भाषा का प्रयोग करने रहे थे । इस पत्र से स्पष्ट था कि चीन धुरु से यह जानता था कि भारत उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा ।

जैसा स्पष्ट था, भारत सरकार ने १४ सितम्बर को चीन के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया क्योंकि चीनियों के इस पत्र के बावजूद 'आक्रमक पक्ष का अधिकार अभी तक उसके द्वारा अनधिकृत ढंग मे प्राप्त की हुई जमीन पर है ।' वास्तव में, भारत ने पहली बार चीन को 'आक्रमक' करार दिया था ।

१७ सितम्बर को चीनियों को एक बटालियन दम दम ता पहुँच गयी । यह स्थान त्सांगसी (जो यांगत्सा के रास्ते मे भूटान, तिब्बत और भारत के बीच

एक मार्क का स्थान है) में हमारी चौकी के सामने था। अगले दिन, दम दम ला से एक चीनी गश्ती दस्ता ढोला क्षेत्र में पुल नं० ५ की ओर बढ़ा; भारतीय सैनिकों ने उस दस्ते पर गोली चलायी जिसमें एक चीनी काम आया।

१६ अक्टूबर को त्सांगघर में हमारी चौकी ने खबर दी कि २,००० सैनिकों का एक चीनी दस्ता त्सांगली से घागला की तरफ बढ़ रहा है। उसी शाम यह देखा गया कि एक चीनी वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जीप द्वारा अपने सीमान्त के पीछे जा रहा है—स्पष्ट था कि आक्रमण करने से पहले वह अपने सैनिकों और स्थितियों का मुयाइना कर रहा था। वास्तव में अक्टूबर १५ से १६ तक चीनी सीमा के पीछे काफ़ी सरपर्सी देखी गयी।

ढोला क्षेत्र में स्थित ७वें ब्रिगेड के कमान्डर, ब्रिगेडियर दलवी ने मुझे बताया कि अप्रैल, १९६२ से हो चीनी युद्ध के लिए इतनी पूरी तरह तैयार थे कि नेफा में स्थित उनकी सेना के साथ फ़ोटोग्राफ़ों और दुभाषियों की एक टोली भी थी।

ब्रिगेडियर दलवी ने बताया कि : "जबकि साधारण सैनिक सिद्धांतों के अनुसार आक्रमण के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि शत्रु से अपनी संख्या तीन गुनी हो, माघों के अनुसार यह अनुपात ५ : १ होना आवश्यक था। इसी अनुपात को पूरा करने के लिए चीनियों ने नेफा में अपनी सैनिक संख्या बढ़ाने का कार्य जारी रखा जिसके फलस्वरूप उनके लिए यह सम्भव हो सका कि वे, एक के बाद एक सैनिकों के रेस्ते युद्ध में डाल सकें।" ब्रिगेडियर दलवी के अनुसार, अक्टूबर १९६२ तक नेफा मोर्चे के कार्मिंग सेक्टर में चीनियों की सैनिक संख्या १०,००० हो गयी थी।

२० अक्टूबर को जब चीनियों ने नेफा मोर्चे पर जोरदार आक्रमण किया तो, अन्य अपर्याप्तताओं के अलावा, भारतीय सेना के पास कोई कोर कमान्डर नहीं था जो हमारी सेना की युद्ध कार्रवाइयों को निर्देशित और संगठित करता। जनरल कौल को ऐन मौके पर दिल्ली पहुँचना पड़ा था क्योंकि उन्हें एडीमा नामक ऐसी बीमारी हो गयी थी जो खास तौर से ऊँचाइयों पर ही होती है।

टी-जिक्स को सुबह साढ़े चार बजे 'चीनी सैनिकों का एक सैलाब' ढोला में हमारी चौकी पर टूट पड़ा। इन दो चीनी बटालियनों (२,००० सैनिकों) के पास स्वचालित राइफ़लों, ६ मिलीमीटर तोपें, भारी मॉर्टर और अन्य किस्म के गोला-बारूद थे। आधी दर्जन भारतीय स्थितियों की रक्षा करने के लिए केवल ६०० सैनिक थे।

चीनी सैनिक सैलाब के सामने हमारे सैनिक प्रतिष्ठान-बात की बात में उलझ गये। ढोला में स्थित हमारी मुख्य चौकी वष्ट हो गयी। लगभग इसके

साथ ही दोला से दस मीन पूव सिद्धमान पर भी चीनियों ने बमबाद कर दिया। तत्पश्चात् म स्थित हमारा छोटा-सा दस्ता हट कर भूगर्भ बना गया। अगले दिन सुबह तक हाथु ग सा धनु के हाथ में था।

अगले दिन सुबह पाँच बजे चीनियों ने स्मार्गपर से स्थित हमारे ७९ त्रिगड हड्कवाटर पर आक्रमण किया और भीषण गोलाबारी की। भारतीय दल न भी गोलाबारी की लेकिन गोघ ही उनके पास गोले चूक गये। धनु की विजय हुई और उन त्रिगडिपर दल की सहाय्य अधिकारियों को पकड़ लिया।

द्वितीय त्रिगड हड्कवाटर द्वारा रेखा हुआ एक हेवीकाँटर एक बायरनेस सेट तथा एक विमान अधिकारी के साथ उस समय स्मार्गपर से उतरा जब चीनियों ने उस पर बमबाद कर दिया था। हेवीकाँटर का आतन गोली का गिराव हुआ और हेवीकाँटर पर धनु ने अपना अधिकार कर लिया।

अब तक लगभग ५ के सामने चीनियों का एक पूरा द्वितीय त्रिगड था और दोला म सिद्धमान तक दस मीन के मोर्चे पर बड़ा हुआ था। इससे फलस्वरूप हमारी प्रतिक्रिया रक्षा मित कर बहुत भीषण हो गयी थी और हमें अपने दलों को पुन मगठित करना अनिवार्य हो गया था।

इसी बीच जिस चीनी दल ने सिद्धमान पर बमबाद किया था वह पूर्व में कुछ मीन और आगे बट गया और उसने वुम सा नामक भारतीय सीमान्त नगर पर बमबाद कर दिया। यहाँ स्थित सैनिकों ने बट कर धनु का मुकाबिला किया था और धनु के काफी सैनिक काम आये थे लेकिन धनु की सैनिक सहाय्य बहुत घटित होने के कारण हमारे वीर सैनिकों को यह चीजें छोड़कर हटना पड़ा था।

वुम सा त्रिगड से ठीक ७ मील उत्तर में है। वुम सा की ऊँची स्थिति पर बमबाद कर लेने के कारण चीनियों के लिए त्रिगड पर आक्रमण करना असंभव हो गया। और २१ अक्टूबर को लुम्पू के पतन के बाद, सारे दोला-पायल क्षेत्र से हमारा संपर्क खत्म हो गया।

यह सारे स्थान बाट की वान म दुश्मन के हाथों में चले गये थे। और २२ अक्टूबर को चीनी तावाग पर आक्रमण करने को तैयार थे।

हमारे मान्यता कि तावाग म भारत का सबसे विज्ञान मीन-मठ था, यह नगर इस सारे प्रदेश का प्रशासकीय केन्द्र था, सेना के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण रोड-हड्ड था और हमारी प्रतिरक्षा रेखा—तावाग-सेला सा—बामदी सा-जेजपुर में सबसे मार्गे का स्थान था।

हमारे पीछे हटे हुए सैनिक काफी सुव्यवस्थित हालत में त्रिगड पहुँचे थे। त्रिगडिपर दल की अनुपस्थिति में उस क्षेत्र के आर्टिलरी कमांडर

त्रिनेत्रियर ( अब मेजर जनरल ) कल्याणसिंह ने भारतीय सैनिक दल का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और तोबांग की प्रतिरक्षा का कार्य सम्हाला । इस अवसर पर अद्भुत वीरता और नेतृत्व के गुणों का परिचय देने के कारण त्रिनेत्रियर कल्याणसिंह को विशिष्ट सेना पदक प्रदान किया गया ।

चीनियों ने तीन तरफ से—पश्चिम, उत्तर और पूर्व से—तोबांग पर आक्रमण किया । स्टांगघर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पतन और हमारी सेना के काफ़ी हद तक नष्ट होने के कारण तोबांग की प्रतिरक्षा काफ़ी कमजोर हो गयी थी । कल्याणसिंह उस समय तक अपने स्थान पर हटे रहे जब तक उनके गैरिसन को पाँच मील पूर्व, जांग, तक हटाने का आदेश नहीं मिला । पीछे हटनेवाला भारतीय दस्ता काफ़ी रसद तथा अन्य सामग्री वहीं छोड़ आया था ।

कोर कमान्डर जनरल कौल के दिल्ली में बीमार पड़े होने की वजह से पूर्वी कमान्ड के सेनापति लेफ्टिनेन्ट जनरल सेन ने तोबांग में आकर कार्य-भार सम्हाला । उन्होंने आदेश दिया कि तोबांग गैरिसन अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर जांग के दक्षिण में चला आये क्योंकि इस बात का खतरा था कि शीघ्र ही चीनी उसे चारों तरफ से घेर लेंगे ।

अतः २५ अक्टूबर को शत्रु ने बिना किसी विरोध के तोबांग पर अधिकार कर लिया । उसके बाद हमारी सेना जांग से खदेड़ दी गयी और उसने स्ने ला में शरण ली । थके हुए, निराश तोप-सैनिक जांग छोड़ कर एक पतले से जीप मार्ग पर लोगों को ढकेलते हुए पीछे हटे ।

इसी बीच २२ अक्टूबर को चीनियों ने नेफ्रा मोर्चे के सुदूर पूर्व में एक नया मोर्चा खोल दिया । लोहित सीमान्त डिवीजन में लोहित नदी के नीचे के किबीटू की तरफ बढ़े—उनकी आँख बालोंग पर लगी हुई थी । उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि यह केवल हमारी सेना के एक टुकड़े को नष्ट करने की ही तरकीब है ।

×

×

×

वहाँ तक नेफ्रा का प्रश्न था, चीनी आक्रमण का पहला दौर २५ अक्टूबर को खत्म हो गया ।

लेकिन साथ ही साथ, २० अक्टूबर को चीनियों ने लद्दाख में हमारी सैनिक स्थितियों पर आक्रमण बोल दिये थे । किन्तु लद्दाख में युद्ध का तरीका भिन्न था । नेफ्रा में वे भूमि तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दरों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे । लद्दाख में संपर्क था एक-दूसरे से दूर पर स्थित तथा सब ओर से कटी हुई चीनियों पर कब्जा करने के लिए । इनमें से किसी चीकी पर तीस-चाबीस सैनिक से अधिक नहीं थे और भारतीय तथा चीनी

चीनियाँ एक-दूसरे से मुष्ठी हुई थीं। चीनी करने यह थे कि मुकाबिले में कहीं अधिक सैनिकों को लेकर वे हमारी चौकी को घेर लेने में धीर न हिरा तो छाट से भारतीय मरिस्तन को वहाँ से निजात देने थे या धन्य तब मुड़ कर वे उने पुनत नष्ट कर देने थे।

भूमि पर संचार व्यवस्था विस्तृत न होने के कारण हमारी इन चौकियों को पूरी तरह हवाई-समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था और इसलिये आक्रमण होने की हालत में यह कमजोर और असहाय थीं। इसके विपरीत चीनी चीनिया के पीछे सारे पूर्वी महासमुद्र में बिछा हुआ ८०० मील की लम्बाई का सड़कों का जाल था जिसके कारण उनके सामने कोई समार समस्या नहीं थी।

इसके अलावा चीनियों के पास इस इलाक़े में हथ में बने ची—७० टैंकों के हा स्वबाहुन थे। खुगुल मेक्टर में मरिजाप पर आक्रमण करने समय चीनियों ने बम्बरबन्दी में अपनी इस उत्तमता का प्रयोग अत्यन्त घातक ढंग से किया।

पहले ही दिन, उत्तरी मेक्टर में, उन्होंने साइन से १६ में से ११ भारतीय चौकियों पर हमला किया।

कराकोरम के ठीक नीचे दोन वेग मोल्डी उत्तर में सबसे दूरस्थ भारतीय चौकी थी। संचार के मामले में यह चौकी सब तरफ से कटी हुई थी और पूरी तरह हवाई-समर्थन पर निर्भर थी। चीनी सड़कों में से एक काफ़ी मार्ग की मदद कराता दर्रे से मोल्डी की तरफ जाती है। चीनी इसी सड़क से आये और उन्होंने मोल्डी पर आक्रमण किया। चीनी सैनिक भारतीयों से हम गुना क्यादा थे फिर भी मोल्डी के भारतीय रक्षक वीरता से लड़ते रहे। २३ अक्टूबर को उन्हें आदेश मिला कि वे मोल्डी को छोड़कर पीछे हट जायें।

अगले दो दिनों में बिन्दु १८४४० तथा दस्तावे में स्थित हमारी चौकियाँ भी दुरमन के हाथ खनी गयीं।

दोन वेग मोल्डी में हमारी सेनाओं के हटने के कारण कराकोरम दर्रे के दोनों ओर चीनियों का प्रभुत्व हो गया और युद्ध-क्षेत्र में पहुँचने के लिए उन्हें एक और महत्वपूर्ण मार्ग मिल गया। इसका अर्थ यह भी था कि कराकोरम दर्रे से दमचाँक तक उत्तर-पूर्वी महासमुद्र पर चीनियों का अधिकार हो गया है।

जिप चांग नदी के दक्षिण में एक भारतीय चौकी के ३० जवानों ने मारे दिन १०० चीनी सैनिकों का मुकाबिला किया—मुकाबिले के अन्त में केवल ४ भारतीय जवान जीवित बचे थे, कहा जाता है कि चीनियों के १५० सैनिक काम आये। सारे महासमुद्र में भारत-चीन मध्यस्थ संधियों में लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था।



मध्य सेक्टर में चीनियों ने हमारे सैनिकों को कोंग का और चेंग चेनमो से निकाल दिया। एनी ला तथा चातसे से फोआंग तक भारतीय सैनिक अपने आप पीछे हट गये।

२४ अक्टूबर को युला पर कब्जा कर लेने के कारण, केवल ४८ घंटों में पूरा उत्तरी लद्दाख चीनियों की मृष्टी में आ गया था। २७ अक्टूबर को छांग ला, जारा ला, दम चाँक, दक्षिण सेक्टर में नल्सा जंक्शन तथा मध्य सेक्टर में हॉट स्प्रिंग में स्थित हमारी चौकियों पर या तो शत्रु ने कब्जा कर लिया था हमारे सैनिक उन्हें छोड़कर स्वयं पीछे हट गये।

फिर भी लद्दाख में भारतीय सेना का अपमान काफ़ी व्यवस्थित ढंग से हुआ हालाँकि शत्रु के संख्या में कई गुना होने के कारण उन्हें बराबर ही पीछे हटते रहना पड़ा था। इस व्यवस्थित अपमान तथा एयाश जमकर शत्रु का मुकाबिला करने का कारण यह हो सकता है कि लद्दाख में स्थित भारतीय सेना उस प्रदेश में काफ़ी समय से थी और इसलिए वहाँ की जलवायु तथा भूमि विशेषताओं की आदी हो चुकी थी। उसकी युद्ध-तत्परता भी तुलनात्मक रूप से अधिक थी और उसके नेता अधिक कुशल थे।

इसके बाद चीन ने आक्रमण करने बन्द कर दिये और इस बीच में कि दूसरे दौर के लिए वे अपनी सेना और साधनों को पुनः व्यवस्थित करें, उन्होंने फिर समय भरने के लिए धान्ति का नाटक किया। २४ अक्टूबर को पेकिंग ने नेहरू-चाउ वार्ता का प्रस्ताव रखा।

इस प्रस्ताव के तीन अंग थे : (१) कि दोनों पक्ष हिमालय के सीमान्त के दोनों सिरों पर 'वास्तविक अधिकार रेखा' के २० किलोमीटर पीछे हट जायें; (२) कि दोनों उस रेखा का उल्लंघन न करने का वचन दें और (३) सीमा समस्या का समझौता 'मैत्रीपूर्ण ढंग' से करने के लिए पेकिंग में या यदि श्री नेहरू चाहें तो तभी दिल्ली में नेहरू-चाउ वार्ता हो।

ऐसा ही एक प्रस्ताव चाउ इन-लाई ने १३ अक्टूबर को रखा था जिसे भारत ने उसी समय रद्द कर दिया था इसलिए कि दोनों में सीमा सम्बन्धी समझौते की वार्ता केवल तभी होना सम्भव था जब पहले चीनी सेनाएँ उन प्रदेशों से हट जायें जिनके बारे में झगड़ा था और युद्धपूर्व यथास्थिति पदा हो जाये। अब और भी सन्नत स्थिति से चीन ने यह प्रस्ताव दोहराया था और वह आशा करता था कि आहत और परेशान भारत उसके इस प्रस्ताव को अव स्वीकार कर लेगा।

भारत सरकार ने उसी दिन इस दूसरे प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया यह कह कर कि बात-चीत तभी सम्भव है जब चीनी सेनाएँ २ सितम्बर, १९६२ की स्थितियों पर वापस लौट जायें। साथ ही यह भी आग्रहपूर्वक कहा गया

कि भारत हमेशा मैत्रीपूर्ण ढंग से समस्याओं को हल करने का इच्छुक है लेकिन ऐसा वह केवल 'चीन और आत्म-सम्मान के आधार पर ही कर सकता है, तब नहीं जब शत्रु की सेनाएँ उसकी भूमि पर हटी हों।

श्री नेहरू ने चाउ इन-साई को लिखा "आपने अपने पत्र में अपनी तरफ से ही यह बात मान ली है कि भारत पर चीनी आक्रमण द्वारा निर्धारित की हुई 'वास्तविक अधिकार रेखा को स्वीकार करके मुझ-विराम वास्तव की आप और यूँ भूमि पर इस अनधिकृत स्थिति को पकड़ा करने के बाद, सीमा समस्या पर दाना प्रधान मंत्रियों के बीच समझौते की बात हो। सत्रोप में आपका प्रस्ताव का यह मतलब हुआ कि चीन आक्रमणों द्वारा प्राप्त की हुई भारतीय भूमि को अपने अधिकार में रचना चाहता है और बाकी के बारे में समझौता करने को तैयार है यह एक ऐसी बात है जिससे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा बल्कि ही इसका नतीजा कुछ भी हो और हमें जितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े इसमें अपना कुछ भी करने का मतलब होगा एक आक्रमण, विस्तारवादी और दण्डपूर्ण पद्धति के रहम पर ज़िंदा रहना।"

उन्ने, श्री नेहरू ने चाउ का प्रस्ताव दिया "यदि चीन वास्तव में अपने हम शान्तिपूर्ण प्रस्ताव में विश्वास रखना है और मैत्रीपूर्ण ढंग से सीमा समस्या को हल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि पहले सारे सीमान्त पर अपनी सेनाओं को कम से कम उन स्थितियों तक हटा लें जहाँ वे २ अक्टूबर १९६२ से पहले थीं। उसका बाद ही भारत किसी भी आपसी तौर पर तब किये गये स्तर पर बात-चीत करने का तैयार होगा और सभी पारस्परिक रूप से ऐसे तरीके निर्दिष्ट किये जा सकेंगे जिनसे तनाव कम हो और एक तरफ़ा रूप से शक्तिपूर्वक परिवर्तन की हुई पूर्व स्थिति को फिर से ठीक किया जा सके।"

२६ अक्टूबर को श्री नेहरू ने विभिन्न राज्यों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनका चीनी प्रस्ताव मात्र एक छिपी हुई घमेली है जिससे द्वारा भारत को, सीमा के प्रश्न पर, चीन द्वारा निर्दिष्ट समझौते की स्वीकार करने के लिए विवश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री नेहरू के इस पत्र ने स्पष्ट किया कि चीन ने सन् १९५७ से तब तक लद्दाख में १२,००० वर्ग मील भारतीय भूमि पर कब्ज़ा कर लिया था, कि चीनी सेना ने २ सितम्बर, १९६२ को पहली बार पूर्वी सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया था और २० अक्टूबर का विज्ञान चीनी आक्रमण पिछले नई अति-क्रिया का चरम रूप था।

साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों के बीच इस अध्यान्तर को दोनों पक्ष, दूसरे दौर के लिए, अपने अपने सैन्य-साधनों को तेज़ी से परिवर्द्धित तथा संगठित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।

चीनी बड़ी तेजी से सीमान्त पर घुम जा से तोबांग तक एक १५ मील लम्बी सड़क बनाने में व्यस्त थे। चट्टानों को बारूद से उड़ाने की आवाज सीमा के इस पार स्थित भारतीय सैनिक सुन सकते थे। हमारे हवाई सर्वेक्षकों ने इस अधबनी सड़क पर रेंगते हुए कुछ घन्टे भी देखे जो उनके ग्याल से भारवाहक याक थे लेकिन वास्तव में वे सैनिक टुक थे।

भारत ने इस नकली युद्ध-विराम का प्रयोग किया तो ला को एक अभेद्य दुर्ग का रूप देने में। हमारा इरादा था कि इस अपराजेय स्थिति में जमकर हम चीनियों के दांत खट्टे कर देंगे और दक्षिण के इस प्रवेश द्वार की सफलता-पूर्वक रक्षा करेंगे।

अनुमान है कि युद्ध के पहले दौर में भारतीय पक्ष के २०००-२५०० सैनिक या तो युद्ध में काम आये या शायद ही गये। २० अक्टूबर के बाद से चीनी १३ विन्दु घाने बढ़ गये थे और वे सहाय्य के दो सेक्टरों में उस भूमि पर पहुँच गये थे जिस पर उन्होंने स्वयं भी कभी दावा नहीं किया था। उस काल में चीनियों ने सहाय्य में ३००० वर्ग मील भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त, धीरे-धीरे १९५७ से तब तक, वे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण १२००० वर्ग मील पर्वतीय भूमि पर भी कब्जा कर चुके थे।

उस समय सारे देश की और विशेषतः सेना की मनोवृत्ति उन आलोचनाओं में स्पष्टतः प्रगट हुई जो सैनिक अधिकारियों ने नेफ्रा युद्ध की दुर्घट घटनाओं के बारे में पत्रकारों से की। यू०पी० आइ० के अमेरिकी सम्वाददाता से एक सैनिक अधिकारी ने कटुतापूर्वक यह शिकायत की : “भारतीय सेना पर यह जिम्मेदारी डाली गयी थी कि वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी स्थिति की नहीं बल्कि एक राजनैतिक आन की रक्षा करे। जिन सैनिकों का संहार नमका नदी के किनारे हुआ वे एक ऐसी जीर्ण प्रतिरक्षा रेखा में छितरे हुए थे जिसे न तो युद्ध सामग्री पहुँचायी जा सकती थी और न जिसे सुरक्षित रखना सम्भव था।”

२७ अक्टूबर को ऐबी रोजेनथाल ने अमेरिका के न्यूयार्क टाइम्स को यह कैवल भेजा : “पिछले कुछ दिनों में नयी दिल्ली ने यह कटु सत्य समझा है कि चीनी आक्रमणों के रेलों का सामना करने के लिए जिन भारतीय सैनिकों को भेजा गया था उनके पास इतने भी आधुनिक अस्त्र नहीं थे कि उन्हें शत्रु का सामना करने का जरा भी अवसर मिलता। सेना में तय्य आम जनता में सैनिक योजनाएँ बनाने वालों, विशेषतः मेहन के खिलाफ क्रोध बढ़ता ही जा रहा है।”

जनमत के द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की माँग के बढ़ते हुए दबाव के कारण, कृष्णमेहन ने ३० अक्टूबर को त्याग-पत्र दे दिया। उसके बाद एक सप्ताह तक श्री मेहन केवल प्रतिरक्षा उत्पादन के मंथी रहे। सैनिक

साधनों का उत्पादन करने वाली पंचक्रिया का संगठन, शोध तथा विकास ही श्री मेहन की जिम्मेदारियाँ रह गयी थीं। लेकिन नेडबुर में एक घाम रामा में चीनने हुए थीं। मेहन ने कहा कि उनके सविभाग में परिवर्तन होने का वास्तव में कोई महत्त्व नहीं था। मेहन के इस बयान से स्वयं कांग्रेस पार्टी और भी बुद्ध हो गयी और श्री मेहन को मंत्रिमंडल में पूरी तरह बाहर होना पड़ा। श्री रघुरमया, जो तब तक उभरती नहीं थे, प्रतिरक्षा उत्पादन के सभी निरुक्त हुए।

३० दिसंबर को प्रधान सेनापति जेम्स यावर ने एक विशेष सैनिक-आदेश में सेना को चेतावनी दी कि 'मध्य का घम भी गहरी हुआ है। अभी और भी भीषण युवा घाना आक्रमण हाने,' लेकिन उन्होंने यह भी विचार दिया कि, "इस बात के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाएगा कि आप लोग को हर ऐसी मुश्किल और कष्टमय जिसे आप पुनः आक्रमण कर करने की स्थिति में हो।"

और इस समय जब नैना पर विस्फोट से पहले का तनाव छाया हुआ था, तब तैला पर मयवी प्रति केन्द्रित हो गयी—भारतीय जनता की, पत्र-कारों की तथा शत्रु की जिसने घमने आक्रमण का अब वह मुख्य निशाना बन गया। ऊपर शत्रु १३,७५० फिट की ऊँचाई पर स्थित इस मार्ग के दर्रे पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, इधर हमने अपनी दृष्टि में इसे एक धमक दुग बना दिया था।

१५ नवम्बर को संगमन बीच विदेशी और भारतीय सम्वाददाता विमान द्वारा नयी दिल्ली से कैफ़ा से जाये गये और भारतीय सैनिक अधिकारियों ने बड़े गव से उन्हें तैला दुग का मुभाइना कराया। सैनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि हम बार भ्रमदेश उनके अनुरूप है और वे शत्रु का मुकाबिला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

तैला वास्तव में एक प्राकृतिक दुर्ग था—उस पर कभी सामने से आक्रमण करके कब्जा नहीं किया जा सकता था। यह बात चीनियों ने अच्छी तरह समझ ली थी।

तोला और तैला के बीच अत्यन्त दुर्गम भ्रमदेश है—दोनों स्थानों के बीच बस एक टेवी तिरछी, ५० मील लम्बी पतली सी सड़क थी। तोलांग घाटी से मृपरातल एकांक ६००० फिट उठ जाता है जिसके कारण तैला दर्रा १३,७५० फिट की ऊँचाई पर है और इसलिए किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ वह सामरिक दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है।

हमारे सैनिक अधिकारियों ने कहा कि शत्रु ने यदि तैला पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया तो उसका मुँह टूट जायेगा और यदि वह ज्यादा दिन उस इलाके में टिका तो घानेवाली सड़क में ठिठुर कर रह जायेगा।

त्सेला प्रदेश में हमारा एक डिब्रीज्जन स्थित था। दिरांग दज़ांग में हमारा डिब्रीज्जनल हेडक्वार्टर तथा ६५ वाँ ब्रिगेड था। अपने सामरिक अनुभव के लिए प्रशंसित ब्रिगेडियर होजियारा सिंह के नेतृत्व में ६२ वाँ ब्रिगेड त्सेला में स्थित था। ४८ वाँ ब्रिगेड ब्रिगेडियर गुरुवल्स सिंह के नेतृत्व में बोंमदी ला में स्थित था। त्सेला और बोंमदी ला के बीच ७० मील लम्बी एक सड़क थी।

त्सेला में तीन हफ्तों के लिए पर्याप्त रसद, तोपें, मोला बन्दूक आदि थे। अत्यन्त गुप्त रूप से हमने चार हल्के टैंक भी त्सेला में पहुँचा दिये थे—चारह वर्ष पहले कश्मीर युद्ध में खोजी जा में भी यह करिश्मा दिखाया गया था। उसके अगले दिन सुबह ही पेंकिंग रेडियो ने खबर दी कि भारतीय टैंक त्सेला में पहुँच गये हैं। संयोग की बात यह है कि उस भूप्रदेश और ऊँचाई पर टैंकों से कोई खास काम नहीं लिया जा सकता था और अन्त में वे बड़ी आसानी से दुश्मन के हाथ लग गये थे।

आक्रमण के दूसरे दौर के लिए चीनियों ने तोबांग-बुमसा के क्षेत्र में अपने दो डिब्रीज्जन केंद्रित कर दिये थे—वे तोबांग और बुमसा के बीच की सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने का इन्तज़ार कर रहे थे। तोबांग से आगे वे त्सेला बोंमदीला-तेज़पुर को मिलाने वाली नयी बनी भारतीय सड़क का प्रयोग कर सकते थे।

द्विती कृत्रिम शांतिपूर्ण मध्यांतर में, ८ नवम्बर को राष्ट्रपति राधाकृष्णन स्वयं नेफ़ा के दक्षिण क्षेत्र में गये और जवानों का साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे बातचीत की। सारा राष्ट्र संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश लागू कर दिया गया। मंत्रिमंडल में एक आपाती उपसमिति बना दी गयी। टी.टी. कृष्णमाचारी, जो उस समय तक संविनायक मंत्री थे, अर्थ और प्रतिरक्षा समन्वय के मंत्री बना दिये गये। एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा काउन्सिल की भी स्थापना हुई जिसमें देश के हर पक्ष के नेता शामिल थे।

भारत सरकार ने बड़ी सरलता से अमरीका और इंग्लैंड से शस्त्र सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत शुरू की। २६ अक्टूबर को नवी दिल्ली ने लन्दन तथा वाशिंगटन से तुरन्त यह अपील की कि चीनी संकट का मुकाबला करने के लिए उन्हें फ़ौरन अस्त्र दिये जायें। वास्तव में अमरीकी पक्षों का पहला परेपण ३ नवम्बर को भारत पहुँच गया यद्यपि औपचारिक रूप से शस्त्र सम्बन्धी समझौते पर १४ नवम्बर को हस्ताक्षर हुए थे।

## दुर्दशा की चरम सीमा

चीनी आक्रमण का दूसरा दौर १४ नवम्बर को शुरू हुआ। नैत्रा में ताँहिउ तथा कामेग सेक्टरों पर चीनिया ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरे नैत्रा मोर्चे पर चीनियों ने अब पूरे तीन दिवोंजन लगा दिये।

महाग म चार दिन बाद चीनी आक्रमण शुरू हुए। १८ नवम्बर को चीनिया न, मध्य सेक्टर म रजाग मा गुरु ग पर्वत, स्पाम्पुर गैप और चुगुन हवाई अड्डों के पास के क्षेत्र पर एक साथ मोला-बाहद की बीछार कर दी।

इसी बीच, हुआ मेनन मन्नीमडल से बाहर हो गये थे। ४पी कोर के स्थानान्तरण कमान्डर लफिजेंट जनरल हरवल्हासिह से कोर का नेतृत्व फिर जनरल कौन ने से लिया था। मेजर जनरल निरजनप्रसाद के बचाव मेजर जनरल पन्निपा अब कामेग सेक्टर के द्वितीयजन कमान्डर नियुक्त हो गये थे।

अगले ४८ घंटों म चीनियों ने महान ये अपनी दावे की रेखा तक सारे प्रदेश पर कब्जा कर लिया—इस प्रदेश में रजागना पर्वत, रजाग स्पर, भार पर्वत, गुरु ग पवन तथा बिन्दु १८३०० शामिल थे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन स्थानों पर बहुत ही छोटी छोटी चीनियाँ थी जिनमें से हर एक म केवल ३०-४० सैनिक ही थे।

रजागना म भारतीय दस्ते ने जबरदस्त पराक्रम का परिचय दिया। इती मुकाबिले म मेजर सैत्रासिह वीर गति को प्राप्त हुए थे। वास्तव में, मन् १९६२ के भारत चीन संधर्ष की सज्जाजनक गाथा में रजागना का युद्ध पराक्रम का एक ज्वनन और गौरवमय अध्याय है।

भारतीय सैनिकों के गौरव का दूसरा उदाहरण का चुचुल में स्थित भारतीय गैरिसन द्वारा चीनी आक्रमणों की कई बाढ़ों का मुकाबिला करना हानाकि

चुसल हवाई अड्डे पर चीनी निरन्तर बम वर्षा कर रहे थे। २१ नवम्बर की रात को युद्ध समाप्त होने तक भारतीय गैरिसन सफलतापूर्वक शत्रु का मुकाबिला करता रहा।

दो आक्रामक दोरों में चीनियों ने २००० वर्गमील और भारतीय भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और उत्तर में दक्षिण तक, निपचाप घाटी, गल्दाम घाटी, चेंग चेनमो घाटी, पांगॉंग भील प्रदेश और दमचॉक क्षेत्र में स्थित ४० भारतीय चौकियों को कब्जे में कर लिया था।

नैफा में चीनियों की आक्रमण नीति थी विशाल त्रिभुजीय सैनिक चाल से त्सेला को दिरांग जॉंग (डिबीजनल हेडक्वार्टर) तथा बोमदीला से और बोमदीला को फ़ुट हिल से काट देना। यह त्रिभुजीय घेरेदार चाल १५ नवम्बर की रात को शुरू हुई।

इस नीति के अन्तर्गत १७ नवम्बर की सुबह चीनियों ने पहला आक्रमण त्सेला दर्रे के उत्तर में स्थित नीरानान की अग्रिम स्थिति पर किया। वहाँ के गढ़वाली सैनिकों ने अपने शौर्य से शत्रु के पाँच हमलों का मुकाबिला किया। उसके बाद चीनियों ने त्सेला के पूर्व में एक दूसरी भारतीय स्थिति पर आक्रमण किया और उसकी रक्षा करने वाले सिविल सैनिकों का वध करके वे आगे बढ़ गये।

इसी बीच तीन चीनी दस्ते अपने-अपने तीन निश्चित गन्तव्यों की ओर बढ़ रहे थे। एक दस्ता, हिमपात की आड़ में, याक मार्ग से पालित पर्वतमाला के पार आगे बढ़ रहा था। त्सेला के गैरिसन पर पीछे से अचानक छापा मारने तथा उन्हें बोमदीला से पृथक् करने के लिए।

दूसरा चीनी दस्ता पूर्व से आकर त्सेला से आगे बढ़ गया और बोमदीला के कुछ मील उत्तर में तथा चौथे पैदली डिबीजन के हेडक्वार्टर दिरांग जॉंग से आठ मील दक्षिण में उसने भारतीय सड़क पर अधिकार करके अवरोध पैदा कर दिया। इस प्रकार त्सेला की रक्षा के लिए उत्तर में जमे हुए भारतीय सैनिक भ्रमण कट गये और बोमदीला पृथक् हो गया।

तीसरा दस्ता और दक्षिण में चला गया तथा चाकू पट्टेचकर बोमदीला और फ़ुटहिल के बीच के मार्ग पर जम गया।

१७ नवम्बर की शाम को जनरल पठानिया बड़ी नैवीनी से टेलीफ़ोन द्वारा कोर हेड क्वार्टर से सम्पर्क स्थापित करने और जनरल से मशवरा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जनरल कोल उस समय थारोम में थे। संयोग से उस समय प्रधान सेनापति जनरल आपर और पूर्वी कमान्ड के सेनापति जनरल सेन कोर हेड क्वार्टर में ही थे।

जनरल पठानिया ने बताया कि त्सेला की स्थिति भोचनीय है और इस बारे में आदेश माँगे कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी अपनी राय यह

थी कि तेली को छोड़ कर पीछे हट जाया जाये और हमने लिए के आदेश चाहते थे ।

लेकिन बापर और मेन उन्हें हम धारे में किसी प्रकार का आदेश देने का संसार मिला था । उन्होंने जनरल पटानिया से कहा कि जनरल बीन के सीटने पर फिर टेनीकोन करें और कोर बमाल्डर से ही हम धारे में आदेश लें ।

गाम का ७४३ पर पटानिया ने फिर फोन किया—उम समय तक जनरल बीन मोट चुके थे । पटानिया ने आग्रहपूर्वक इस शान की आज्ञा जारी की कि ६२ के विरोध को तेली में विरामदायक हटा दिया जाये क्योंकि उन्हें डर था कि उम रात तक ही तेली का संग से सम्पर्क बट जायेगा ।

पटानिया के अनुसार बीन ने उन्हें यह समझा दी कि वे जैसा टीक समय करें और कहा कि यदि वह (पटानिया) यह मानता है कि तेली की रक्षा नहीं कर सकते तो वह वहाँ से हटने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

लेकिन जनरल बीन के अनुसार उन्होंने बड़ी मुश्किल में और अपनी मर्जी के विरुद्ध पटानिया की बात मानी थी । बीन का कथन है कि उन्होंने पटानिया को आग्रहपूर्वक यह समझाया था कि रेलगाड़ी में डटे रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है और पटानिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि यदि रात्रि तेली को पीछे से काट देने में सफल हुआ तो भी तेली के रीरिसन के पास कम से कम एक हफ्ते के लिए पर्याप्त हथियार, गोली बारूद और रसद आदि हैं । बीन यह चाहते थे कि तेली में स्थित ६२ का विरोध अपने स्थान पर डट कर अन्य तक पुढ करे ।

इस फोन वार्ता के बाद, बीन ने उसी दिन रात को पटानिया को यह लिखित आदेश भेजे \*

“(१) आप अपनी वर्तमान स्थिति पर डटे रहने की भरसक कोशिश करेंगे,

(२) जब किसी भी स्थिति पर डटे रहना असम्भव और अनुचित हो तो मैं आपको यह अधिकार देता हूँ कि ऐसी स्थिति पर हट कर चले जायें जहाँ आप टिक सकें,

(३) लगभग ४०० रात्रि सैनिकों ने बोमदीला से विरामदायक की सहायता की है,

(४) मैंने बोमदीला के ४०० विरोध के बमाल्डर को आदेश दिया है कि आज ही रात को तेली से रात्रि पर आक्रमण कर दें और किसी भी हालत में इस सहायक को साफ रखें,

\*सेमिरेड जनरल बी० एम० बीन “अनकही कहानी”



(५) हो सकता है कि शत्रु आपको सेंग से काट दे ;

(६) १८ तारीख की सुबह दो अतिरिक्त बटालियन बोमदीला पहुँच जायेंगे ;

(७) अपने संचार सूत्रों को अवरोधहीन रखने के लिए टैको तथा अन्य सहायक यन्त्रों का प्रयोग कीजिए ।”

पठानिया कौल के आभारी थे कि इन आदेशों के द्वारा उन्हें बचा दिया गया था कि त्सेला से हटने के बाद उनकी चाल क्या हो, विशेषतः इसलिए कि त्सेला से हटने का निर्णय कौल ने उन पर ही छोड़ दिया था । स्पष्ट था कि पठानिया ने अपना मनचाहा निश्चय ले लिया और ६२वें ब्रिगेड को फौरन त्सेला से हटा लिया ।

उस शाम जब ६२वाँ ब्रिगेड त्सेला को छोड़कर दिरांगजॉंग की तरफ बढ़ रहा था तो उन्हें राह में सड़क के पार चीनी सैनिक मिले जिन्होंने उन पर मार्टर फेंके और मशीनगन से फायर किये । काफ़ी सोंपों की क्षति हुई । शाम के बढ़ते अन्धकार में भारतीय दस्ते में भगदड़ मच गयी और घस्त्रों, गोला-बारूद तथा बायरलेस सेटों को छोड़कर वे जंगलों में छिप कर भाग निकले ।

जनरल कौल के अनुसार त्सेला को शत्रु से टक्कर लिये बरीर छोड़ दिया गया और इसका सारा क़सूर उन्होंने जनरल पठानिया पर डाला ।

त्सेला में भारतीयों का एक पूरा ब्रिगेड स्थित था, उसके पास पर्याप्त रसद तथा हथियार थे और इसके अलावा चार हल्के टैंक भी थे । यदि उनमें लड़ने का ज़रा भी हौसला या इच्छा होती तो वे दो नहीं तो कम से कम एक दिन डट कर शत्रु से टक्कर ले सकते थे ।

मुझ से एक बातचीत में स्वयं पठानिया ने यह बताया कि इस बार शत्रु की सैनिक संख्या हम से अधिक नहीं थी—दोनों बराबर थे क्योंकि दोनों पक्षों के पास एक-एक टिबीजन था । लेकिन पठानिया ने खेदपूर्वक कहा : “लेकिन किसी रहस्यपूर्ण कारण से जवानों में लड़ने का साहस और उत्साह था ही नहीं ।” पठानिया ने यह भी बताया कि उन्होंने दो और ब्रिगेडों की माँग की थी लेकिन सिर्फ़ एक और ब्रिगेड की स्वीकृति मिली और उसके आने से पहले ही चीनियों ने घेरा डालना शुरू कर दिया था । चीनी त्सेला में एक अतिरिक्त ब्रिगेड के साथ पहुँचे थे । हमारा भी एक ब्रिगेड त्सेला में, एक बोमदीला में और एक कमज़ोर ब्रिगेड दिरांगजॉंग के डिबीजनल हेडक्वार्टर में था ।

नीरानाग पर आक्रमण शुरू करते समय चीनी लाभाओं के वेप में आये—वे लम्बे लाल चोरो, ऊँचे तिब्बती बूट और फ़र की टोपियाँ पहने थे ताकि वे दौड़ भौतपा जाति के लोग लगें । गढ़वाल राजकुल के सुवेदार प्रतापसिंह ने

बाद में बताया 'व चीनी ने मामूम मदरगा की तरह, १०० का दल बांध कर मोरानांग की तरफ बढ़ रहे थे।'

'लेकिन ज़ब्त के ४०-५० यज्ञ के फासने पर रद्द गये तो उन्होंने अपने घोणा के नीचे से अस्त्र निकाल लिए और फायर करना शुरू कर दिया।

इसके बाद चीनी आक्रमणकारियों की और भी बाड़ें छापीं। जैसे-जैसे वे दल बांधकर घातें थे वैसे-वैसे भारतीय सैनिक उन्हें गोलीबारी से उड़ा देते थे। सूबेदार का दस्ता फँसा हुआ था और वे कम-प्रूफ माइनों में स्थित थे। दोपहर में एक बजे तक चीनियों ने चार बार आक्रमण किया। हर आक्रमण पिछले से ज्यादा बड़ा था। चौथे आक्रमण में ब्रैन-मन लिये हुए एक चीनी सैनिक भारतीय गोली का शिकार हुआ। उस ब्रैन-मन को वापस पाने के लिए चीनी सैनिक टिड्डियों की तरह दूट पड़े। भारतीय सैनिक बराबर फायर करते रहे लेकिन मॉर्टर बिम्पोटों के बावजूद चीनियों ने उस ब्रैन-मन को प्राप्त कर लिया। आक्रमण के बाद घाटी में चीनी राबों के ढेर लग गये थे।

अनुमान यह है कि चौथे आक्रमण के बाद चीनी मृतकों की संख्या ३०० थी। इसके बाद कुछ समय शांति रही जिसका उपयोग, सम्मेलन, चीनियों ने अपने पुनर्निर्माण तथा अतिरिक्त शक्ति एकट्ठी करने के लिए किया।

पाँचवें आक्रमण में चीनीजी ने भारी गोलबारी की। कम घोलों की तरह गिर रहे थे और जमीन में चार फिट तक बहरे गहरे बन गये थे। पाँचवें आक्रमण में हल्की मशीन-गन से सँस एक चीनी दस्ता भारतीय सैनिकों के रसोईघराने पर चढ़ा म घुस गया। भारतीय मॉर्टरों ने रसोई विभाग पर बमों की वर्षा कर दी और एक चीनी सैनिक काम आया। जो दो-तीन चीनी सैनिक बचे थे वे सामने-सामने के दुष्ट में मारे गये।

दोपहर में ३:३० को सूबेदार की आदेश मिला कि वह अपने को हटाकर स्लेता की मुख्य प्रतिरक्षा स्थिति को से जावे—अपने दिन मुबह तक सूबेदार ने आदेश का पालन कर दिया।

सूबेदार प्रतापसिंह ने बताया कि वह चीनी दबाव के कारण नहीं हटे थे बल्कि इसलिए कि उन्हें हटने का आदेश मिला था इस कारण कि वह स्लेता से बच न पायें। सूबेदार प्रतापसिंह का यह पटला सामरिक अनुभव था।

पी० टी० आई० की उपरोक्त डिसपैच यहाँ पूरी तरह इसलिए दी गयी है कि सन् १९६२ में नेफ़ा युद्ध के बारे में दो तथ्य स्पष्ट हो जायें : पहला यह कि जब भी भारतीय सेना ने डटकर प्रत्याघात किया तो उन्होंने अपने जवरदस्त शौर्य का परिचय दिया और साबित कर दिया कि चीनी अजेय महामानव नहीं हैं ; दूसरे, इस कहानी से यह साबित होता है कि मानव जीवन का चीनियों के लिए कोई मोल नहीं है—साथ ही चीनियों के 'मानवी ज्वार' समर-तन्त्र का भी पूरा ज्ञान प्राप्त होता है।

एक बात और इस डिसपैच से स्पष्ट होती है और वह यह है कि यदि कमान्डर श्रेणी के भारतीय अफ़सरों के हाथ-पांव नहीं फूल जाते तो नीचे की श्रेणी के अफ़सर तथा जवान डट कर चीनियों से लड़ने के लिए तैयार थे। वास्तव में भारतीय सेना के इस अंग ने तनिक भी अवसर मिलने पर अपने साहस और शौर्य का अत्यन्त गौरवमय परिचय दिया और हो सकता था कि यदि चीजें उनके हाथ में होती तो वह अपने देश को पराजय और अपमान से बचा लेते।

अपमान इस बात में नहीं था कि भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा—अपमान और अभियान का क्रम तो युद्ध में चलता ही रहता है—अपमानजनक बात यह थी कि भारतीय सेना का अपमान एक घम्यस्थित भयदह बन गया था और हमारे सैनिक बिना लड़े भाग खड़े हुए थे। सारे राष्ट्र का सिर इस पर अपमानवश झुक गया था।

मैं कई ऐसे युवक अफ़सरों से मिला हूँ जो १९६२ के त्सेला-चोमदीला युद्ध में थे और उन सबने आग्रहपूर्वक यही बताया कि उन्हें पीछे हटने के आदेश ठीक उस समय मिले थे जब वे शत्रु के साथ युद्ध करने में सुये हुए थे, जानें ले रहे थे और दे रहे थे, दुश्मन को पीछे धकेलने में रत थे और जब पीछे हटने का विचारमात्र भी उनके मन में नहीं था।

इलाहाबाद के 'सीटर' के एक विशेष सम्वाददाता के अनुसार ( जो नेफ़ा में भारतीय पतन के ठीक बाद ही यहाँ गये थे) इनमें से कई अफ़सरों का यह कहना था कि आवश्यकता पड़ने से पहले ही उन्हें अपनी-अपनी स्थितियों से हटने के आदेश दिए गए थे। इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं कि हटने के आदेश मिलने के बाद भी कम्पनी कमान्डरों ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया तथा शत्रु पर जवाबी हमले किये जिनमें शत्रु के काफी सैनिक काम आये।

इसी सम्वाददाता ने लिखा है कि इसके बावजूद कि चीनी सैनिक बहुत बड़ी संख्या में सारे प्रदेश पर फैले पड़े थे, भारतीय जवान सामरिक रूप से सुरक्षित ट्रिन्चों में स्थित थे और यदि उन्हें लड़ने का मौका दिया जाता तो वे अपनी स्थितियों पर डटे रह सकते थे।

लेकिन हुआ यह कि डिवीजनल कमण्डर से लेकर ऊपर के सभी अधिकारियों के सम्मानित हाथ-पाँव फूट गये और उनके मन में केवल एक ही स्वास रह गया कि जल्दी से जल्दी युद्ध स्थल से भाग गया हुआ जाये। इस प्रकार की कार्रवाई सत्रामस होनी है और इन कारण नीचे की सैनिक व्यंगियाँ इससे प्रभावित होने से नहीं बचीं। मनीषा यह हुआ कि अधिकारियों ने दुश्मन का सामना करने से इंकार कर दिया, उनके दमने तितर-बितर हो गये और गन्धु के लिए डेर के डेर रमद, प्रमद घाटि पीछे छोड़कर, वे जंगलों में भाग निकले।

१८ नवम्बर को जब स्लेसा और बोमदीला के बीच की भारतीय सड़क पर चीनी धक्के को तोड़ने का प्रयत्न किया गया तो दोनों तरफ़ में छ हल्के टैंक इन काम के लिए लगा दिये गये लेकिन इनकी सहायता के लिए पैदल सेना थी ही नहीं। और यह एक आम सामरिक मिथ्या है कि पैदली सहायता के बिना टैंक पूरा निर्भरक होते हैं। इन के सामान्य से घन्धु के निवार हो गये।

क्योंकि उस प्रदेश की सारी भारतीय सेना की यह जिम्मेदारी थी कि स्लेसा पर गन्धु के आक्रमण का मुकाबला करें इसलिए उह चीनियों के बाजू से छापा मारने वाले सैनिक गुलाब (स्लिपर-हैंड) पर आक्रमण करने के लिए फिर से संगठित नहीं किया जा सकता था। इस गुलाब ने बोमदीला और स्लेसा के बीच के भागों के समस्त मार्ग को काट दिया जिसके कारण भारतीय सेना का दम टूट गया और वह स्लेसा तथा विरागबाग से अत्यन्त अभ्यवस्थित रूप से जंगली घाटियों में भाग निकली।

बाकू पर एक चीनी दस्ते ने छिपकर बोमदीला से दक्षिण की तरफ़ प्रयाण करने हुए भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया जिसके कारण भारतीय दस्ते में भगदड़ मच गयी। रमद तथा अस्ती से लड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सार्थ (कॉन्सर्वे) सड़क पर ही छोड़कर उसके द्वाइवर जंगलों में भाग निकले।

इस प्रकार १८ नवम्बर को स्लेसा का 'अभेद्य दुर्ग' बाल पर पक कर सड़ हुआ चीन की तरह दुश्मन के हाथ में आ गया। अगले दिन चीनियों ने बोमदीला पर कब्जा कर लिया।

युद्ध विराम और भारतीय प्रयाण के बाद जो सामान पीछे छोड़ा गया वह अन्दाज लगाया जाना है, २२,००० चीनी सैनिकों के लिए लगभग दो हफ्ते के लिए काफी था। बुने हुए कनी बस्त्रों की गठि जो विमानों द्वारा गिराई गई थी तथा अनाजों की बाँटी जाने वाली थी, वे भी दुश्मन के हाथ लगी।

नवम्बर, १८ को नेफ़ा में सैनिक संघर्ष के जिस दौर का अन्त हुआ उसमें भारतीय पक्ष की कमजोरी यह नहीं थी कि उसके पास सैनिकों या साधनों का

अभाव था बल्कि यह कि सेना संगठन अव्यवस्थित था और समन्वित रूप से काम नहीं किया गया था।

इसी बीच, लोहित सेक्टर में बालोंग में, भीषण युद्ध चल रहा था। यहाँ पर स्थित ११वाँ ब्रिगेड एक पूरे चीनी डिवीजन की आक्रमणशील वाढ़ को रोकने का प्रयत्न कर रहा था।

२रे पैदली डिवीजन का ५वाँ ब्रिगेड नेफ्रा सोर्च के मध्य सेक्टर पर सतर्क रूप से निगरानी रख रहा था—उस क्षेत्र में बहुत कम युद्ध हुए थे। २रे पैदली डिवीजन के कमाण्डर एक और पठानिया—मेजर जनरल एम० एस० पठानिया थे।

ब्रिगेडियर 'नवीन' रॉली के नेतृत्व में ११वाँ ब्रिगेड दो दिन तक बिना रुके चल कर बालोंग में अपनी स्थितियों तक पहुँचा था। भारतीय सेना में यहाँ सबसे अधिक पराक्रम से शत्रु का मुकाबिला किया। उन्होंने एक के बाद एक १५ बार आक्रमणकारियों को पीछे धकेला जिसके फलस्वरूप ५,००० चीनी मारे गये और दक्षिण की तरफ शत्रु की प्रगति को सीमा होना पड़ा।

लेकिन चीनियों की सैनिक संख्या कहीं ज्यादा थी और इसलिए १७ नवम्बर को बहादुर ११वें ब्रिगेड को मजबूरन बालोंग से हटना पड़ा। ब्रिगेडियर रॉली तथा उनके सैनिकों ने जंगल में शरण ली।

हालांकि बालोंग में स्थित भारतीय ब्रिगेड पर यह एक असम्भव और सामरिक दृष्टि से अनुचित जिम्मेदारी खाली गयी थी कि एक कमजोर स्थिति की रक्षा करें फिर भी उसने अपने शौर्य का जोरदार परिचय दिया, जानें दीं और लीं तथा मजबूर होने पर व्यवस्थित रूप से प्रयास किया।

नेफ्रा में चीन के तद्वि-गति युद्ध से भारत में ज्वरदस्त चलधली मच गई। २१ नवम्बर तक चीनी बमदीला तथा फुटहिलो के बीच अन्तिम भारतीय प्रतिरक्षा रेखा को तोड़ कर आसाम के मैदानों के छोर तक पहुँच गये। वे अब ब्रह्मपुत्र तथा तेजपुर से ४० मील और डिब्रुगढ़ के तेल क्षेत्रों से ८५ मील दूर थे।

तबो दिल्ली में यह आतंक फैल गया कि चीनी पूरे आसाम पर कब्जा कर सकते हैं। प्रधान सेनापति जनरल थापर ने त्याग-पत्र दे दिया और उनकी जगह दक्षिणी कमाण्ड के सेनापति जनरल जे० एन० चौचरी ने ली जो कुछ ही समय में अवकाश ग्रहण करने वाले थे। लेफ्टिनेंट जनरल कोल के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल मानिकर्षों ४थी कोर के कमाण्डर नियुक्त हुए। ४था पैदली डिवीजन नेफ्रा के जंगलों में तितर-बितर हो गया था; २रा पैदली डिवीजन चुरी तरह माहृत हो चुका था।

१६ सितम्बर को भारत सरकार ने त्वरित रूप से अमरीका से लड़ाकू हवाई सहायता की माँग की। इसके पहले कि बार्सिंगटन का कोई उत्तर आये,

चीन ने अपनी तरफ से युद्ध-विराम की घोषणा कर दी। एक घण्टी पचासक के अनुसार ची नेहरू ने इंग्लैंड और अमरीका से १५ बॉम्बर विमान स्वच्छन्दता की भाँति की ची ताकि नेफ्रा में आगे बढ़ती हुई चीनी सेना को रोक जा सके।

पाँच दिन में चीनी सेना लेंवा तथा योमदीना से होती हुई वामेन द्वीपसमूह में अपनी दावा-रेखा तक पहुँचने के लिए १६० मील आगे बढ़ गई थी और फूटहिलो से केवल ४ मील दूर थी। साथ ही चीनियों ने एक प्रसम्भवात्मक कर दिखाया था और वह था केवल १८ दिनों में बुमना से लोवा तक प्रसन्न दुयम पहारी प्रदेश में तथा वहीं-वहीं पर १७००० फिट की ऊँचाई छूने वाली एक १५ मील लम्बी सड़क का निर्माण तथा १२० मीलमीटर के ५ मीटर और गोला-बारूद उतार देने के में पहुँचाना।

साथ ही लोहिन सेक्टर में नेफ्रा के पूर्वी छोर पर अपनी दावा-रेखा तक पहुँचने के लिए ४ लोहिन घाटी में बालाग से ८० मील आगे हायुतियाग तक पहुँच गये थे।

नेफ्रा में चीनी दावा-रेखा भूटान के दक्षिण-पूर्वी छोर से पूर्व की ओर बढ़ती है हिमालय के दक्षिण भ्रमण से लगी हुई और लोहिन नदी के प्रसन्न भाग तक, जहाँ भारत, तिब्बत और बर्मा मिलते हैं, पहुँचती है।

पकिंग से भेजी गई चीनी समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में लगभग १२,००० चीनी सैनिक काम आये। हजारों चीनी सैनिक, पर्याप्त बर्तन वस्त्रों की कमी के कारण, बर्फ में ठिठुर कर मर गये।

सप्तर में प्रगट किये गये सरकारी अनुमान के अनुसार २० अक्टूबर के बाद हमारी सैनिक क्षति ६,७६५ थी जिसमें २२४ मृत तथा ४६८ घायल सैनिक शामिल थे। 'बायब हू' और 'बन्दी बनाये गये' सैनिकों की संख्या इस प्रकार लगभग ६,००० थी। १६ नवम्बर को चीनियों ने दावा किया था कि एक त्रिगेटिवर तथा १६ अन्य अस्त्रों को मिलाकर उन्होंने ६७७ भारतीय कैद किये थे।

इन्ने कम समय में भारत की इतनी जबरदस्त क्षति करके तथा अपमानित करके चीनियों ने इस बात के लिए समझ नहीं दिया कि भारत अपने सौ सम्मान कर प्रस्थापित करे। २०-२१ नवम्बर की रात को चीन ने एक-पक्षी युद्ध-विराम की घोषणा कर दी।

घोषणा में कहा गया कि २० नवम्बर को ००.०० घंटे से चीनी 'सीमा-रक्षक' युद्ध रोक देंगे। १ दिसम्बर १९६२ से चीनी 'सीमा-रक्षक' ७ नवम्बर १९६६ की "वास्तविक सीमा-रेखा" के २० किलोमीटर पीछे तक हटना शुरू कर देंगे।

माया की एक उक्ति है 'यदि विजय निश्चित हो तो आक्रमण करो—उसके बाद मुलह कर लो। शत्रु के आक्रमण को एक बार रोक कर तथा उसके

दूसरे आक्रमण से पहले हमें उचित समय पर रुक जाना चाहिए और उस विशेष युद्ध को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। यही है हर संघर्ष का अस्थायी स्वभाव।”

और इसलिए पूर्ण सफलता प्राप्त करने के बाद (और इसके पहले कि इस सफलता के लंडित होने की सम्भावना पैदा हो) चीन ने युद्ध-विराम की घोषणा कर दी।

लन्दन ‘टाइम्स’ के प्रतिरक्षा सम्पादकता के अनुसार चीन ने भारत तथा सारे संसार को यह सिद्ध कर दिया कि वे जब और जैसे चाहें सीमा को इच्छा-नुसार परिवर्तित कर सकते हैं और शक्तिपूर्ण स्थिति से सम्झौते की बात निर्देशित कर सकते हैं।”

इस संक्षिप्त और तक्षित युद्ध में—जिसमें वास्तविक सड़ाई बस दिन से अधिक नहीं हुई थी—चीनी नेफा में मैक्महॉन रेखा के २०० मील दक्षिण, आसाम के छोर तक पहुँच गये थे जहाँ कामेंग डिवीजन में उनकी दावा-रेखा थी।

नेफा के दूसरे सिरे पर, लोहित डिवीजन में, वे दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम की तरफ १०० मील नीचे तक बढ़ कर किबीटू से बालोंग और हापुलिपांग तक फैल गये थे। वे एक ऐसे स्थान तक भी पहुँच गये थे जो डिब्रुगढ़ तैल क्षेत्र से ५५ मील दूर था।

नेफा के मध्य सेक्टर के सुवनसिरि और सियांग डिवीजनो में चीनी, मैक्महॉन रेखा के कुछ ही स्थानों से केवल ३०-४० मील नीचे तक बढ़ पाये थे। बर्मा की सीमा पर स्थित नेफा का तिराक डिवीजन अछूता था क्योंकि चीन के साथ उसका सीमा सम्पर्क नहीं था।

सबसे गहरा चीनी अतिक्रमण कामेंग सेक्टर में हुआ था—यहाँ वे भूटान सीमा से लेकर थुमला से तोवांग तक के ३० मील लम्बे भोचें के किनारे-किनारे आगे बढ़े थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० बी० एम० गांगुली के अनुसार चीनी डॉ० सन यात सेन द्वारा बनाई गई रेलवे तन्त्र की रूप-रेखा ने दिखाये गये मार्ग से आगे बढ़े थे—इस रूपरेखा में चीनी रेलवे का अन्तिम स्थान तोवांग था।

चीनी तोवांग से, त्सेला और वोमदीला होते हुए फुटहिल की तरफ बढ़े थे जिसका अर्थ था कि भारतीय भूमि पर कब्जा करने से ज्यादा वे अपनी दावा-रेखा तक पहुँचना चाहते थे।

लद्दाख में चीनियों का उद्देश्य यह मालूम पड़ता था कि वहाँ जिस १४००० वर्ग मील भारतीय भूमि पर वे दावा करते थे उस पर कब्जा करके अपना अधिकार सुदृढ़ कर लें।

## आखिर यह गडबड क्यों हुई ?

इस युद्ध में परिस्थितियाँ भारतीय पक्ष के विपरीत थीं। हमारी सेना मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए इतनी तैयार नहीं थी और युद्ध छिड़ने पर ऊँपड़ी हुई पायी गई थी। हमारे अलावा, शत्रु के मुकाबिले, मैनिक्सों की संख्या कम थी, हथियार कम थे और जनरलों में युद्ध-कौशल की कमी थी।

विशेषतः कामेग सेक्टर में तो हर चीज गड़बड़ थी। वहाँ की शत्रु के साथ विभिन्न मुठभेड़ों में, सुनियोजित सामरिक नीति तथा युद्ध-कौशल का प्रमाण बहुत कम मिलता है। कमांडर रह-रह कर बदले गए थे। अग्रिम दस्तों की इस बात की शिकायत थी कि नयी दिल्ली हर बात में टाँग मचाता है, यहाँ तक कि इस बात में भी दखन दिया जाता था कि सैनिकों को वहाँ और कैसे स्थित किया जाये। इस बात की भी शिकायत थी कि कोर हेडक्वार्टर से उन्हें उन्ट-सीधे आदेश मिलते थे।

डोना में चीनियों से युद्ध करने के लिए सेना की आदेश देना भी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी। यह आदेश उन्होंने सैनिक अधिकारियों की राय के विरुद्ध दिया था।

भारतीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाली चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए जो समय भारत सरकार ने चुना वह भी गलत था। भारत सरकार को यह जानना चाहिए था कि सैनिक दृष्टि में देश उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं है।

२० घनूबर को जब चीनियों ने जोरजोर से डोना पर आक्रमण किया तो उस स्थान के भारतीय रक्षकों के पास रसद थी, जूतों की, जूती कपड़ों की तथा हथियारों की कमी थी और भारी अस्त्र तो वे ही नहीं।



जनरल कौल के अनुसार मेफ्रा मोर्चे पर भारतीय सैनिकों के पास खुदाई के औजारों की कमी थी और उनके इस्त्र, गोला-बारूद तथा वायरलेस सेट दोषपूर्ण थे। इस बीहड़, मार्गहीन भूप्रदेश में, जहाँ घायलों तथा मृतकों को केवल हवाई साधनों से ही हटाया जा सकता था, हेलिकॉप्टरों की भी कमी थी।

कौल के ही अनुसार हमारी सेना अस्त्रों, साधनों तथा संहार की दृष्टि से पर्वतीय युद्ध के लिए विल्कुल योग्य नहीं थी।

सारे सागला-डोला प्रदेश में हमारा सिर्फ एक ब्रिगेड वितर-वितर फैला पड़ा था और उससे यह आशा की जाती थी कि वह गोला-बारूद तथा भारी मॉर्टारों से लेस एक पूरे चीनी डिवीजन का मुकाबिला करे।

और जैसे कोई कमी बची थी, जब चीनियों ने मेफ्रा मोर्चे पर आक्रमण शुरू किया तो भारतीय सेना ने अपने को नेताहीन पाया क्योंकि ठीक उसी समय उनके कोर कमान्डर जनरल कौल दूरस्थ नयी दिल्ली में बीमार पड़े थे।

यही नहीं, ब्रिगेड, डिवीजन तथा कोर कमान्डरों में आपस में पड़ती ही नहीं थी। निरंजन प्रसाद के वज्राय ए० एस० पठानिया ४थे पैदली डिवीजन के कमान्डर बन गये थे और जनरल कौल तथा उनकी ४थी कोर ने उमराव सिंह तथा उनकी ३३ वीं कोर का स्थान ले लिया था। नये कोर कमान्डर तथा सैनिक कमान्डर के बीच उतना ही वैमनस्य था जितना भारतीय तथा चीनी सेनाओं के बीच।

मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक दृष्टि से युद्ध के लिए हमारी अतत्परता इतनी स्पष्ट थी कि सेना के पास उक्त प्रदेश के मानचित्रों की भी कमी थी और इनमें से कुछ तो गलत भी थे। उदाहरणार्थ इन नक्शों में दिखाया गया था नमका नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है जबकि वास्तव में वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।

मनोवैज्ञानिक अतत्परता का एक उदाहरण यह भी था कि अधिकारी 'मेस' के बाँदी के वर्तन, कालीन, कमोड आदि भी सावकर कामेंग सेक्टर के डिवीजन हेडक्वार्टर तक पहुँचाये गये थे।

एक और उदाहरण है कि जब यह माँग की गयी कि चीनियों का मुकाबिला करने में सहायता देने के लिए एक शोरखा बटालियन तुरन्त डोला भेज दिया जाये तो पूर्वी कमान्ड ने इस माँग को तुरन्त अस्वीकार कर दिया क्योंकि ऐसा करने से उस दिन के दसहरे के उत्सव में बाधा पड़ती।

जबकि मेफ्रा मोर्चे पर चीनियों के चार डिवीजन थे, शुरू में हमारे एक डिवीजन से भी कम (२ ब्रिगेड और एक बटालियन) था उनका मुकाबिला करने के लिए। इस सङ्घटित युद्ध के बीच तक हम अपनी शक्ति बड़ी मुश्किल से दो कमजोर डिवीजनों की कर पाये थे। इनमें से भी एक डिवीजन (दो ब्रिगेड

और एक बटालियन) वालीड, सिपाय और सुबनगिर मेक्टरों के युद्ध में उतारा हुआ था।

२१ नवंबर को अचानक युद्ध-विराम होने के समय तक हम बहुत मुश्किल से तीसरा घंटा प्रती दिव्यज्ञान मोर्चे तक पहुँचाने में सफल हुए थे।

डा भीमल बठिनाइया में हवाई नावों का सामरिक प्रयोग न करना वास्तव में एक असम्यक्त भूत थी। सन् १९६२ के भारत-पाक युद्ध में छत्र मेक्टर में बठिनाई में फही हुई सेना को सहायता देने के लिए भारतीय वायु सेना का पूरी तरह प्रयोग करने से थी भारतीय बिल्कुल नहीं भिन्नते थे और उनके इस निश्चय के कारण पराजय विजय में बदल गयी थी।

बामेन मेक्टर में, विशेष रूप से, वायु सेना के सामरिक प्रयोग की स्पष्ट आवश्यकता थी लेकिन अज्ञानवश हम यह समझ बैठे थे कि वायु की वायु शक्ति अत्यन्त विनाश है और हम डरते थे कि यदि हमने अपनी सेना का वायु संरक्षण दिया तो वायु उसका प्रभुत्व बहुत बड़े पैमाने पर देगा। बाद में अपने गुप्त सूचना विभाग तथा अमरीकी रिपोर्टों से पता चला कि उस समय चीनियों की हवाई प्रभुत्व देने की शक्ति अत्यन्त ग्लून थी।

कमांडर जगता के भग हो जाने में अत्यन्त तथा असम्यक्त और भी बड़ गये थे। मसूर ऐसा भी हुआ कि कमांडर हेडक्वार्टरों की सम्मति लिए बगैर मैजिस्ट्रेट हेडक्वार्टर में स्वयं विरोधों तथा बटालियनों को संचालित किया।

उदाहरणार्थ, सितम्बर के आरम्भ में सैनिक हेडक्वार्टर ने दोला के बटालियन कमांडर, लेफ्टिनेंट बर्नन मिथा को सीधे यह आदेश दिया कि वह १६ सितम्बर तक धागला-यामला-कापीना के पूरे प्रदेश पर कब्जा कर लें। दिव्यज्ञान कमांडर मेक्टर जनरल निरजन प्रसाद ने इस आदेश के विनाश आपत्ति की कि 'उन्हीं पूर्ण बगैर यह आदेश दिया गया था।

इसके अलावा, ३३ वें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह और पूर्वी कमांड के सेनापति जनरल सेन के बीच सामरिक मामलों पर तीव्र मतभेद पैदा हो गया और उमराव सिंह ने निनायत की कि जनरल सेन अनुचित रूप से दखनवादी करते हैं। उमराव सिंह को नेत्रा मोर्चे से हटा दिया गया।

'चीनियों को बाहर निवाने के लिए जब नयी ५वीं कोर की स्थापना हुई तो उसके कमांडर, जनरल कौल ने प्रादेशिक कमांड की परवाह किए बगैर सीने नयी दिल्ली से सम्पर्क रखकर अपने चारों तरफ बिफरने हुए अमन्तोष को और भी तीव्र कर दिया।

दोला में जहाँ युद्ध की चिंगारी सबसे पहले पड़ी थी, हमारे सैनिकों के पास भारी हथियार थे ही नहीं। यह हथियार ऐन मोर्चे पर पैदल सैनिकों के

द्वारा तोबांग से डोला की तरफ खाना किये गये थे लेकिन उन्हें तोबांग वापस पहुँचाना पड़ा क्योंकि इन तोपों के वहाँ पहुँचने से पहले ही डोला का पतन हो गया था। इसके विपरीत चीनी मोला-वाल्द और भारी मॉर्टर खच्चरों पर साद कर अपने साथ लाये थे।

सड़कों के अभाव के कारण अग्रिम क्षेत्रों में स्थित हमारी सेना को रसद आदि प्राप्त करने के लिए पूर्णतः हवाई अवपतन पर निर्भर रहना पड़ता था। यह तरीका न सिर्फ अत्यधिक कीमती या वस्तुि अवयवांश और असन्तोषजनक भी था। अक्सर हवा से गिराया गया सामान या तो ऐसे क्षेत्रों में पहुँच जाता था जहाँ से उसे वापस पाना असम्भव था या वधु के इलाक़े में गिर पड़ता था।

इसके विपरीत चीनी सेना पूरी तरह तैयार और सुसज्जित थी—वास्तव में काफी समय से वह इस युद्ध की तैयारी कर रही थी। उसके पीछे उत्तम सड़कों और हवाई अड्डों का जाल बिछा हुआ था। उनके संचार तन्त्र मोर्चे से केवल दो-चार मील ही पीछे थे।

मैकुमहॉन रेखा से लगी हुई उनकी मुख्य सड़क पर पाँच-छनी ट्रक चल सकत थे और वह तीन हवाई अड्डों से सम्बन्धित थी। रेखा के उस पार उनका मुख्य प्रतिष्ठांन ले मोर्चे से केवल दस मील के फ़ासले पर था। इसके विपरीत हमारा सबसे करीबी रोड-हेड मोर्चे से साठ मील पीछे तोबांग में था।

चीनियों के पास स्वचालित तथा प्रतिक्षेप राइफल, मोला-वाल्द तथा भारी तोपें थीं जबकि, युद्ध के पहले दौर में भारतीय सैनिकों के पास केवल २०५ राइफल थीं और भारी अस्त्र तो थे ही नहीं।

जो भारतीय सैनिक युद्ध मोर्चे से लौटे उन्होंने बार-बार यह बताया कि सैकड़ों पूरी तरह सशस्त्र चीनी सैनिकों के अभ्यात्मक आक्रमण करते और तड़ित गति से उन्हें चारों तरफ से घेर लेने से कितनी ख़बरदस्त बौखलाहट पैदा हो जाती थी और आतंक फैल जाता था। पहाड़ों में चीनियों के पास सैकड़ों मॉर्टर थे जिन्हें कौशल से चलाना वे कोरिया के युद्ध में सीख चुके थे। भारतीय अफसरों ने बताया कि यह मॉर्टर चीनियों के सबसे असरदार अस्त्र थे।

हमारे युद्धनीतिक तथा सामरिक उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित थे, इसके विपरीत चीनी सेना जानती थी कि वह किस तरफ बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है तथा राजनैतिक दृष्टिकोणों से प्रतिबन्धित हुए बावजूद वह अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी शक्ति से लग जाती थी।

अथवा पैदली दस्ता, जो अपने युद्ध कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जब नैका पहुँचाया गया तब तक मात्र उसकी प्रसिद्धि ही बची थी। अब उसमें

केवल मय घामिन किया गये ब्रिगेड के जिह्वा आपसी समन्वय विकसित करने और एक-दूसरे से तथा अपने मुख्य कमान्ड से अच्छी तरह परिचित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। इनके ऊपर जब चीनी आक्रमण से ठोड़ पहल उभरा कमान्डर बदला गया तो तेन सीके पर उभरी नीति भी बदल गयी। वास्तव में चीनिया ने नम द्विबीजन का गुब मन्त्राण उठाया—पूछा उन प्रसिद्ध लड़ाई ४५५ द्विबीजन को क्या हुआ जिनमें जमनो का हराया था।

२४ नवम्बर को जनरल निरञ्जन प्रसाद को हटा कर जनरल ए० एन० पटानिया को ( जिन्हें मज ४८ के जोड़ी ला के पुष्ट में महावीर चक्र प्रदान किया गया था ) ४५५ पैदली द्विबीजन का कमान्डर बनाया गया। उस समय उस द्विबीजन में केवल दो ब्रिगेड और एक बगमियन थे।

स्वना पुष्ट पर मुमंज बाप करने हुए पटानिया ने गिकामन की "आरम्भ में ही एक व्यापक साहसिकता तथा असन्तोष की भावना थी—सायद इसलिए कि उन्हें पता था कि उन पर एक तेजी जिम्मेदारी मढ़ दी गयी है जिसे पूरा करना असम्भव है। फिर यह पेयन्दार द्विबीजन बन गया था जिनमें ऐसे बटालियन शामिल थे जिन्होंने अभी तक दूमेरे के साथ मिलकर काम नहीं किया था। 'मैंने बताया न कि वहाँ की जनशक्त के बाढ़ी के और न इन उँचाइयाँ पर लड़ने लिए उनके पास पर्याप्त साधन थे।'

इनके बादजुद पटानिया ने यह स्वीकार किया कि जिन समय चीनियों ने स्लेता पर आक्रमण किया उस समय उनके पास तीन दिन के लिए पर्याप्त गोला-बारूद और छ दिन का राशन था।

बौर कमान्डर कौल ने स्लेता के लड़ाकू पन की सारी जिम्मेदारी पटानिया पर डाय दी। कौल के अनुसार पटानिया के हाथ-बाँध फूल गये थे और उन्हें बराबर बस एक ही बात की फिर थी कि कैसे होशियारा सिंह के त्रिपड को स्लेता में हटाकर द्विबीजनन हेडक्वार्टर निर्माणवाग पहुँचा दें ताकि वह और भी सुरक्षित हो सके।

काश पटानिया एक दिन भी स्लेता में इट जाने लो सायद स्लेता की कहानी भिन्न होती—चीनी आक्रमणकारी विफल हो जाते और उनके धक्करोषो को पीरवर हम सीमदीला को भी बचा लेते।

स्वयं पटानिया ने स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया है कि स्लेता पर आक्रमण करने समय उनकी सहाय्य भारतीयों से अधिक नहीं थी। दोनों के पास मुकाबले में एक-एक ब्रिगेड था—इसके ऊपर हमारे ब्रिगेड के पास पर्याप्त राशन, अस्त्र और गोला-बारूद थे।

लेकिन इसके साथ ही पटानिया को अपने ऊपर के अधिकारियों से कई शिकायतें थी। उन्होंने कहा कि अन्त तक यह उच्चतर अधिकारी इस बारे में

निश्चय नहीं थे कि हमारा मुख्य युद्धनीतिक लक्ष्य क्या है। इसके अलावा यह भी तय नहीं किया जा सका था कि प्रयत्नों को कहाँ केन्द्रित किया जाये : कामेंग में या बालोंग में।

“पहले ये योजना बना लेते थे फिर उस पर सोचना शुरू करते थे,” पठानिया ने कहा। “कौल निश्चय ले ही नहीं पाते थे और जब लेते भी थे तो ये निश्चय अस्पष्ट होते थे।” १७ नवम्बर के उस महत्वपूर्ण दिन कोर कमान्डर अपने हेड क्वार्टर में अनुपस्थित थे—वे उस दिन शाम को ही लौटे थे और तभी उनसे आदेश लिए जा सके।

पठानिया ने कौल के उस पर लगाये इस आरोप को गलत बताया कि उस रात उन्होंने (पठानिया ने) होशियारासिंह को त्सेला से हटने का आदेश दिया था। पठानिया ने कहा कि होशियारासिंह वहाँ से इसलिए हटे थे कि काफ़ी पहले कौल ने उन लोगों से कहा था कि शायद होशियारासिंह को त्सेला से हटना पड़े और ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था।

ज्ञान पर पठानिया से होशियारासिंह के अन्तिम ब्रह्म थे : “त्सेला में कुछ गड़बड़ है—मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ।” यह वास्तविक १५ नवम्बर को सुबह पाँच बजे हुआ था। इसके बाद पठानिया और होशियारासिंह की मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। पठानिया ने इस बात की भी शिकायत की कि स्पासीम कमान्डर अक्सर बिना आदेश के अपमान कर देते थे।

पठानिया ने बताया कि जब २४ अक्तूबर को उन्होंने ४थे डिवीजन के नये कमान्डर के रूप में दिरांगजांग में रिपोर्ट किया तो न तो उनके पास सेना प्रमुख के कोई आदेश थे, न पर्याप्त सैनिक और न ऐसे आवश्यक साधन जैसे खुदाई के औजार, वायरलेस सेट, गोलाबारूद और राशन। एक सिक्ख लाइट पैदली बटालियन, जो तब तक गोधा के गर्म इलाक़े में था, फ़ौरन हवाई जहाज द्वारा उस ठंढे प्रदेश में पहुँचा दिया गया। और सीधे युद्ध मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। पठानिया ने दो और ब्रिगेडों की माँग की थी लेकिन एक ही स्वीकृत किया गया और उसके भी पहुँचने से पहले चीनियों ने घेरा डालना शुरू कर दिया था।

त्सेला में चीनियों की बाधू से घेरनेवाली सामरिक आल के बारे में बात करते हुए पठानिया ने बताया कि त्सेला के बायें पार्श्व पर स्थित दो राजपूत कम्पनियों ने १७ नवम्बर की रात को सामने की पहाड़ी पर मशालबाहूकों का एक दस्ता देखा था। वास्तव में यह दस्ता चीनियों का एक बटालियन था जो बीच की खाई का चक्कर काट कर त्सेला के पीछे पहुँच रहे थे।

इन दोनों कम्पनियों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और न उन्होंने डिवीजनल हेडक्वार्टर को इस बात की सूचना दी क्योंकि उनका वायरलेस सेट काम नहीं कर रहा था—इस युद्ध के पूरे दौरान में भारतीय सेना के अधिकतर

बायरन सेना न काम नहीं किया था इसके अनादा हमेशा बर्टरिया का अनाद भी रहता था ।

रात हो रात हार्गियोगमिह ने दूसरे मित्रों की दो कम्पनिनी पहाड़ी से हटा ली थी और उनके अगवान म चीनिनों ने उनका पीछा किया था । और के समय किसी और चीनी सैनिक आगने सामने की मुठभेड़ में गुये हुए थे ।

१० नवम्बर का महत्वपूर्ण सुबह तेजपुर से सुचारु सम्बन्ध टूट गये जिसके कारण डिविजनल और कोर हेड क्वार्टरों के बीच सम्पर्क खत्म हो गया था । १६ नवम्बर का, पटानिया के वहाँ पहुँचने से पहले, कोमरीला पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था जिससे पचस्वरप पटानिया तथा उनके सैनिकों को १२० मील पैदल चलकर मुटहिल पहुँचना पड़ा था ।

जिस ठेकी और अनीपचारित डग से नयी कोर की स्थापना और उसके कमांडर की नियुक्ति हुई थी उससे और भी गड़बड़ पैदा हुई । स्वयं कौल का कथन है कि उन्हें अपनी नियुक्ति की सूचना ३ अक्टूबर की रात को ६ बजे प्रधान सेनापति से मिली । अगले दिन सुबह वह विमान द्वारा तेजपुर पहुँचे ४०० मील लम्बे मोर्चे का कमांड हाथ में लेने के लिए । उस समय कोर का अस्तित्व एक नहीं था, न कोई स्ट्राफ़ था और केवल दो ही बिंदु थे जबकि साधारणतः एक कोर में छ से नौ बिंदु तक होते हैं । कौल के पास न तो कोई सुचारु तंत्र था और न तोपखाने इन्जीनियरिंग, वातायान तथा सभरण के यूनिट जो कोर हेडक्वार्टर के आवश्यक भग होते हैं ।

कौल को भारत सरकार का सबसे पहला आदेश था कि डोला—वागना क्षेत्र से चीनियों को निकाल देंगे । लेकिन स्वयं डोला क्षेत्र का मुआयना करने के बाद कौल ने दिल्ली सौटकर सरकार तथा सैनिक हेडक्वार्टर को बताया कि जो द्विमेसारी उनकी सौपी गयी थी वह पूरी नहीं की जा सकती ।

कोर कमांडर की हैसियत से कौल पर यह आरोप लगाया जाता है कि मराठों और आदेशों के लिए वह कोर हेडक्वार्टर में बहुत कम मिलते थे—उनका अधिकतर समय अग्रिम क्षेत्रों में ही गुजरता था ।

अपने बचाव के लिए कौल ने द्वितीय महायुद्ध के अमरीकी जनरल पैटन का उदाहरण दिया है । यही बात अर्मेनी के फोन्ड मार्शल रमन के बारे में सही थी जो अपना अधिकतर समय अग्रिम क्षेत्रों में स्थित सेना के साथ बिताते थे । लेकिन रमन जब भी अग्रिम प्रदेशों में होते थे तो उनकी बायर-लेस गाड़ी बराबर उनके साथ रहती थी और सारे मोर्चे पर होनेवाली गति-विधियों का उन्हें थड़ी-थड़ी का ज्ञान प्राप्त होता रहता था । इसके अलावा जब भी रमन किसी अग्रिम क्षेत्र में होते थे तो अधिकतर वहाँ का कमांड वह स्वयं अपने हाथों में ले लेते थे और युद्ध का निर्देशन खुद ही करते थे ।

कहा जाता है कि अधिकतर समय कौल अग्रिम खेपों में रोय जमाते घूमते थे जिससे व्यस्त अग्रिम कमान्डर के काम में खलल पड़ता था। तनाव की चरम सीमा पर कौल के इस आदेश से कि कोर हेडक्वार्टर तेजपुर से गौहाटी हटा दिया जाये (जिसे बाद में फिर तेजपुर साना पड़ा था) सेना में भय और सहासहीनता तथा जनता में आतंक फैल गया था जिसके कारण लोगों ने बड़ी संख्या में तेजपुर छोड़कर नागना भ्रष्ट कर दिया था।

×

×

×

संक्षिप्त रूप में संसद के सामने रक्षा मंत्री श्री चन्हाण द्वारा प्रस्तुत की गयी हेन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि हमारे सैनिकों का प्रशिक्षण मैक्रा के दुर्गम प्रदेश तथा वहाँ के लिए आवश्यक युद्ध तत्परता को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। न इन सैनिकों का प्रशिक्षण इस दृष्टि से किया गया था कि उन्हें कमी चीन से युद्ध करना पड़ेगा। अतः : "हमारे सैनिकों को चीनी सामरिक नीति और युद्ध के तरीकों का, उनके अस्त्रों का, साधनों का और सैनिक कौशल का बिल्कुल ज्ञान नहीं था।" सत्य यह था कि हमारी सेना पूरी तरह से सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित थी। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किये गये दक्षिणाधुरी सामरिक तरीके चीनियों के असाधारण सामरिक तरीकों के सामने बिल्कुल निरर्थक थे। न पर्याप्त मात्रा में कंट्रीले तार तथा 'भाइने' थी जिनमें चीनी आक्रमणकारियों के 'मानवी ज्वार' रोके जाते।

ब्रुक्स रिपोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी अधिकारियों को नेतृत्व का पूरा प्रशिक्षण देना। जाँच से यह बात सिद्ध हुई थी कि प्रशिक्षण तथा वास्तविक युद्ध, दोनों, के लिए साधनों की सर्वांग कमी थी।

संभार समस्या युँ भी बहुत खराब थी, उसके ऊपर बाहनों की विशेष कमी थी और जो बाहून थे भी "उनमें से भी अधिकतर पुराने थे और पर्वतीय प्रदेश तथा ऊँचाइयों पर भार वहन करने के अयोग्य थे।"

कमान्ड व्यवस्था की आलोचना करते हुए ब्रुक्स रिपोर्ट ने दिखाया कि "कठिनाइयाँ तब पैदा हुईं जब पूर्व निर्धारित कमान्ड शृंखला से हट कर निश्चय लिये गये," लेकिन रिपोर्ट ने इस ओर भी ध्यान दिखाया कि "ऐसा सिर्फ़ इस लिए हुआ कि पहले से पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था और मुगठित योजनाएँ नहीं बनायी गयी थीं।"

रिपोर्ट ने इस बात की भी मद्धिम-सी आलोचना की कि उच्च सैनिक अधिकारी (जो मोर्चे से दूर पर स्थित थे) सामरिक मामलों में इस हद तक हस्तक्षेप करते थे कि अपनी कुर्तियों पर बैठे हुए दूर से युद्ध स्वतः पर स्थित

सैनिकों के काम भी निर्धारित कर देने थे। 'युद्ध क्षेत्र के कमांडरों का यह काम है कि आवश्यकता पड़ने पर, अपने आप ही निश्चय से और युद्ध की स्थानीय समस्याओं को हल करना उहाँ पर छोड़ देना चाहिए था।'

सैनिकों की गारीरिक स्वस्थता के बारे में रिपोर्टें ने यह स्वीकार किया था "अपेक्ष्य अवस्था के अनुभवों की गारीरिक स्वस्थता में कभी आ गयी थी" साथ ही रिपोर्टें में कहा गया था कि अवर अधिकारियों की गारीरिक स्वस्थता का स्तर अच्छा था।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि कमांडरों के युद्ध कौशल के बारे में रिपोर्टें का यह मत था कि 'सेना के प्रवर अधिकारियों में असमताएँ बराबरी सीमा तक दृष्टिगोचर हुई थी।' यह भी स्पष्ट किया गया कि अवर प्रवर कमांडर अवर कमांडरों की निश्चय लेने की गति तथा पहल क्षमता पर असोसा महा करते थे यद्यपि वास्तव में उनका (अवर कमांडरों को) ही भू-प्रदेश का तथा अपने नीचे के सैनिकों की स्थानीय स्थिति का आवश्यक ज्ञान था।

स्टाफ काय तथा क्रियात्मक के बारे में रिपोर्ट की राय थी कि "एक बड़ा सबूत यह मिला है कि जनरल स्टाफ की कार्यविधि की उत्तमता और दक्षिण समय पर पूर्व योजना बना लेने की क्षमता तथा भीषणता का हमारी भावी युद्ध क्षमता पर विचार तथा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।"

स्टाफ की कार्यविधि की मामूली बात करते हुए, अव्यवस्था का यह उदाहरण ध्यान देने योग्य है। मई १९६२ के युद्ध के बीच में एक बार इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि सन्धिगत प्रशासकीय केन्द्र को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया जाय। सैनिक नियमों के अनुसार ऐसे यूनिट में यह क्षमता होनी चाहिए कि एक घंटे के अन्दर स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाये। एक दिन सुबह जब इस केन्द्र को हटाने की कार्यवाही शुरू हुई तो पता यह चला कि वाहनों का कालिदा संगठित ही नहीं किया जा सकता। उस दिन शाम तक भी आवश्यक सहायता में बाह्य इकाई नहीं बिये जा सके।

स्थान परिवर्तन का काम अगले दिन सुबह तक शुरू किया जा सका। स्टार्क केन्द्र से सदा हुआ कालिदा काफी दूर चलने के बाद घटो एक नदी के किनारे अटक रहा क्योंकि उसे नदी के पार से जाने के लिए नाव के बड़े का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। अंत में केन्द्र किसी तरह नये स्थान पर पहुँच गया लेकिन चौबीस घंटे के भीतर ही उसे यह आदेश दिया गया कि फिरपुताने स्थान पर वापस पहुँच जाने और वहाँ से किसी हालत में न हटे।

गम्भीर गारियों का छूट जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने समय दस्तों का अस्त व्यस्त हो जाना और सैनिकों का अपने साधनों से पृथक् हो जाना



बुरी और दुस्संगठित स्टाफ़ कार्यविधि के प्रमाण ये हालांकि देश में यह समझा जाता था कि जनरल स्टाफ़ इन बातों में अत्यन्त कुशल है।

भारतीय सेना की गतिशीलता किसी सीमा तक इस बात से भी प्रभावित होती थी कि भारतीय सैनिकों के पास मूलतः काफ़ी भारी व्यक्तिगत सामान होता था। यह आम बात थी कि अपने रेजिमेंटल केंद्र से नेफ़ा मोर्चे पर जाते समय जवान के साथ ७० पाउंड के भार का व्यक्तिगत सामान तथा युद्ध सामग्री होती थे। अधिकारी वर्ग अपने साथ ट्रंक, सूटकेस, भारी विस्तर, कैम्प किट, यहाँ तक ग्रैंडशे केस आदि लेकर चलते थे।

यह ध्यान में रखने योग्य बात है हेन्डरसन ब्रुकस रिपोर्ट, रक्षा मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त करके, जिस रूप में, प्रस्तुत की गयी थी वह व्यास-शीली तथा बातों को घटाकर कहने का एक सर्वोत्तम नमूना है। संग्राम निर्देशन पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में कहा गया : "सेना शासन का यन्त्र होती है इसलिए विशाल-सम और पूर्णरूप से सुसज्जित सेनाओं के लिए भी यह आवश्यक होता है कि सरकार द्वारा उसे उचित नीति निर्देश तथा महत्त्वपूर्ण आदेश मिलें। यह निर्देश और आदेश इस बात को ध्यान में रखकर देने चाहिए कि समय-समय पर सेना का आकार क्या है और उसके सैनिक साधनों की स्थिति कैसी है।"

दूसरे शब्दों में रिपोर्ट ने इस बातक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि सरकार की नीतियों और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सैनिक क्षमता में काफ़ी अन्तर था।

अन्त में रिपोर्ट ने बताया कि १९६२ के भारत-चीन युद्ध में केवल २४,००० भारतीय सैनिक ही वास्तव में इस्तेमाल हुए थे। इनमें से जो सैनिक लड़ाई में स्थित थे उन्होंने शत्रु के अधिक संख्या में होने तथा उससे घिर जाने के बावजूद, अपने शौर्य का अवरोधक प्रमाण दिया था। पूर्वी मोर्चे पर हालांकि शत्रु के अवरोधक संख्या में होने के कारण भारतीय सेना को मजबूरन पीछे हटना पड़ा था, हमारे सैनिकों ने बालोंग से अत्यन्त व्यवस्थित ढंग से अपरान किया तथा शत्रु के कई सैनिक आहत किये लेकिन कामेंग सेक्टर में उनकी बुरी गति हुई।

कामेंग में भारतीय सेना की यह दुर्गति क्यों हुई इसके बारे में हेन्डरसन ब्रुकस रिपोर्ट का रक्षा मंत्रालय का संक्षिप्त संस्करण सामोस है। स्पष्ट है कि मूल रिपोर्ट में इस बारे में बहुत कुछ कहा होगा क्योंकि कामेंग सेक्टर की लज्जाजनक घटनाओं के कारण ही यह जांच की गयी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश रिपोर्ट के इसी अंग को जनता से पूरी तरह छिपा कर रखा गया—सरकार का ऐसा करना राजमर्मजता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

मेजर पद तक के अवर अधिकारी अत्यन्त कटु मनोस्थिति के साथ मोर्चे से वापस लौटते—उनके मन में यह भावना थी कि सरकार ने उन्हें एक

प्रसम्भव स्थिति में पसा कर छोड़ दिया था। प्रवर अधिकारियों के दूरे नेतृत्व तथा उनकी गतियों के कारण उन्हें जो बचायी जा मचनेवाली गौरीरिक्त मातनाएँ सहनी पड़ी थी उनके कारण यह भावना और भी गूढ़ हो गयी थी। इसके अलावा इन प्रवर अधिकारियों का प्रवर अधिकारियों के नेतृत्व में बनई विश्वास नहीं था। इसका उदाहरण यह कहानी है जो मेजर जनरल ए० एम० पटानिया ने मुझे बतायी थी और जिसका अनुमोदन श्रीरं ने भी किया है।

पटानिया ने मुझे बताया कि २६ अक्टूबर की रात रेडियो के पास बैठे हुए अफसरों ने जब यह सुना कि जनरल कौन टोच ही गये हैं और उन्होंने फिर से 'जयी कौर का बमांड घट्टा कर लिया है तो वे एक स्वर में बोले,' 'यह लौट आये हैं? हा अब भाषा ही हमारी रंगा बरे।' सेना प्रमुख के हार में भी प्रवर अधिकारियों की और जजाना की राय प्रकटी नहीं थी। और उनके स्थानीय द्वितीयक बमांडर ना दुर्ध्व भय में और भी प्रयोग्य नेत्र साबित हुए थे।

सेना में स्थित सैनिकों में आतंक और साहसहीनता का एक और कारण था मोर्चे से लौटने हुए सैनिकों की बर्ताव में प्रचलित बातों का। सेना से हो कर जब वे नेजपुर में पहुँचते थे तो मोर्चे पर जाने वाले नये सैनिकों से घुलने मिलने में और उन्हें चीनिया का वार में आनर्जित करनेवाली कहानियाँ सुनाने में। चीनिया की निम्न सामरिक नीति तथा 'दुर्ध्व करने के भीषण तरीकों की बड़ा चढ़ा कर बताने से यह लौटने हुए सैनिक सिद्ध करना चाहते थे कि उनका पराजित होना और अपमान करना अस्वाभाविक नहीं था। बात की बात में नये सैनिकों में जो लौटने हुए सैनिकों की साहसहीनता भर जाती थी।

यह बालोप में नहीं हुआ क्योंकि यह नेजपुर से बहुत दूर था और इसलिए यह आतंक कयाएँ मोर्चे पर लड़नेवाले सैनिकों तक नहीं मज्जी पहुँच सकी थी।

डोना और तौवांग में पराजित होने के अलावा सेना और बोमडीला में सेना में साहसहीनता का भाव बम होने के दो अन्य कारण उन लोगों ने बताया है जो उस समय उसी क्षेत्र में थे। वे ये हैं

(१) यह व्यापक भावना कि नयी दिल्ली में स्थित प्रवर अधिकारियों ने उन्हें इस प्रसम्भव स्थिति में पसा दिया है। यह भावना इस बात से जन्मी थी कि सैनिकों के पास राशन का, कपड़े का, छत्रों तथा मोना बाइबल का जबरदस्त अभाव था और उन पर निम्नतापूर्ण ऐसी हिम्मेदारी थोप दी गयी थी जिसे पूरा करना असम्भव था। इसके अलावा उन्हें यह भी मालूम था कि सुरक्षाहीन स्थितियों में उन्हें सच्चा में वहीं अधिक तथा सैनिक साधनों से पूरी तरह सुसज्जित जानू से युद्ध करना है।

(२) सैनिक हेल्क्वार्टर से लेकर कोर, डीवीजन तथा ब्रिगेड के स्तर तक सैनिक नेतृत्व में पूर्ण अविश्वास ।

यह भी एक नया सत्य था जो ब्रुक्स रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि कश्मीर युद्ध के बाद के तेरह वर्षों में सेना को धुन लग गया था । इस युद्धहीन अवधि में राजनीतिज्ञों की सरकार ने सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और इतना पर्याप्त धन अधिकृत नहीं किया था कि वह आवश्यक तथा आपुनिक सैन्य-साधन प्राप्त कर सके । और इन कारणों से सेना के अधिकारियों के मन में यह भावना पैदा हो गयी थी कि उनके साथ सोतेली माँ का सा व्यवहार किया जा रहा है । इस भावना के कारण वह उत्साह तथा युद्ध प्रवृत्तता पैदा होना मुश्किल था जो सफल सैनिक नेताओं में होना आवश्यक है ।

शायद इस सम्बन्ध में फ्रील्ड मार्शल रमल का यह कथन उद्धरित करना युक्तिसंगत होगा :

"सैनिक का युद्ध के प्रति क्या दख होता है यह अच्छी तरह से समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है । जो आदमी अपने घर और परिवार को छोड़ कर मोर्चे की अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में लड़ने-मरने के लिए जाता है वह वास्तव में उच्चतम आदर्शों से प्रेरित होकर ऐसा करता है और यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में कमान्डरों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए । इसलिए अधिकारियों का सबसे पहला कर्तव्य है कि सैनिकों के दिलों में किसी भी तरह आदर्श का यह बीज प्रज्वलित रहें । सैनिकों को अपने आदर्शों में विश्वास क्रमशः रखने के लिए बराबर कारण मिलते रहने चाहिए वरना यह विश्वास शीघ्र ही खत्म हो जाता है ।"

हेन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट के संक्षिप्त संस्करण को पेश करते हुए रक्षा मंत्री बगवान ने अपने वक्तव्य के अन्त में संसद को बताया कि त्रुटियों को ठीक करने का काम जब रिपोर्ट के प्राप्त होने तक के समय के लिए नहीं रखा गया था । इस दिशा में सुधार का काम जल्द शुरू होने के साथ ही प्रारम्भ कर दिया गया था ।

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सेना को पुनर्संगठित, पुनर्विन्यासित तथा परिष्कृत करने का त्रिमुखी काम और भी तेजी से किया जाने लगा । भविष्य में नेफा मोर्चे पर किसी भी सम्भावित चीनी आक्रमण का सामना करने की हमारी वर्तमान युद्ध तत्परता के बारे में मुझे कई उत्साहजनक प्रमाण मिले हैं । पूर्वी कमान्ड के वर्तमान सेनापति सेफ्टिनेट जनरल मानिकशा अत्यन्त कुशल सैनिक हैं जो अपने काम में पूर्णतः कुशल हैं । उनसे बातें करना एक जीवनदायक अनुभव है ।

असम्भव स्थिति में फटा कर छोड़ दिया था। प्रवर अधिकारियों के दुर नेतृत्व तथा उनकी गलतियों के कारण उन्हें जो बचायी या गहनकारी पारोक्षिक माननाएँ सही थीं उनके कारण यह भावना और भी दृढ़ हो गयी थी। इसके अलावा इन प्रवर अधिकारियों को प्रवर अधिकारियों के नेतृत्व में कई विस्वास नहीं था। इसका उदाहरण यह कहानी है जो मेजर जनरल ए० एम० पटानिया ने मुझे बतायी थी और जिसका अनुमोदन धीरो ने भी किया है।

पटानिया ने मुझे बताया कि २६ अक्तूबर की शाम रेडियो के पास बैठे हुए प्रभुमों ने जब यह सुना कि जनरल कैंन टीक हा गये हैं और उन्होंने फिर से ४पी बार का बमार्ड घट्टा कर लिया है तो वह एक स्वर में बोले, "बट सौट बाय है ? तो अब मरान ही हथारी ग्या बने ।" सेना प्रमुख के बार में भी प्रवर अधिकारियों की और अवाना की राय प्रकटी नहीं थी। और उनके स्थानीय हिंदीकरण बमार्ड का टुट ध्वज में और भी प्रयोग नों साधित हुए थे।

स्लेमा में स्थित सैनिकों में मानक और साहसहीनता का एक और कारण था मोर्चे से सौटने हुए सैनिकों की बजाय नये सैनिकों की बाँटें। स्ले से हो कर जब वे नेत्रपुर में पहुँचते थे तो मोर्चे पर जाने वाले नये सैनिकों से घुलने मिलने के और उन्हें सीनिया के बारे में जानकारी करनेवाली कहानियाँ सुनाने के। सीनिया की निम्न सामरिक सीमा तथा मुठ कराने के भीषण तरीकों की बढ़ा चढ़ा कर बताने में यह सौटने हुए सैनिक सिद्ध करना चाहते थे कि उनका पराजित होना और प्रपदान करना अस्वाभाविक नहीं था। बाज की बात में नये सैनिकों में भी सौटने हुए सैनिकों की साहसहीनता भर जाती थी।

यह बानों में नहीं हुआ क्योंकि यह नेत्रपुर से बहुत दूर था और इसलिए यह घाटक कदाएँ मोर्चे पर लड़नेवाले सैनिकों तक नहीं पहुँच सकी थी।

होला और तोबाग में पराजित होने के अलावा स्लेमा और बोयडीना में सेना में साहसहीनता का भाव कम होने के दो अन्य कारण उन लोगों ने बताये हैं जो उस समय उसी क्षेत्र में थे। वे ये हैं-

(१) यह व्यापक भावना कि नयी दिल्ली में स्थित प्रवर अधिकारियों ने उन्हें इस असम्भव स्थिति में फटा दिया है। यह भावना इस बात से उभरी थी कि सैनिकों के पास राशन का, कपड़ों का, अस्त्रों तथा गोला बारूद का अवरोधक प्रभाव था और उन पर निर्भरतापूर्वक ऐसी जिम्मेदारी थोप दी गयी थी जिसे पूरा करना असम्भव था। इनके अलावा उन्हें यह भी मालूम था कि सुरक्षाहीन स्थितियों में उन्हें सम्पूर्ण में कही अधिक तथा सैनिक साधनों से पूरी तरह सुसज्ज नष्ट से मुक्त करना है।

(२) सैनिक हेडक्वार्टर से लेकर कौर, डीवीजन तथा ब्रिगेड के स्तर तक सैनिक नेतृत्व में पूर्ण अविश्वास ।

यह भी एक नग्न सत्य था जो द्रुपद रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि कश्मीर युद्ध के बाद के तेरह वर्षों में सेना को धुन लग गया था । इस युद्धहीन अवधि में राजनीतिज्ञों की सरकार ने सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और इतना पर्याप्त धन अधिकृत नहीं किया था कि वह आवश्यक तथा आधुनिक सैन्य-साधन प्राप्त कर सके । और इन कारणों से सेना के अधिकारियों के मन में यह भावना पैदा हो गयी थी कि उनके साथ भीतली माँ का सा व्यवहार किया जा रहा है । इस भावना के कारण वह उत्साह तथा युद्ध प्रवृत्ता पैदा होना मुश्किल था जो सफल सैनिक नेताओं में होना आवश्यक है ।

शायद इस सम्बन्ध में फ्रीड मार्शल-रमन का यह कथन उद्धरित करना युक्तिसंगत होगा :

“सैनिक का युद्ध के प्रति क्या रुख होता है वह अच्छी तरह से समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है । जो आदमी अपने घर और परिवार को छोड़ कर मोर्चे की अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में लड़ने-मरने के लिए जाता है वह वास्तव में उच्चतम आदर्शों से प्रेरित होकर ऐसा करता है और यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में कमालदोरों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए । इसलिए अफसरों का सबसे पहला कर्तव्य है कि सैनिकों के दिलों में किसी भी तरह आदर्श का यह दीप प्रज्वलित रहें । सैनिकों को अपने आदर्शों में विश्वास कायम रखने के लिए बराबर कारण मिलते रहने चाहिए वरना यह विश्वास शीघ्र ही खत्म हो जाता है ।”

हेन्डरसन द्रुपद रिपोर्ट के संक्षिप्त संस्करण की पेश करते हुए रक्षा मंत्री कन्हाय ने अपने वक्तव्य के अन्त में संसद को बताया कि बुटियों को ठीक करने का काम उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने तक के समय के लिए नहीं रखा गया था । इस दिशा में सुधार का काम जाँच शुरू होने के साथ ही आरम्भ कर दिया गया था ।

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सेना को पुनर्संगठित, पुनर्विन्यासित तथा परिवर्धित करने का त्रिमुखी काम और भी तेजी से किया जाने लगा । भविष्य में नेफा मोर्चे पर किसी भी सम्भावित चीनी आक्रमण का सामना करने की हमारी वर्तमान युद्ध तत्परता के बारे में मुझे कई उत्साहजनक प्रमाण मिले हैं । पूर्वी कमान्ड के वर्तमान सेनापति जेफ्टिनेट जनरल मामिकशा प्रत्यन्त कुशल सैनिक हैं जो अपने काम में पूर्णतः कुशल हैं । उनसे बातें करना एक जीवनदायक अनुभव है ।

जानकार विदेशी सैनिक पर्यवेक्षकों ने इस बात का समर्थन किया है कि सन् १९६२ में चीन द्वारा बड़ी चोट खाने के बाद से भारतीय सेना ने आश्चर्य-जनक प्रगति कर ली है। भारत तथा चीन के आस-पास के अन्य देशों का दौरा करने के बाद हेरिमन सैलिसबरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखी गयी एक लेखमाला में कहा है

"विदेशी पर्यवेक्षकों को विश्वास है कि हिमालय के मोर्चे पर भारत चीन की किसी भी विनाशकारी शक्ति का मुकाबला कर सकता है। एक भारतीय जानकार भारतीय सैनिक का मत है कि भारत अब किसी भी चीनी आक्रमणशील प्रयत्न का सामना कर सकता है।"

बाद में लिखी गयी अपनी पुस्तक 'मॉन्टेड मॉन्ट वाइता' में सैलिसबरी ने एक भ्रमरीजी विशेषज्ञ का यह मत प्रस्तुत किया है कि सारे सप्ताह में भारतीय सैनिक सबसे अच्छे, कठिनाइयों सहने की सबसे ज्यादा क्षमता रखने वाले, सबसे उत्तम ढंग से आधुनिक पहाड़ी सैनिक हैं। वे किसी भी चीनी आक्रमण का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं।

अपनी १९६८ की वार्षिक समीक्षा में भ्रमरीजी प्रतिरक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने कहा है कि साम्यवादी क्षेत्र के बाहर सैनिक क्षमता के दृष्टिकोण में एशिया में भारत की सर्वोच्च स्थिति है। उन्होंने कहा है कि चीन के पास २३ लाख सैनिक हैं। जिनमें इस बात की सीमित क्षमता है कि अपनी सीमाओं के बाहर आक्रमण कर सकें। इसके मुकाबले भारत के पास अब ११ लाख सैनिक हैं जो चीनियों से अपने देश की रक्षा करने के पुरखत योग्य हैं। मैकनमारा ने यह भी कहा है कि भारतीय सेना के हर सदस्य की व्यक्तिगत फायर शक्ति चीनियों की तुलना में ज्यादा है, और "संचार तथा वातावरण की व्यवस्था सुधारने के कारण अब वे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आसानी और तेजी से प्रतिरक्षा सैनिक सहायता पहुँचा सकते हैं।"

वास्तव में पर्वतीय सीमा पर ५००० मील लम्बी मिलानेवाली सड़कों का जाल बिछ जाने के कारण अब भारतीय सेना इस हलाके में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचायी जा सकती है। चीन अपनी तरकीब अब थोड़ा नहीं सकता क्योंकि अब सन् १९६२ की तरह वे हमें अपनी तेजी से चरित्र नहीं कर सकते। हमारी सेनाएँ वहाँ डटी हुई हैं और कभी भी किसी चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे अब स्थानीय जनवायु की भाँदी हैं। उनके पास पर्याप्त वस्त्र और भोजन हैं और उनकी समार समस्याएँ काफी सीमा तक हल हो चुकी हैं। इसके अलावा उनमें असीम साहस और उत्साह है।

## दुर्बुद्धि के पीछे सुबुद्धि

चीनी अपनी विजय-यात्रा के बीच में ही क्यों रुक गये ?

इसके कई कारण हैं । यूँ अपनी तरफ से चीनी इस बात का दावा करते हैं कि वे केवल आराम-रक्षा के लिए ही युद्ध करने पर मजबूर हुए थे और अतिक्रमण एक बार खरम हो जाने पर युद्ध जारी रखने का कोई अर्थ नहीं था ।

लेकिन चीन द्वारा युद्ध-विराम की एकपक्षी घोषणा में उनकी घबड़ाहट का संकेत भी मिलता है । जिस तेजी से उन्होंने युद्ध बन्द किया उससे यह जाहिर होता है कि उनके आक्रमण की पुष्टता खरम होने लगी थी और भलाई इसी में थी कि घनी हुई वात बिगड़ने से पहले युद्ध बन्द कर दिया जाये । ऐसा प्रतीत होता था मानो किन्हीं असम्भावित बातों के पैदा होने से वे सोच में पड़ गए थे और उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा था ।

लगता है कि शुरू में चीनियों का यह ख्याल था कि पराजय का पहला स्वाद चखते ही भारत के पाँव उखड़ जायेंगे और वह युद्ध बन्द करने की याचना करेगा । इस प्रकार युद्ध की जो आग उन्होंने भड़कायी थी वह फौरन ठंडी हो जायेगी । वह अपना काम पूरा कर लेये इसके पहले कि सारे संसार की भाँखें खुलें और इस घटना के विरुद्ध उनमें प्रतिक्रिया पैदा हो ।

उनकी यह आशाएँ नयी दिल्ली, कलकत्ता आदि अन्य स्थानों में स्थित उनके राजनयिकों तथा ऐजेन्टों की इन रिपोर्टों पर आधारित थीं कि भारत में फूट और अराजकता फैल रही है । चीन को यह आश्वासन मिला था कि भारत सरकार लड़खड़ा रही है और सारा देश साम्यवादी विद्रोह के लिये तैयार है—वेर केवल इस बात की है कि उसे किसी बाहरी, सहानुभूतिपूर्ण निकटवर्ती साम्यवादी देश से बाह्य प्रोत्साहन मिल जाये ।

चीनी यह देखकर परेशान न हो गये कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तद-  
रुद्धा कर गिरने के वज्राय, अपनी प्रतिरक्षा तथा अपने अस्तित्व मान की  
यह भीषण धुनौती मिलने के कारण सारे राष्ट्र में एकता तथा देशभक्ति का  
अभूतपूर्व सीलाब उमट पड़ा। समस्त म सासकीय तथा विरोधी दलों ने सर्व-  
सम्मति से प्रस्ताव पास किया कि यह राष्ट्र जब तक निर्गुण सपथ करना  
रहगा जब तक आक्रमणकारी पूर्वी तरह से भारत भूमि से निराल नहीं दिये  
जायेंगे। भारतीय साम्यवादियों ने भी सबसे साथ यह दावा सी और चीनी  
आक्रमणकारियों को पिचकारा। इस दृश्य से पकिय की आँखें खुल गयीं।

२४ अक्टूबर को भारत द्वारा अपने प्रस्ताव रद्द दिये जाने के बाद चीन  
न पुनः आक्रमण शुरू किया और स्लेता तथा वोंमदीश में भारत को बुरी  
तरह पराजित किया। २० नवम्बर तक चीनी सेनाएँ नज्पुर से ४० मील के  
फास पर पुदहिन तक आ गयी थीं। इस प्रकार वे नेपा में अपनी दावा-  
रखा तक पहुँच गये थे। २१ नवम्बर की रात को चीनियों ने मुड बिराम की  
एक पत्नीय घोषणा कर दी और इस प्रकार भारत को यह सीखा नहीं दिया कि  
यह चीनी प्रस्ताव रद्द करे।

मुड-बिराम की घोषणा से भारत का चेतावनी दी गयी थी कि मुड फिर  
शुरू कर दिया जायेगा यदि भारतीय सेनाओं ने मैकमहॉन रेखा तक बढ़ने या  
पूर्वी सेक्टर में बागला और लाङ्ग क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयत्न किया,  
यदि मध्य सेक्टर में भारतीय सेना २० किलोमीटर पीछे नहीं हटी या बारा-  
हाली पर उसने अपना दासन काममें रखा और यदि पश्चिमी सेक्टर में  
भारतीय सेना २० किलोमीटर पीछे नहीं हटी या उसने इन ४३ चौकियों पर  
पुन अधिकार करने का प्रयत्न किया, जिन्हें चीनी अन्तिम आक्रमण में उन्हाड़  
चुके थे।

इस घोषणा के अन्तर्गत पश्चिमी सेक्टर में चीन ने यह दावा किया कि  
अपने अन्तिम आक्रमणों द्वारा वे जिन स्थानों पर पहुँच गये थे वही उनकी  
नवम्बर १९५६ की वास्तविक अधिकार रेखा है। एतद्वरूप चीनी भाग का  
अर्थ था कि भारतीय सेना अपनी ही भूमि पर २० किलोमीटर पीछे हट जाये।

जिस मुड का उन्होंने स्वयं शुरू किया था उस खाम करने के लिए अपनी  
जल्दी क्यों ?

पहली बात तो यह थी कि नवम्बर का गया था और किसी भी क्षण  
हिमालय की अमहनीय सर्दियाँ शुरू होने वाली थी—और ही हर चीज पर हिम  
की सपद यवनिता गिरने वाली थी। चीनियों के लिए तुरन्त निरन्धय करना  
आवश्यक था क्या उनके लिए यह उचित था कि आक्रमण की सीमा भारतीय  
सैदानों में आगे तक बढ़ा दें जब कि उनका संचार तंत्र हृद से ज्यादा फैल  
गया था और कुछ दिना में बर्फ से अवरुद्ध हो सकता था ? या यह उचित



या कि अच्छे समय में ही आक्रमण बन्द कर दें, अपने युद्ध लाभों को सुदृढ़ और लंगठित करें और शत्रु प्रदेश में आगे तक बढ़ कर लम्बी अवधि के युद्ध में पोंस कर हम लाभों को दाँव पर लगाने के बजाय श्राद्ध और अपमानित भारत को अपने द्वारा प्रस्तावित राजनैतिक समझौते को स्वीकार करने पर विवश करें ? इस दूसरी बात के लिए पेकिंग सरकार तैयार नहीं थी क्योंकि पर में और बाहर बहुत-सी गम्भीर समस्याएँ दरपेश थीं ।

भारत को इंग्लैंड और अमरीका से सैनिक सहायता मिलने की सम्भावना से चीन और भी डर गया था । ३ नवम्बर को अमरीकी अस्त्रों तथा सैनिक साधनों का पहला शेष हमदम हवाई अड्डे पर उतरा था और चीन को यह चेतावनी थी कि वह अपना आक्रमण रोक दे ।

वास्तव में अमरीका, कनाडा, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया ने स्वयं भारत को सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा था ताकि वह चीनी आक्रमण का मुकाबिला कर सके । ७५ देशों ने भारत को नैतिक सहायता दी थी ।

सारे संसार का जनमत भारत पर आक्रमण करने के लिए चीन को धिक्कार रहा था । चीन ने अब तक यह नहीं समझा था कि उसके विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया पैदा हो जायेगी जिससे चीन के एक शान्तिप्रिय देश होने का स्वरूप कलंकित हो जायेगा । वास्तव में साम्यवादी गुट में भी रुस तथा अन्य देशों ने चीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए धिक्कारा था ।

सोवियत संघ उस समय क्यूबा के गम्भीर मामले में फँसा हुआ था इसलिए पहले उसने भारत को यह राय दी कि पेकिंग के प्रक्सुर के प्रस्तावों को स्वीकार कर ले । बाद में यह पता चला कि ख़ुशख़बरी माओ त्सेतुंग से इस बात पर बहुत फुट्ट है कि माओ ने उनकी सारी योजना ही बिगाड़ दी थी । चीनी आक्रमणशीलता के सोवियत संघ द्वारा धिक्कारे जाने से इन दोनों विशाल साम्यवादी देशों के बीच दरार पड़नी शुरू हो गयी थी । वास्तव में ख़ुशख़बरी ने श्री नेहरू को स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि सोवियत संघ इस बात का दुरा नहीं मानेगा कि भारत ने चीन से अपनी रक्षा करने के लिए अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त की है ।

संयोग से भारत को इस अवसर यह भी पता चल गया कि अफ्रीकी-एशियायी देशों में उसके ऐसे बहुत कम मित्र हैं जो चीन के खिलाफ उसके साथ लड़े होने को तैयार होंगे । भारत को व्यापक सहानुभूति साम्यवादी देशों से मिली थी ।

५५ अफ्रीकी-एशियाई देशों में से केवल दो भारत की सहायता करने के लिए आगे बढ़े और १८ देशों ने भारत के प्रति केवल सहानुभूति प्रगट की, वह भी भारत द्वारा बहुत मनाये-जाने पर ।

इस बीच चीनी नेता क्षेत्र में अपनी दावा-रेखा तब तो पहुँच ही चुके थे। पश्चिमी सेक्टर में पूरे अक्सार्ड चिन प्रदेश पर कब्जा करने का उनका ध्येय-कालीन उद्देश्य भी पूरा हो चुका था। इससे ज्यादा भारतीय भूमि पर कब्जा करने पर ता मसार की भाँखों में अपने आप को सही साबित करना अगम्य हो जायेगा।

इन सब कारणों से चीनियों ने निश्चय किया कि बात बिगड़ने से पहले ही मुँह बन्द कर दें। क्योंकि उन्हें यह मान्य था कि मुँह बन्द करने के लिए उनके किसी भी प्रस्तावों को श्री नेहरू स्वीकार नहीं करेंगे और न समझौते की बात चीन करने के लिए समय बचा था—इसलिए २१ नवम्बर को चीन ने मुँह-विराम की एक पगोब घोषणा कर दी और समझौते के लिए अपनी शर्तें रख दी।

लेकिन गवास अब तब यह है कि चीन ने मुँह धुँक ही क्यों किया था ?

भारत निम्न सीमा समस्या पर भारत में बातें करने में चीन की ओर से एक बात बराबर स्पष्ट थी और वह थी कि चीन अक्सार्ड चिन क्षेत्र पर अपना पूर्ण अधिकार होने का जबरदस्त भ्रष्टव देता है। वास्तव में यह मायदा चीनी दृष्टिकोण से सारी बातचीत का आधार मूल था।

१९६० में चाउ इन साई नयी दिस्ती भाये थे और उन्होंने श्री नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा था। कि यदि भारत चीन को अक्सार्ड चिन प्रदेश दे दे तो चीन मैकमहान रेखा को स्वीकार करने को तैयार है। श्री नेहरू ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था।

बाद में २४ अक्टूबर के प्रस्तावों और २१ नवम्बर के एक पक्षीय मुँह विराम की शर्तों में भी चीन का यही मागठ था—वह मैकमहान रेखा स्वीकार करने को तैयार था लेकिन पूर्वी महात्त में एक इंच भूमि भी छोड़ने को तैयार नहीं था।

२१ नवम्बर के मुँह-विराम की शर्तों में चीन की यह भाग कि नितम्बर १९६२ के बजाय नवम्बर ५६ की पूर्वे स्थिति पुन स्थापित हो उनके इस इरादे को प्रमाणित करता है कि व न केवल ज्यादा बड़े भू-प्रदेश पर अपना अधिकार कायम रखना चाहत थे बल्कि सारे अक्सार्ड चिन तथा उनके आस-पास के इलाके से भारत को पूरी तरह निकाल देना चाहते थे। वास्तव में नवम्बर १९५६ के बाद ही भारत ने पूर्वी महात्त में कई नयी सैनिक चौकियाँ स्थापित की थीं और उस प्रदेश की चीनी चौकियों के बीच फँसी हुई थी।

२१ नवम्बर के मुँह-विराम की शर्तों के अनुसार पूर्वी सेक्टर में भारतीय तथा चीनी दावा-रेखाओं के बीच कोई विशेष अन्तर नहीं था। लेकिन पश्चिमी सेक्टर में चीनी सारे अक्सार्ड चिन प्रदेश पर (जिसमें हो कर निम्नलिखित सिक्किम मार्ग

तथा सहायक सड़कों का पूरा जाल गुजरता है) अपना एकाधिकार कायम रखना चाहते थे। वास्तव में इस बात को निश्चित करने के लिए कि यह प्रदेश उन्हीं के कब्जे में रहेगा, चीनियों ने कई श्रौर भी शर्तें लगा दी थी। भारत को स्पष्ट रूप से जता दिया गया था कि न तो उसे ८ सितम्बर १९६२ से पहले स्थापित की हुई स्थितियों को दोबारा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और न तिब्बत सिक्कांग मार्ग से कुछ दूर पर स्थिति अपनी ४३ चौकियों पर फिर से अधिकार करने की कोशिश करनी चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० गांगुली के अनुसार लद्दाख तथा नेफा के सीमान्त प्रदेशों पर चीनी दावे का आधार भूराजनीतिक है। सिक्कांग तथा तिब्बत (जो हिमाचल में शहलीर की तरह घंसे हुए हैं) चीन के अनुसार ऐशिया में साम्यवादी प्रभाव के प्रहरी हैं। इसलिए चीन लद्दाख के उन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था जिनमें होकर वह सिक्कांग तथा तिब्बत के बीच सड़कें बना सके।

“लद्दाख, तिब्बत तथा सिक्कांग पर जिस प्रभुत्व का स्वप्न चीन देख रहा था उसके तीन मुख्य जीवन सूत्र थे। इनमें से एक मार्ग सिक्कांग में लान्कर दर्रे तथा अक्साई मार्ग से होता हुआ यत्तोंक से कौटांग तक था। दूसरा मार्ग चुशुल और काराकोरम दर्रे से होता हुआ दमचोंक से सिक्कांग तक था और तीसरा मार्ग उत्तर प्रदेश में स्थित बाराहोती से तिब्बत तक था।”

सोवियत तुर्किस्तान तथा सिक्कांग के बीच सीमा अनिश्चित होने के कारण (जो कभी भी संघर्ष की जड़ बन सकता था) और सोवियत संघ तथा चीन के बीच की छाई दिन व दिन चौड़ी होने की वजह से चीन के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि मध्य एशिया के इस बुरख प्रान्त से वह कुशल तथा तुरन्त संचार सम्बन्ध रहे।

आज यह आम तथ्य है कि जब रूस ने भारत के प्रति चीन के आक्रमणशील व्यवहार को विस्कार था तो उनके पीछे मॉस्को तथा पेंकिंग के बीच आदर्श सम्बन्धी मतभेद के प्रतिबिम्ब और भी कारण थे। वास्तव में १९५९ में ही भारत-तिब्बत सीमा पर चीन की नीति की सोवियत संघ ने कड़ी आलोचना की थी। सोवियत दृष्टिकोण यह था कि इस प्रकार की नीति पूर्व-पश्चिम के शीत युद्ध में साम्यवादी गुट के दांव-पेचों के विरुद्ध पड़ती थी क्योंकि इससे यह उत्तरा था कि इससे डर कर आपस देख पश्चिम की ओर मुक जाएंगे।

लेकिन वास्तव में सोवियत संघ को इस बात की चिन्ता थी कि मध्य एशिया में अपने सीमान्त को वह अनियंत्रित और विस्तारवादी चीन से सुरक्षित रहे। पेंकिंग सरकार ने अपनी इस नीति को कभी छिपा कर नहीं रखा था कि वह

पुरानी 'दममान संधियों' को सुधारना चाहती है और इन संधियों में उसने अनुसार एक बड़ा जोड़ी जिसने ज़ाराफीन हम मया प्रतिस्पर्धावादी चीन के बीच मित्रता की सीमा निर्धारित की थी ।

वर्षा १९५५ चिन के बीच निर्मित तिब्बत-मिकवाग मार्ग इस उद्देश्य से बनाया गया था कि उसके द्वारा सिक्किम को इस चीन सीमा पर चीन की आवश्यकता गतिमान हो सके इसलिए जब भारत ने अपनी भूमि पर इस सड़क के बनाने पर आपत्ति की तो गोविंदन हम उनके साथ था ।

एक दमरोही लेखा के अनुसार कम के राजनीतिज्ञों के मन में गंदा यह भय रहता है कि बहुत जल्दी चीन, चाक्रमण द्वारा या राजनैतिक उत्पन्न गये राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर पूर्ण प्रभाव प्राप्त न करने ऐसा होने पर साक्ष्यन मध्य पाव से फिर आयेगा और पूरे साक्ष्यन मूल्य पूर्व की पक्षों से अधिक गहरा हो जाएगा ।

यदि और राष्ट्रवादी नीति के कारण चीन गोविंदन मध्य में अपने सम्बंध विगाटना चला गया तो उसका एक पक्ष यह होगा कि भारत की सुरक्षा में कम अधिक 'दलचम्पी' लेने लगेगा और पाकिस्तान का अपने नए मित्र चीन से हटा प्रचार से तात्पर्य का प्रयत्न किया जायेगा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यह बड़ा समस्या है जिसमें हम तथा परिषदी गतिशील की समान दिग्दर्शी है ।

मुद्रा मुक्त करने के साथ कारणों में एक कारण यह भी था कि चीन भारत का नीचा दिखाना चाहता था । बाकी समय से यह बात प्रचलित थी कि ऐगिया का मतलब प्राप्त करने के लिए चीन और भारत में होठ लगी हुई है यह होठ साम्यवादी और जनतन्त्रात्मक आदर्शों के बीच है जिसके प्रतीक चीन और भारत हैं ।

एगिया और अफीका के राष्ट्रों को चीन यह दिखाना चाहता था कि ऐगिया का नेता चीन है और भारत की अफ्रीका क्या है ? इस उद्देश्य से चीनिया ने भारत को अपमानित करने का तरीका निकाल लिया । सन १९६२ के युद्ध से चीन ने काफी सीमा तक यह सिद्ध कर दिया कि दक्षिण-पूर्व पर उसका एकदम प्रभाव है ।

सन १९६२ के युद्ध से भारत के आर्थिक विकास को भी जबरदस्त धक्का पहुँचा था और चीन की दृष्टि में, इससे यह साबित होता था कि मानवी विकास के लिए जनतन्त्रात्मक तरीका अच्छा है, साम्यवादी तरीका उत्तम है ।

X X X

इस तल्लि-मुद्रा के ओर से चीनी निम्न की सीमा पर करके भारत में तेजी से घुसने जा रहे थे, ऊपर अफीकी और एगियाई देग इन घटनाओं से अफीक और उत्तरी हो रहे थे । उन्होंने साथ मिलकर भारत-चीन युद्ध का धन करने के लिए और भारत चीन भाड़े की घातिपूर्ण उग से मुश्किलों के लिए दोनों पक्षों को राखी करने के प्रयत्न शुरू किये ।

लंका के प्रधान मन्त्री श्रीमती सिरिभावो बन्दरनायक के पहल करने पर अफ्रीका तथा एशिया के छः देश—बर्मा, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, घाना, संयुक्त अरब तथा लंका—१०-१२ दिसम्बर के बीच कोलम्बो में मिले। (इस सम्मेलन के लिए इन छः देशों को निमन्त्रण भेजने के कुछ ही घंटों में, चीनियों ने बुद्ध-विराम की एकपक्षीय घोषणा कर दी थी।)

संक्षिप्त में, कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव यह थे :

(१) पश्चिम सेक्टर : नवम्बर २१ तथा २२ के प्रधानमन्त्री चाट इन-लाई के प्रधान मन्त्री नेहरू को लिखे गये पत्रों के अनुसार चीनी सेना २० किलोमीटर पीछे हट जाय भारतीय सेना अपनी वर्तमान सैनिक स्थितियों पर कायम रहे। सीमा सम्बन्धी झगड़े का अन्तिम फैसला होने तक, चीनी अग्रगण्य के कारण खाली हो जाने वाले क्षेत्र विसैन्यीकरण किया हुआ इलाका होगा जिसका प्रशासन, आपसी समझौते से, दोनों पक्षों की प्रशासकीय चौकियाँ करेंगी—इस निर्दय पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि भारत और चीन की उस प्रवेशों में पहले क्या स्थिति थी।

(२) पूर्वी सेक्टर : अपनी-अपनी बुद्ध विराम रेखाओं को दोनों सरकारों द्वारा मान्य अपनी-अपनी वास्तविक अधिकार-रेखाओं से निर्धारित होना चाहिए इस सेक्टर के याकी क्षेत्रों के बारे में दोनों देश वाद में, आपसी वाद-विवाद के बाद, निदय ले सकते हैं।

इस धारा का स्पष्टीकरण सम्मेलन ने इस प्रकार किया कि इन प्रस्तावों के अन्तर्गत भारतीय सेना, उन दो क्षेत्रों को छोड़ कर जिनके बारे में दोनों सरकारों में मतभेद था, वास्तविक अधिकार रेखा के दक्षिण तक अर्थात् मैकमहॉन रेखा तक बढ़ सकती है। इसी प्रकार, उक्त दो क्षेत्रों को छोड़ कर, चीनी सेना मैकमहॉन रेखा तक बढ़ सकती है।

जिन दो क्षेत्रों की तरफ संकेत था वह थे त्से जांग अर्थात् भांगला तथा लांगजू क्षेत्र। इन दोनों स्थानों में वास्तविक अधिकार रेखा के बारे में भारत तथा चीन में मतभेद था।

(३) मध्य सेक्टर : इस सेक्टर की समस्याओं को बिना बुद्ध किये शांति-पूर्ण ढंग से सुलझा लेना चाहिए।

भारत को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया गया कि कोलम्बो सम्मेलन की यह इच्छा है कि इस सेक्टर में पूर्व स्थिति कायम रखी जाये और दोनों में से कोई पक्ष इस पूर्व स्थिति को भंग करने का प्रयत्न न करे।

कोलम्बो सम्मेलन ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि इन प्रस्तावों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया होने का अन्तिम रूप से सीमा निर्धारण करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दोनों में से कोई सरकार अपने को दुबिधापूर्ण स्थिति में नहीं पायेगी।

जनवरी १९६३ के पहल हफ्ता में जब सभा के प्रधान मंत्री तथा दूतों गिया के विदेश मंत्री कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों को समझाने के लिए पश्चिम यूरोप तथा चीनी सरकार न पौरन इस बात की घोषणा की कि उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है। लेकिन बाद के चीनी जर्नल और उनके द्वारा इन प्रस्तावों की व्याख्या में यह स्पष्ट हो गया कि इन प्रस्तावों का स्वीकार करने का कार्या-चित्र करने की चीन की कोई नीयत नहीं है।

कुछ समय बाद श्रीमती वेङ्गनायक को मिले गए एक पत्र में चाउ-इन-मार्ग ने इस बात पर धाड़ट किया कि यह प्रस्ताव कि भारतीय सैनिक अपने वर्तमान स्थानों पर ही रहे केवल पाँचवीं सेक्टर में नहीं पूरे भारत चीन सीमा प्रदेश पर लागू होना चाहिए।

पूर्वी सेक्टर के बारे में चीनी सरकार ने यह भाग की कि चीनी सैनिकों द्वारा जानी बिदे हुए उन प्रदेशों में, जो ७ नवम्बर १९६६ की वास्तविक अधिकार रेखा के दक्षिण में हैं, भारतीय सेना को फिर से नहीं घुसना चाहिए जबकि केवल अपने प्रशासकीय कमचारियों को, भारत-रक्षा के लिए आवश्यक प्रस्तावों में सैन्य बर्तने भेजना चाहिए जैसा भारत सरकार पहले भी करती थी। साथ ही पत्र में यह कहा गया था, चीन पूर्वी सेक्टर के लो जंग (बागना पहाड़ी), तथा सागजू क्षेत्रों में, मध्य सेक्टर के यू—जे (बाराहोनी) क्षेत्र में और पश्चिमी सेक्टर के उन क्षेत्रों में (जिसमें अभी भारत में ४३ चौकियाँ कायम की थी) प्रशासकीय चेक-पोंटियाँ स्थापित नहीं करेगा किंतु इस तर्क पर कि भारतीय सैनिक या प्रशासकीय कमचारी इन क्षेत्रों में न घुसें।

यह भाग भी उस स्पष्टीकरण के खिलाफ थी जो कोलम्बो शस्त्रियों ने भारत को दिया था। उस स्पष्टीकरण के अनुसार पश्चिमी सेक्टर (सहास) में भारतीय चौकियाँ वास्तविक अधिकार रेखा के किनारे किनारे की और चीनी सैनिकों के २० किलोमीटर पीछे हट जाने में सक्षम हुए क्षेत्र का प्रशासन दोनों पक्षा की प्रशासन-चौकियों को करना था। कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों का यह एक 'सारभूत भाग था। इन चौकियों के समूह, उनकी संख्या और स्थिति के बारे में 'भारत सरकार तथा चीन सरकार के बीच समझौता होना आवश्यक' था।

कोलम्बो सम्मेलन के अनुसार इस व्यवस्था से 'इस क्षेत्र में भारत तथा चीन के पहल में उपस्थित होने के कारण प्राप्त अधिकारों को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी।' (यह क्षेत्र २,५०० वर्गमील का था जहाँ से २० अक्टूबर के चीनी आक्रमण के कारण, भारतीय सैनिक सहास में पीछे खेच दिए गए थे। चीन ने पश्चिम में अपनी सैनिक स्थितियों से पीछे हटने से इन्कार कर दिया है।)

चीन की दृष्टिकोण प्रतिक्रिया के विपरीत भारत सरकार ने कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया।

इसके फलस्वरूप जो गतिरोध पैदा हुआ वह आज तक चल रहा है। आज स्थिति यह कि पूर्व में चीन मैकमहॉन रेखा तक पीछे हट गए हैं लेकिन पश्चिम में, लद्दाख में, अब भी १५,००० वर्ग मील भारतीय प्रदेश पर उनका कब्जा है।

इसके बाद, १ मार्च १९६३ को चीनी सरकार ने घोषणा की कि भारत-चीनी सीमा पर विभिन्न स्थानों पर २६ चेक चौकियां बना रहे हैं। लोक सभा में दिये गए श्री नेहरू के एक वक्तव्य के अनुसार इनमें से सात चौकियां एक तरफा रूप से पश्चिम सेक्टर के विसैन्यीकरण किये हुए प्रदेश में बनायी गयी थी। इस प्रकार चीन ने कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों को भंग किया या क्योंकि प्रस्तावों के अनुसार उक्त प्रदेश में दोनों देशों की प्रशासकीय चौकियां स्थापित होना आवश्यक था।

पूर्वी सेक्टर के विसैन्यीकरण किये हुए प्रदेशों में, जिसमें केवल १६ प्रशासकीय चौकियां अधिकृत थी, चीन की एक पक्षीय घोषणा के अनुसार ५२ मिली-गुली सैनिक और प्रशासकीय चौकियां स्थापित की गयी थीं। इन चौकियों के अलावा सीमा के किनारे, विशेषतः पूर्वी सेक्टर में काफी गश्तें लगायी जाने लगी थी।

वास्तव में, एक पक्षीय बुद्ध-विराम के बाद, तिब्बत में और सीमा के पास चीन ने अपनी सेना को बढ़ा लिया था। हमारी सीमा के किनारे, अक्टूबर १९६२ के मुकाबले, चीन की शक्ति अब कहीं अधिक बढ़ गयी थी। परिस्थिति में एक और विकास यह हुआ था कि चीनी सेना ऐसे कैम्पों तथा मार्च के स्थानों तक पहुँच गयी थी जो सन १९६२ की तुलना में भारतीय सीमा के और भी निकट हैं। साथ ही यह भी देखा गया था कि भारतीय सीमा के पास के तिब्बती प्रदेश में बैरेकों, तोप-अभिस्थापनों, गोदामों तथा हवाई अड्डों को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है।

## एक व्यक्ति के उठान की हत्या कैसे हुई ?

सन् १९६२ में भारत की स्थिति में माघो के हस्तक्षेप के कारण एक व्यक्ति की जमीनमय उठान बीच में ही बट गयी ।

यदि सन् १९६२ की यह दुष्टता न होनी ता मेसिटनेट जारल 'बजनी' कील बहुत दूर तक तरबकी परत—'गायद प्रधान सेनापति में भी यहा कोई पर उह प्राप्त होना और देग के इतिहास में व अपने लिए एक स्थान बना लेने । वास्तव में दलेम हूंगन ने अपनी पुस्तक 'नहर के बाद कील ?' में जिन सम्भव उत्तराधिकारियों का डिक किया है उनमें कील भी है ।

मार्च १९६२ में अचानक पराभव होने के समय तक सफलता की सीढ़ी पर जनरल कील की प्रगति बिजला की तरह तेज थीर धाँसे धींधिया देने वाली थी । यदि माघो का साथ भारत पर नहीं पड़ता तो कोई नहीं कह सकता था कि भाग्य का ज्वार कील को किस ऊँचाइयों पर पहुँचा देता ।

इस विचार से मन गम्भीर हो जाता है कि मानवी महत्वाकांक्षियों के बहु-रूपदर्शी यन्त्र में बनने वाले प्रतिरूप जरा से मटके से मिट जाने हैं । अतः ही मरता है कि माघो ने घनबाने में भारत के 'राजनैतिक मय' से एक भावी भयपूर्व की हमला के लिए हटा दिया है । यह कहना सायद अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि स्वयं कील तथा कुछ धीर लोग यह विश्वास करने से कि इस भूमिका का अंदा करने के लिए उनके पास पर्याप्त नीजल और क्षमता है । महत्वाकांक्षा तो उनमें भी हो, उनके अतिरिक्त अय मूल गुण भी थे—असाधारण पट्ट-क्षमता तथा शक्ति, गहरा राष्ट्रप्रेम, पूर्ण आत्म विश्वास, आत्म गौरवपूर्ण अहम भाव और राजनैतिक समझ । इसके अलावा देश के सामाजिक जीवन में उनके



ठोस तथा महत्त्वपूर्ण सम्पर्क थे और सेना के युवक अफसरों में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी।

'विज्जी' कौल राजनीतिज्ञों के बीच जनरल थे और जनरलों के बीच राजनीतिज्ञ। यह उनकी अद्भुत विशेषता थी और बाद में यही उनके पराभव का कारण बनी—उनके साथी जनरल इस बात से चिढ़ते और जलते थे कि राजधामी की राजनैतिक गोष्ठी-कक्षों में वह अत्यन्त क्रियाशील रहते हैं और 'राजनीतिज्ञों' को मूलतः ऐसे महत्त्वाकांक्षी प्रवर सैनिक अधिकारी हैं; मरोसा नहीं था जिसकी सॉन्ड-बाँठ ऊँचे-ऊँचे लोगों से थी। जब तक कौल अपने उच्च स्थान पर धारुढ़ थे तब तक सब ठीक था—उनके प्रशंसकों का दायरा बढ़ता गया और सेना में भी उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गयी।

अंग्रेजी सैनिक परम्परा से प्रभावित भारत के वरिष्ठ सैनिक अधिकारी राजनीति से ऐसे बचते थे जैसे किसी संक्रमक रोग से और इसलिए कौल की राजनैतिक युक्तिचालों को देखकर वे उखड़ जाते थे। और बाद में जब अपने से ऊँचे अधिकारियों के सिर से ऊपर कौल सैनिक हेडक्वार्टर के मामलों में बेजा रूप से दखल देने लगे तो उखड़ने के बजाय इन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के अन्दर क्रोध की भावना पैदा होने लगी। बस महसूस करने लगे थे कि इस प्रकार का व्यवहार सैनिक व्यवहार संहिता के विरुद्ध है। लेकिन जहाँ तक कौल का सम्बन्ध था, वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की इस मनोवृत्ति से उनका पता कमजोर हो गया था।

वास्तव में कौल अपने साथी जनरलों से भिन्न थे। और हर सम्भव रूप से वह अपनी इस भिन्नता को जताने से चूकते नहीं थे। अंग्रेजी जनरलों के नमूने पर बने हुए भारतीय जनरलों की आदतों से भिन्न, कौल न शराब पीते थे, न सिगरेट, हॉसी-खेल, डान्स-पार्टी और पश्चिमी षव के सामाजिक जीवन में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका अधीर, नाटकीय व्यक्तित्व दूसरों को उनकी ओर ध्यान देने के लिए बिलस करता था। १९४२-४३ के धर्मा युद्ध में दो वर्ष तक जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम करता व्यर्थ नहीं गया था। पत्र और पत्रकारी से कौल की खूब पटती थी; पत्रकारों के प्रति वह मैत्री तथा सद्भावना-पूर्ण थे, दिल खोलकर बातें करते थे और पत्रों की बिलचस्प मसाला प्रदान करते थे।

रमल विश्वास करते थे कि जन नेता को अपने व्यक्तित्व के चारों ओर एक तिलस्म पैदा कर लेना चाहिए। जनरल मॉन्टगोमरी का भी यही विश्वास था। अपनी विद्युत्तीय स्फूर्ति, साहसपूर्णता, भयहीनता और योगियों समान जीवन के बल पर कौल ने अपने व्यक्तित्व के चारों तरफ भी एक तिलस्म बुन लिया था। वेलेस हेगन ने लिखा है कि कौल को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई अविश्वसनीय शक्ति से मुलाकात करने के लिए तेजी से आया जा रहा हो।

प्रदत्तनील स्वभाव का होने के कारण, यह अपने साथी दफ्तरों के मामले धक्कर यह जता देता था कि प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री पर उनका विशेष प्रभाव है और इससे दूसरे अधिकारी चिढ़ जाते थे। यह माफी अधिकारियों पर यह भी स्पष्ट कर दिया करने के कि महत्त्वपूर्ण राजकीय मामलों में प्रधान मंत्री उनका सलाह लेते हैं और ऐसे कथन बीन के सिलाफ़ उनके माफी अधिकारियों के मन में खूब का एक और बीज बो देता था।

अपने सम्मान दिनों में बीन ने कई बरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को नाराज कर दिया था और इस प्रकार सेना में उनके अनेक शत्रु बन गये थे। जन-प्रबन्धन १९६२ में बीन का पतन हुआ तो वे सब बीन मित्रों की तरह उन पर टूट पड़े।

बीन, वास्तव में प्रधान मंत्री के निबटनम और विद्रोह व्यक्तियों में से थे। स्वतन्त्रता मिलने के बाद उनको कई मिशन दिये गये थे—राष्ट्र प्रबुद्धता को बढ़ावाने के काम का पर्यवेक्षण करने के लिए वे चीनगर भेजे गये थे—और इनमें राजनैतिक तथा सैनिक दोनों में उन्हें एक अद्भुत स्थिति प्राप्त हो गयी थी। इसके पश्चात् सभी क्षेत्रों के प्रबन्धकारी तथा अपने को अपने बचाने की इच्छा रखने वाले लोग उन्हें घेरे रहने लगे।

बीन को इन लोगों से आनन्द मिलता था। तरह-तरह के लोग उनके घर और कार्यालय के बाहर भीड़ लगाए रहते थे और वे उनमें से हर एक से मिलते थे हर एक को सुनते थे। लोग उनके पास अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ, नीकरी सम्बन्धी शिकायतें, यही सब कि राजनैतिक उन्मत्त भी लाते थे हल करवाने के लिए या इसलिए कि उनकी दास्तानें यही नेहरू के कारोबार पट्टे पर जायें। बीन इन सब लोगों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करते थे और इस तरह सब की मित्रता और बराबरी उन्हें प्राप्त हो जाती थी।

भारत के बरिष्ठ सैनिक अधिकारियों में केवल बीन में ही यह गुण था कि वह राजनीति में पटु थे—यही नहीं उनमें राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ भी थीं। साथ ही अपनी सारी मानसिक धातुनिष्ठा के बावजूद बीन को ज्योतिष में विश्वास था और एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वह भारत के शासक बनेंगे।

लेकिन इस सबके अलावा, बीन में अद्भुत मजबूत तथा कार्यकारी क्षमता थी, साल कीटों के अत्यन्त सघन जंगल के बीच से अपना रास्ता काट कर वह काम करवा लेते थे। अत्यन्त कम समय में, 'अपने घोष बनाओ' की नीति लागू करते अम्बाला में सैनिकों के लिए मकान बने करने का फरिदमा दिया कर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। यह काम उन्होंने मराठूर ४ के पैदली हिंदी-जन से कराया था। इन्होंने प्रसिद्ध हिंदीजन में अपना छोटा काम कराने की भी उनके रुढ़िवादी साथी दफ्तरों ने बीन के सिलाफ़ ही आकांक्षा थी।

जब नेफा युद्ध में इस ढंके पैदली डिबीजन ने अपनी रण-क्षमता का अत्यन्त असतुल्यजनक परिचय दिया तो इन्हीं रुढ़िवादी अफसरों ने इसका कारण यह बताया कि इस डिबीजन के बीर सैनिकों को पहले राज-मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया जा चुका था जिसकी वजह से वे काफ़ी समय तक समर-कार्य से दूर रहे थे और उनका धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया था ।

जब कौल, संयुक्त राष्ट्र के तटस्थ प्रत्यावर्तन कमीशन के सभापति, जनरल थिर्मैया के स्टाफ़ प्रमुख होकर कोरिया गये तो उन्होंने सभाचार संसार में सन-सनी पैदा कर दी और उनके व्यक्तित्व के चारों ओर प्रतिवादों की भड़की लग गयी । कोरिया में स्थित भारतीय दस्ता दो पक्षों में विभक्त हो गया : एक चीनपक्षी, एक अमरीका पक्षी । चीनपक्षी दल के नेता कौल थे और अमरीका पक्षी दल के नेता जनरल थिर्मैया ।

यह स्पष्ट था कि कौल की चीनियों से बहुत पटती थी । चीन ने कौल को राज्य प्रतिधि के रूप में आमंत्रित किया और जहाँ भी वह गये उनका शौरदार स्वागत हुआ । कौल पर यह भी आरोप लगाया गया कि जनरल थिर्मैया की तथाकथित अमरीकी पक्षी कार्यवाहियों के खिलाफ़ वह प्रधान मंत्री को सूचनाएँ भेजते रहते हैं । इस सन्देह के कारण सैनिक दायरे में उनके विरुद्ध कानूनी अभियंता फैल गयी । सौम्य स्वभाव के, सौजन्यपूर्ण थिर्मैया भारतीय सेना के अधिकारी वर्ग के आदर्श थे और इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को धिक्कारा जिसने ऐसे अच्छे व्यक्ति तथा बरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ़ जासूसी की थी । वास्तव में यदि श्री नेहरू और मेनन को कौल में व्यक्तित्वगत दिलचस्पी न होती तो सैनिक पदसोपान उन्हें कभी मेजर जनरल के पद से आगे नहीं बढ़ने देता ।

प्रधान सेनापति की मर्जी के खिलाफ़ और कृष्ण मेनन की विद पर कौल को पहले लेफ़्टिनेंट जनरल बनाया गया और फिर क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किया गया । तत्कालीन सी० जी० एस०, लेफ़्टिनेंट जनरल एल० पी० सेन के अनुसार क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर कौल की नियुक्ति सैनिक चुनाव मंडल के द्वारा नहीं हुई थी । लेकिन “कौल के अलावा मेनन किसी और की तरफ़ देखने को भी तैयार नहीं थे और इसलिए थिर्मैया कौल को स्वीकार करने पर मजबूर हो गये थे—लेकिन काफ़ी गम्भीर भगड़े के बाद । थिर्मैया स्वभाव से सज्जन थे इसलिए कौल के पूछने पर उन्होंने इन्कार किया कि यह बात उनके त्याग-पत्र देने का कारण थी ।”

लेकिन क्वार्टर मास्टर जनरल की हैसियत से कौल अत्यन्त सफल साबित हुए । अपनी शीघ्र पहल-क्षमता से उन्होंने उत्तरी सीमान्त पर सड़कें बनाने का एक तद्वि-प्रोग्राम शुरू करा दिया हालाँकि १९६२ के चीनी आक्रमण के समय यह प्रोग्राम बीच में ही स्थगित करना पड़ा ।

वास्तविक युद्ध का रण अनुभव न होना कोई बड़ी कमी नहीं थी। जिन लोगों ने द्वितीय महायुद्ध में बड़ा नाम कमाया वे उसके प्रारम्भ होने समय केवल घबर स्टॉफ अधिकारी थे। द्वितीय महायुद्ध के पूरे दौरान में जनरल कलवल सिंह उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर पठान कबीलों की जमी मरगर्भी पर निगाह रखन का ही काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी १९४७-४८ के कश्मीर युद्ध में कलवल सिंह ने बार कमान्डर की हैमियन में एक प्रभुभुन सेना की हान का परिचय दिया था।

यह होने हुए भी साथी अधिकारियों को कौल के खिलाफ यह आपत्ति थी कि न केवल गत महायुद्ध या कश्मीर युद्ध में उन्होंने कोई रण अनुभव प्राप्त किया था बल्कि द्वितीय महायुद्ध भर, अपने नियामक वर्गों में, व केवल एक सक्षम कोर अधिकारी रहे थे और वास्तविक रण के निवृत्तम व सिर्फ नमी पहुँचे थे जब एक माटर यानावान बटालियन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें प्रारम्भिक भेजा गया था।

घराबी कौल के खिलाफ बराबर यह प्रतिकूल भाव रहा कि उन्हें रण अनुभव नहीं है और उनके साथी अधिकारियों ने उन्हें कभी एक योद्धा के रूप में स्वीकार नहीं किया। साथ यह है कि कौल को रण स्थल पर सैनिकों को कमाण्ड करने का पहला योद्धा मन १९६२ में नेफा मोर्चे पर ही मिला और वह भी कोर कमान्डर की हैसियत से।

अपनी पुस्तक 'अनकही कहानी' में स्वयं कौल इस बारे में एक अजीब-सा धाम-तकोच प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें कभी एक बटालियन कमाण्ड करने का अवसर नहीं मिला। वह विस्तारपूर्वक बताते हैं कि बहुत कोशिशें करने के बावजूद, भाग्य की किसी न किसी चाल के कारण, वे किसी पैदली दल के निरुद्ध फटक भी नहीं सके। काफी समय के बाद, १९४९ में—पश्चात् में स्थित एक पैदली ब्रिगेड का कमाण्ड करने के लिए नियुक्त किये गये और उसके बाद उन्होंने अम्बाना में नियत प्रसिद्ध ४ वे पैदली डिवीजन को कमाण्ड किया।

१९६१ में सी० जी० एस० के पद पर नियुक्त होने पर कौल इस समस्या की विशालता और अनिवार्यता के बारे में अत्यन्त सजग हो गये कि उत्तरी सीमान्त की प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और सगठित करना सबसे पहली आवश्यकता है। अतः इस काम को उन्होंने अपनी स्वाभाविक क्षमता और स्मृति के साथ औरत हाथ में ले लिया। परिस्थिति को निजी तौर पर धाकने और प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का सही अंदाज लगाने के लिए उन्होंने स्वयं सहाय्य तपा प्रयत्न इसका के अधिनियम क्षेत्रों का दौरा किया। कौल ने मुझे बताया कि जिन १६ यहीनों में वह उस पद पर रहे उनमें उन्होंने रक्षा मंत्री को इस विषय पर आठ पत्र लिखे कि उत्तरी सीमान्त की रक्षा के बाधों पर

युद्ध करने के लिए सेना को उचित और पर्याप्त सैनिक साधन प्रदान करना उस समय की प्राथमिक प्रतिरक्षा आवश्यकता है।

अगस्त १९६१ में श्री मेनन को लिखे हुए एक पत्र में कौल ने स्पष्ट रूप से कहा था “यदि आवश्यक सैनिक साधनों को फ़ौरन प्राप्त नहीं किया गया तो देश पराजित हो जायेगा।” मेनन ने वाक्य के अन्तिम भाग पर आपत्ति की और कौल से उसे बदलने को कहा लेकिन कौल ने इनकार कर दिया तथा प्रायःपूर्णक वाक्य को यथास्थान रखा।

कौल पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे ‘अग्रिम नीति’ जालू कर दी थी और १९६१ के पतझड़ में सीमान्त को दूरस्थ स्थितियों पर अघायुन्ध चौकियाँ कायम करवा दी थीं जिसके कारण चीन बिड़ गया था और उसने अगले वर्ष ही ऐसे मौके पर आक्रमण कर दिया था जब भारत कतई तैयार नहीं था।

वेलेस हेगन के अनुसार कौल ने धुविता जाल से मेनन को पीछे छोड़ कर, सीधे श्री नेहरू से इस बात की अनुमति ले ली थी कि भारतीय भूमि पर बनी चीनी चौकियों का मुकाबला करने के लिए अग्रिम चेक-चौकियाँ स्थापित कर ली जायें। मेनन का बहुत दिनों यह आदेश कि भारतीय गश्ती दस्ते किसी हालत में चौकियों से मुठभेड़ न करें, रह कर दिया गया और भारतीय सैनिकों को यह आदेश दिया गया कि अपनी चौकियाँ पर डटे रहें और यदि चीनी उन्हें भारतीय भूमि पर स्थित किसी चीकी से निकालने की कोशिश करें तो वे गोली चलाना शुरू कर दें।

कौल को बिफकारने वाले लोगो ने उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सीमान्त पर एक उत्तेजक नीति को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया था बिना यह ध्यान दिये कि सैनिक रूप से उसकी पुष्टि करना असम्भव है। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधान सेनापति जनरल थिमैया ने अग्रिम नीति को कार्यान्वित करने के लिए कौल की योजना का विरोध किया था क्योंकि वह जानते थे कि संसार-सन्ध के पूर्णतः अव्यवस्थित होने के कारण यह प्रयत्न मात्र एक भयानक स्वप्न साबित होगा।

लेकिन अपनी पुस्तक ‘अनकही कहानी’ में कौल ने स्पष्ट किया है कि ‘अग्रिम नीति’ को कार्यान्वित करने का फैसला श्री नेहरू के कार्यालय में हुई एक मीटिंग में लिया गया था जिसमें उनके और कौल के अलावा श्री मेनन और जनरल थापर भी उपस्थित थे।

सैनिक भान-चित्र पर दिखाये गये कई चीनी अतिक्रमणों को देख कर श्री नेहरू ने उस मीटिंग में कहा था कि वो पक्ष प्रतीक रूप में एक चीकी भी स्थापित कर देगा वह उस विशेष क्षेत्रांश पर अपना अधिकार स्थापित करने में

सकन होगा क्योंकि वास्तविक अधिभार दन में मे नी भाग बाभूनी अधिभार भी माना जाता है । और यदि चीनी चीनिया घना सकन थे तो हम क्या नहीं बना सकत ?

"उनमे (ची नेहरू से) कहा गया कि सख्या और सभार सम्बन्धी कटिमाइयो के कारण हम चीनियो से दुरा होड में नहीं जीत सकने । यदि उनका मुकाबिला करने के लिए हमने और चीनियों स्थापित की तो सामाजिक दृष्टिकोण से हम उन चीनियों का पोषण नहीं कर पायेंगे । यह भी कहा गया कि अपने अधिक उत्तम सैनिक साधनो के जोर से वह हमारी छोटी छोटी चीनियों की स्थिति ऐसी कर सकने हैं कि वे टिकने में असमर्थ हो जायें ।

"इसके बाद एक विवाद दुरु हो गया जिसका नतीजा मेरे ख्याल से यह निकला कि क्योंकि इस बात की कोई सम्भावना नहीं थी कि चीन भारत के साथ युद्ध छेडे, इसका कोई कारण नहीं था कि जहाँ तक चीनियों स्थापित करने का प्रश्न है हम चीनियों के साथ घातकता का धन न लेने और बुद्धि-वीर्य का युद्ध न करें । यदि वे एक क्षेत्र में घागे बडे तो हमे दूसरे में घागे बड जाना चाहिए ।

"अर्थात् चीनियो के साथ होड कायम रखी जाये और जहाँ तक सम्भव हो, उन क्षेत्रों में जिन्हें हम पूर्णरूप से भारत का घन सम्भवते हैं, अपनी कुछ प्रतीक रूपी चीनियों स्थापित की जायें । हमारे इस प्रतिरक्षा कदम से चीन अधिक से अधिक बिड़ जायेगा लेकिन दमने अधिक और कुठ न होगी । मेरे ख्याल मे इस प्रकार सीमान्त के सम्बन्ध न हमारी यह नयी नीति प्रतिपादित हुई थी (जिसे कुछ लोग 'अधिम नीति' भी कहते हैं) ।"

मैजिन इस बात पर विद्वान्त करने के भी कारण हैं कि ५ अक्टूबर, १९६२ तक (जब गोले उनके चारों तरफ छूटने लगे) स्वयं जनरल चीन यह नहीं समझने थे कि चीनी भारत पर आक्रमण शुरू कर दिये । 'अनकही कहानी' में वे स्वीकार करते हैं कि जब तक अभी और सगठित नहीं हुई तब तक "विभिन्न रेडवाटरो के अधिकाइयो के मन मे सामान्य इस बारे में सन्देह था कि चीन और भारत के बीच युद्ध इतनी जल्दी शुरू हो सकता है । इसलिए हम इस सम्भावित सकट के प्रति बहुत कम सज्ज और मजेल थे । स्पर्धा मे भागे होने के बजाय हम बहुत देर मे जागे और वह भी गामला टोला क्षेत्र मे चीनी आक्रमण के बाद । इसके बाद घटनाक्रम इतना तेज हो गया कि हमारे पांव उलझ गये ।"

सन् १९६१ के अन्त तक लद्दाख और नेफा प्रदेशों में हमने ५० से अधिक चौकियाँ बना दी थीं। कौल का यह मत है कि बिरोवी पक्षों तथा जनमत के दबाव के कारण श्री नेहरू को यह छतरनाक नीति अपनानी पड़ी थी यह सोच कर कि इससे देश के लिए कोई-विशेष संकट खड़ा नहीं होगा।

केवल वही लोग जो पूर्वाग्रह से अन्धे हैं कौल पर नेफा में भारत की दुर्दशा का सारा अपराध थोप सकते हैं—विभिन्न सीमाओं तक इस अपराध में कई लोग साक्षीदार हैं, अन्तर केवल इतना है कि दुर्दशा के समय कौल नेफा में स्थित ४थी कोर के कमान्डर थे।

यदि यह सही है कि कौल एक 'अनित्यहीन बेवृत्तिवादी 'अग्रिम नीति' को कार्यान्वित करने के कारण सन् १९६२ के चीनी आक्रमण की आग भड़काने के उत्तरदायी थे तो काफ़ी हद तक अपराध उनका है। लेकिन प्राप्य प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि 'अग्रिम नीति' को कार्यान्वित करने का निश्चय एक उच्च स्तरीय मीटिंग में श्री नेहरू द्वारा लिया गया था यद्यपि यह सम्भव है कि इस निश्चय के लिए कौल ने श्री नेहरू को उकसाया हो।

साम्य ही यह भी सही है कि सी० जी० एस की हेसियत से कौल ने इस नीतिका जोरदार ढंग से विरोध नहीं किया था और इस संकट की स्पष्टरूप से नहीं जताया था जो इस नीति को कार्यान्वित करने से पैदा हो सकता था और वह भी विशेषतः इसलिए कि भारतीय सेना उस समय युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसा उन्होंने धापव इसलिए किया था कि 'लुढ़ बे भी यह विपवास-करते थे कि चीनी 'भीकते रहेंगे, काटेंगे-नहीं'।

एक दूसरा इल्जाम जो कौल पर लगाया जाता है वह यह है कि जब कि 'अग्रिम नीति' के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री का आदेश यह था कि केवल सांभरिक रूप से सुवृद्ध अद्दों से ही सैनिक कार्रवाई परिचालित की जाये और बिना सोचे-समझे भागे न बढ़ा जाये, कौल ने सेना को यह आज्ञा दे दी थी कि, संचार व्यवस्था का ख्याल रखे वरि, वह अनियंत्रित रूप से भागे धड़ती बली जाये।

इसके विपरीत इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी प्रमाण हैं कि सी० जी० एस० के पद पर नियुक्त होने के बाद कौल इस बात को सख्ती तरह समझ गये थे कि देश की सेना उत्तरी सीमान्त पर आक्रमणों का भुक्तानिला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रक्षा मन्त्री को लिखे गये आठ पत्र और मंत्री भण्डल की सुरक्षा समिति को लिखा गया एक पत्र इस बात का केवल एक ही प्रमाण है। सी० जी० एस के पद पर उनकी कार्य-अवधि में सेना अपने तत्कालीन आकार से १/५ और बढ़ गयी थी।

कोर कमान्डर की हेसियत से जब उन्होंने नेफा युद्ध में पंदापण किया तो वे आरम्भ से ही अनेक अक्षमताओं से दबे हुए थे। स्वयं उनकी कोर ही रातों-

रात ओढ़-गाठ कर तैयार की गयी थी जिसके फलस्वरूप कई प्रकार की कमियाँ और अपर्याप्तताएँ पैदा हो गयी थी ।

लेकिन आखिर इसमें दोष किम्वया था ? जनरल चौधरी का कहना है कि सी० जी० एस० की हैसियत में नेफा युद्ध को रूप-रेखा तैयार करने में उनरदायी स्वयं कौन थे और बाद में यदि उन्हें पर्याप्त रूप से मापन सम्पन्न और सगठित कौर नहीं मिली तो इसकी जिम्मेदारी भी कौन की अपनी हो थी ।

कौल ने प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री को यह क्यों नहीं समझाया कि एक सुगठित कौर चार दिन में नहीं बनायी जा सकती ? इसलिए कि स्वभावतः कौल यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे असम्भव को भी सम्भव कर सकते हैं । इसने अभावों उन्हें विश्वास था (और यह विश्वास कौर कमान्डर बनने ही प्राप्तमान तक पहुँच गया था) कि नेफा में कोई खास वास्तविक युद्ध नहीं होगा ।

जनरल चौधरी का कहना यह है कि कौल के आदेश अस्पष्ट होते थे । उनके ब्याप्त से सेना की युद्ध योजना तथा वहाँ से भ्रमण करने का डग दोनों गूटियों से भरपूर थे ।

कौल ने कौर कमान्डर का काम भार सभाला था कि वे बहुत अधिक बीमार पड़ गये थे । कौल पर यह आरोप लगाना कि कौल के हाथ-पाँव फूल गये थे और वे बीमारी का बहाना करके चले गये थे अत्यन्त निर्भर और अनुचित बात है ।

इससे बड़ा कुमूर तो भारत सरकार और सैनिक हैडक्वार्टर का था कि केवल कौल का मुँह फिर से चिढ़ा करने के लिए उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण काम सभाला के लिए मोर्चे पर भेज दिया था । जब हर चीज हमारे विपरीत थी तो कौर हैडक्वार्टर में हमारा कर्णधार एक कटुतापूर्ण, मानसिक रूप से परेशान और शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था ।

पूर्वी कमांड के सेनापति जनरल सेन ने प्रधान सेनापति थापर से शिकायत की कि कौल को फिर से क्यों भेजा गया है कौर को कमान्ड करने के लिए—उन्होंने कहा कि वे स्थानापन्न कमान्डर हर्गबक्षसिंह से ही काम चलाना ज्यादा पसन्द करेंगे । थापर ने उत्तर दिया कि कौल का कौर कमान्डर के पद को फिर से सभालना आवश्यक था क्योंकि “उच्चतर लोग कौल की प्रतिष्ठा को पुनर्वासित करना चाहते थे ।”

स्पष्ट रूप से साबने और ठण्डे दिमाग से निश्चय लेने की जो क्षमता उस कठिन परिस्थिति में आवश्यक थी वह उस समय कौल में नहीं थी । यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि कौल कमान्ड श्रुतता को तोड़ कर पूर्वी कमांड के सेनापति की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे प्रधान सेनापति, रक्षा मंत्री



तथा प्रधान मन्त्री से सम्बन्ध रखते थे और आदेश सेते थे—इससे जनरल सेन नाराज हो गये थे और उनके खिलाफ हो गये थे । जनरल सेन का खूब यह हो गया था कि कौल अपनी मुसीबतों में खुद ही छटपटाये, वह किसी प्रकार की सहायता करने को तैयार नहीं थे ।

तो क्या कोर के स्तर पर किसी और प्रकार का नेतृत्व होने से नेफ्रा के युद्ध और उसके फल में कोई अन्तर पड़ता ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कोर कमान्डर ऐसा व्यक्ति होता जिसे अधिक सामरिक अनुभव होता और जिसके प्रति मोर्चे पर स्थित सेना को अधिक श्रद्धा होती तो कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता । सुदृढ़ और सुनियोजित निर्देशन से अपमान का काम व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से होता ।

कुशल नेतृत्व का अपमान करती सेना पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका एक उत्तम उदाहरण है रमल द्वारा जर्मन तथा इटालियन सेनाओं का नेतृत्व । द्वितीय महायुद्ध की उत्तरी अफ्रीका की लड़ाई में जनरल मॉन्टगोमरी ने अलामीन में जर्मन तथा इटालियन सेनाओं को बुरी तरह पराजित करके खदेड़ दिया था । रमल के नेतृत्व में अपमान करती हुई जर्मन तथा इटालियन सेनाएं शत्रु से संख्या और साधनों में हीन थी । युद्ध से ग्राह्य, थकी हुई इटालियन सेना की साहसिकता इतने नीचे (या शायद इससे भी अधिक) स्तर तक उतर गयी थी जितना सन् १९६२ में नेफ्रा से अपमान करते हुए भारतीय सैनिकों का था । लेकिन अपमान का नेतृत्व और निर्देशन रमल ने स्वयं इतने कौशल से किया कि पीछे हटते समय भी उनकी सेना का सिर ऊँचा रहा । अपने सैनिकों और सम्पत्तियों की क्षति बहुत कम हुई और उल्टे, अपमान करने हुए भी, रमल ने शत्रु का बहुत नुकसान किया ।

यह प्याबली होती कि सन् १९६२ के नेफ्रा युद्ध में हम रमल की टक्कर के जनरल की माँग करते । लेकिन फिर भी इतना तो सत्य है कि कोर कमान्डर के कुशल और व्यक्तिगत नेतृत्व से हमारी सेना का अपमान भगदड़ का रूप न लेता और शायद हम तैला तथा योगदोला की रक्षा भी कर लेते क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि हमारी सेना ऐन मोर्के पर घबड़ा न जाती और जम कर हुदमन का मुक़ाबिला करती तो इस बात की काफ़ी सम्भावना थी कि हमारी यह दुर्दशा न होती ।

युद्ध में अपमान और अभियान दोनों ही स्वाभाविक हैं । लेकिन जब अपमान भगदड़ का रूप लेता है और उसके कारण सैनिक और साधनों की अनावश्यक क्षति होती है तो अनभय यह जानना चाहता है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ ।

यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है कि आक्रमणकारी पक्ष मूल रूप से अधिक अच्छी परिस्थिति में होता है क्योंकि वह आक्रमण करने और शत्रु पर

अचानक छापा मारने के समय और स्थान आसानी से चुन सकता है। यह भी इम्पनिंग, स्पष्ट है कि युद्ध में जीत उसी पक्ष की होगी। लेकिन यदि रक्षा करने वाला एक पीछे हटने न दिये जाने के बावजूद अपना सन्तुलन कायम रखता है तो अपनी भूमि पर दृढ़ कर सफलतापूर्वक शत्रु से युद्ध कर सकता है। संगठित रूप से गहराये लक्ष्य फेंक कर शत्रु का मुकाबिला करना एक सफल सामरिक नीति होती है।

वास्तव में भारतीय सेना की वही गलती यह थी कि उसने स्लो में पैर जमा कर शत्रु का मुकाबिला करने का निश्चय किया था। कई दृष्टिकोणों से स्लो इस काम के लिए एक अनुचित स्थान था — इसके भूमिरिक शत्रु उसे कई तरफ से घेर सकता था।

कई सैनिक विगैपन अनरल घोराट की इस राय में सहमत हैं कि कामेसा नेक्टर में शत्रु का मुकाबिला करने के लिए सबसे उत्तम स्थान बोमदीला था। यदि कोर प्राय्य मैना की स्लो और बोमदीला के बीच न बाँट देनी और अपनी शक्तियों को बोमदीला में ही केन्द्रित रखती तो युद्ध का फल निश्चित रूप से भिन्न होता।

अचानक छाया नारन के मध्य धीरे स्थान प्राप्तानी से पुन स्रष्टा है । यह भी हमसिद्ध स्पष्ट है कि धर्म म जीत उसी पक्ष की होगी । इतिन यदि रक्षा करने वाला पक्ष पीछे हटकेन दिने जाने के बावजूद अपना सन्तुलन कायम रखता है तो अपनी नीति पर दृढ़ कर सफलतापूर्वक धनु से युद्ध कर सकता है । सगठित रूप से गहराये तक फैल कर धनु का मुकाबिला करना एक सफल सामरिक नीति हाकी है ।

वास्तव म भारतीय समा की बड़ी गलती यह थी कि उसन स्वेमा में दैर समा कर धनु का मुकाबिला करने का विश्वास किया था । कई दृष्टिकोणों से स्वेमा हम काम के लिए एक अनुचित स्थान था — इसके अतिरिक्त धनु उसे कई मज्जा न देर सकता था ।

कई मैलिक विशेषण अमरल धाराट की इस राम से सहमत हैं कि कामेन्य सन्दर म धनु का मुकाबिला करने के लिए सबसे उत्तम स्थान बोमदीना था । यदि कोर प्राप्य सेना को स्वेमा और बोमदीना के बीच न बाँट देती और अपनी शक्तियों को बोमदीना म ही केंद्रित रखती तो मुझ का फल निश्चित रूप से भिन्न होता ।

## एक महान् भ्रम

उस समय हमारे प्रधान मंत्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व हिमालय की तरह ऊँचा था, जिनका एक शब्द भी देश की जनता के लिए करमान था और जो एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय राजमर्मज्ञ का पद प्राप्त कर चुके थे।

जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को और अपने देश को यह विश्वास दिला दिया था कि युद्धोपरान्त अणु युग में, जब कि सारे संसार में धमन कायम रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की हो गयी थी, युद्ध न सिर्फ अनावश्यक और दकियानूसी जोड़ बन गया था बल्कि राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने का अस्त्र भी नहीं रह गया था। वैयक्तिक राजनय ही अब इसका एक मात्र और नया सामन था।

श्री नेहरू के आदर्शवादी दिमाग ने तुरन्त एक ऐसे अनुकूल और कल्पित संसार की स्थापना कर ली थी जहाँ से युद्ध का प्रेत सदा के लिए निर्वासित कर दिया गया है, जहाँ अधिकार शक्ति के बल पर नहीं है (जो एक अत्यन्त कालपूर्ण धारणा थी), जहाँ एक राष्ट्र का स्तर उसकी सेवा तथा युद्ध साधनों से नहीं माँका जाता है।

श्री नेहरू को विश्वास था कि रुमानी आदर्शवाद के इस कल्पित स्वर्ग में भारत, अहिंसा और आध्यात्मिक गान्धताओं की लम्बी परम्परा के आधार पर, विकास के उच्चतम बिन्दु तक पहुँच सकेगा और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और इसी विचार के अन्तर्गत श्री नेहरू ने कड़ा प्रयत्न किया था कि उनका राष्ट्र पूरी तरह इस सव्य भूमिका को अदा करने के योग्य बन जाये।

सन् १९५६ में भारतीय सम्पादकों के साथ धनीपचारिक ढंग से देश की विदेश नीति के बारे में बातचीत करने हुए थी नेहरू ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण बात है कि युटोपेरान्त युग में, जबकि उसकी प्राथमिक शक्ति नान्म है और सनिक धर्मता अत्यन्त साधारण, भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रभावशाली भूमिका भवा कर सकता था । यह बात युद्ध पूर्व, धनुपूर्व युग में अत्यन्तव थी ।

और विचारशील मुद्रा में प्रधान मंत्री ने धार्य कहा था यदि पूर्व-पश्चिम के बीच यह सपप न होता और दोनों शक्ति गुटों के बीच चीत-युद्ध की स्थिति न होती तो पता नहीं भारत का क्या हुआ ?

यह कथन थी नेहरू के इस विस्वास की पुष्टि करता था कि पुराने खवे हमेषा के लिए खरम हा मय है, नया युग आ मया है, युद्ध का निर्वासित कर दिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का खन अब सौमन्यता से गुंता जाने वाला है । इससे थी नेहरू का यह आत्म विस्वास भी भूमकता था कि इस नये खेल के यह मुख्य खिलाड़ी हैं ।

बान्मद में, अपनी अद्भुत पार्श्वभूमि और ख्याति के कारण थी नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जा युद्ध-आहत मानवता का नेतृत्व करके उसे नये स्वम में सट्टा सकते थे । सन् १९५० के आसपास की अन्तर्राष्ट्रीय विवादों ने उन्हें एकमात्र होकर एक परिपक्व राजमर्मज्ञ तथा तेजो से विवसित हात हुए और प्रभावशाली अफीकी एशियाई गुट के (जिसने धनुस्त राष्ट्र ख में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था) एकमात्र नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था ।

इसके अतिरिक्त थी नेहरू महान् नेता तथा प्रथम प्रधान मंत्री थे अफीका और एशिया के उस सट्टन देश के जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद की जक़ीरें तोड़ कर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी । थी नेहरू ने अय धौपनिधधिक देशों के स्वतन्त्रता सप्राप्त का अवगदस्त प्रेरणा तथा नैतिक सम्बल भी दिया था । बारों तरफ थी नेहरू की प्रतिष्ठा थी । सन् १९५५ के बान्दुग सम्मेलन के पीछे थी नेहरू ही मुख्य क्रिया शक्ति य और उहाने ही इस धवसर पर अपने मित्र चाड इन भाई का परिषद अफीका तथा एशिया के नेताओं से कराया था । बडे आत्म विस्वास तथा गौरव से अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर थी नेहरू अपनी महान भूमिका भवा कर रहे थे ।

‘सह विनाश’ के भय से काँपने हुए ससार की थी नेहरू न धातिपूर्ण ‘सहप्रस्तित्व’ का महामय दिया था और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक नयी पद्धति प्रतिपादित की थी । नये विवसित हुए राष्ट्रा तथा पश्चिम के पुराने देशों में अपने नय दशन के लिए इतना हादिक समर्पण पाकर, थी नेहरू पूरे जतन से जुट गये थे इस प्राथिक ससार में अपनी कल्पना के आवसवादी स्वम का निर्माण करने के लिए ।

अतः हम देखते हैं कि सन् १९५५ के आस-पास श्री नेहरूपेंकिंग, मास्कों, अमरीका और संयुक्त राष्ट्र संघ गये 'शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व' की शुभवार्ता का प्रचार करने। श्री नेहरू के नये दर्शन का दूसरा अंग था 'अपक्षवाद'। श्री नेहरू ने कहा कि 'अपक्षवाद' ही ऐसी नीति है जो दो विपक्षी शक्ति गुटों के बीच के संश्लेषक तनाव को रोक सकती है। नये स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों ने (जिन्होंने अब तक दोनों में से किसी गुट में शामिल होने का निश्चय नहीं किया था) श्री नेहरू के 'अपक्षवाद' को स्वीकार कर लिया।

श्री नेहरू ने आग्रहपूर्वक इस बात से इन्कार किया कि वे ऐसा करके एक 'तीसरे गुट' को रचना कर रहे थे—अपक्षवाद की नीति मूलतः गुटबन्दी के खिलाफ थी। उन्होंने 'तीसरी शक्ति' के नाम को भी रद्द कर दिया; इस अपक्ष संघ को उन्होंने 'शान्ति का तीसरा क्षेत्र' का नाम दिया—उनके अनुसार यह एक ऐसा शुभ और आवश्यक माध्यम था जिसके द्वारा पूर्व तथा पश्चिम के बीच सम्पर्क स्थापित हो सकता था और जिसके बीच में होने से दोनों गुटों के टकरा जाने का संकट टल सकता था।

१९५४ में जब चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किये तो श्री नेहरू निश्चिन्त हो गये कि उनका यह सुन्दर स्वप्न साकार हो गया है कि सारे विश्व में सहअस्तित्व की भावना क्रियात्मक रूप से प्रचलित हो। समझौते में इस बात पर जोर दिया गया था कि दोनों देश एक-दूसरे के आदर्शों को मान्यता दें, एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करें और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा झगड़ों को हल करने के लिए शान्तिपूर्ण साधनों का प्रयोग करें। यह समझौता भारत-चीन सम्बन्धों की आधार-सिला थी और श्री नेहरू की विदेश नीति का मूल तत्व।

अपने आदर्शवाद तथा उत्साह में स्वयं ही डूब जाने के कारण श्री नेहरू ने यह नहीं सोचा कि अणु युग में विशाल पैमाने पर युद्ध भले ही असम्भव हो गये हों लेकिन छोटी-छोटी सीमा सम्बन्धी तथा प्रादेशिक लड़ाइयाँ बराबर चलती रहेंगी जिनमें परम्परागत अस्त्रों तथा सेनाओं का प्रयोग होगा।

एशिया के दो विशालतम देश—चीन तथा भारत के बीच हुए पंचशील समझौते को श्री नेहरू जवरदस्त महत्त्व देते थे। चीन और भारत—दो पड़ोसी देश जिनकी सीमाएँ एक-दूसरे से मिली हुई थी और जिनके आदर्श भिन्न थे—ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का फ़ैसला कर लिया था। श्री नेहरू द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की नयी पद्धति का यह एक गौरवपूर्ण और सफल उदाहरण था और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वह इस उदाहरण को सफल बनायेंगे।

जवरदस्त वैयक्तिक राजनय से—जिसका मूल अंग था चीनी प्रधान मंत्री चाउ-इन-साई से गहरी मित्रता श्री नेहरू ने भारत-चीन मित्रता को सुदृढ़

बंगाल का बाज धातुम किया। यह वा महान् एशियाई देश पूर्वी एशिया की नियति का निर्माण करने काम था।

जमा मानव शक्ति को न थी नेहरू ने अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में इन स्वयं निम्न तथ्य का ध्यान न भुलें मोठ किया था कि गुप्तों के कार्य द्वारा विश्व नहीं शांति है केवल उनके स्वयं स्थायी ही है।

उसी वर्ष १९४६ में जब जान गया भारत के बाह्य परिस्थितियों, पश्चात्तत्त्व सम्बन्धी दृष्टि ध्यान मात्र पर साथ ही भारतीय जनता के साथ ही सम्बन्धों को पर जाने बल दृष्टि थी नेहरू ने अपने विचार प्रकट किए।

यह जानना पड़ता है मुझ के भारत के समय हुई था और इस पुस्तक का रचना भी वही उपस्थित था। था नेहरू समय-समय पर परिवारा के साथ इन बातों के अनुभवों को विचारों का विनिमय करना समझ कर था।

उत्तरनाथ धानसोई के दौरान न थी नेहरू ने कहा कि विनी-न-विनी दिन निश्चित रूप से इन दो मतों देना में गण्य पैदा हो जायेगा और यह स्थिति आगे एशिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इन सब का कर्तव्य है कि इस दुपटना को घटने में राह।

अक्टूबर '६२ तक थी नेहरू वही करने का प्रयत्न करते रहे। था नेहरू के उत्तराका रूप में उनके विचारों की ही नजर नहीं मिलती बल्कि यह भा स्पष्ट होता है कि सन् '४४ में भी थी नेहरू को ज्ञात था कि भारत का चीन की धार से उत्तरा है।

यू महात्मावादा तथा धार्मिक मूल्यभित्त की नीति भारत के लिए आदर्श थी। इसके फलस्वरूप, प्रतिरक्षा की धनक और पहुँच आदर्शवादों की धार ध्यान दिए बिना सारे साधन और शक्तियों को आर्थिक विकास के उद्देश्य के काम में लगाया जा सकता था—इस क्षेत्र में भारत को अपनी बुरी तरह पिछड़ी हुई स्थिति का ठीक करना अनिवार्य था।

इन महान् उद्देश्यों को पूरा करने के लिए थी नेहरू ने कड़ी मेहनत की, बहुत कुछ बलिदान किया—चीन की अनुचित माँगों को उठा, भारत के सीमांत पर उनके प्रतिभमों की तरफ से छोड़े मूँद सी और काफ़ी समय तक इन प्रतिभमों को देश से छिपाने भी रखा—वास्तव में उन्होंने अपनी सारी राजनैतिक प्रतिष्ठा तक का सब पर नया दिया अपने प्रिय आदर्शों की रक्षा करने के लिए (समय न इन आदर्श नीतियों को पापजनित बताया था)। लेकिन पक्षमंड की एक बदला मुझ थी नेहरू की एक क्रूर भटके के साथ जापना पड़ा और सब—बहुत विलम्ब से—उन्होंने यह देखा कि उनका वास्तव एक ईमानदार दास्त से नहीं, एक जानाक और सिद्धांतहीन शत्रु से पड़ा है।

थी नेहरू की चीन के प्रति एक भावनात्मक आश्चर्य था क्योंकि भारत की तरह चीन न भी बहुत समय तक और बहादुरी से पश्चिमी साम्राज्यवाद

के खिलाफ संघर्ष किया था। चीन के प्रति उनके मोह की शुरुआत सन् ३०-४० के बीच पायी जा सकती है। महायुद्ध के समय उन्होंने दिल्ली आये हुए मार्शल चिवांग काई शेक से मित्रता की थी और स्वतन्त्रता मिलते ही सबसे पहले पेकिंग में भारतीय राजदूत की नियुक्ति की थी।

श्री नेहरू का चीन-प्रेम उस देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद और भी प्रगाढ़ हो गया था। इसी कारण मार्च १९५६ में नयी दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में श्री नेहरू ने कहा था कि तिब्बत में चीनी कार्रवाइयों को (जिनके कारण दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी) पत्र-सम्बादों में 'अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है'। १७ मार्च, १९५६ को संसद में भाषण करते समय श्री नेहरू ने कहा था कि ल्हासा का खून सरावा "इस समय केवल दो संकल्पों का पारस्परिक संघर्ष है, शारीरिक या हथियारबन्द संघर्ष नहीं।"

यूँ १९५४-५६ के बीच जब श्री नेहरू '२००० वर्ष पुरानी भारत-चीन मित्रता का बखान कर रहे थे' उस समय चीन के सरहद्दी दस्ते व्यस्त थे (बाद में पेकिंग के अनुसार) 'सैनिक छानबीन' में और सिक्किम तथा तिब्बत को मिलाने वाली प्रस्तावित अक्साई चिन सड़क के लिए दस से ज्यादा रास्तों का कार्यवेक्षण करने में।

इन पर्यवेक्षणों में जो वैकल्पिक रास्ते पाये गये थे उनमें से कई अन्त में चुने गये मार्ग की तुलना में भारतीय भूप्रदेश में ज्यादा अन्दर तक आते थे। लेकिन अपनी ही भूमि पर होने वाली इस तथाम सरगर्मी से हमारी सरकार पता नहीं क्यों पूरी तरह देखबर थी। हम अक्साई चिन मार्ग के अस्तित्व से उस समय तक अनभिज्ञ रहे थे जब तक चीनी सरकार ने स्वयं सितम्बर '५७ में यह घोषणा नहीं कर दी थी कि अगले महीने इस मार्ग पर भ्रमणदरपत्र शुरू हो जायेगी। और उसके बाद भी अगले गर्मी के मौसम तक भारत सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया था।

जब भारत ने अक्साई चिन प्रदेश में बनी इस नयी सड़क का मुआइना करने के लिए दो टोह लेने वाले दल भेजे और उनमें से एक को चीनियों ने कैद भी कर लिया तब भी १८ अक्टूबर, १९५८, तक श्री नेहरू पेकिंग से कोई आपत्ति नहीं कर सके।

सड़क के निर्माण के खिलाफ आपत्ति प्रगट करते तथा कैद किये हुए भारतीय दल के बारे में विवशतया पूछ-ताछ करते हुए श्री नेहरू ने अत्यन्त दयनीयता से लिखा था : "जैसा कि चीन की सरकार को मालूम है भारत सरकार इन छोटे-छोटे सरहद्दी झगड़ों को खत्म करने की इच्छुक है ताकि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहे।"



१ नवम्बर के अपने उत्तर में चीनियों ने आग्रहपूर्वक कहा कि प्रस्ताव चिन मान भारतीय भूमि से नहीं, चीनी भूमि से होकर गुजरता है।

श्री नेहरू ने बाद में स्वीकार किया कि वे इन गतिविधियों से चिन्तित प्रभाव हो गए थे लेकिन १९५९ तक उन्होंने मसद या जनता को इन बातों का पता नहीं चलने दिया था। उनका कहना था 'ऐसी कोई विशेष परिस्थिति पैदा नहीं हुई थी कि इस मामले को मसद के मामलें रखा जाना आवश्यक हो क्योंकि हम जानते थे कि पत्र-व्यवहार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के क्षेत्र में काफी प्रगति की जा सकेगी और उचित समय पर मसद को इस बारे में पूरी सूचना दे दी जायेगी।'।

श्री नेहरू ने स्वीकार किया कि "शायद यह मेरी गलती थी कि मैंने इन तथ्यों को मसद के सामने प्रस्तुत नहीं किया।" फिर भी १९५९ के पतझड़ तक यह सीमा समस्या को विपटित रूप में ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहे और प्रस्ताव चिन की बात को यह कह कर उठाते रहे कि यह एक ऐसा "इलाका है जहाँ पास की एक पत्ती भी नहीं उगती।"

पेरिय ने अपने इस दावे को कतई छिपा कर नहीं रखा कि उनके दस्तों ने महात्मा प्रदत्त मेजुलाई १९५१ से ही गलत सामान्य गुरु कर दी थी। फिर भी श्री नेहरू ने चाहे इन साई के साथ मित्रतापूर्ण पत्र-व्यवहार में इस विषय को कभी उठाया तक नहीं। बाद में मसद के सामने उन्होंने स्पष्टरूप से स्वीकार किया - "मैंने कभी इस बात की आवश्यकता नहीं समझी थी कि चीन की सरकार से सीमा के बारे में कोई विवाद कहे क्योंकि शायद मूलतः वस्तु में यह समझता था कि ऐसी कोई बात है ही नहीं जिस पर विवाद किया जा सके।"

विरोधी दलों के निरन्तर दबाव के कारण श्री नेहरू ने उसी वर्ष नवम्बर में लोक सभा में यह आश्वासनक वक्तव्य दिया 'लेकिन मैं मसद को यह बता सकता हूँ कि आकाशी से लेकर आज तक हमारी प्रतिरक्षा सेनाएँ कभी ऐसी अच्छी हालत में नहीं थी और न कभी उनके पीछे औद्योगिक उत्पादन की इतना उबरदस्त सहायक क्षमता थी जितनी आज है। मैं स्थिति को निरपेक्ष रूप से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेना वस्तु की रक्षा करने के लिए पूणत योग्य है।'

क्या रक्षा मन्त्रालय ने श्री नेहरू की भाँखों के सामने धुन्ध फैला दिया था? या यह एक तरकीब थी उत्तजित विरोधी दलों को शान्त करने की?

दिसम्बर १९६१ में श्री नेहरू ने मसद को आश्वासन दिया कि पिछले दो वर्षों में परिस्थिति मोटे तौर पर हमारे अनुकूल हो गयी थी। "मनचाही सीमा तक ही नहीं फिर भी यह सत्य है कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने अधिकार कर लिया है वहाँ, सैनिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से, स्थिति बराबर हमारे

अनुकूल होती गयी है।” यहाँ संकेत है लहास में अधिक भारतीय चौकियाँ बनने की ओर वास्तव में यह वक्तव्य छलनात्मक था।

बड़ी चतुराई से श्री नेहरू इस स्थिति से हट कर कि : ‘युद्ध नहीं होना चाहिए’ इस विश्वास पर पहुँच गये थे कि : ‘युद्ध होना असम्भव है। उन्होंने उन क्षुरप तथा तकलीफ़देह वास्तविकताओं की ओर से आँखें मूँद ली थीं जो उनके कल्पित स्वर्ण के दरवाज़ों की ओर-ओर से सटखटा रही थी।

इस प्रकार अपने दर्शन तथा राजनयिक चामुर्य में श्री नेहरू के असौम्य विश्वास ने, मानवी अच्छाई के प्रति उनकी भावना ने और चीनी नेताओं से उनकी मित्रता ने मिलकर इस देश में, व्यापक रूप से, यह महान् भ्रम फैला दिया था कि २००० वर्ष के सम्बन्धों पर आधारित मित्रता कभी खत्म नहीं होगी और चीन जैसा प्रिय तथा विश्वस्त मित्र कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा।

इस भ्रम का नशा दुर्भाग्य से भारत के सैनिक नेताओं की नसों में भी भर गया था जिसके कारण पूरा देश तथा उसके रक्षक शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से, किसी भी आक्रमण के लिए सर्वथा अतत्पर थे।

उदाहरणार्थ, सितम्बर १९५६ में, लहास के अक्साई चिन प्रदेश में चीनी अतिक्रमण के बाद श्री नेहरू ने हमारे प्रशासन तथा सैनिक अधिकारियों को आदेश दिया था कि “संघर्ष से तब तक बचो जब तक हम मजबूरन उसमें फँस ही न जायें। मतलब यह है कि हमें वहाँ सशस्त्र संघर्षों से नहीं, छोटे संघर्षों से भी बचना चाहिए। उसी हालत में हमारे सैनिकों को गोली चलानी चाहिए जब उन पर गोली चलायी गयी हो।”

साथ ही श्री नेहरू ने कहा : “मेरे ख्याल से चीनी इस (नेफ़ा) सीमान्त पर आक्रमणशील दल अस्तित्व नहीं करेंगे अर्थात् अब और आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे।”

इसी प्रकार उनके अनुसार लहास में भी बस सेंधे भरने का खेल चल रहा था—दोनों पक्ष सखी स्थानों पर अपनी-अपनी चौकियाँ स्थापित करके लुका-छिपी का खेल खेल रहे थे।

५ नवम्बर, १९६२, को लोक सभा में चीनी आक्रमण पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री नेहरू ने स्वीकार किया : “पिछले पाँच वर्षों में चीन हमारे सीमान्त पर जो अग्रगर्वण करता रहा है—जो एक बहुत बुरी बात थी और उनकी विस्तारवादी प्रवृत्तियों का परिचायक थी—उससे हमें तकलीफ़ें जरूर हुईं लेकिन हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना असम्भव था कि चीन कभी भी बड़े पैमाने पर आक्रमण करेगा।”

सरकारी मनोस्थिति थी कि कोई ‘निर्णयात्मक युद्ध’ नहीं होगा, हव से हव कुछ स्थितियों को लेकर सीमित संघर्ष होये हग़लांकि वृष्ट सूचना विभाग यह

खबर दे चुका था कि मेक्या मोर्वे पर चीनी सैनिक बहुत बड़ी संख्या में एकत्र थे और सीमा के उस पार बहुत तेज सैनिक सरगर्मी चल रही थी।

इसलिए सन् १९५७ में शुरू होने वाले चीनी प्रतिजमणों से भी भारत सरकार की भ्रांति नहीं खुली। सन् १९५६ में दलाई लामा के भारत में धारण लेने के बाद चीन के साथ राजनयिक पत्र-व्यवहार में स्पष्ट उनकी उपरत धात्रमणशीलता भी भारत सरकार की शान्त, निश्चित मुद्रा अंग नहीं कर सकी।

अक्तूबर १९६२ तक, जब निर्णयात्मक चाल चली जा चुकी थी, श्री नेहरू का क्वास था कि चीनी वास्तविक मुझ नहीं चाहते हैं। जनरल पील ने अपनी पुस्तक 'अनकही कहानी' में २ अक्तूबर को लिखा है: "उसी दिन जनरल थापर और जनरल सेन प्रधान मंत्री से मिले। प्रधान मंत्री ने कहा कि यह पहला अवसर था जब हम चीनिया के विरुद्ध अस्त्र इस्तेमाल करने जा रहे थे। हालांकि हमारे पर्याप्त कारण थे, उन्होंने कहा, लेकिन इस बात का तन्भीर परिणाम निकलना निश्चित था। नेहरू ने कहा कि बिन्ही घण्टे आघातों पर उनको यह विचार है कि चीनी हमारे विरुद्ध कोई भीषण सैनिक कारवाई नहीं करेंगे।"

उसी महीने में जब चीनियों ने वास्तव में अव्यवस्थित पैमाने पर भारत पर आक्रमण कर दिया तो २५ अक्तूबर को लोक सभा में बोले हुए श्री नेहरू ने इस आक्रमण को एक 'महारा आघात' बताया और आश्चर्यजनक स्पष्टता ■ स्वीकार किया "हम आधुनिक सत्तार की असंख्यता से दूर होते जा रहे थे और हमने अपने ही बनाये हुए एक कृत्रिम वातावरण में रहना शुरू कर दिया था।"

दो दिन बाद, मानो श्री नेहरू की इस आत्म स्वकृति की साक्षी देते हुए, पेकिंग के पत्र 'पीपुल्स डेली' ने भारतीय प्रधान मंत्री पर जहर उगसा। चीनी सरकार के मुखपत्र ने लिखा

"इस महत्वाकांक्षी नेहरू का उद्देश्य रहा है भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व साम्राज्य की स्थापना करना। इस साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र में मध्यपूर्व से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक के सब देशों को शामिल कर लेने की योजना बनायी गयी है। किसी जमाने में अश्वजी साम्राज्यवादियों ने एशिया में जो औपनिवेशिक जाल बिछाया उससे भी कहीं बड़ा है यह साम्राज्य स्वप्न।"

वास्तव में १९६१ के बाद केवल एक अथवा आदमी के लिए ही यह प्रसम्भन था कि यह देख सके कि भारत तिब्बत सीमा पर चीनी क्या करना चाहते हैं।

यह निरुद्ध दृष्टि पूरी तरह भारत सरकार की विदेश नीति और उसके एकमात्र निर्माता के कारण थी जो (आश्चर्य की बात है) अन्त तक यथार्थ के कुर धपेड़ों के धावजूद अपने रूमान्नी भ्रम को सीने से लगाये रहे थे।

दुर्भाग्य की बात यह थी कि आन्तिपुरुष नेहरू जो अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व तथा सद्भावनाओं की नीति कार्यान्वित करने में पूरी तरह सफल हुए थे, पूर्णतः अयोग्य थे युद्ध समय के नेता की भूमिका अदा करने के लिए। उन्हें युद्ध से हीन अरुचि थी और उन्होंने अपने आप को विश्वास दिला दिया था कि चीनी आक्रमण का खतरा एक नकली खतरा है।

श्री नेहरू को उस नयी भूमिका से घृणा थी जो उन्हें विवश होकर अदा करनी पड़ी थी लेकिन उत्तरदायित्व की गहरी भावना और देश के लिए उनके नेतृत्व की अनिवार्यता के विचार से वह अपने पद पर डटे रहे थे।

५ दिसम्बर, १९६१ को लोक सभा में चीन सम्बन्धी बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने यह आत्म-प्रदर्शक वक्तव्य दिया था : "कहीं भी युद्ध होने के विचार से मेरी आत्मा विद्रोह कर उठती है। मुझे जीवन भर यही शिक्षार्थमिली है और अब ७२ वर्ष की आयु में मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता।"

१९६२ के चीनी संकट से पहले के श्री नेहरू की यह तस्वीर भ्रष्टरी रहेगी और उनके प्रति अन्याय होगा यदि दूसरा रत्न न विश्वास जाये। क्योंकि इस बात के भी प्रचुर प्रमाण हैं कि उन्हें संभाव्य चीनी संकट का तीव्र आभास था, कि युद्ध को छोड़कर उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पर रोकथाम और संरक्षण के लिए कई काम किये थे, कि वे बराबर रक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को यह आदेश देते रहे थे कि सीमान्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाये और सीमा के विवादपूर्ण स्थानों पर चौकियाँ स्थापित कर दी जायें ताकि चीन किसी दिन सम्पन्न-कार्य की स्थिति प्रस्तुत न कर सके।

वास्तव में सन् १९५४ से ही प्रधान मंत्री प्रतिरक्षा संगठन को यह समझाते रहे थे कि पूरे उत्तर पूर्वी सीमान्त पर शारीरिक रूप से नियन्त्रण रखना अनिवार्य है और यह आवश्यक है कि आगे तक चौकियाँ स्थापित कर दी जायें, उस सारे प्रदेश पर प्रशासकीय नियन्त्रण ज़ायम कर दिया जाये ताकि स्थानीय जनता का भावनात्मक एकीकरण सम्भव हो सके।

इस बात की काफ़ी सम्भावना है कि यदि रक्षा मंत्रालय और सैनिक हेडक्वार्टर १९५४ के बाद के श्री नेहरू के आदर्शों और इच्छाओं का पालन करते तो जटिल में वह न होता जो हुआ।

नेफा सीमा के बारे में विशेषतः श्री नेहरू सैनिक हेडक्वार्टर से बार-बार कहते रहे थे कि मैकमहॉन रेखा के किनारे-किनारे सब मार्को के स्थानों पर

चीनियाँ स्थापित कर दी जायें ताकि इस विवादपूर्ण सरहद्दी इलाके में भारत सरकार की उपस्थिति एक अकाट्य तथ्य बन जाये।

एक अवसर पर प्रधान मंत्री ने सैनिक अधिकारियों को इस बात के लिए डाँटा था कि वे ऐसे प्रदेश में टोह दल भेजने से भिन्नक रहे थे जो चीनियों के किसी भी दाव के बावजूद, अविवाद रूप से भारत का हो घग था। श्री नेहरू इस बात को अत्यन्त असन्तोषजनक समझते थे कि हमें यह भी न मानूस हो कि जिस सीमा तक चीन ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

महात्मा श्वर ने एक गरीबी दस्ता भेजने को अपनी स्वीकृति देत हुए प्रधान मंत्री ने फिर नो, इस बात पर जोर दिया था कि हमारा दस्ता किसी भी हालत में चीनी दस्तों से संघर्ष सम्पन्न न करे।

श्री नेहरू का निश्चयन मत था कि हमें उन इलाकों में टोह दल भेजने से नहीं भिन्नकना चाहिए जो भारत का अंग हैं, भले ही चीनी उन पर दावा करने लगे।

वह नेत्रा में चीनी खतरे के प्रति बाज़ी खराब थे और चाहते थे कि उस दूरस्थ सरहद्दी इलाके पर भारतीय बम्बा मुद्रा कर दिया जाये और उन्हें विश्वास था कि यह इलाका पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है। २२ अगस्त, १९६२ को राज्य सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा

“१९४९ १० की स्थिति का देखते हुए हमारा क्याल था कि नेत्रा में खतरा है और तब से हमने नेत्रा सरहद्द को सुरक्षित करने की हर कोशिश की। धीरे-धीरे हमने उस प्रदेश में अपनी चीनियाँ स्थापित कर ली हैं और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नेत्रा में प्रशासकीय वस्त्र फैल गया है। जिस एक सरहद्द को हमने काफ़ी सफलतापूर्वक सुरक्षित किया है, वह है नेत्रा सीमान्त।”

श्री नेहरू की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्हें घट्ट विश्वास था वैयक्तिक राजनय तथा मानवी सम्बन्धों में और उन्होंने मानसिक रूप से दुष्ट को नीति अस्त्र के रूप में रद्द कर दिया था। उनकी असफलता का मुख्य कारण था कि उन्हें अपनी राज्य ममती प्रतिभा और राजनयिक वातुय में अत्यधिक विश्वास था और वह समझते थे कि अपने व्यक्तित्व के आकर्षण मात्र से वह सारी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ सुलभ कर सकते हैं।

उन्हें अपनी इस निर्यात में घट्ट विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तथा उन्हें रूप देने के बाव में उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका भदा करनी है और अपनी पारवर्भूमि तथा बौद्धिक योग्यता के कारण इस भूमिका के लिए वे अपने धाय को सबसे योग्य व्यक्ति समझते थे।

स्वतन्त्रता मिलने के पहले से विदेश सम्बन्धी मामलों में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने कांग्रेस को विश्व चेतना प्रदान की थी। स्वतन्त्रता के बाद प्रधान मंत्री के अलावा वे विदेश मंत्री भी थे और इस भूमिका को अदा करने में उन्हें बहुत आनन्द मिलता था।

उन्होंने अपना सब कुछ इस विश्वास पर लगा दिया था कि उनकी विदेश नीति न केवल सही है, बल्कि ऐसी है जिसके असफल होने की कोई सम्भावना नहीं। अतः अक्टूबर १९६२ में चीनियों ने भारत पर आक्रमण किया तो न केवल उन्होंने भारत तथा नेहरू की पीठ में खूरा रोंका बल्कि उस विदेश नीति की नींव उड़ा दी जिससे नेहरू ने अपने आप को एकरूप कर लिया था। यही वास्तव में वह आघात था जिससे श्री नेहरू कभी संभल नहीं सके।

## एक गत्यात्मक मंत्री

सन् १९५७ में रक्षा मन्त्रालय में श्री बी० के० कृष्ण मेनन का घुसना हुआ के एक ताजे भोजन की तरह था जिसने उस मन्त्रालय में बर्षों से जमती हुई धूल को उड़ा दिया और जानो को मोच फेंका ।

रक्षा मन्त्रालय पिछले ७-८ बर्षों से भारत सरकार की सौतेली सन्तान की तरह रहा था । और उसमें एक पानक ठहराव की स्थिति पैदा हो गयी थी । इन बर्षों में प्रयोग्य व्यक्तियों ने इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय का कार्य भार सम्भाला था—इससे यह स्पष्ट पता चलता था कि भारत सरकार इन मन्त्रालय को कितना महत्व देती थी ।

एक बांधीबादी छातिप्रिय, सहृदयत्व के दर्शन में विश्वास रखने वाले देश के लिए रक्षा मन्त्रालय और सेना दोनों अनावश्यक समझे जाने लगे थे । सरकार और सब से दोनो उसके खर्च अधिकृत करने से पीछे हटते थे । सेना के उत्कालीन अधिकारी निराशा और कटुता से भर गये थे और देश के युवकों की सर्वोत्तम श्रेणी के लिए सैनिक सेवा में कोई आकर्षण नहीं रह गया था जबकि आजादी से पहले इसे एक प्रत्यक्ष उत्तम पेशा समझा जाता था ।

कृष्ण मेनन के गत्यात्मक नेतृत्व के कारण प्रतिरक्षा सेवामो में नयी जान आ गयी । बहुत समय के बाद रक्षा मन्त्रालय पर फिर आकर्षण केन्द्रित हुआ । एक बहुत बड़ी म्हाङ्गू से मेनन ने पूरे मन्त्रालय को सरफ करके कितासील बना दिया और बरिष्ठ सैनिक अधिकारियों तथा उनके स्टयफो के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अब वे अपना नहीं हैं । बहुत देर बाद उन्हें एक ऐसा नेता मिला था जो उनके अधिकारों को सुरक्षा कर सकता था, उनके लिए सफ़ सकता था । अब मेनन के मनो बनने पर वे प्रत्यक्ष हर्षित हुए और उनके पार्श्व तरफ जुट गये । वे मेनन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे ।

मेनन ने अधिकारी श्रेणी तथा सेना के तीनों अंगों के रैंकों के वेतन, भत्ते तथा रहने और काम करने की परिस्थितियों के बारे में जांच की। उन्होंने उनका निवृत्ति-वेतन बढ़ा दिया, कटे हुए राशन भत्ते को फिर से दिलाया, अफसरों का वेतन (जो पुलिस अफसरों के वेतनों की तुलना में बहुत कम था) बढ़ाया और यह निश्चित कर दिया कि मेजर के बजाय लेफ्टिनेन्ट कर्नल के पद से निवृत्ति हुमा करेगी। उन्होंने उन्हें भूकान दिलवाने की व्यवस्था करवायी और कल्याणकारी प्रोग्राम चालू करवाये। मृत्योपरान्त उपदान तथा परिवार को दी जाने वाली पेन्शन की भी वृद्धि कर दी गयी।

वास्तव में, मेनन का दावा है कि वेतन, कल्याण तथा रहने की परिस्थितियों के क्षेत्र में उन्होंने सेना को कूट मिला कर ७२ रियायतें दिलवायी थीं।

मेनन ने मुझे बताया कि १९५६ में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि सेना के अधिकारी वर्ग की संख्या दुगुना कर दी जाये लेकिन जनरल शिमेया तथा जनरल कुमारमंगलम ने (जो उस समय एडजुटेंट जनरल थे) इस दलील पर उनके प्रस्ताव का विरोध किया था कि संकटपूर्ण स्थिति खत्म हो जाने के बाद उनकी समझ में नहीं आयेगा कि इतने प्रतिरिक्त अफसरों का क्या किया जाये। पर्य मंत्री, मोरारजी देसाई ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था।

मेनन ने यह भी कहा कि जनरल शिमेया स्वचासित अस्त्रों के उत्पादन के खिलाफ थे क्योंकि उनका कहना था कि सेना के पास अगले ४७ वर्षों के लिए पर्याप्त तोपें थीं।

मेनन ने इसके बाद देश में ही प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया क्योंकि इससे देश आत्म-निर्भर होगा और प्रतिरक्षा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशों पर उसका निर्भर होता कम हो जायेगा।

जो ग्रांटेन्स फैक्ट्रियां उस समय मौजूद थीं उन्हें पूरी समता तक उत्पादन कार्य में लगा देने का आदेश दिया गया और कुछ का संवर्धन भी किया गया। यह फैक्ट्रियां, इसके बाद, गोला-बारूद, भारी मॉर्टर, जल सेना की तोपें तथा बंदूकों के लिए 'रिक्वायल' प्रणालियां, भारी तथा मध्यम कैलिबर की तोपों के लिए मार्टलिंग, कैंरेज तथा बफ़र, साधारण अस्त्र, कई प्रकार के बम, भाइन्, उच्च विस्फोटक, जल बम, पैराशूट तथा पर्वतीय युद्ध के लिए आवश्यक साधन आदि उत्पादित करने लगीं।

मेनन की ही पहल के फलस्वरूप बंगलौर और कानपुर में एयरक्राफ्ट फैक्ट्रियां खोल दी गयीं, जबतपुर में ट्रकों तथा भारी वाहनों का निर्माण शुरू हुआ और दक्षिण के अवाडी नामक स्थान में टैंक बनाने की एक फैक्ट्री शुरू की गयी। बंबारा में विस्फोटकों का, बंगलौर में नियंत्रित मिसाइलों का, बम्बई तथा



कलकत्ता में मेरील इन्वो का, ममुरी में स्वधातिउ धग्ना, मिधपानु इस्ताउ धीर निजतिव साधपदाचों का उत्पादन होने लगा ।

उन्होंने ध्व-स्वधामित उद्दिष्टना, ७६२ मिलीमीटर गाना-बाह्य, १२० मिलीमीटर बाट मॉर्टरों तथा उनके गोला क उत्पादन की एक योजना भी बनायी । यह सब याचनाएँ सन् '६२ के अन्त तक या '६२ के पारम्भ से क्रियात्मक रूप लेने वाली थीं—चीनी धाकनप के समय या उसके कुछ बाद ।

बहुत समय से विभिन्न सैनिक डिपो तथा बाड़ों में घरों तथा साधना के सम्भार बेकार पड़े हुए थे । मेहन न यह धादेउ दिया कि इनमें से अधिक-से-अधिक को वहाँ से हटा कर ठीक किया जाय ताकि वे फिर काम में आ सकें । हजारों ऐसे वाहनों को जिन्हें चढ़ी बढ़ कर छोड़ दिया गया था, पुनर्पुर्ति को गयी और उन्हें काम में लाया गया । जो मर-नश्व डिपो अब तक थे उन्हें क्रियाशील बनाया गया और नई और किनो स्थापित किए गये ।\*

मेहन ने अपने मन्त्रालय तथा सुना के तीनों धर्मों के बीच धीर अतय-अतय रूप से दूर भग के अन्दर अधिक समन्वय स्थापित किया । घोष तथा विरासत समिति ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी बौधस को आकर्षित और क्रियाशील करने का काम शुरू किया और काफी वैज्ञानिक सेवा के लिए काम करने के लिए निमन्त्रित किए गये । १९५८ में सारे घोष प्रतिपञ्चमी को मिला कर एक नये प्रतिरक्षा घोष तथा विकास संस्थान की स्थापना की गयी ।

मुड़कालीन मेटेनेश्व डिपो पूरे रूप से काम करने वाली ईकित्थ्या में परिवर्तित कर दिये गये बिनम घरों तथा विमानों से लेकर प्रेशर कुकर तक का उत्पादन शुरू हो गया ।

सन् १९६५ में मेरे साथ एक मुलाकात में, जन घालोचन का उत्तर देते हुए मेहन न बताया कि उन मार वर्षों में ज्यादा से ज्यादा छ' क्रांती पकौलटर प्रतिरक्षा कश्चिद्र्यों में बनाये गये थे । उन्होंने कहा "बाल काटने की मशीनें इसलिए बनायी गयीं कि वे सैनिकों को बाल काटने के लिए आवश्यक भी और प्रेशर कुकर इसलिए बनाये गये कि उत्तरी सीमान्त पर स्थित सैनिकों को पैदल चलने के लिए उनकी आवश्यकता थी ।"

रक्षा मन्त्रालय में अपनी पहली चार वर्ष की अवधि में मेहन ने केबेट कोर की सूच्या दुगुनी करके २, ६३, ४६६ कर दी । इसके प्रतिरिक्त उन्होंने भौतिकनियमों केबेट कोर की स्थापना की, नुबका को सहभाय तथा अनुशासन की सिधा दन के लिए तथा उनमें देशप्रेम का भाव जाग्रत करने के लिए ।

इ गतम्ब के इम्पीरियल स्ट्रफ नविय के नमूने पर दिल्ली में एक नेशनल रिफ्रेन्स कॉलेज खोला गया ताकि सेना के तीनों धर्मों के अवर अधिकारियों को

\*वे वे पम शीर्षों की पुस्तक 'कृष्ण मेहन' से ।

विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। इस कॉलेज में युद्ध के उच्चतर निर्देश तथा नीति के साथ युद्ध से सम्बन्धित सैनिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तत्त्वों की भी शिक्षा दी जाती थी। सैनिक इंजीनियरिंग तथा सैनिक चिकित्साशास्त्र के कॉलेज पूना में खोल दिये गये।

मेनन ने मुझे बताया कि ६१-६२ तक देश का सैनिक बजट ३०० करोड़ रुपये हो गया था। शुरू में प्रतिरक्षा उत्पादन की निर्गत १४ करोड़ रुपये की थी लेकिन सन् ६२ में मेनन के रक्षा मन्त्री के पद से त्याग पत्र देने के समय तक यह १०० करोड़ रुपये तक की हो गयी थी।

भारत को प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने का जो आधार मेनन ने स्थापित किया था उसका नाम १९६५ के भारत-पाक युद्ध में पता लगा जब स्वदेश में ही बने प्रतिरक्षा साधनों से बहुत प्रायदा हुआ।

लेकिन इस सब के बावजूद यह बात घटल रूप से अपनी जगह पर है कि जब चीन ने हमारे उत्तरी सीमान्त पर आक्रमण किया तो हमारी सेना उसका मुकाबला करने के लिए कतई तैयार नहीं। उस संकट कालीन अवसर पर तथा उसके पाँच वर्ष पहले से रक्षा मन्त्री होने के कारण मेनन को चाहिए कि पराजय और दुर्दशा के लिए देश को जवाब दें। और वहाना यह नहीं हो सकता कि भारत की और अपनी आक्रमणशील नीयत का चीन ने पर्याप्त परिचय नहीं दिया था। चीन की आक्रमणशील कार्रवायी १९५९ के बाद ही बढ़नी शुरू हो गयी थी—अप्रतूबर ६२ में तो सिर्फ उसका विस्फोट हुआ था।

सत्य यह है कि रक्षा मन्त्री की हैसियत से मेनन ने ऐसी नीतियाँ अपनायी थीं जो प्रधान मन्त्री द्वारा निर्धारित भारत सरकार के सर्वमान्य दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से पालन करती थीं। यह दृष्टिकोण या कि भारत को बाहर से प्रतिरक्षा सम्बन्धी कोई खतरा नहीं है कि चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और पाकिस्तान आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया भी तो हमारी सेना उसके दाँत खट्टे करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।

इस दृष्टिकोण का पालन करने में मेनन को कोई आपत्ति नहीं थी : ये स्वयं कट्टर शांतिवादी थे। शाब्दिक आक्रमणशीलता तथा ज़हरीली जवान के बावजूद मेनन युद्ध नेता की भूमिका खड़ा करने [के उतने ही अयोग्य थे जितने नेहरू]।

उत्साह तथा कौशल से प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए निर्माणशील तथा दीर्घ-अवधि की योजनाएँ कार्यान्वित करना एक बात है और रक्षा मन्त्री की हैसियत से युद्धकाल में देश का नेतृत्व करना विल्कुल दूसरी बात। मेनन मूलतः इस काम के योग्य थे ही नहीं। उनका बौद्धिक

गाठन उनका जीवन-दशन और पृष्ठभूमि, उनका सारा व्यक्तिगत इन भूमिका को प्रदा करने के विरुद्ध था और राजोरान उन्हें बदना नहीं जा सकता था। यदि जहरीले सन्दा और घमन में डूबे कलमों से युद्ध सहे जात तो मनन दश, जिनसे मनन नाराज थे, नष्ट हो जाते। समुक्त राष्ट्र के एक प्रत्यानुष्ठान ने मनन को घमदी शांति दूत कहा था।

कई वर्षों से समुक्त राष्ट्र तथा अन्य स्याकों में मनन पूरे उत्साह से निरस्त्रीकरण की पैरवी करत रहे थे और युद्ध को पूरे जोर से धिक्कारत रहे थे। नेहरू की तरह उनका भी विश्वास था कि इस घण्टी युग में युद्ध एक दक्खिनी चीज है और मानवता की आत्म हत्या का साधन है।

समुक्त राष्ट्र सभ में निरस्त्रीकरण पर एक बहुसंख्यक मनन ने कहा था। युद्ध तब से चले पा रहे हैं जब से मानवता है। लेकिन आज हम ऐसे समय में रहे रहे हैं जब सम्य मानवता युद्ध को अनिवार्य नहीं समझती है या तो मनुष्य युद्ध को खत्म कर देगा या युद्ध मनुष्य का।"

स्वयं घपना यह दशान होने हुए मनन ने दश की सुरक्षा आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया और प्रतिरक्षा उत्पादन की योजनाओं पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर दी—यह योजनाएँ कुछ वर्षों के बाद ही देश के लिए लाभदायक हो सकती थीं।

प्रथम व सेना के सामने स्वरित रूप से उपस्थित कार्य की आवश्यकताओं से बेखबर थे। यह वाप था हिमालय की दुम वर्षाओं की चोटियाँ पर डट कर देश के सीमान्त की रक्षा करना। ऐसा अनुभव भारतीय सेना को पहले कभी नहीं हुआ था और इसके लिए भिन्न तथा विशेष प्रकार के प्रशिक्षण तथा साधनों की आवश्यकता थी। वास्तव में इसका कुछ स्वाद सेना की भित चुका था। सन् ४८ के कश्मीर युद्ध में जोशीला सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों ने सड़ने में।

सन् ४७ में देशविभाजन के समय भारत के पास काफी सैनिक साधन थे। सन् ६२ तक उनमें से अधिकांश बेकार हो गये थे। बारबार सरकार का ध्यान इस ओर आरुपित किया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई ऊर्ध्व नहीं उठाया गया था। सन ६२ तक गोला बारूद का स्टॉक बहुत कम रह गया था और बाहनों की हालत बहुत खराब थी।

सन् १९६२ में केवल रायप्रनों की ही आवश्यक संख्या में ६०,००० की कमी थी। पश्चिमी कमांड के दो पूरे टैंक रेजिमेंट निष्क्रिय हो चुके थे। राठार द्वितीय महायुद्ध के समय के थे और दक्खिनी हो चुके थे २५ पाउंड की तोपों के लिए मुद्रिकन से तान बहने के लिए पर्याप्त होते थे। इन्जिनियरिंग उपकरण होने पुराने ढब के थे कि लगभग बेकार थे और सिमल के उपकरणों का प्राथमिकीकरण करना आवश्यक था।

गोघ्रा में पुर्तगालियों के साथ युद्ध करने वाले १७ वें डिवीजन के पास जूतों की बहुत कमी थी। सोभाय की बात यह थी कि गोघ्रा युद्ध केवल एक हफ्ते में समाप्त हो गया था। देश में बने होने के कारण सेना को दिये गये उपकरण न उतने अच्छे थे और न पर्याप्त। उदाहरणार्थ, नेफ्रा में एक दस्ते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे दस्ते को उन चीजों से वंचित रखा जाता था।

कौल ने अपनी पुस्तक 'घनकहो कहानी' में लिखा है—

मेरे स्याल से मेनन काफ़ी सीमा तक श्री नेहरू के इस दृष्टिकोण की अपनाने के उत्तरदायी थे जिससे वह सेना के आधुनिककरण के लिए पर्याप्त पूंजी, अधिकृत करने तथा कई कमियों को पूरा करने के लिए हमारे प्रस्तावों तथा विनितियों को प्रतिकूल भाव से देखते थे।"

अतः मेनन इस बात के अपराधी हैं कि उन्होंने अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं किया कि भारतीय सेना को हर तरह से इस योग्य बनायें कि ऊँचे तथा पहाड़ी भूप्रदेश पर वह ऐसे शत्रु का सामना सफलतापूर्वक कर सके जो इस प्रकार के युद्ध में दक्ष था और जो संख्या तथा साधनों में हमसे उत्तम था। कम से कम तीन वर्ष पहले से मेनन को मालूम था (या मालूम होना चाहिए था) कि चीन आक्रमण करेगा। देश की प्रतिरक्षा से खेल करने के लिए प्रतिरक्षा मन्त्री को क्षमा नहीं किया जा सकता।

देश में उस समय दो विचारधाराएँ थीं और मेनन उस विचारधारा के नेता थे जो पाकिस्तान की ओर से खतरे की सम्भावना को बढ़ा-चढ़ा कर बताती थी और चीन से खतरे की सम्भावना को घटा कर। इस बात के प्रभाव कि मेनन आदर्शवादी रूप से साम्यवादी चीन के पक्ष में थे, उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक मात्र शत्रु निश्चित कर लिया था—भावनारमक रूप से विस्फोटक कश्मीर प्रश्न पर वह वर्षों से अत्यन्त कुशल सेनानी की तरह पाकिस्तान की धज्जियाँ अपने चतुर तकों से उड़ाते रहे थे। वास्तव में उनकी इसी ध्याति से उन्हें ग्राम चुनावों में भी बहुत सहायता मिली थी।

प्रतिरक्षा मन्त्री की हेसियत से मेनन से यह आशा की जाती थी कि वे हमारे उत्तरी सीमान्त पर तेज़ी से विगड़ती हुई परिस्थिति के बारे में ज्यादा जानकर और सचेत होंगे। सैनिक हेडक्वार्टर तथा उनके मन्त्रालय में आनेवाली गुप्त सूचना विभाग की अनेक रिपोर्टों से पर्याप्त चेतावनी प्राप्त हो गयी थी और तिब्बत सीमा पर संगठित चीनी शक्ति के आकर का भी अन्दाज़ हो गया था। लेकिन इन रिपोर्टों का सरकार की पूर्ण निश्चित धारणा से कोई सम्बन्ध नहीं था और इसलिए मेनन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था।

वास्तव में कई लोग इसे बंद जिम्मेदारी की बात न सहो तो परिस्थिति को समझने की नूल धवद्वय समझत हैं कि जब नेफ़ा सीमा पर सकट के बादल मयनतर हो रह थे तो रक्षा मन्त्री अपना स्थान छाडकर निसो और भिगन के मिलमिले में मयुक्त राष्ट्र चले गये थे ।

उनके जीवनीकार टी० जे० एस० जॉन्सने कहा है कि कृष्ण मेनन, वियेपत १९५६ के बाद, पूरी तरह इस पक्ष में थे कि सीमान्त के बीनी सकट के खिलाफ पूरी गति और क्रियाशीलता से काम किया जाये और उन्होंने इस बात के लिए कहा प्रयत्न किया था कि तिव्वत सीमापर अपने प्रतिरक्षा साधनों को संगठित करने के लिए सरकार पर्याप्त पूँजी अधिकृत कर दे लेकिन मन्त्रिमंडल वियेपत अथ मन्त्री ने उनका हर प्रयत्न विफल किया था और जॉर इस बात पर दिया था कि चीन के खिलाफ सैनिक नही राजनयिक कारवाई की जाय । जॉन्स न लिखा है

“सन् ५७ में अक्माइ चिन घामते के बाद कृष्ण मेननने मन्त्रिमंडल से स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सीमान्त प्रतिरक्षा का ऐजी से संगठित करना अनिवार्य है । लेकिन मन्त्रिमंडल का विचार था कि इन सकट को राजनयिक रूप से छल्ल करना चाहिए ।” मन्त्रिमंडल की यह प्रवृत्ति होने के कारण मेनन को हर बात में बाधाधा और कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा था कार्यान्वित होने के स्तर तक पहुँचन-पहुँचन उनकी सारी योजनाएँ धटक जाती थी ।

“उत्तरी सीमान्त पर हमारे तैयार रहने की आवश्यकता को पूरी तरह अनूबर १९५६ में घोषित गया था लेकिन इस पर भी अथ मन्त्रालय का आग्रह था कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और प्रोग्रामों को धीरे-धीरे एक-एक अंग करके कार्यान्वित किया जाय । रक्षा मन्त्री के अनुसार इस काम को पूरा करने के लिए ५,६०० लाख रुपये की आवश्यकता थी, जिसमें १३७० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी थी ।

‘अर्थ मन्त्रालय ने विदेशी मुद्रा अधिकृत करने में इनकार कर दिया और कहा कि रक्षा मन्त्रालय को समय-समय पर अधिकृत की जाने वाले विदेशी मुद्रा से ही काम चलाना चाहिए । इसके फलस्वरूप १९६२ तक केवल ४,१०० लाख रुपये खर्च किये जा सके और १,३७० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के बजाय ४५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा ही प्राप्त हुयी ।”

इस विषय पर बात करत हुए मेनन ने झुझसा कर अर्थ मन्त्रालय द्वारा स्थापित समय खराब करने वाली कार्यविधियों की ओर सकेत किया जिनकी वजह से आवश्यक पूँजी बहुत देर से अधिकृत हो पाती थी । उन्होंने यह भी

कहा कि अर्थ मन्त्री मोरारजी देसाई तथा उनके बीच व्यक्तिगत वैमनस्य था जिसके कारण अक्सर झगड़ा हो जाता था ।

लेकिन श्री देसाई ने मुझ से बात करते हुए इस बात से इनकार किया कि उनके तथा मेहन के बीच कभी कोई जाती बहस हुयी । उन्होंने कहा कि यह बहस मेहन तथा रक्षा मन्त्रालय में अर्थ मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा रक्षा मन्त्रालय के किसी नये अर्थ को अधिकृत करने वाले वित्त सलाहकार के बीच ही होती थी ।

यह बात कि मेहन तथा मोरारजी को एक दूसरे से कतई प्रेम नहीं था दिल्ली में एक खुला राज था । मेहन ने कहा कि मोरारजी के अलावा पंडित पंत भी मन्त्रिमंडल की बैठकों में हमेशा उनका विरोध करते थे । मेहन के अनुसार पंत उन्हें साम्यवादी समझते थे और जानबूझ कर मेहन की हर बात को काटते थे ।

रक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय के बीच इन झगड़ों पर बात करते हुए इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि कम से कम मनोबैज्ञानिक रूप से, मेहन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे ।

फिर भी कई तटस्थ दर्शन साक्षियों ने कहा है कि अधिकतर झगड़े और कठिनाइयाँ इस कारण पैदा होती थी कि वितरण के लिए प्राप्य विदेशी मुद्रा को देखते हुए रक्षा मन्त्री की मांगें बहुत ऊँची होती थीं । मूल्यवान विदेशी मुद्रा के संरक्षक की हैसियत से अर्थ मन्त्री का कर्तव्य था कि किसी भी मांग को पूरी तरह जाँचें और इसलिए वह दूसरे को कृपण तथा कल्पना शून्य लग सकते थे । और मेहन के अपने स्वभाव के कारण परिस्थिति और भी खराब हो जाती थी ।

'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में 'एक मिलीटरी ऑक्सवॉर' \* ने कील की पुस्तक 'अनकही कहाती' की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह झगड़े क्यों और कैसे पैदा होते थे । "अपने कमरे में होने वाली मीटिंगों में, जिसमें तीनों सैनिक मांगों के सेनापति-सेना केपी० एस० आ० तथा प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित रहते थे, मेहन अर्थ मन्त्री और उनके मन्त्रालय के बारे में इतनी कटु टिप्पणियाँ करते थे कि स्पष्ट था कि वे दोनों में से किसी की परवाह नहीं करते । वास्तव में कई महत्वपूर्ण मीटिंगें बीच में ही खत्म हो जाती थी इसलिए कि रक्षा मन्त्री तथा वित्त सलाहकार के बीच बहुत गर्भ बहस छिड़ जाती थी और अन्त में वित्त सलाहकार कह देते थे कि उस विशेष प्रस्ताव के बारे में (जिस पर सारी बहस थी) उन्हें अपने मन्त्री के आदेश लेने पड़ेंगे ।"

'मिलीटरी ऑक्सवॉर' ने आगे कहा है "वित्त सलाहकार कभी भी बीच में तोड़ा डालने का प्रयत्न नहीं करते थे—कुल झगड़ा इस कारण होता था कि

\* विस्वास किया जाता है कि जनरल एल. पी. सेन इस नाम से लिखते थे ।

जिन पूँजी की माँग की जाती थी वह बजट में सेना के नाम अधिष्ठित विदेशी मुद्रा की माँग से नहीं स्पादा हानी थी।"

मनन के जीवनीकार ने एक और बाधा की ओर मक्रेन किया है और वह यह कि "मभरए तथा निपटान का महानिदेशालय, जिस पर सेना का बजट देन का उत्तरदायित्व है, माँग को नभय से पूरा नहीं कर पाता था। इसका कारण था कि वह प्रतिबद्ध था सरकार को इस नीति से कि मधुउद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय। इसलिए इस निदेशालय के लिए अनिवार्य था कि छात्र धुनिडा से सामान मगाये और हमसे अनावश्यक देरी हो जाती थी।"

एक तारा उदाहरण—प्रतिरक्षाघोष विभाग ने १९५९ में ही स्वचालित राइफल का प्रतिकल्प तैयार कर लिया था लेकिन वह भारी योजना संनिक हेडक्वार्टर में पहुँच कर अटक गयी थी और मार्च १९६० तक वह प्रतिकल्प पास नहीं हो सका था।

इसो के समयन में यह बताया गया कि सन् '६२ में श्री नेहरू ने संसद में यह गवाही दी थी कि रक्षा मंत्री १९५८-६९ में इस बात पर जोर देन रहे थे कि धाधुनिकतम अस्त्रों का कई मुत्रो से, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों से भी प्रौन्न खरीदना अत्यन्त आवश्यक है 'लेकिन कई कठिनाइयाँ पैदा हो गयी और दृष्टिकोणों में मतभेद पैदा हो गया।"

वास्तव में जॉर्ज तो यह ठक कहते हैं कि आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में ही मेनन का प्रधान मंत्री की चीन सम्बन्धी नीति से मतभेद था। इस बात का स्पष्ट करने हुए जॉर्ज ने निष्ठा है "चीन में स्थित भारतीय राजदूत (सरदार पनिकर) ने श्री नेहरू को आश्वासन दिया था कि चीन तथा भारत के बीच संधर्ष की कोई सम्भावना नहीं है। इस आधार पर भारत ने अपनी चीन नीति बनायी थी। मेनन ने उस समय भारतीय राजदूत के इस आश्वासन पर सन्देह प्रकट किया था लेकिन अपनी बात का समर्थन करने के लिए उनके पास प्रमाण नहीं था। अतः मेनन ने सरकार की नीति से अपने को एक रूप कर लिया और भारत तथा चीन के बीच सन्धी मित्रता स्थापित करने के लिए हर प्रयत्न किया।

अनसाइचिन की घटना के बाद मनन का प्रारम्भिक सदेह फिर आपत हुआ हाताकि सेष मन्त्रिमण्डल को अपने अनुकूल बनाना फिर भी मुदिकन था। फिर भी स्वभावगत, आदर्शवादी तथा धार्मिक आधामों को किसी तरह फला-गते हुए मेनन ने मार्च निर्माण, पवतीय मुद्रा प्रशिक्षण तथा अस्त्र उत्पादन का एक तद्वि प्रोग्राम शुरू किया। भारत के इतिहास में पहली बार दुग्म हिमालय पवत पर अपनी प्रतिरक्षा को समलित करने का प्रयत्न किया जा रहा था। लेकिन गुरुभात देर से हुयी थी। मेनन का प्रोग्राम अभी तेजी से चलने का प्रयत्न कर ही रहा था कि चीनियों ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया।"

## सेनापतियों के लिए एक दुस्स्वप्न

रक्षा मंत्री बनने के बाद कृष्ण मेनन ने यह तय कर लिया था कि देश की प्रतिरक्षा के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम है—यही नहीं, वह यह भी समझ ले कि सेना के तीनों धगों के प्रमुखों को वह कुछ सिखा भी सके हैं। इसमें भी बुरी जान यह थी कि उन्होंने रक्षा मन्त्रालय में राजनीति चलाने शुरू कर दी थी जिससे बारण सैनिक हेडक्वार्टर में गुट बन गये थे।

उन्होंने प्रवर अधिकारियों को अपने से बड़े अफसरों के खिलाफ खड़े होने में प्रोत्साहित किया था और उन्हें बड़ावा दिया था कि प्रवर अधिकारियों के मिर के ऊपर, सीधे उनसे सम्पर्क रखें। वह सेना के तीनों धगों के प्रमुखों को भ्रष्ट होने में और उपेक्षापूर्वक उनकी प्रवीण राय टाल देते थे। इस प्रकार उन्होंने बरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के धातम-सम्मान को घोट पड़ोचायी थी और सेना की अफसर श्रेणी में आवश्यक अनुशासन को पूरी तरह बिगाड़ दिया था।

नक्सले के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' नामक पत्र में 'एक मिलिटरी प्रॉब्लम' के विषय में "अधिकारियों को पीछे छोड़कर, मेनन सीधे स्टॉफ अफसरों को बुला भेजते थे या उनसे टेलीफोन पर बात करते थे। उनकी इस भावना से बात और भी बिगड़ गयी थी। उनके इस रवैये को न स्टाफ अफसर पसन्द करते थे, न तत्कालीन सेनापति जनरल पिमेंथा। लेकिन सत्ताही दौर पर शासन करने के लिए भारत में, यह तय कर लिया गया था कि स्टाफ अफसर मंत्री को मांगी गयी सूचना तो आवश्यक दे देंगे लेकिन साथ ही अपने-अपने प्रमुखों को सतिसप्त रूप में बना देंगे कि क्या सूचना दी गयी थी।"

सबसे खराब यह दिखायत भी की गयी थी कि सेना के तीनों धगों के प्रमुखों को मेनन केवल "गौरवपूर्ण कार्यकर्त्ता" समझते थे। इस प्रकार उन्होंने उनके प्रभुत्व तथा प्रभाव को खत्म कर दिया था और सैनिक प्रमुखों को हम



वात पर मजबूर कर दिया था कि वे उनके निश्चयों को स्वीकार करें भले ही वे निश्चय सही हों या गलत ।”

‘मिलिटरी ऑवर्जर्नर’ ने यह भी बताया कि मेनन हमेशा विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद करने के लिए मीटिंगें किया करते थे लेकिन या तो उन विषयों पर कभी बहुत होती ही नहीं थी या यह वहाँ से अदूर रह जाती थी । “इस बात से बचने के लिए कि उन्हें कोई निर्णयात्मक निश्चय न लेना पड़े, मेनन या तो किसी अक्सर विषय पर या सामान्यतः सेना के किसी ग्रंथ पर कोई न कोई कटु टिप्पणी कर देते थे । कभी-कभी उन्हें किसी प्रस्तुत विषय में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी और ऐसी हालत में वे किसी असम्बन्धित विषय पर बात करके सारा समय खर्च कर देते थे और यह बहाना करके मीटिंग खत्म कर देते थे कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है । स्वाभाविक था कि ऐसी हालत में सेना प्रमुख तथा उनके पी० एस० ओ० कूट तथा निराश हो जाते । प्रस्तुत विषय पर सुलासा तैयार करने तथा उसे समझाने में उनका काफ़ी मूल्यवान समय नष्ट हो जाता था ।”

मेनन ने सैनिक हेडक्वार्टर में अपना विद्वत्स गूठ बनाने का भी प्रयत्न किया था और इसके लिए ऐसे लोग इकट्ठे कर लिये थे जो या तो उनके पिछू थे या उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार थे । अपनी इसी नीति के अन्तर्गत, सेना प्रमुख तथा उनके पी० एस० ओ० के विरोध के बावजूद, वे कौल को सैनिक हेडक्वार्टर में ले आये थे । इस विषय पर ‘मिलिटरी ऑवर्जर्नर’ ने लिखा है :

“इसके बाद प्रश्न उठा कि क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर किसको नियुक्त किया जाये । कौल की नियुक्ति सैनिक चुनाव मंडल के द्वारा नहीं हुई थी । सैनिक कमान्डरों आदि ने जनरल थिर्मिया को यह सलाह दी थी कि वे इस पद के लिए कौल का नाम प्रस्तावित न करें । कौल के इस पद पर नियुक्त होने में, सबसे बड़ा खतरा यह था कि क्वार्टर मास्टर जनरल होते ही वे सैनिक चुनाव मंडल के सदस्य बन जायेंगे और इससे सेना के अधिकारी वर्ग की अक्रादारी और उनके अनुशासन पर और भी बुरा असर पड़ेगा । लेकिन इस पद के लिए मेनन कौल के अलावा किसी और अक्सर के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं थे । इसलिए काफ़ी शम्मीर भगड़े के बाद, थिर्मिया को इस बात पर विवश होना पड़ा था कि कौल को क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में स्वीकार करें । अपने मूलतः सज्जन स्वभाव के कारण, कौल के पूछने पर, थिर्मिया ने इस बात से इनकार किया था कि यह बात उनके त्याग-पत्र देने का कारण थी । मेनन तथा

धिमैया के बीच के काफी समय से दकड़े होते हुए तनाव का यह अन्तिम विस्फोट था।”

मेनन तथा भारत ने सर्वोत्तम सेनानी धिमैया के बीच का मतभेद एक सर्वविदित कहानी बन गया था और उसकी चरम अभिव्यक्ति थी धिमैया का त्यागपत्र देना। बाद में प्रधान मंत्री ने धिमैया को इस बात पर मना लिया था कि वे अपना त्याग-पत्र वापस ले लें। मेनन दूसरे सैनिक अगो के प्रमुखों के साथ भी इसी ही बुरे तरह पेश आते थे।

जनरल धिमैया के त्याग-पत्र के विषय पर बोल कर रहे हुए मेनन ने कहा कि नयी दिल्ली में स्थित पोलैण्ड के दूतावास की एक पार्टी में स्वयं धिमैया या उनके कुछ मित्रों ने (धिमैया के त्याग-पत्र वापस ले लेने के बाद) यह सारी बात खुफ़े से ‘स्टेड्समैन’ के सम्वाददाता को बता दी थी। मेनन का यह भी कहना है कि अशोक मेहता ने धिमैया का त्याग-पत्र लिखा था।

कौन की नियुक्ति की तरह अन्य विवादपूर्ण नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों की जिम्मेवारी भी मेनन ने स्वीकार नहीं की। मेनन के आग्रहपूर्वक कहा यह सारी नियुक्तियाँ सेना प्रमुख द्वारा स्वीकृत थीं हालांकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नियुक्तियों के तथा अन्य मामलों में मेनन ने तीनों सेना प्रमुखों को इस बात पर विचार कर दिया था कि वे उनकी बात मानें।

१९६१ के एक उपादन सम्मेलन में मेनन ने कहा था “७५ फ्री सरी कठिनाइयाँ तीनों सेना प्रमुखों के कारण पैदा होती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे निरक्षर नहीं होते, मैं यह कह रहा हूँ कि उनके पास निश्चय लेने की मानसिक क्षमता है ही नहीं।”

मेनन भले ही अपनी इस वाक् पटुता पर खुश हुए हों लेकिन लुली सना ने प्राप्त हुए इस सबारण अपमान के तिकार उनकी इस उक्ति को मनोरञ्जक नहीं समझते थे।

इसके अलावा मेनन की यह आदत भी कि ‘परामर्श’ के लिए वे किसी न किसी सेना प्रमुख की अटपटीय समय पर, यहाँ तक कि आधी रात की भी बुला बैठने के पीर उसके बाद उनकी घटों इन्तजार करवाते थे। अन्त में जब मेनन, काफी देर बाद प्रगट भी होने से तो या यह कह देने से कि वे विलुप्त ही मूल गये कि उन्होंने सेना प्रमुख को क्यों बुलाया था या उनके साथ ऐसे किसी महत्वहीन विषय पर बात चुरू कर देते थे जिसके लिए अगले दिन तक रत्ता या सबना था।

जब मैंने मेनन से कहा कि इन आरोपों का उत्तर दें तो उन्होंने सक्षिप्त और रहस्यपूर्ण ढंग से सिर्फ इतना ही कहा “युद्ध से क्यों पूछने हैं?”

इस प्रकार मेनन जो शुरू में अत्यन्त सर्वप्रिय रक्षा मंत्री थे अब अत्यन्त अप्रिय रक्षा मंत्री बन गये थे ।

मेनन को चिढ़ थी ऐसे सब सैनिक अधिकारियों से जो स्वतन्त्ररूप से सोचने और निश्चय लेने की क्षमता रखते थे । धिमैया, योराट, चौधरी, सेन, मानेकशाँ और वर्मा जैसे जनरल सेना के लिए जिनकी सेवाएँ गौरवपूर्ण थीं, मेनन को हादिक रूप से नापसन्द थे ।

वास्तव में, किन्हीं अभिकथित टिप्पणियों के कारण मेनन ने धिमैया और योराट के खिलाफ जाँच कारंवाई शुरू करवा दी थी । वर्मा के विरुद्ध तो एक पूरी जाँच समिति ही बैठा दी गयी थी लेकिन इस समिति ने उन्हें अपराधहीन करार दिया था । इस प्रकार की समिति मानेकशाँ पर लगाये गये आरोपों की छान-बीन करने के लिए भी बैठायी गयी थी । समिति ने जनरल मानेकशाँ को निर्दोष पाया था लेकिन इस पर भी मेनन ने उनकी तरफकी रोक दी थी ।

मेनन ने एक बार इस बात की तरफ भी संकेत किया था कि धिमैया राज्य विप्लव करना चाहते हैं और विश्वास किया जाता है कि रक्षा मंत्री के आदेशों के अनुसार प्रशासकीय अफसर उन पर निगरानी रखते थे । उस समय यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि धिमैया को भारत का सबसे पहला पांच-स्टार जनरल बना दिया जाये लेकिन मेनन ने ऐसा नहीं होने दिया था ।

सेना के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ मेनन के मन में इतना खरबखत पूर्वाग्रह पैदा हो गया था कि वे उनमें से किसी में कोई अच्छाई नहीं समझते थे । योराट को वह जिद्दी और बड़-बड़कर बातें करने वाला आदमी समझते थे और इस कारण, धिमैया के निवृत्ति प्राप्त कर लेने के बाद, उन्होंने योराट को सेनापति नहीं बनने दिया था । मेनन के अनुसार एक वरिष्ठ सैनिक अफसर 'काहिल' था, दूसरा 'पूर्णतः अयोग्य', तीसरा 'विद्विमान', चौथा 'औरतों में दिलचस्पी रखनेवाला' ।

रक्षा मंत्री की हेसियत से उन्हें सेना से कितना गहरा असन्तोष था यह मेनन के इन शब्दों से प्रगट है : "सैनिक अधिकारियों के नैतिक आचरण का स्तर बहुत नीचा था और उनमें कोई गुण नहीं थे । भारतीय वायु सेना पूर्णतः अयोग्य थी और रसद तथा अन्य सामान गहरी खाइयों और दूसरी गलत जगहों में गिराती थी । सरकार पर्याप्त विदेशी मुद्रा अधिकृत नहीं करती थी—सब इस बात के खिलाफ थे कि प्रति रक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाये । यह महात्मा गांधी का देश था । ऐसी हालत में हम अपने निर्भय सशस्त्र के साथ केवल शत्रु-रंज का खेल ही खेल सकते थे ।"

मेनन के मन में जनरल थापर के लिए भी अपेक्षा थी हालाँकि उन्होंने योराट के बजाय थापर को सेनापति नियुक्त किया था । मेनन ने १९६४ में

मुर्कें बताया कि चापर की नेफ़ा के विभिन्न स्थानों के माध तब नहीं मालूम थे। नेफ़ा की पराजय के बाद मेनन ने इस बात से भी इनकार किया कि सेनापति के पद पर चापर की नियुक्ति वे वे जिम्मेदार थे। उल्टे, मेनन ने कहा 'सेना में अपने प्रभाव के कारण चापर ने अपने आप को पश्चिमी कमान्ड के सेनापति के बरिष्ठ पद पर नियुक्त करवा लिया और पोरबट का तबादला पूर्वी कमान्ड को हो गया।'

१९६१ के बजट के डीक पहले मेनन ने बरिष्ठ पत्रकारों को निमंत्रित किया था उन्हें प्रतिस्था की समस्याओं की जानकारी देने के लिए। इस अनौपचारिक मीटिंग में मेनन ने प्राग्रपूर्वक मुँह से कहा था कि पोरबट के मुकाबिले चापर की देबाई ज्यादा योग्यतापूर्ण और उत्तम थी। मैंने जब उन्हें इस बात पर चुनौती दी तो उन्होंने मजाक किया : 'धृष्टा तो एक महाराष्ट्रियन दूसरे महाराष्ट्रियन का बल लेते हैं कोशिश कर रहा है।'

मेनन पर सबसे गम्भीर आरोप यह है कि आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे सफ़रपूर्ण समय उन्होंने सेना के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण पदों पर दो अव्यक्त जनरल नियुक्त किये। भारत के सबसे उत्तम जनरल उस समय या तो युद्ध क्षेत्र से दूर मजबूरन टमुआ बैठे थे या उन्हें रिटायर किया जा रहा था। पोरबट बाहर ही ही चुके थे, चौपरी बाहर निकाले जा रहे थे।

प्रत्यक्ष रूप से प्रधान सेनापति के पद के लिए चापर की सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि वे मोम की तरह ढाले जा सकते थे—मेनन के अनुसार पोरबट यही स्वभाव के थे। मेनन की विश्वास था कि अपने अत्यन्त साधारण सेवा रेकार्ड के बावजूद प्रधान सेनापति नियुक्त किये जाने के कारण चापर मेनन के प्रति ईर्ष्या होंगे और उनके हाथों में कठपुतली बन जायेंगे।

लेकिन बाद में मेनन की निराश होना पड़ा क्योंकि चापर ने मात्र कठपुतली बने रहने से इनकार कर दिया। दो अवसर पर चापर ने डट कर अपने विद्विष्टे रक्षा मंत्री का विरोध किया।

श्री मेना हेडक्वार्टर के प्रमुख के रूप में, इसी तरह, पत्रिका-दुःखकर्ता जैसे बरिष्ठ तथा योग्यतर अधिकारी के बजाय उन्होंने शान्त स्वभाव वाले एयर एडमिरल वी० एम० एस० सोमन को पसन्द किया और वायु सेना के प्रमुख के रूप में आसानी से ढाले जा सकने वाले एयर वाइस मार्शल हजीनियर की।

इसी तरह जनरल स्टाफ के प्रमुख के पद पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल वी० एम० कौन को नियुक्त किया इसलिए नहीं कि कौन में साधारण सैनिक गायनता थी बल्कि इसलिए कि प्रधान मंत्री कौल की बात सुनते थे।

देश में मेनन के बहुत कम मित्र थे और भी नेहरू ही उनके राजनितिक प्रतिस्तर के एक मात्र आधार थे। अतः उनका विशेष हित इस बात में था कि

## अपराधियों के बीच

जब बात बिगड़ने लगती है तो सम्बन्धित लोग तेजी से एक-दूसरे पर दोषारोपण करने में व्यस्त हो जाते हैं। अतः चीन के हाफो १९६२ में पराजित होने के विषय पर प्रकाशनीय धामूचना एजेन्सी, सी० घाई० बी०, को भी (जिस पर सेना निर्भर थी) खत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक शोध दिया गया है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि युद्ध स्थल पर स्थित सेना की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी० घाई० बी० की बायबिपि तथा उसके तरीकों की काफी हद तक बख्ता जरूरी है। एशामशालय द्वारा प्रस्तुत किए गये हथिरतन वृत्त रिपोर्ट के संक्षिप्त संस्करण में कहा गया है "जब से यह पता चला है कि धामूचना के इकट्ठा करने का ढंग सामान्यतः सन्दीपनक नहीं था। धामूचना मुस्ती से प्राप्त की जाती थी और उन्हें प्रस्पष्ट ढंग से रिपोर्ट किया जाता था।"

भागे कहा गया है 'धामूचना का दूसरा पहलू है उसको एकत्रित करना तथा उसको मूल्यांकन करना। यह बात मानी जा सकती है कि धामूचना के प्रस्पष्ट होने के कारण उसका मूल्यांकन पूरी तरह ठीक ढंग से न किया जा सका हो। इसीलिए चीनी सैनिक सचित्र की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त नहीं हो सकी थी। इस बात का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था कि खत की पुरानी सैनिक व्यवस्था से नये संगठन का सम्बन्ध जोड़ा जाय। इस प्रकार मोर्चे पर हमारे दलों को इस बात की बहुत कम सूचना थी कि 'खत' के पास नये दस्ते हैं या पुराने दस्ते ही नये स्थानों में धा गये हैं। तीसरा पहलू है धामूचना का प्रसार। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि धामूचना से कोई लाभ उठाना है तो महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रविष्टीभूत से मोर्चे पर स्थित दस्तों तक पहुँचाया आवश्यक है।

रक्षामंत्री ने लोक सभा में अपने वक्तव्य के अन्त में कहा कि "इस बात में कोई सन्देह नहीं कि हमें अपनी आसूचना व्यवस्था की काफी सीमा तक कायापलट करनी होगी।"

सन् '६५ के भारत-पाक युद्ध के समय भी सैनिक हेडक्वार्टर ने सी० आइ० वी० की कड़ी आलोचना की थी। इसके विपरीत सी० आइ० वी ने शिकायत की थी कि सैनिक हेडक्वार्टर अक्सर उनकी रिपोर्टों और मूल्यांकनों को ध्यान नहीं देता और उस समय तक उन पर कार्य नहीं करता जब तक घटनाओं से यह साबित नहीं हो जाता कि वे रिपोर्टें सही थीं।

उदाहरणार्थ, सी० आइ० वी० का दावा है कि १९६५ में कई दिन पहले सैनिक हेडक्वार्टर को यह सूचना दे दी गयी थी कि पाकिस्तानी भारी संख्या में अन्तःसरण कर रहे हैं और जम्मू के छंव सेक्टर में पाकिस्तानी आक्रमण की पूर्व सूचना दे दी थी। लेकिन हेडक्वार्टर ने उनकी रिपोर्टों की ध्यान नहीं दिया था और दी गयी सूचना से कोई साभ नहीं उठाया था।

लेकिन इस बात का लासिक उदाहरण कि सी० आइ० वी० के लिए सेना की विशेष आवश्यकताओं को समझना जरूरी है, वह सूचना रिपोर्टें जो १९६५ में सैनिक हेडक्वार्टर को दी गयी थीं और जिनमें बताया गया था कि सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान का आर्मंड डिवीजन देखा गया है।

क्योंकि उस समय तक सैनिक हेडक्वार्टर को यह पता नहीं था कि पाकिस्तानी सेना ने एक दूसरा आर्मंड डिवीजन संगठित कर लिया है, इसलिए यह तथ्य मान लिया गया कि सियालकोट में १ ला आर्मंड डिवीजन ही देखा गया है। बाद में यह प्रगट हुआ कि सियालकोट में जो आर्मंड डिवीजन देखा गया था वह नव संगठित ६ठा आर्मंड डिवीजन था और उनका अत्यन्त सक्षम १ ला आर्मंड डिवीजन भारत पर क़बरदस्त तड़ित आक्रमण करने के लिए खेमकरण सेक्टर में स्थित था।

सियालकोट सेक्टर में देखे गये पाकिस्तानी आर्मंड डिवीजन को पहिचानने में सी० आइ० वी० की असमर्थता सैनिक दृष्टिकोण से अक्षम्य थी और इसकी वजह से खेमकरण सेक्टर में काफी क्षति उठानी पड़ी थी। क्योंकि हमें यदि पता होता कि पाकिस्तान का अधिक शक्तिशाली आर्मंड डिवीजन सियालकोट के बजाय दक्षिण में स्थित है तो हम खेमकरण पर पाकिस्तान के जोरदार आक्रमण का ज्यादा अच्छी तरह मुकाबिला कर पाते।

जहाँ तक १९६२ की घटनाओं तथा सी० आइ० वी० के काम का प्रश्न है, वहाँ यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि उसकी कुछ रिपोर्टों में स्पष्टता की कमी थी, फिर भी सी० आइ० वी०, विशेषतः १९५६ के बाद की रेखा के उस पार शत्रु की सरगर्मी के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाओं का सारा महत्व खत्म हो गया

या क्योंकि सैनिक हेडक्वार्टर को इन रिपोर्टों पर बहुत कम विश्वास था और वे उनके आधार पर बहुत कम काम करते थे।

१९१६ और १९६२ के बीच सीमा के निम्न पक्ष पर चीनियों की तेज सैनिक सरगर्मी के बारे में कुछ प्रत्यक्ष प्रमुख और विस्तारपूर्ण रिपोर्ट पत्रों में छपी थी लेकिन रखा गया विद्वत् मन्त्रालयों ने पूरी कोशिश करके उनको दबा दिया था केवल इसलिए कि वे उनके अपने अनुमानों से मेल नहीं खाती थी।

यह स्पष्ट है कि सी० आइ० बी की रिपोर्टों पर (जिनमें से कई प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा महत्वपूर्ण थी) सैनिक प्रामुखता निदेशालय के विश्वास न करने के कारण १९६२ के वेप्रा युद्ध में मैनिफेस्ट कार्रवाइयों में और भी अधिक कठिनाइयाँ पैदा हुई थी।

सैनिक हेडक्वार्टर का नवीनतम दृष्टिकोण (जिसे १९६१ के भारत-पाक युद्ध के कारण और भी प्रोत्साहन मिला है) यह है कि प्रामुखता कार्रवाई के सैनिक पक्ष की सी० आइ० बी से छोन कर सैनिक प्रामुखता निदेशालय को सौंप दिया जाये। इसमें यही खराबी नहीं है कि ऐसा करने से अतिरिक्त खर्चा होगा और काम दोहराये जायेंगे बल्कि यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सैनिक प्रामुखता निदेशालय (जिनमें प्राक्कल सम्भवताही तथा बकरी अपि-कारियों की भरमार है) सी० आइ० बी से ज्यादा कुशल और कारगर रूप से काम कर सकेगा।

इसके अलावा सैनिक प्रामुखता निदेशालय का प्रमुख एक 'उपेक्षी चिन्ता' है। यह केवल दो वर्ष के लिए इस पक्ष पर नियुक्त किया जाता है और न वह कोई विशेषज्ञ होता है। प्रामुखता एक अत्यन्त विशिष्ट विज्ञान है और उसका अपना एक अत्यन्त विकसित तन्त्र है। केवल विशेषज्ञ और अध्ययायी लोग ही इस कार्य का कुशलता से कर सकते हैं।

X

X

X

यह प्रस्तुत है कुछ और तथ्य तथा तत्त्व जिनमें १९६२ की चेष्टा में भारत पराजय का अपराध बाट देना चाहिए।

श्री नेहरू, मेन्न तथा उत्काञ्चीन सैनिक नेवाघो के बाद अपराधियों की पेशकश में नाम है सचद विरोधी दल का। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विरोधी दलों ने अपने विचारहीन व्यवहार से प्रधानमन्त्री को गलत अवसर पर चीन की समस्या पर एक कड़ा दृष्टिकोण लेने के लिए विवश कर दिया था। विवशता के कारण अपनाये गये इसी दृष्टिकोण के फलस्वरूप उन्होंने गलत समय और गलत स्थान पर सन्धि की चीनियों से मुद्रा करने का आदेश दिया था।

अक्तूबर १९६२ में जब तैफा सीमा पर युद्ध शुरू हुआ, तब तक विरोधी दल ने नेहरू सरकार को समय से पहले एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से लौटना असम्भव था और जिसके बाद केवल एक ही कदम उठाया जा सकता था कि फायर करना शुरू कर दो भले ही बन्दूक में गोली न हो।

और न विरोधी दल इस बात से इनकार कर सकते हैं कि चीनी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने देश को बिल्कुल तैयार नहीं किया था।

वास्तव में वही थी कुपलानी, जो श्री नेहरू की चीन सम्बन्धी नीति के सबसे कट्टर विरोधी थे, १९५६ तक दूसरा ही राग अनापते रहे थे। पूर्णतः गांधीवादी होने के कारण उन्होंने १९५७ में लोक सभा में प्रतिरक्षा बजट पर बोलते हुए कहा था : "सेना पर बढ़ते हुए व्यय को काट देना चाहिए। गांधी के अनुयायियों तथा विद्वत्तांति की कामना करनेवाले लोगों को सैनिक खर्च नहीं बढ़ाने चाहिए अन्यथा उन आदर्शों के नाम में ली गयीं उनकी सारी शपथें भूठ सिद्ध हो जायेंगी।

अगले वर्ष प्रतिरक्षा बजट पर फिर बोलते हुए कुपलानी इससे आगे भी बढ़े। उन्होंने कहा : "मैं निवेदन करना चाहता हूँ—और यह एक ऐसी नाजुक बात है जिसकी ओर मैं संसद का और सारे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—कि हम यह विश्वास करते थे कि अहिंसावादी भारत में, सरकार सैनिक बजट का परिवर्धन करने की बात ध्यान तक में नहीं लायेगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और मेरे ख्याल से वापू की आत्मा को भी इससे कुछ पहुँचा होगा, कि पिछले कुछ वर्षों में प्रतिरक्षा बजट में १३-१४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम अपना सैनिक संगठन क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या किसी देश पर कब्जा करने की हमारी नीयत है?"

वास्तव में १९४७ के बाद सारा संसद ही कुपलानी की तरह, प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च करने के खिलाफ था और बराबर ही प्रतिरक्षा संगठन को बढ़ाने तथा सेना के आधुनिक करण के लिए आवश्यक पूँजी को अधिकृत करने पर आपत्ति करता था।

काफी समय तक संसद में इस बात पर बहस होती रही थी कि एक अहिंसात्मक, गांधीवादी देश को बॉम्बर हवाई कमान्ड की आवश्यकता है या नहीं। इस बहस का आधार यह तर्क था कि बॉम्बर आक्रमणशील हथियार हैं और चूँकि भारत की नीयत किसी देश से युद्ध करने की नहीं है इसलिए भारत को उनकी कोई आवश्यकता नहीं।



इसी तरह बरसों तक सरकार और संसद विमान बाहक जैसी आवश्यक चीज के लिए नौ सेना की इस मांग को अनसुनी करते रहे ।

पूरा राष्ट्र और उसकी संसद इस बात में दृढ़ रूप से विरक्त करत थे कि गांधी के देश के लिए एक बड़ी सेना रखना अनुचित है, कि मात्र के प्रभु गुप्त में मुझ एक दशियानुसी चीज हो यही है और नीति का भस्म नहीं रह गयी है ।

इस प्रकार प्रकृतिगत नृसिद्धा र्व सैनिक अधिकारियों की जाने और मनवाने में की गयी मूलतः गीण हो जाती है ।

## उपसंहार

पिछले छः वर्षों में भारत ने जो दो युद्ध लड़े हैं उनके कारण हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था की कई गम्भीर कमजोरियाँ प्रकाश में आयी हैं। उन्होंने हमें अधिकाधिक इस बात के प्रति सचेत किया है कि हमारी सेना, उसके युद्ध-साधन तथा प्रशिक्षण भयानक रूप से दक्षियानुसी हैं। वास्तव में वे सय द्वितीय महायुद्ध के काल के हैं। उस समय से दूसरे देशों की सेनाएँ नीति, प्रशिक्षण तथा अस्त्रों के क्षेत्र में बहुत दूर तक प्रगति कर चुकी हैं।

हेन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट ने इनमें से काफ़ी बातों का अध्ययन किया होगा। लेकिन उस जाँच का प्राथमिक कार्य था १९६२ की पराजय के कारणों का विश्लेषण करना। १९६२ में चीन के खिलाफ उत्तरी सीमा पर लड़े गये युद्ध में किन कमियों के कारण भारतीय सेना की इतनी भीषण दुर्दशा हुई इसका विश्लेषण करने और इन कमियों को ठीक करने के लिए सुझाव पेश करने के बाद, समिति के लिए प्रत्यक्ष रूप से यह सम्भव नहीं था कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के प्रश्न का व्यापक रूप से अध्ययन करती और देश की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के अनुपात में उसका मूल्यांकन करती।

वास्तव में, उस सीमित कार्य को देखते हुए भी जो उसको सौंपा गया था, हेन्डरसन ब्रुक्स समिति के रास्ते में एक मूल बाधा थी। उसका स्तर इतना उच्च नहीं था कि कार्य की गम्भीरता और उसके महत्त्व को देखते हुए, वह निर्भीकता और स्पष्टवादिता से काम ले पाती।

सेना में काफ़ी लोगों की यह राय थी कि लेफ्टिनेंट जनरल इतना ऊँचा अफसर नहीं कि इस कठिन कार्य को सन्तोषजनक रूप से पूरा कर सके। दूसरों का स्वागत था कि हेन्डरसन ब्रुक्स भारतीय सेना के सर्वोत्तम अफसर नहीं हैं—कहा जाता था कि उनका व्यक्तित्व इतना सौजन्यपूर्ण है कि वे कड़ी जाँच करने के अयोग्य हैं।

हजरतन ब्रुकस समिति को (जिसके दूसरे सदस्य मेजर जनरल प्रेम भगत था) जिन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था यह इसी एक बात से स्पष्ट है कि वह जनरल कौल को गवाही देने के लिए अपना सम्मुख नहीं बुलवा सकी। कौल इस जीव के लिए सबसे कहत्वपूर्ण गवाह थे लेकिन समिति को उनकी लिखित गवाही पर ही संतोष करना पड़ा था।

वास्तव में समिति का कतब्य था कि कौल से विस्तारपूर्वक प्रश्न कर्त्तों क्योंकि वही एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र थे इस बात का पता लगाने के लिए कि अक्टूबर-नवम्बर १९६० में नफ़्ता में बारतब से क्या गड़बड़ हुई थी। कौल ने स्वयं समिति से मिल कर यह भाव की थी कि जबानों गवाही देने के लिए उन्हें बुलाया जाये लेकिन उनकी मांग को प्रत्योकार कर दिया गया था।

इसके लिए यह बहाना दिया जाता है कि कौल पद के दृष्टिकोण से हजरतन ब्रुकस से ऊँचे थे और एक धर धधिकारी के सामने एक प्रवर अधिकारी के गवाह के रूप में बठधरे में खड़े होने से नया भार भग होता था।

होना यह चाहिए था कि कोई अवकाश प्राप्त, पूर्ण जनरल ऐसी महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता करता। जनरल करियप्पा इस पद के लिए सबसे आदर्श व्यक्ति थे—एक उत्तम सेनानी के रूप में उनका बहुत मान था, सेना के सब वर्ग उनका आदर करते थे और वे अत्यन्त ईमानदार तथा साहसी व्यक्ति थे।

पर जिन सीमाओं के बीच हेण्डरसन ब्रुकस समिति काम कर रही थी उन्हें देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसकी रिपोर्टें और उसके सुझाव इतने व्यापक तथा दूर तक पहुँचने वाले नहीं हो सकते थे जितना विषय की गम्भीरता ने दृष्टिकोण से आवश्यक था। उनके लिए अवसर था कि तीनों सैनिक सेवाओं को ध्यान में रख कर हमारे प्रतिरक्षा समूह के पूरा आपुनिकीरण के लिए यह महत्वपूर्ण सुझाव पेश करें।

ऐसी जीव करत समय, इस समिति को धमकीका, इस तथा ब्रिटेन उस मित्र राष्ट्रों से राय लेने में अधिकता नहीं चाहिए था।

भारत के सारे इतिहास में हमारी सेनाओं ने अनेक धाक्रमणों को भेता है और उनमें कभी साहस और शौर्य नी कमी नहीं रही है। लेकिन अक्सर उनके पास उचित अस्त्र नहीं रहे हैं और अक्सर अयोग्य सेनापतियों ने उनका नेतृत्व किया है। एक अच्छे सेनापति का मतलब होता है एक सुप्रशिक्षित, अनुशासित सना।

यह पाठ राष्ट्र के दिल पर अमिट रूप से सुदा हुआ है—१९६२ में चीन के साथ युद्ध ने इस पाठ की ओर भी पुष्टि की है।

इसके पहले कि हमें फिर अपनी सुरक्षा के लिए मुड़ करना आवश्यक हो, हमें इन गम्भीर कमजोरियों को क्रौर्य ठीक कर लेना चाहिए।

इसके बावजूद कि १९६५ में पाकिस्तान से लड़े गये युद्ध में हमारी सेना ने अपना अच्छा परिचय दिया था इस बात की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से है कि हम अपने प्रतिरक्षा संगठन का पूर्ण कार्यान्वयन कर दें ताकि युद्ध नीति तथा असम तन्त्र के दृष्टिकोण से वह पूरी तरह आधुनिक हो जाये और वैयक्तिक पहल क्षमता तथा गतिशीलता को उचित महत्त्व दिया जाये।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब कि हम युद्ध पूर्व की ब्रिटिश सैनिक प्रणाली को अपनाये बैठे हैं, स्वयं ब्रिटिश सेना में कई और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। सेना को डिवाइजनों में विभक्त करने की पद्धति के बजाय लचीले टास्क दलों और काम्यूट दलों की पद्धति अपनायी जा रही है। उदाहरणार्थ इन्फैन्ट्री-आर्टिलरी-आर्मर संगठन के स्थान पर पैराट्रूप-हेलीकॉप्टर-कमाण्डो संगठन की व्यवस्था अब अधिक काम में लायी जा रही है।

१९६२ में स्पष्ट हो गया था कि चीनी सेना, यद्यपि वह हमारी भूमि पर लड़ रही थी, गतिक्षमता, अनुशासन तथा विशेष भू-प्रदेश में लड़ने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में हमारी सेना से कहीं उत्तम थी। चीनी गोरिल्ला युद्ध पर जोर देते हैं और वैयक्तिक पहल क्षमता उनकी सैनिक शिक्षा का मूल अंग है।

पुरानी ब्रिटिश प्रणाली में बंधी हुई भारतीय सेना अभी तक समतल मैदान पर लड़ने के योग्य है और इसलिए ऊँचे तथा दुर्गम भू-प्रदेश पर लड़ने के तरीकों तथा आवश्यकताओं को वह धीरे-धीरे ही अपना पा रही है। मैं जानता हूँ कि १९६२ के बाद से आज तक इस दिशा में काफी प्रगति हुई लेकिन मेरे ख्याल से उतना नहीं हुआ है जितना आवश्यक है—शायद हम अभी तक इस समस्या की सतह पर ही हैं।

हमारा मुख्य शत्रु आज भी चीन है और हमारा मुख्य युद्ध प्रांगण हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। यदि ऐसा है तो हमें अपनी सारी सैनिक विचारधारा तथा सामरिक प्रशिक्षण को इसके अनुकूल ही बनाना होगा। आज पाकिस्तान की समस्या गौण है और यह समस्या कभी लड़ी भी हुई तो हमारी सेना परिचित भूमि पर उत्तम मुकदिला करने की समता रखती है।

ब्रिटिश परम्परा का और अनावश्यक प्रभाव है कि भारतीय सेना का प्रशासकीय अंग उसके लड़ने वाले अंग के अनुपात में कहीं बड़ा है। चीन की सेना में भूमिकल से कोई प्रशासकीय अंग है और इसलिए उसका लड़ाकू अंग बहुत विशाल है। हर चीनी सैनिक अपना राखन अपने ही पैर में रखता है। इसके अलावा यह भारतीय खजाने से ज्यादा कष्ट सहने वाला भी है।

जून १९६७ में रक्षा मन्त्री स्वर्णसिंह ने लोक सभा को यह आश्वासन दिया था कि उन्होंने भारतीय सेना में 'दुब टु टेल्' अनुपात को ५७ : ४३ से घटा कर ६२ : ३८ कर दिया है। यह एक सराहनीय बात है लेकिन काफ़ी

नहीं क्योंकि भारतीय सेना के मुकाबिले में चीनी सेना है जिसे आत्म-निभर होने तथा स्थानीय रूप से प्राप्य भोजन पर जीवित रहने की शिक्षा दी जाती है और जो प्राधुनिक सामरिक नीति के साथ गोरिल्ला युद्ध का भी प्रयोग करती है।

१९६२ के युद्ध में यह प्रदर्शित हुआ था कि ऊँचे पर्वतीय भूप्रदेश पर लड़ने के लिए चीनी सामरिक नीति का मुनाबिला हम नहीं कर सकते। १९६५ के भारत-पाक में यह और भी अच्छा तरह साबित कर दिया कि हमारी युद्ध-नीति प्रशिक्षण, प्रस्न तथा अन्य सामग्री दरियानूसी हैं। भारत-पाक युद्ध के बारे में एक प्रसिद्ध अमरीकी सैनिक टिप्पणीकार ने लिखा है "पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की प्रतिरक्षा पद्धति सफल साबित हुई लेकिन ऐसे युद्धलक्ष्य के खिलाफ यही पद्धति बिल्कुल बेकार साबित होती जो रात में बाजू से परा डालफ, पैराट्रूपों और हेलिकॉप्टर विरचना का प्रयोग करता, टैंकों के आगे आग बँदली सेना तथा नॉम्बैट इन्जीनियरों को रख कर वार करता और घूम घूमता तथा बमों की घनवर्षा वर्षा के पीछे से आक्रमण करता।"<sup>\*</sup>

फील्ड मार्शल सर विलियम स्मिथ ने, जिनके नेतृत्व में भारत तथा ब्रिटिश सेनाओं ने १९४५ में जपानियों को पराजित किया था, भविष्य की आदत सेना की दो मुख्य आवश्यकताएँ बतायी हैं— (१) कुशल तथा दृढ़ संकल्पवाले प्रवर अधिकारी और (२) आतुरीय रूप से कठिनाई सहने की क्षमता रखनेवाले, आत्म निभर तथा अनुशासित सैनिक।

सर विलियम के अनुसार भविष्य के भूमि युद्ध में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसे अधिकारी तथा सैनिक औरत प्राप्त हो जो प्रलग प्रलग छोटी छोटी विरचनाओं में बस कर युद्ध कर सकें। उन्होंने कहा है कि "नये अस्त्रों तथा तांत्रिक युक्तियों को इस्तेमाल करने की शिक्षा सीधे ही दी जा सकती है। कठिनाईयाँ सहन करने की शक्ति पहले क्षमता, आपसी विश्वास तथा निपट नेतृत्व के गुण विकसित करने में ज्यादा समय लगता है।"

क्योंकि युद्ध अस्त्रों के बीच नहीं व्यक्तियों के बीच होता है, इसलिए सर विलियम ने अन्त में कहा है "अस्त्र क्षमता बराबर भी होने के बावजूद जीत उसी पक्ष की होगी जो प्रशिक्षण तथा होसले के दृष्टिकोण से ज्यादा उत्तम होगी। यह ऐसे गुण हैं जो न आसानी से न जल्दी से न धन से ज्यादा और चीजों के बलिदान के बिना।" यह बात जून प्राप्त किये जा सकते हैं १९६७ में अरब-इजराइल के उदित युद्ध में बहुत अच्छी तरह सिद्ध हुई थी।

\* अमरीका के निलिटरी रिव्यू के फरवरी १९६६ के अंक में लिखे होमान के लेख से उद्धृत।

इस बात में कतई सन्देह नहीं कि भारतीय वायु सेना में अत्यन्त कुशल साहसी और अनोचे युवक हैं लेकिन वे भी स्पष्ट रूप में यह स्वीकार कर लेंगे कि तनिक और अधिक कसाव तथा आधुनिकीकरण की गुंजाइश है।

१९६२ में हिमालय में दूर दूर पर बिखरी हुई तथा अत्यन्त दुर्गम स्थितियों में बनी हुई हमारी चौकियाँ को अवपातन द्वारा समान पहुँचाने का काम भारतीय वायु सेना का था लेकिन इस काम को उसने अत्यन्त प्रकुशल ढंग से किया था और अक्सर यह असफल ही रही थी। कठिन परिस्थितियों में फंसी हुई हमारी भूमि सेना को केवल यही सहायता पहुँचाने का उत्तरदायित्व वायु सेना पर डाला गया था।

१९६५ में भारतीय वायु सेना ने बहुत गौरवपूर्ण तथा सफल ढंग से भूमि सेना की सहायता की थी लेकिन यही बात उसके युद्ध नीतिक बमबारी मिशनों तथा ऐयर ब्रिज सप्लाय कार्रवाई के बारे में नहीं कही जा सकती।

इसके अलावा छः विभिन्न देशों से मंगाये हुए विमानों तथा उनके उपकरणों के कारण यदि मरम्मत, स्पेयर पाटों तथा रखने की सुविधाओं का मानकीकरण करना अव्यावहारिक है तो कम से कम किसी सीमा तक युक्तिकरण करना आवश्यक है।

आधुनिक युद्ध व्यवस्था में वायु सेना का श्रेष्ठतम महत्व होने के कारण यह जरूरी है कि भारतीय वायु सेना को सुधारने की बात को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये और नीति, प्रशिक्षण तथा उपकरणों के क्षेत्रों में उसे पश्चिम के अन्य देशों की वायु सेनाओं के घरातल तक विकसित किया जाये।

चूँकि अपने २६०० मील लम्बे सीमान्त पर चीव का आतंक आज भी जीवित है इसलिए हमारे लिए इस समस्या को अभी पूर्णतः सन्तोषजनक रूप से हल करना शेष है कि सही तरह के विमान प्राप्त करें और उन ऊँचाइयों तथा दुर्गम प्रदेश पर और बुरे मौसम में युद्ध करने के लिए अपनी भूमि सेना को उपकरणों तथा अस्त्रों से सुसज्जित करें।

और सबसे अनिवार्य बात यह है कि हम हिमालय के अत्यन्त दुर्गम प्रदेश द्वारा प्रस्तुत चकरा देने वाली संभार समस्याओं के हल ढूँढें क्योंकि अग्रिम चौकियों को मिलाने वाली सड़कों का जाल बिछा देने के बाद भी काफ़ी सीमा तक हवाई अवपातन पर ही निर्भर रहना होगा।

केवल इसी एक विषय पर लगातार शोधात्मक प्रयत्न करने पड़ेंगे और निकट से इस बात का अध्ययन करना आवश्यक होगा कि समान भूप्रदेश तथा मौसमवाले अन्य देशों ने इस समस्या को कैसे हल किया है। १९६० तक सैनिक हेडक्वार्टर जो बहाना करता था कि इन स्थानों पर शारीरिक रूप से असम्भव है, वह कब नहीं चल सकता।

हमारी नौ सेना वास्तव में रक्षा समर्थन की सीढ़ी सी सन्तान है। उसी तरह कर्तव्य ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी सबसे कम धारणाया गया है और तीनों सैनिक धर्मों में बहुत कम प्रभावदाय है। जब कि मनुष्य धर्म तथा इंसानियता के पाठ सब-मैरीन हैं (यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास भी दो हैं) हमारे पास एक भी सब-मैरीन नहीं है। जब कि हमारा तट बहुत ज्यादा सम्बा है और हम विशाल समुद्री विचारों की रक्षा करनी है, हमारी नौ सेना मात्र एक खिलौना है—और वह भी एक अत्यन्त साधारण खिलौना।

उसका एक मात्र विमान बाहक धर्मन्त सस्ता हाथ में है और उसे 'सोमर राय' का नाम दे दिया गया है क्योंकि अधिष्ठित वह शुष्क डॉक में ही रहता है और समुद्री युद्ध में नाव लेने के लिए विलुप्त बेकार है। १९६१ में जब भारत-पाक युद्ध छिड़ा था तब भी वह शुष्क डॉक में ही पड़ा हुआ था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद की नौ सेनाओं में विमान वाहक और सब-मैरीन पर बफादा डार दिया जाता है। हमारे पास कम से कम एक और विमान-वाहक होना चाहिए और यह आवश्यक है कि उसके उपकरण आधुनिक हो और यह युद्ध योग्य हो। उसके अलावा यदि भारतीय नौ सेना को अपने उत्तरदा-रित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करना है तो उसके पास बहुत-सी सब-मैरीनों, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सब-मैरीन जहाज हान चाहिए।

रक्षा मन्त्रालय के हक में यह कहना आवश्यक होगा कि १९६२ की पराजय के बाद, सेना को ठीक करने के लिए काफ़ी लगन से प्रयत्न किये गए हैं। १९६६ के शुरू में भारत सरकार ने प्रतिरक्षा के लिए एक पंच वर्षीय योजना अधिष्ठित की जिसके अन्तर्गत सैनिक सुस्था को ८,२५,००० तक बढ़ाने तथा उसकी आधुनिकतम असली तथा अन्य युद्ध समर्था से लैस करने की, आधुनिक विमानों तथा उपयुक्त अनुपनी सुविधाओं से युक्त ४१ स्क्वाड्रन की पायु सेना स्थापित करने की और नौ सेना में पुराने जहाजों को बदल कर नये विदेशी या भारतीय जहाजों को प्राप्त करने की योजना थी।

इसी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सैनिक सामग्री प्राप्त करने के क्षेत्रों में बाहर के स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन सुविधाएँ पैदा करना, सीमान्त क्षेत्रों में संचार तन्त्र को उत्तमतर बनाने और घाघ समर्थन को बढ़ाने का निश्चय भी किया गया था। इस योजना की लागत ५००० करोड़ निश्चित की गयी थी।

वास्तव में समरणीय प्रतिरक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने अपनी १९६८ की वार्षिक रिपोर्ट में साम्प्रदायी प्रभाव क्षेत्र के बाहर भारत को एशिया की सबसे बिलाल सैनिक शक्ति बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन की २ करोड़ ३० लाख सेना (अपनी सीमा के बाहर जिसकी आक्रमण क्षमता सीमित थी)

के मुकाबिले भारत की सैनिक संख्या १ करोड़ दस लाख है और इस सेना में चीनी आक्रमण के खिलाफ अपने देश की रक्षा करने की शक्ति है।

नेकनमारा ने यह भी कहा कि चीनियों के मुकाबिले अब प्रति भारतीय सैनिक की फायर-शक्ति ज्यादा थी और "अधिक अच्छी संचार तथा यातायात व्यवस्था की सहायता से अब वह ज्यादा तेजी से मार्कों के स्थानों में पहुँच सकते थे।"

वर्तमान प्रतिरक्षा व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण कमी इस बात की थी कि उसमें ऐसा कोई तन्त्र हो जो व्यापक युद्ध नीति की रचना करे, जो देश की विदेश नीति के संदर्भ में इस युद्ध नीति को ढाले और जिसमें ऐसा विभाग भी हो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तत्वों के बारे में निरन्तर सोच करता रहे।

ऐसा विशेष तन्त्र स्टाफ प्रमुखों की समिति को बराबर अधिकृत आधार सामग्री देता रहेगा जिसकी सहायता से यह समिति प्रतिरक्षा क्षमता पर पड़ने वाले विदेशी नीति के प्रभाव के बारे में सरकार को उचित सलाह दे सकेगी। यों कि यदि स्टाफ प्रमुखों की समिति को सार्यक रूप से काम करना है तो उसका कर्तव्य केवल यही नहीं है कि तांत्रिक रूप से सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करे बल्कि विचार करके सलाह देकर उन नीतियों को इस रूप से ढालने में सहायक हो कि देश की प्रतिरक्षा क्षमता से उनका साम्य हो।

ऐसा तन्त्र भारत जैसे देश में और भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ की सरकार को चलाने वाले राजनीतिज्ञ अव्यवसायी हैं और प्रतिरक्षा की समस्याओं की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए इस आवश्यक क्षेत्र में यह जरूरी है कि उन्हें सैनिक संगठन से सही परामर्श प्राप्त हो।

१९६४ में रक्षा मंत्रालय के स्थापित होने के बाद जो प्रणाली ब्रिटेन में प्रपनयी गयी थी वैसी ही प्रणाली चायद हमारी आवश्यकताओं के लिए भी उत्तम हो सकती है। यहाँ एक प्रतिरक्षा स्टाफ समिति की स्थापना की गयी है जिसके सभापति सैनिक व्यवसाय से लिए गये प्रतिरक्षा स्टाफ के प्रमुख हैं और नौ सेना, भूमि सेना तथा वायु सेना के प्रमुख जिसके अन्य सदस्य हैं।

समिति के सभापति होने की हैसियत से प्रतिरक्षा स्टाफ के प्रमुख का यह कर्तव्य है कि समिति का सम्मिलित परामर्श राज्य सचिव को दे। स्टाफ समिति के प्रमुख सम्मिलित रूप से सरकार के प्रति इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि कि युद्ध नीति तथा सैनिक कार्रवाई और प्रतिरक्षा नीति के सैनिक प्रभावों के बारे में व्यावसायिक सलाह दें।

स्थायी उपराज्य सचिव तथा प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के साथ प्रतिरक्षा स्टाफ के प्रमुख भी रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार हैं।



१९६७ में नसद में दिये एक भाषण में रक्षा मंत्री जवाहर लाल ने कहा था कि प्रतिस्पर्धा विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए आज सरकार के लिए इसी बात की विशेष आवश्यकता है कि प्राधुनिक सदन में देश की प्रतिस्पर्धा आवश्यकताओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करे और प्रकाश में आये हुई कमियाँ को पूरा करने के लिए एक उच्च प्राथमिक प्रोद्योगिकी प्रारम्भ कर दे।

एक नये परिवर्तित देश में जिसमें अनेक पट्ट पंदा करने वाली शक्तियाँ काम करती हैं सेना का यह भी कर्तव्य होता है कि वह इन घरायशवादी शक्तियों से सरकार की रक्षा कर और उसके संगठन को क़ायम रखे।

सेना को अक्सर आम जनदली बलवों का दमन करना पड़ता है और भविष्य में हम याद की भी सम्भावना पैदा हो सकती है कि संगठित साम्यवादी गोरिल्लाओं तथा प्रादेशिक असहजतावादीयों से शासन के स्थायित्व की रक्षा करनी पड़े।

जिस रफ़्तार से देश की राजनैतिक स्थिति बिगड़ रही है उस दखन हुए ऐसी परिस्थिति को असम्भव नहीं कहा जा सकता। भारत में साम्यवादियों ने पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी, २४ परगने और सासनगोन आदि क्षेत्रों में उत्पातों का काम शुरू कर हो दिया है। पश्चिमी बंगाल के साम्यवादी खुद तौर पर गोरिल्ला विद्रोह शुरू करने की बात करते रहे हैं।

इसके अलावा उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रों के उपद्रवों का दमन करने के लिए सेना अधिकाधिक काम में आयेगी या रही है। नागालैण्ड तथा मिज़ो जिले में सेना को वास्तविक गोरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ा है।

इसलिए यह वह समय था गया है जब भारतीय सेना को उचित रूप से गोरिल्ला युद्ध तथा विद्रोह दमन का प्रशिक्षण देना आवश्यक हो गया है। इसके लिए विशेष तन्त्रों और सामरिक नीतियों का ज्ञान, गतिशील प्रारम्भ क्षमता तथा निकटतम प्रादेशिक नियंत्रण आवश्यक होता है। विद्रोह-दमन में सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उस प्रदेश के राजनैतिक तथा सामाजिक स्थितियों की पूरी जानकारी हो जिसमें विद्रोह का दमन करना है।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को यह समझ सेना चाहिए कि प्राधुनिक सेना के लिए राजनैतिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। यदि सेना को अपना उत्तरदायित्व नृसन्न और असुरक्षित देश से पूरा करना है तो उसमें देश की राजनैतिक गतिविधियों को भली भाँति समझने का ज्ञान होना आवश्यक है।

## उत्तराक्ति : नीतियों में दौधवृत्ति

अपने पड़ोसियों के प्रति किसी भी देश की जो नीति होती है उसे विदेश नीति कहते हैं ।

अब तक भारत की विदेश नीति की जड़ें उपनिवेशवाद विरोध तथा अणुशक्तिवाद के भावनों में जमी रही हैं। लेकिन अब यह दोनों आवर्ण लगभग रिक्त और निरर्थक हो चुके हैं। और इसलिए अपने पड़ोसी चीन तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों की विवशता के संदर्भ में हमारी विदेश नीति असंगत सिद्ध हो रही है ।

वास्तव में हमारी नीति और यथार्थ परिस्थिति की आवश्यकताओं के बीच जो असंगतता थी उसी के कारण हमें ६२ में चीन के साथ संघर्ष करने में जलझना पड़ा था ।

जहाँ तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान के प्रति भी हमारी नीति निश्चित रूप से सचेत और उद्देश्यात्मक नहीं है । इसके विपरीत, भारत के प्रति पाकिस्तान के रुख में बराबर ही एक सुनिश्चित प्रणाली और स्थायित्व रहे हैं। यदि हमारी पाकिस्तान-नीति में भी यही बात होती तो हम इतनी सलतियाँ नहीं करते और समय-समय पर हमें अपनी नीति में उलट-फेर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

यदि हमारी विदेश और प्रतिरक्षा नीतियाँ पाक-आधारित हैं तो ऐसा इस कारण नहीं है कि हमने जान-बूझ कर उन्हें यह रूप दिया है बल्कि इसलिए कि हमारी भूल सहज प्रवृत्तियों तथा कुंठाओं ने उन्हें इस रूप में ढाल दिया है । इसका एक उदाहरण यह है कि जब भी कभी कश्मीर का जिक्र होता है तो हम आवश्यकतन भड़क उठते हैं ।

इसके प्रतिरिक्त यदि विदेश नीति का समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता न हो तो वह नीति नपुंसक होती है । इसी प्रकार यदि देश की प्रतिरक्षा क्षमता उसकी विदेश नीति से असम्बद्ध हो तो वह निरर्थक होती है । प्रतिरक्षा क्षमता की ओर से आँखें मूँद कर विदेश नीति की रचना करना वास्तव में राष्ट्रीय आत्मघात है ।

अतः व्यापवादी विदेश नीति यह है जो देश की प्रतिरक्षा क्षमता का ध्यान में रख कर अपने को दायित्व और परिवर्तित करती है। साथ ही, अक्सर विदेश नीति को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा संगठन को विशेष रूप से कमना पड़ता है और प्रतिरक्षा को और चीजों के ऊपर प्राथमिकता देनी पड़ती है। यदि देश का सकल से बचाना है तो विदेश तथा प्रतिरक्षा नीतियों के बीच समन्वय होना आवश्यक है।

सन १० १० के बीच के घान्ति पूर्ण दशक में भारत सरकार इन नीतियों सम्बन्धी स्वयंनिर्णय सत्यो को न देख सकी थी, न समझ सकी थी। इसी कारण हमें १९६२ का यह कहना अधिक सटीक पड़ा था। इस सबक ने स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध कर दी थी कि देश की प्रतिरक्षा क्षमता और विदेश नीति मूलतः एक-दूसरे पर निर्भर है और इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विदेश कार्य सच और प्रतिरक्षा संगठन या ज्वाइंट चीफ्स ऑफ़ कमेटी के बीच निकटतम सम्पर्क रहे।

इसके अलावा इस बात की भी अनिवार्यता स्पष्ट हो गयी थी कि सैनिक हेडक्वार्टर लगातार विदेश नीति का पुनर्विचिन्तन करता रहे ताकि प्रतिरक्षा क्षमता विदेश नीति के किसी भी पक्ष और माह से पैदा हुई आवश्यकता के अनुकूल समीक्षा जा सके। यह सबक भी हमने अपने अग्रमान और दुश्मन की शीमत पर १९६२ में सीखा था।

पिछले अध्याय में हम इस बात पर चिन्तन कर चुके हैं कि प्रतिरक्षा संगठन को किन तरीकों से सशक्त और इस योग्य बनाया जा सकता है, कि देश की बाहरी सुरक्षा के प्रति यह अपना कर्तव्य सफलता से पूरा कर सकें।

सैनिक हेडक्वार्टर या ज्वाइंट चीफ्स ऑफ़ स्टॉफ़ कमेटी देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं और इसलिए उनका प्राथमिक कर्तव्य है कि यदि विदेश नीति प्रतिरक्षा क्षमता से कदम मिला कर नहीं चल रही है तो वे इस बारे में सरकार का स्पष्ट चेतावनी दें। सन् ६२ के पूर्व के दशक में सैनिक हेडक्वार्टर अपने इस उत्तरदायित्व का पूर्ण न करने का अपराधी है।

उत्तरी सामान्य पर घुमते हुए सबक के बादलों के प्रति सैनिक हेडक्वार्टर पहली बार १९६० में सचत हुआ था लेकिन उस तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वर्ष सैनिक हेडक्वार्टर ने, परिस्थितियों का परवेक्षण करके यह अनुमान लगाया था कि सम्भावित चीनी आक्रमण १९६३ में होगा। आक्रमण एक वर्ष पहले ही हो गया।

जनवरी, १९६२ के बाद से सरकार ने सैनिक हेडक्वार्टर से यह कहना शुरू किया कि वह धीरे धीरे घट कर घबु को रोकने और सैनिक हेडक्वार्टर ने यह आपत्ति प्रकट करनी शुरू की कि प्राप्य साधनों को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता।

और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से हताश और साधनाभाव की चिन्ता से श्रुत भारतीय सेना सन् ६२ की पतझड़ में शत्रु का सामना करने के लिए युद्धस्थल में उतरी ।

फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि हम युद्ध के पहले के बारह वर्षों में मिलने वाली चेतावनियों की ओर ध्यान देते और सारी शक्ति लगाकर २, ६०० मील लम्बी सरहद्द पर अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को संगठित करते तथा उस क्षेत्र की संभार समस्याओं को हल करते तो हम सन्, ६२ में क्यादा अच्छी तरह अपनी रक्षा कर पाते । हमें चीनी आक्रमण का पूर्व ज्ञान होता और हम सैनिक तथा राजनयिक दोनों दृष्टिकोणों से उससे क्यादा सफलता पूर्वक निवट पाते ।

×

×

×

आक्रमण से तीन महीने पहले, जुलाई १९६२ के 'सेमिनार' नामक पत्र में जनरल चिमेया (जो १९६१ तक सेना प्रमुख थे) ने स्वीकार किया है—

"जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, मैं युद्ध सम्भव सम्भत्ता हूँ लेकिन चीन के बारे में मैं यह बात नहीं कहूँगा । एक सैनिक की हिसियत से मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता कि भारत भूकेला चीन के साथ युद्ध कर सकता है । सोवियत रूस की पूरी सहायता के कारण सैनिक संख्या, सामन और हवाई क्षमता के दृष्टि कोण से चीन की शक्ति हमसे सीगुनी है और इस लिए निकट भविष्य में हम चीन से मोर्चा लेने की बात सोच भी नहीं सकते । देश की रक्षा का भार आज राजनैतिकों और राजनयिकों पर ही है ।"

स्पष्टतः सेना प्रमुख की हिसियत से भी चिमेया के यही विचार थे जो उन्होंने रक्षा मंत्री को प्रस्तुत किये थे । लेकिन मेनन को यह परामर्श देना अनावश्यक था क्योंकि सरकार को यह विश्वास था कि चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा ।

इस स्वयं सिद्ध सत्य को व्यक्त करने के लिए किसी जनरल की आवश्यकता नहीं थी । सोवियत सहायता के बिना भी चीन की सैनिक शक्ति भारत से कहीं ज्यादा थी । आज जब चीन-पाक गठबन्धन ने एक ठोस असलियत का रूप ले लिया है तो चीन या पाकिस्तान के साथ किसी भावी संघर्ष में हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा । इसलिए यह बात सीधे की तरह साफ है कि हमारी सेना इतने बड़े संकट से नहीं निवट सकती थी और इसलिए आज देश की सुरक्षा व्यवस्था को राजनैतिक तथा राजनयिक समर्थन देना आवश्यक है ।

यदि हम अपने प्रिय अर्म्हों को सीने से लगाये न बैठे रहते तो परिस्थिति की असलियत हममें यह विवेक जाग्रत कर देती कि अपनी सैनिक क्षमता को राजनयिक युक्तिमों से और सशक्त बना लें । हमस्यास देशों के साथ मिलकर

घट' यथार्थवादी विदेश नीति वह है जो इस की प्रतिष्ठा क्षमता का ध्यान में रख कर अपने को दानवी और परिवर्तित करती है। साथ ही, घसर विदेश नीति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा संगठन को विशेष रूप से बचना पड़ता है और प्रतिरक्षा को और चीजों के ऊपर प्राथमिकता देनी पड़ती है। यदि देश को सफटस बनाना है तो विदेश तथा प्रतिरक्षा नीतियों के बीच समन्वय होना आवश्यक है।

सन् १०-६० के बीच के सानि पुन ह्मक में भारत सरकार इन नीति समन्वयी स्वयंसिद्ध सत्यों का न हथ सकी थी, न समझ सकी थी। इसी कारण हम १९६१ का यह कड़ा सबक सीखना पड़ा था। इस सबक ने स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध कर दी थी कि देश की प्रतिरक्षा क्षमता और विदेश नीति मूलतः एक-दूसरे पर निर्भर है और इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विदेश कार्य सय और प्रतिरक्षा संगठन या ज्वाइंट चीफ्स ऑफ़ कमेटी के बीच निकटतम सम्पर्क रहे।

असके अलावा इस बात की भी अनिवार्यता स्पष्ट हो गयी थी कि सैनिक हेडक्वार्टर लगातार विदेश नीति का पुनर्विचिन्तन करता रहे ताकि प्रतिरक्षा क्षमता विदेश नीति के किसी भी पेश और मोड़ से पैदा हुई आवश्यकता के अनुकूल ढाली जा सक। यह सबक भी हमने अपने अपमान और दुर्दशा की सीमा पर १९६२ में सीखा था।

पिछले घप्पयाय न हम इन बात पर चिन्तन कर चुके हैं कि प्रतिरक्षा संगठन को किन तरीकों से सहायता और इस योग्य बनाया जा सकता है कि देश की बाहरी सुरक्षा के प्रति वह अपना कर्तव्य सफलता से पूरा कर सके।

सैनिक हेडक्वार्टर का ज्वाइंट चीफ्स ऑफ़ स्टॉफ़ कमेटी देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं और इसलिए उनका प्राथमिक कर्तव्य है कि यदि विदेश नीति प्रतिरक्षा क्षमता से ऊँच मिला कर नहीं चल रही है तो व इस बारे में सरकार की स्पष्ट चेतावनी दें। सन् ६२ के पूर्व के दशक में सैनिक हेडक्वार्टर अपने इस उत्तरदायित्व को पूर्ण न करने का घपराधी है।

उत्तरी सीमान्त पर घुमड़त हुए सफट के बादलों के प्रति सैनिक हेडक्वार्टर पहली बार १९६० में सचेत हुआ था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक सैनिक हेडक्वार्टर ने, परिस्थितियों का पयवेक्षण करके यह अनुमान लगाया था कि सम्भावित चीनी आक्रमण १९६३ में होगा। आक्रमण एक वर्ष पहले ही हो गया।

अनवरी, १९६२ के बाद से सरकार न सैनिक हेडक्वार्टर से यह कहना शुरू किया कि वह भाये घड़ कर शत्रु को रोके और सैनिक हेडक्वार्टर ने यह प्राप्ति प्रगट करनी शुरू की कि प्राप्य साधनों को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता।

और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से हताश और साधनाभाव की चिन्ता से प्रस्त भारतीय सेना सन् ६२ की पतझड़ में शत्रु का सामना करने के लिए युद्धस्थल में उतरी।

फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि हम युद्ध के पहले के बारह वर्षों में मिलने वाली चेतावनियों की ओर ध्यान देते और सारी शक्ति लगाकर २,६०० मील लम्बी सरहद्द पर अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को संगठित करते तथा उस क्षेत्र की संभार समस्याओं को हल करते तो हम सन् ६२ में ज्यादा अच्छी तरह अपनी रक्षा कर पाते। हमें चीनी आक्रमण का पूर्व ज्ञान होता और हम सैनिक तथा राजनयिक दोनों दृष्टिकोणों से उससे ज्यादा सफलता पूर्वक निवट पाते।

×

×

×

आक्रमण से तीन महीने पहले, जुलाई १९६२ के 'सेमिनार' नामक पत्र में जनरल विमैया (जो १९६१ तक सेना प्रमुख थे) ने स्वीकार किया है—

"जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, मैं युद्ध सम्भव समझता हूँ लेकिन चीन के बारे में मैं यही बात नहीं कहूँगा। एक सैनिक की हेलियत से मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता कि भारत अकेला चीन के साथ युद्ध कर सकता है। सोवियत रूस की पूरी सहायता के कारण सैनिक संख्या, साधन और हवाई क्षमता के दृष्टि कोण से चीन की शक्ति हमसे सौगुनी है और इस लिए निकट भविष्य में हम चीन से मोर्चा लेने की बात सोच भी नहीं सकते। देश की रक्षा का भार प्राण राजनैतिकों और राजनयिकों पर ही है।"

स्पष्टतः सेना प्रमुख की हेलियत से भी विमैया के यही विचार थे जो उन्होंने रक्षा मंत्री को प्रस्तुत किये थे। लेकिन मेहन की यह परामर्श देना अनावश्यक था क्योंकि सरकार की यह विश्वास था कि चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा।

इस स्वप्न सिद्ध सत्य की व्यक्त करने के लिए किसी जनरल की आवश्यकता नहीं थी। सोवियत सहायता के बिना भी चीन की सैनिक शक्ति भारत से कहीं ज्यादा थी। आज जब चीन-माक गठबन्धन ने एक ठोस असलियत का रूप ले लिया है तो चीन या पाकिस्तान के साथ किसी मावी संधि में हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा। इसलिए यह बात बीजे की तरह साफ है कि हमारी सेना इतने बड़े संकट से नहीं निवट सकती थी और इसलिए आज देश की सुरक्षा व्यवस्था को राजनैतिक तथा राजनयिक समर्थन देना आवश्यक है।

यदि हम अपने प्रिय भ्रमों को सीने से लगाये न बैठे रहते तो परिस्थिति की असलियत हममें यह विवेक जाग्रत कर देती कि अपनी सैनिक क्षमता की राजनयिक शक्तियों से और सशक्त बना लें। हमन्त्याल देशों के साथ मिलकर

सामूहिक सुरक्षा का एक ठोस प्लान बनाया जा सकता था। ऐसी विदेश नीति भात्म रक्षा और राष्ट्रीय हित पर आधारित होती जैसा कि हर देश की विदेश नीति का वास्तव में होना चाहिए।

सारे संसार, विशेषतः पड़ोसी देशों में चीन की प्रति भय तथा घब्रियता की भावनाएँ बराबर बढ़ती जा रही हैं। अब पूर्वी एशिया तथा छेप संसार के कई देश ऐसे हैं जो अपने हित, अपने आदर्शों और अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मूलतः इस बात में सहरी दिलचस्पी रखते हैं कि किसी भी तरह साम्यवादी खल के दमन हो। भारत इसलिए भयंकर नहीं है।

ताइवान, थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपीन, लका, दक्षिण विyetनाम, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि बर्मा और बम्बोडिया—सभी इस भय से ग्रस्त हैं कि पूर्वी एशिया की छाति को साम्यवादी चीन से छतरा है। वास्तव में इस पैटर्न में जापान और आस्ट्रेलिया के नाम भी शामिल किये जा सकते हैं।

सन् ६२ में भारत पर चीन के आक्रमण से इन सब देशों को बेताबनी मिल गयी थी और अमरीका के इस विवरान को पुष्टि हुई थी कि चीन विश्व छाति को स्वाधी छतरा है।

अब यदि भारत की तरह एक विपक्ष एशियाई राष्ट्र चीन के खिलाफ़ एक ठोस प्रतिरक्षा व्यवस्था संगठित करने का बड़ा उठावेगा तो छेप एशियाई देश (जिनके नाम ऊपर गिनाये गये हैं) उत्साहपूर्वक इस कठिन कार्य में उसका हाथ बढ़ावेंगे। वास्तव में, दक्षिण पूर्वी एशिया में अमरीका का यही सर्वेस र्हा है।

सन् १९५० के आठ-वास्तव स्वर्गीय जॉन फ़ोस्टर डलेस यही विचार प्रचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे। बाद में, प्रेसिडेंट केनेडी और एडलाई स्टीवसन ने भी इस प्रस्ताव की पैरवी की थी कि चीन की विस्तारवाद के पत्ता को काटने के लिए भारत और जापान मिलकर एक घबियान का नेतृत्व करें।

वाशिंगटन के दृष्टिकोण से पूर्वी एशिया में साम्यवादी चीन को मात देने के लिए सबसे आदर्श पान यह थी कि भारत और जापान जैसी लोचन शक्तियाँ और उस क्षेत्र के स्वाभाविक नेता दक्षिण पूर्वी एशिया की सामूहिक सुरक्षा के लिए पहल करें।

को नेहरू के ऐसा करने से इनकार करने के कारण अमरीका का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। उसके बाद अमरीका ने यह प्रयत्न किया कि चीन के चारों तरफ़ के छोटे-छोटे देशों की सरकारों को अपना प्रथम और समर्थन देकर खरा करे। लेकिन यह नीति नुरी तरह से असफल रही है।

इसलिए अमरीका का स्टेट डिपार्टमेंट आज फिर अपनी पहले की आदर्श नीति को अपना रहा है, खास तौर पर इसलिए कि उसे विश्वास है कि १९६२ की हार के बाद भारत उसकी इस विचारधारा की तरफ झुक गया है।

१९६१ में न्यूयार्क में मुम्बते हुई एक मुलाकात में एडलाई स्टीवेंसन ने अधीरता से कहा था : "अपने नेहरू से कह दीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में हम उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उन्हें खुद होश होना चाहिए कि उनके देश का हित किस बात में है।" संयुक्त राष्ट्र सच में अमरीका के दूत, स्टीवेंसन ने फिर व्याख्या की इस नीति की कि पूर्वी एशिया में चीनी विस्तारवाद की रोक-थाम करने के लिए एशिया के दो महानतम देश भारत और जापान, एक आपसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को संगठित करने में पहल करें।

दक्षिण वियतनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति एन्गोदिन वियेन ने १९५६ में मुक्त से कहा था कि वे भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया के साम्यवादी देशों का स्वाभाविक नेता मानते हैं और जहाँ तक उनका प्रश्न है, वे इस अभियान में श्री नेहरू का नेतृत्व मानने को तैयार हैं।

यहाँ एक ऐसा सतर्क रहने वाला तटस्थ देश है जो किसी भी खतरनाक पड़ोसी से दिगाड़ नहीं करना चाहता। जून के महीने में रंगून में हुए चीन विरोधी प्रदर्शनों तथा पेकिंग में हुए बर्मा विरोधी प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बर्मा को अपने आक्रमणशील पड़ोसी से भय है और उसके प्रति अविश्वास है। अपनी विलिंग्स्टोन राजनयिक शैली के अनुसार पेकिंग ने राष्ट्रपति में विन को चुरा भला कहा है और यह बमकी दी है कि उनके शासन का तख्ता उलटवा देगा। वास्तव में चीन ने बर्मा के साम्यवादियों को बिप्लव करने के लिए उकसाया भी है।

कम्बोडिया साम्यवादी चीन के इतना निकट है कि वह विषय है पेकिंग पक्षी तटस्थ देश बने रहने के लिए। फिर भी राजकुमार सिहानुक ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनका नन्हा-सा राज्य स्नेह के नहीं विवशता के सूत्रों से चीन से बँधा हुआ है।

उत्तर वियतनाम तथा उत्तर कोरिया राजनैतिक आदर्शों के कारण चीन के मित्र है लेकिन उत्तर वियतनाम के लोगों में चीन के प्रति एक ऐतिहासिक और परम्परागत घृणा न सही तो विद्वेष अवश्य है।

जहाँ तक साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीति की रोकथाम करने का प्रश्न है, दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के बाकी देशों का हित भारत के हित से सम्बद्ध है।

इस नयी परिस्थिति को देखते हुए कि आज रूस और अमरीका, अधिक-थक, समान दृष्टि से विश्व शांति के प्रश्न को ही नहीं बल्कि साम्यवादी चीन



द्वारा विश्वशांति को बढ़ा देने वाले छतरे के मसले तथा अपनी अन्तराष्ट्रीय दित्वास्तियों का देख रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के इस प्रस्तावित सुरक्षा संगठन को इन दोनों देशों की सहमति मिलना स्पष्ट है।

सन् १९५० में शुरू होने वाले दक्षिण के आरम्भ में पश्चिमी तथा (साम्यवाद) गुटों के बीच अन्तराष्ट्रीय राजनीति ध्रुवण हुआ था जिसने तृत्व, क्रमशः, अमेरिका तथा रूस ने किया था। सन् १९६० के दशक, मध्य में अन्तराष्ट्रीय राजनीति ने एक नया रूप ले लिया है। आज चीन अणु-शक्ति बन जाने के कारण संघर्ष का एक विशेष बन गया है जिस अमेरिका और रूस का समान हिन इस बात में है कि इस नई शक्ति को बिर भी तरह कुचला जाये।

इस विशेषीय संघर्ष का दखत हुए अणुबाद की नीति निरर्थक हो जाती है जब तक कि वर्तमान अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस नीति का उचित रूप से फिर से दावा न जाये। आज भारत के लिए अणुबाद का मतलब होना चाहिए अमेरिका और रूस के बीच एक समदुस्त्व बन्धी बनना, दोनों से समदुस्त्व अवस्था नहीं।

यदि रूस और अमेरिका जैसे दो सशक्त प्रतिद्वन्द्वी एक-दूसरे से इतने निकट आ सकने हैं कि अन्तराष्ट्रीय मामलों में वे एकमत हो—विश्वका निरन्तर उदाहरण या संयुक्त राष्ट्र में अरब इब्राहिम युद्ध के बारे में दोनों का अविचारक दृष्टिकोण—तो निश्चित रूप से भारत, बिना किसी एक से नाता तोड़े, दोनों के निकट आ सकता है और एक आगसी अणु की कुचलन के लिए वाशिंगटन-मॉस्को-नयी दिल्ली मित्र संघ की स्थापना कर सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन विरोधी संगठन की स्थापना करने के लिए भारत की किसी भी पहल का अमेरिका स्वागत करेगा। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि रूस भी ऐसी किसी चीज का समर्थन करेगा।

यदि केवल वे लोग, जो भारत की नियति के निर्माता हैं, साहस और विवेक से काम लें और अनुराग से भाल चलें तो भारत अन्तराष्ट्रीय प्राप्ति में अपनी कोई हुई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर सकता है और इससे उसे विशेष आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

ऐसे सत्कार में जिसमें एक-दूसरे पर निर्भर होना एक यथार्थवादी तथ्य है, किसी दूसरे देश से भय-जन को कुठित कर देने वाली निश्चिन्ता समझना एक दक्षिणानुसी और तकहीन विचारधारा है। चीन ने सुरक्षा को जो स्थायी छतरा है उसका सामना हम केवल तभी कर सकते हैं जब दूसरे के साथ मिल कर सामूहिक सुरक्षा का एक ठोस नीति निर्माताओं को यह स्पष्ट सत्य समझने में दे दिए।

यदि वक्त की माँगों को पूरा करने के लिए सोवियत रूस मार्क्सवादी सिद्धान्त की पुनर्व्याख्या कर सकता है तो भारत की अपक्षवादी नीति भी जो सन् १९५० को देखकर रची गई थी, १९६७ की बदली हुई स्थिति को देखकर निश्चित रूप से परिवर्तित की जा सकती है।

भारत को छोड़कर मुक्त राष्ट्रों के गुट में हर देश के लिए अपक्षवाद की नीति मात्र एक ऐसा साधन है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से, अपने-अपने हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि केवल भारत के लिए ही अपक्षवाद एक ठोढ़ सिद्धान्त है; किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं, स्वयं एक उद्देश्य है।

लेकिन जहाँ तक भारत का भी प्रश्न है, अपक्षवाद की नीति मूलतः अपने हितों तथा आत्म-रक्षा को देखते हुए ही अपनायी गयी थी। आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में भारत का हित इसी में था कि खतरनाक अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों से दूर रहकर एकाग्र भाव से आर्थिक विकास और प्रगति के काम में लग जायें।

मित्र के राष्ट्रपति नासिर के लिए अपक्षवाद की नीति का केवल यही उपयोग है कि वह उनकी विदेश नीति के मूल तत्वों की पुष्टि करती है—यह नीति अरब राष्ट्रों के इस उद्देश्य में केन्द्रित है कि इजरायल को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाये; यह बात अक्षय्य है कि नासिर की यह नीति जून १९६७ में बुरी तरह विफल हुई। संयुक्त अरब जमतंत्र की प्रतिरक्षा क्षमता इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित की गयी थी। पाकिस्तान की सैनिक नीति पूर्णतः भारत आधारित है और यह उसकी भारत आधारित विदेश नीति के अनुकूल है।

अब इस बात में विलम्ब नहीं करना चाहिए कि हम अपनी विदेश नीति को इस तरह लचीला बना लें कि वह हमारी सुरक्षा और अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने का एक सफल साधन बन जाये।

सबसे ज्यादा हमें इस बात को पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सफलता पारस्परिक आदान-प्रदान पर निर्भर है। हम किसी देश से जो कुछ चाहते हैं उसके बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं? 'मुसीबत के समय की मित्रता' का आदर्श केवल आपसी आदान-प्रदान से ही जीवित रखा जा सकता है।

और दुर्भाग्य की बात यह है कि अपक्षवाद की नीति का जिस रूप में हम व्यवहार करते रहे हैं, वह एसी गाली, व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता के रास्ते में मात्र एक विघ्न सिद्ध हुई है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

## परिशिष्ट-१

दिनांक २१ नवम्बर, १९६२ के चीन सरकार के वक्तव्य का न्यूचाइना प्रेस एजेंसी द्वारा किया गया आधिकारिक अनुवाद :

एक दो वर्षों की अवधि में पहले चीन-भारत सीमा के पश्चिमी सेक्टर में और फिर पूर्वी सेक्टर में भारतीय सेना ने चीन भारत के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, चीनी भूप्रदेश के किन्हीं इलाकों को हड़पा और आक्रमण करने के लिए चौकियाँ प्रायम की जिसके फलस्वरूप कई सीमा संघर्ष हुए।

सामरस्य सैनिक स्थितियों के बल पर और पूरी तैयारी करने के बाद भारत में भारतीय सेना ने २० अक्टूबर सन् १९६२ को पूरे सीमान्त पर स्थित चीनी सीमा रक्षकों पर विशाल सशस्त्र आक्रमण किया।

भारत द्वारा उक्तसाया हुआ यह सीमा-संघर्ष पिछले एक मास से चल रहा है। इन निरंतर उग्रतर होते हुए भारतीय अतिक्रमणों के खिलाफ चीन सरकार ने बराबर चेतावनियाँ दी हैं और इस बात की घोर ध्यान आकर्षित किया है कि इसका नतीजा गंभीर हो सकता है। इस सारे दौर में चीनी सीमा रक्षकों ने आत्म-नियंत्रण और सहनशीलता से काम लिया है ताकि सीमा संघर्ष और अधिक भयानक रूप न लें।

लेकिन चीन का हर प्रयत्न विफल हुआ है और भारतीय अतिक्रमण बढ़ते चले गए हैं।

बाल बर्दाशत के बाहर हो जाने और अपमान के लिये कोई रास्ता न रहने के कारण चीनी सीमा रक्षकों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था कि आत्मरक्षा के लिए जमकर प्रत्याघात करें। इस विशाल सीमा-संघर्ष के फूट पड़ने के बाद भी चीन सरकार ने फौरन इस बात के लिए प्रयत्न किया कि जितनी जल्दी हो सके, इस आग को बुझा दिया जाये।

वर्तमान सीमा-संघर्षों के शुरू होने के चार दिन बाद ही चौबीस अक्टूबर को चीन सरकार ने तीन ऐसे तर्कसंगत प्रस्ताव रखे जिनसे सीमा संघर्षों का

रोका जा सकता था सम्झौते की बात शुरू की जा सकती थी और भारत-चीन सीमा समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता था। ये तीन प्रस्ताव थे—

१. दोनों पक्ष इस बात पर फंसता फाने हैं कि चीन-भारत सीमा समस्या को सम्झौते की बातों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये। इस सम्झौते के होने तक चीन सरकार यह आशा करती है कि भारत सरकार इस बात से सहमत होगी कि सारी भारत-चीन सीमा पर दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता दें और दोनों पक्षों की सेनाएँ इस रेखा से बीस किलो मीटर पीछे हट जायें।

२. यदि भारत सरकार उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करती है तो चीन सरकार इस बात के लिए तैयार है कि दोनों पक्षों की राय लेकर अपने-अपने सीमा रक्षकों को पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उत्तर तक वापस हटा ले। साथ ही भारत और चीन दोनों यह वायदा करते हैं कि दोनों में से कोई सीमा के मध्य तथा पश्चिमी सेक्टरों में पारम्परिक रेखा का अर्थात् वास्तविक रेखा का उत्खनन नहीं करेगा।

दोनों पक्षों की सेनाओं के संपर्क को खत्म करने से सम्बन्धित बातों पर भारत और चीन सरकारों के अधिकारी आपस में निष्पक्ष होंगे।

३. चीन सरकार का यह मत है कि भारत-चीन सीमा समस्या को मैत्री-पूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए यह अच्छा होगा कि दोनों देशों के प्रधानमन्त्री आपस में बातचीत करें। ऐसे किसी भी समय जिसे दोनों पक्ष उचित समझें चीन सरकार पेरिंग में भारतीय प्रधानमन्त्री का स्वागत करने को तैयार है। यदि यह भारतीय सरकार के लिए अनुविधानिक हो तो चीनी प्रधानमन्त्री बातचीत के लिए दिल्ली जाने को तैयार हैं।

जिम्मे दिन भारत सरकार को ये तीन प्रस्ताव मिले उसी दिन उसने उन्हें रद्द कर दिया और उल्टे यह माँग की कि चीन सरकार = सितम्बर, १९६२ से पहले की सीमा का पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हो जिसका अर्थ यह हुआ कि भारत-चीनी नू प्रदेश के विस्तृत इलाकों पर फिर से अधिकार जमा में ताकि भारतीय सेना उन स्थितियों को फिर से प्राप्त कर ले जहाँ १३ चीनी सीमा रक्षकों पर किसी भी समय विद्याल सशस्त्र आक्रमण किया जा सके।

१ नवम्बर को प्रधानमन्त्री पाल्म इन-लाइ को लिखे नये पत्र में प्रधानमन्त्री नेहरून इससे भी अधिक अनुचित माँग कीं जिनके अनुसार न सिर्फ चीन सरकार से यह माँग की गयी थी कि वह इस बात पर राजी हो जाय कि भारतीय सेना ८ नवम्बर से पहले की स्थितियों पर वापस लौट जाये बल्कि यह भी कि चीनी सीमा रक्षक न केवल अपनी ८ सितम्बर की स्थितियों को लौट जायें बल्कि पश्चिमी सेक्टर में ७ नवम्बर, १९६२ की स्थितियों तक प्रपयान करें।

यह स्थितिमाँ भारत ने अपनी तरफ से ही तय कर ली थीं और इसका मतलब यह था कि चीन अपने भू-प्रदेश का ६ हजार वर्गमील इलाका भारत को दे दे।

इसी बीच भारत सरकार ने विशाल अमरीकी सैनिक सहायता के बल पर फिर से भारत-चीन सीमा के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जोरदार आक्रमण किए।

यह केवल संयोग की बात ही नहीं है कि भारत सरकार ने इस मामले में इतना अनुचित हथ अंपनाया है। अपनी आन्तरिक और बाह्य नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार काफ़ी समय से जानबूझ कर भारत-चीन सीमा समस्या को बिबादग्रस्त रखे हुए है जिसके परिणाम-स्वरूप दोनों देश की सेनाएँ आपस में उलझी हुई हैं और भारत चीन सीमा पर बराबर एक तनाव रहा है।

अनुकूल समय देख कर भारत सरकार ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया है, सशस्त्र आक्रमण करने के लिए और भारत की सीमा पर संघर्ष उकसाने के लिए। या उसने परिस्थिति से लाभ उठाकर चीन के विरुद्ध शीत युद्ध कायम रखा है।

फ़ई वर्षों के अनुभव से यह स्वष्ट है कि भारत सरकार ने इस बात के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया है कि भारत-चीन सीमा समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए चीन सरकार की हर कोशिश को विफल करे। भारत सरकार की यह नीति चीन तथा भारत की जनता के मूल हितों और सारे संसार के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध है और केवल साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति करती है।

चीन सरकार के यह तीनों प्रस्ताव पूर्णतः उचित और तर्कसंगत हैं। केवल इन्हीं प्रस्तावों से सीमा संघर्षों को ख़त्म किया जा सकता है, सीमा पर शान्ति कायम की जा सकती है और भारत-चीन सीमा समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है।

चीन सरकार अपने तीन प्रस्तावों पर अटल है।

लेकिन भारत सरकार अब तक इन प्रस्तावों को ठुकराती रही है और सीमा संघर्षों को बढ़ाती रही है जिसके कारण भारत-चीन सीमा समस्या बराबर विगड़ती जा रही है। इस स्थिति को उलटने के लिए चीन सरकार ने अपनी तरफ से यह फ़ैसला किया है कि इन तीन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए स्वयं ही पहला कदम उठाये।

अतः चीन सरकार यह घोषणा करती है कि :

(१) इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के अगले दिन से अर्थात् २२ नवम्बर के ००.०० बजे से पूरी भारत-चीन सीमा पर चीनी सीमा रक्षक युद्ध विराम कर देये।

११ यह भी प्रष्ट हुआ है कि प्रशिक्षण के मुख्य पढ़नू के साथ-साथ पर्य-  
तीय युद्ध के बारे में प्रश्न कमांडरों का दृष्टिकोण दुस्मृत करना आवश्यक है।

१२ लेकिन जचित नेतृत्व के बिना मात्र उत्तम प्रशिक्षण से कोई मान  
नहीं होगा। यत सबसे अधिक इस समय नेतृत्व को शिक्षा देने की  
आवश्यकता है।

### सैनिक उपकरणों की कमी

१३ दूसरा प्रश्न था हमारे सैनिक उपकरणों के बारे में। जब से इस  
बात की पुष्टी हुई है कि प्रशिक्षण तथा युद्ध दोनों के लिए उपकरणों की व्या-  
पक कमी थी। लेकिन हमें ऐसा नहीं होगा या कि कोई उपकरण विशेष  
सेना के पास देश भर में किसी स्थान पर ही हो नहीं। यद्यपि बड़ी कठिनाई  
पक्षर इस बात की हाजी थी कि दक्षिण उपकरणों का पैदान के अन्तिम स्थान  
तक या उसके आगे भी पहुँचाया जा सकता था लेकिन उन्हें किसी भी बाधा  
यात से (विमान के, पशुओं के या कुत्तियों के द्वारा) युद्ध पक्ष अग्रिम विरु-  
द्धाधी तक ठीक समय से पहुँचाना कठिन था। हमारा समस्या इन दो कारणों  
से घोर भी बिगड़ गयी थी

(क) बहुत तेज रफ्तार से जवानों की समस्त प्रदेय में उन्हें पहुँचाने  
इलाक़ों में पहुँचाना, और

(ख) ठीक तरह से बनी सड़कों और अन्य संचार साधना की कमी।

१४ परिस्थिति इन्होंने घोर भी बिगड़ गयी थी कि बाहनों की कमी  
थी और जो बाहनों थे भी उनमें से अधिकतर बहुत पुराने थे और जँवे, पहाड़ी  
इलाक़ों में चलने के लिए बेकार थे।

१५. यत संक्षेप में, यद्यपि इस बीच से यह पता लगा है कि उपकरणों  
की कमी थी फिर भी वे भीतर से मुड़ करने के लिए कारणर से घोर उन्  
के उपकरणों की तुलना में बुरे नहीं थे। इ बचावित राष्ट्रिय ठीक जतवानु में  
मुड़ करने के लिए ज्यादा कारणर हो सकते थे, अब उन्हें काम में लाया जाना  
शुरू किया जा रहा है। बीच ने इस बात पर ज़ार दिया है कि विशेषतः पहाड़ी  
इलाक़ों में मुड़ करने के लिए उपयुक्त उपकरणों की कमी को पूरा किया जाय  
लेकिन इससे भी ज्यादा इस बात की आवश्यकता बतायी है कि ऐसे संचार  
साधन प्राप्त किये जाय जिनसे उपकरणों की सेना के पास ठीक स्थान पर ठीक  
समय पहुँचाया जा सके। इस दिशा में काम शुरू किया जा चुका है और उसमें  
तेजी से प्रगति हो ।

### कमान्ड व्यवस्था

१६ तीसरा प्रश्न है सेना में कमान्ड व्यवस्था का। बीच से यह पता  
चला है कि कमान्ड व्यवस्था घोर सत्ता में मूलतः कोई खराबी नहीं है यदि



हर स्तर पर उसे उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये। फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि हर स्तर पर जिम्मेदारियों को महसूस किया जाये और एक दूसरे में विश्वास रख कर काम किया जाये। यह पता चला है कि युद्ध के समय कठिनाइयाँ केवल तभी पैदा होती थीं जब निश्चित कमान्ड शृंखला को भंग किया जाता था। जल्दबाजी और पहले से पर्याप्त योजना न बनाने के कारण ही कमान्ड शृंखला भंग होती थी।

१७. जाँच से यह भी पता चला है कि प्रवर सैनिक अधिकारी इस सीमा तक सामरिक बातों में दखल देते थे कि जवानों को किन विशेष कामों के लिए तैनात किया जाये। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय कमान्डरों को स्वयं ही निश्चय लेने चाहिए और युद्ध सम्बन्धी छोटी-छोटी बातें उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए थीं।

### सैनिकों का स्वास्थ्य

१८. चौथा प्रश्न है सैनिकों के स्वास्थ्य और उनकी शारीरिक क्षमता का। यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है कि जो सेना किसी विशेष जलवायु की आदी नहीं है वह उससे हीन है जो उसकी आदी है। इसके बावजूद जाँच से यह पता चला है कि हमारे अफसरों और जवानों ने उस कठिन जलवायु को अच्छी तरह सहा हालाँकि उनमें से अधिकतर एकाएक मैदानी इलाकों से ठंडे पहाड़ी प्रदेश में पहुँचाये गये थे। अतः हमारी सेना अपने सामान्य उत्तरवायित्वों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से पूर्णतः योग्य थी लेकिन वह उन ऊँचाइयों की जलवायु की आदी नहीं थी जिन पर उसे लड़ना पड़ा था। जहाँ सेना जलवायु की आदी हो गयी थी (जैसे कि लद्दाख में) वहाँ प्रदेश की ऊँचाई के कारण कोई कठिनाई नहीं पैदा हुई थी। अथेड़ वायु के अफसरों का स्वास्थ्य स्तर गिर गया था। इस कमी को अग्र ठीक किया जा रहा है। प्रवर अधिकारियों तथा जवानों का स्वास्थ्य अच्छा था और अब ज्यादा अच्छा हो रहा है।

### कमान्डरों की योग्यता

१९. पाँचवाँ प्रश्न था कि हर स्तर पर हमारे कमान्डरों में अपने नीचे लड़ने वाले जवानों को प्रभावित करने की कितनी योग्यता है। यह पता चला है कि, सामान्यतः, प्रवर अधिकारियों में यह योग्यता काफी सीमा तक थी। यूनिटों में अच्छे कमान्डिंग अफसर भी थे और मामूली भी। अच्छे और साधारण अफसरों का अनुपात वही था जो गत महायुद्ध के समय सेना में था। ब्रिगेडों में एक-दो को छोड़ कर, कमान्डिंग अफसरों में अपने उत्तरदायित्व पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी। कमियाँ ऊँचे अफसरों में अधिक पायी गयीं हैं। यह भी पता चला

है कि अधिकतर प्रवर अधिकारी पर्याप्त रूप से अपने नीचे के उन कमान्डरों की महत् क्षमता पर भरोसा नहीं करते थे वेदल जिन्हें ही भूपदक का प्रौर अपने नीचे लउन वाले जवानों की स्थानीय स्थिति का पूरा ज्ञान था ।

### अन्य पहलुओं का निरीक्षण

२० उपरोक्त बातों के प्रतिरिक्त जीव समिति ने मुद्र से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का भी निरीक्षण किया है और मैं ससद को इनके बारे में भी बताना चाहता हूँ । ये पहलू हैं—

- (क) हमारी आमुचना व्यवस्था
- (ख) हमारी स्टाफ कायद्रभासी
- (ग) उच्च स्तर पर मुद्र निर्देशन

२१ आमुचना व्यवस्था और साटन के बारे में कुछ भी प्रगट करना प्रत्यक्ष अनुचित होगा । मुद्र यह सबविदित है कि सैनिक इन्स्टांटर में एक आमुचना निदेशालय है जिसका संचालन सैनिक आमुचना सापरेक्टर करते हैं ।

२२. जीव से यह पता चला है कि आमुचना संचालन का कार्य सन्तोप-जनक नहीं था । आमुचना प्राप्त करने का काम बहुत मुस्ती से होता था और रिपोर्टें भरपट्ट हाठी थी ।

२३ आमुचना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है उसका संचालन और मूल्यांकन यह प्रत्यक्ष है कि आमुचनाओं के भरपट्ट होने के कारण उनका मूल्यांकन सही नहीं हो पाता था । इसके परिणामस्वरूप चीनी तैपापी का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका था । एनु के पुराने सैनिक फैलाव सक्षम में उसकी नयी तैमारियों का निरीक्षण करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था । प्रत मोर्चे पर सैनिक विरचनाओं को इस बात का बहुत कम ज्ञान था कि एनु के पास नये सैनिक दस्ते हैं या पुराने दल ही नयी स्थितियों पर सैनिक हैं ।

२४ तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है आमुचना का प्रसार । जीव से यह बात स्पष्ट हुई है कि यदि आमुचना से पूरा लाभ उठाना है तो उचित रूप से संपादन और मूल्यांकन करके उसे जल्द से जल्द मोर्चे पर स्थित विरचनाओं तक पहुंचाना आवश्यक है ।

२५ इसमें कोई सन्देह नहीं कि आमुचना व्यवस्था में विशेष परिवर्तन करना आवश्यक है । इस विद्या में पिछले छ महीनों में काफी काम किया जा चुका है । लेकिन आमुचना व्यवस्था में परिवर्तन करना काफी पेचीदा और लम्बा काम है और चूंकि यह काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसकी ओर व्यक्तिगत ध्यान दे रहा हूँ ।

## स्टाफ़ कार्य प्रणाली

२६. अब लीजिए स्टाफ़ कार्य प्रणाली । हर स्तर पर स्टाफ़ कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में स्पष्ट कार्य विधियाँ हैं । फिर भी जाँच से यह पता चला है कि जनरल स्टाफ़ कमाण्ड हेडक्वार्टरों तथा उसके नीचे की यूनिटों में रणयोजना, संग्रारतन्त्र और सर्विस हेडक्वार्टरों के आपसी सम्पर्क की ओर पहले से कहीं अधिक ध्यान देना होगा । इस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण सबक यह मिला है कि भविष्य में हमारी सैनिक तैयारी में जनरल स्टाफ़ की कार्य योग्यता तथा उसकी पूर्ण योजनाओं के ठोसपन का काफी हाथ होगा ।

## युद्ध निर्देशन

२७. इसके बाद लीजिए उच्च स्तर पर युद्ध निर्देशन का पहलू । सेना सरकार का अस्तित्व है और इसलिए बड़ी से बड़ी तथा सैन्य साधनों से पूरी तरह युक्त सेना को भी सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी निर्देश मिलना आवश्यक है । यह नीति निर्देश सेना के आकार तथा उसकी सामर्थ्य क्षमता को देख कर ही देने चाहिए । सेना का आकार बढ़ाने तथा साधनों और उपकरणों को अच्छा करने के लिये पन की आवश्यकता हो नहीं होती बल्कि सरकारी नीतियों की भी ।

## पिछले वर्ष की पराजय

२८. हमारी सेना को जो पराजय सहनी पड़ी वह उपरोक्त कई कारणों तथा कमजोरियों की वजह से थी । इस जाँच ने विस्तार से इन कारणों का अध्ययन किया है लेकिन साथ ही इस बात की भी पुष्टि की है कि आक्रमण इतनी तेजी से और इतने दूरस्थ इलाकों में हुआ था कि भारतीय सेना उसके लिए तैयार नहीं थी । पिछले वर्ष दो महीने से भी कम की अवधि में हमारे लगभग २४,००० सैनिक वास्तव में युद्ध में उलझे थे । इनमें से उन सैनिकों ने अपनी वीरता का अच्छा परिचय दिया जो लड़ाई में लड़े यद्यपि शत्रु की सैनिक संख्या कहीं अधिक थी । घुर पूर्वी सेक्टर में, शत्रु की सैनिक संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद, यद्यपि हमारी सेना को बाजोंग से अभियान करना पड़ा फिर भी वे अनुशासित रूप से हटे और उन्होंने शत्रु को काफी क्षति पहुँचायी । केवल कामेंग सेक्टर में ही सेना को लगातार करारी हार सहनी पड़ी । इस सेक्टर की लड़ाइयाँ हमारे दूरस्थ सीमान्तर पर लड़ी गयीं थी और हमारी सेना को ऐसी दुर्गम ऊँचाइयों पर शत्रु से मोर्चा सेना पड़ा था जिनसे वह परिचित नहीं थी । इसके अलावा भौगोलिक दृष्टिकोण से यह इलाका हमारे प्रतिकूल था जबकि शत्रु के लिए वहाँ लड़ना सुविधानजक था । लेकिन यह प्रारम्भिक हार लड़ाई की उलट फेर का स्वभाविक अंग है—महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्त में जीत किस की होती है ।

## चौथा द्विवोजन

२९ इस रिपोर्ट का प्रन्त करने से पहले मैं उस प्रसिद्ध चौथे द्विवोजन के बारे में कुछ शब्द बहना चाहूँगा बिना इस मुद्दे में भाग लिया था। यह कह जाता है कि इस पराजय के कारण इस प्रसिद्ध द्विवोजन को अपनी स्थािति का बलिदान देना पड़ा। इससे भी ज्यादा दुःखद बात यह है कि इस मुद्दे में यह द्विवोजन केवल नाम का ही 'चौथा द्विवोजन' था क्योंकि यह अपनी मूल विरचनाओं के साथ मुद्दे में नहीं सड़ा था। विभिन्न विरचनाओं के समिकों को ऐन मौके पर मोर्चे पर पहुँचाया गया था और वह 'चौथे द्विवोजन' के नाम से लड़े थे जबकि इसकी मूल विरचनाएँ और जगह स्थिर थीं। मुझे विश्वास है, और मुझे आशा है कि संसद मुझे इस बात में सहमत होगा, कि यदि भविष्य में देश पर आक्रमण हुआ तो यह प्रसिद्ध चौथा द्विवोजन निरिच्छ रूप से अपने मुद्दे जीतगा।

३० प्रन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आवश्यक सुधार कार्य आरम्भ करने के लिए हमने इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने का इन्तजार नहीं किया। जब शुरू होने के साथ ही सुधार कार्य भी शुरू हो गया था—संसद को याद होगा कि मैंने उसी समय संसद को इस बात की सूचना दे दी थी।

३१ लंबा और बोझाली सा मैं हमारी पराजय निरिच्छ रूप से भीषण थी लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अस्सल अधिक शक्तिशाली देशों को भी मुद्दे के शुरू में हार सहनी पड़ती है। आक्रमणकारी शुरू में अधिक दृढ़ स्थिति में होता है क्योंकि जब आक्रमण उचित गति से किया गया हो और धनु उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। आज हम सज्ज हैं और पूरी तरह अपने को तैयार करने के कार्य में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट से न केवल हमने अपनी कमजोरियों तथा गलतियाँ का पता चला है बल्कि अपनी सुरक्षा सम्बन्धी उत्पत्ता को समष्टि करने तथा मुद्दे निर्देश को करने का अवसर भी मिला है।

## परिशिष्ट-३

१० से १२ दिसम्बर सन् १९६२ को कोलम्बो में हुए ६ अफ़स राइटों के सम्मेलन के प्रस्ताव:

१. सम्मेलन का यह मत है कि वर्तमान वास्तविक युद्ध विराम की अवधि ऐसा सूक्ष्म समय है जब भारत-चीन संघर्ष के बारे में, शान्ति पूर्ण समझौते की बात शुरू की जा सकती है।

२. (क) पश्चिमी सेक्टर के बारे में, सम्मेलन चीन सरकार से यह अपील करना चाहता है कि २१ और २८ नवम्बर सन् १९६२ की प्रधान मंत्री चाउ इन-लाइ द्वारा प्रधान मंत्री नेहरू को लिखे गये पत्रों में दिये गये प्रस्तावों के अनुसार वह अपनी सैनिक चौकियाँ २० किलोमीटर पीछे हटा ले।

(ख) सम्मेलन भारत सरकार से यह अपील करता है कि वह अपनी वर्तमान सैनिक-चौकियाँ यथास्थान रखे।

(ग) सीमा समस्या के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक चीनी सैनिक प्रपयान के कारण खासी हुआ इलाका विसैन्यित इलाका माना जायेगा और उसका प्रशासन दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत प्रशासकीय चौकियाँ करेंगी। इसका कोई असर इस प्रदेश में भारत और चीन की पूर्व उपस्थिति के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

३. पूर्वी सेक्टर के बारे में सम्मेलन का यह मत है कि दोनों सरकारों द्वारा मान्यता पाई हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा क्रमशः उन दोनों के लिए उचित युद्ध-विराम रेखा होगी।

इस सेक्टर के बाकी इलाकों के बारे में भविष्य में बात-चीत द्वारा फैसला किया जा सकता है।

४. मध्य सेक्टर से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सम्मेलन का मत है कि उन्हें शान्ति का प्रयोग किए वगैर शान्ति पूर्ण ढंग से सुलझा लिया जायेगा।

५. सम्मेलन का विश्वास है कि युद्ध-विराम के कार्यान्वित होने के बाद इन प्रस्तावों से ऐसी शान्ति पूर्ण स्थिति पैदा हो जायेगी, जिसके वातावरण में

दानी पक्षा के प्रतिनिधि मुद्र-विषय में पंडा होने वाली समझौते का प्रामाण्य में सुनिश्चित करेंगे।

६ सम्मेलन यह बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में दोनों सरकारों की सहायक प्रतिष्ठा का ध्यान नो-निर्धारण पर कोई आपत्तिजनक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### छह राष्ट्रों के प्रस्तावों के पीछे मूल सिद्धान्त\*

१ भारत-चीन सीमा क्षेत्रों को दोनों सरकारों का शान्तिपूर्ण ढंग से तान कर लेना चाहिए।

२ छह राष्ट्रों के प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि वे ऐसा वातावरण पैदा कर दें जिससे भारत और चीन आपस-सम्मान के साथ समझौते की बात कर सकें।

३ अपने प्रस्तावों पर विचार करत समय, छह राष्ट्रों ने २१ नवम्बर सन् १९६२ को चीन द्वारा उद्घोषित एक पक्षीय मुद्र-विषय और धरान का स्वागत किया है।

४ इन प्रस्तावों की रचना करत समय, छह राष्ट्रों ने निम्नलिखित सिद्धान्तों की ओर विशेष ध्यान दिया है।

- (क) कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा दोनों में से कोई पक्ष लाभ न उठा सके,
- (ख) कि भारत और चीन के बीच समझौते की बात शुरू होने से पहले एक सुनिश्चित युद्ध विषय आवश्यक है,
- (ग) कि युद्ध विषय से किसी भी पक्ष के सीमा सम्बन्धी हक पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (घ) कि सुनिश्चित मुद्र-विषय की कार्रवाई करने के लिए दोनों में से किसी पक्ष से यह नहीं कहा जायेगा कि वे उन प्रदेशों से हटें जिनपर उनका सुनिश्चित अधिकार है या जिनपर उनका अधिकार प्रमाणित रहा है।
- (ङ) कि परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक नहीं होता कि सुनिश्चित मुद्र-विषय स्थापित होने के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट इलाक़े की भी स्थापना हो।

५ इन सिद्धान्तों पर विचार करने के बाद छह राष्ट्रों का यह मत है कि विवादस्थल भारत-चीन सीमा के सब क्षेत्रों के बारे में एक ही समाधान प्रस्तावित करना अनुचित है।

\* यह प्रस्ताव कोलम्बो सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने जनसंख्या के विषय में दिया था।

६. पूर्वी सेक्टर के सम्बन्ध में :

- (क) यह स्पष्ट है कि मैकमहॉन रेखा को वैध माना जाये या अवैध, यह दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसके उत्तर में चीन सरकार का एक छत्र प्रशासकीय नियंत्रण है और जिसके दक्षिण में विवाद प्रस्त चे-डांग और लोंगजू को छोड़कर, भारत सरकार का एक छत्र प्रशासकीय अधिकार है।
- (ख) छह राष्ट्रों का यह मत है कि युद्ध विराम के लिए इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देना उत्तम होगा।
- (ग) यदि इस रेखा को मान्यता दी गयी तो भू-प्रदेश की विरोधता के कारण अपने-आप दोनों पक्षों की सेनाओं का आपस में भिड़ना असम्भव हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप विसंगत इलाकों की स्थापना करना अनावश्यक होगा।
- (घ) छह राष्ट्रों का यह मत है कि पूर्वी सेक्टर के विवादप्रस्त चे-डांग और लोंगजू इलाकों के बारे में चीन और भारत क्रौरन समझौते की बात-चीत शुरू कर दें। यह भी उचित होगा कि अन्तिम निर्णय होने के समय तक चे-डांग के बारे में भी वही व्यवस्था की जाये जो लोंगजू के बारे में की जा चुकी है।

७. मध्य सेक्टर के बारे में ६ राष्ट्रों का यह मत है कि चूंकि इस सेक्टर में कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हुई है और वुजे या वाराहोती को छोड़कर वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए सीमा सम्बन्धि अन्तिम निर्णय होने तक यह उचित होगा कि,

- (क) दोनों में से कोई पक्ष सैनिक कार्रवाही न करें।
- (ख) दोनों पक्ष पूर्व स्थिति को मान्यता दें।

८. पश्चिमी सेक्टर में युद्ध विराम के बारे में, प्रस्तावों की रचना करते समय छह राष्ट्रों ने निम्नलिखित वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखा है :

- (क) कि "७ नवम्बर, १९५६ को वास्तविक नियंत्रण रेखा" के अर्थ और उसकी स्थिति के बारे में भारत और चीन में मतभेद है;
- (ख) कि जिस प्रारम्भिक रेखा पर चीन का दावा है उसके पश्चिम में भारत का एक छत्र प्रशासकीय नियंत्रण था और यह हो सकता है कि १९५६ के पहले समय-समय पर भारत ने उस रेखा से पूर्व की ओर गश्ती दस्ते भेजे हों;
- (ग) कि १९५६ और १९६२ के बीच भारत ने उस रेखा के पूर्व में ४३ सैनिकी चौकियाँ स्थापित कीं जिसे चीन पारम्परिक रेखा मानता है;

- (घ) कि १९५६ से पहले चीन उस रेखा के पूर्व में था जिसे वह पारम्परिक रेखा मानता है,
- (ङ) कि १९५६ और ६५ के बीच चीन ने पश्चिम में कुछ सैनिक-चौकियाँ स्थापित की, लेकिन वह उस रेखा के पूर्व में थीं, जिसे वह पारम्परिक रेखा मानते हैं,
- (च) कि चीन अपनी निक्ट की सैनिक कार्रवाईयों के फलस्वरूप सन् १९६२ तक उस पारम्परिक रेखा तक पहुँच गया जिसे वह पारम्परिक रेखा मानते हैं,
- (छ) कि चीन द्वारा मानी गयी पारम्परिक रेखा के पूर्व का प्रदेश निजाम है और इसलिए यह सम्भव था कि दोनों में से कोई एक इस प्रदेश में कोई वास्तविक प्रशासकीय नियंत्रण रख सके,
- (ज) कि एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा के समय चीन और भारत की सेनाएँ उस रेखा पर एक-दूसरे से भारी लिए हुए थीं जिसे चीन पारम्परिक रेखा मानता है।

६ इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर, छ राष्ट्र प्रस्तावित करते हैं कि युद्ध-विराम के निम्नलिखित आधार होने चाहिए -

- (क) कि पश्चिम सेक्टर में प्रधान मंत्री चाउ इन लाइ के २१ नवम्बर, १९६२, के पत्र के अनुसार चीनी सेनाओं को धपपान करना चाहिए,
- (ख) कि भारतीय सेना को उदात्स्थान रहना चाहिए भर्पात् चीन द्वारा दावा की हुई पारम्परिक रेखा पर स्थित रहना चाहिए,
- (ग) कि सीमा सम्बन्धी भगदों के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक, विर्सेन्वित क्षेत्र का प्रशासन इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें भारत तथा चीन दोनों का हाथ हो,
- (ङ) कि सीमा सम्बन्धी भगदों के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक, उक्त क्षेत्र का प्रशासन इस प्रकार हो कि वहाँ दोनों में से किसी देश की सेना उपस्थित न रहे। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि दोनों देशों की रजामन्दी से स्थापित प्रशासकीय चौकियाँ इस इलाके का प्रशासन करें।

कोलम्बो सम्मेलन के प्रतिनिधियों द्वारा भारत सरकार को १३ जनवरी, १९६३ को दिया हुआ स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के निवेदन पर उक्त धरन तथा पावा के प्रतिनिधि मंडलों ने कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों की धारा २, ३ और ४ का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया



## पश्चिमी सेक्टर :

(क) चीन सरकार के २१ नवम्बर, १९६२ के वक्तव्य में प्रधान मंत्री चाउ इन-लाइ द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को प्रस्तावित सुझाव तथा २८ नवम्बर, १९६२ के प्रधानमंत्री चाउ इन-लाइ के पत्र के अनुसार कोलम्बो सम्मेलन ने भी यह प्रस्ताव रखा है कि चीनी सेनाएँ २० किलोमीटर पीछे हटें अर्थात् चीन सरकार द्वारा प्रसारित मानचित्र नम्बर ३ और ४ में दिखायी गई ७ नवम्बर की दोनों पक्षों के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटें ।

(ख) भारत सरकार अपनी उन्हीं सैनिक चौकियों पर डटी रह सकती है जो उपचारा (क) के अनुसार उस रेखा पर या उस रेखा तक हैं ।

(ग) चीनी सेना के अपवान द्वारा पैदा हुए २० किलोमीटर के विलैन्वित इलाके का प्रशासन दोनों पक्षों की प्रशासकीय चौकियों द्वारा होगा । कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों का यह एक सारभूत अंग है । उन चौकियों की स्थिति संख्या और संगठन के बारे में भारत तथा चीन की सरकारों के बीच समझौता होना आवश्यक है ।

## पूर्वी सेक्टर :

कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुसार भारतीय सेनाएँ, उन दो इलाकों को छोड़कर जिनके बारे में भारत तथा चीन सरकारों के बीच विवाद है, वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात् मैकमहॉन रेखा के दक्षिण तक बढ़ सकती हैं । इसी प्रकार चीनी सेनाएँ उक्त दो इलाकों को छोड़कर, मैकमहॉन रेखा के उत्तर तक बढ़ सकती हैं । कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों में जिनमें दो शेष प्रवेश बताया गया है और जिनके बारे में चीन तथा भारत सरकारों के बीच कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुसार, समझौता होना है, वे हैं वे डांग या थागला पहाड़ी और लोंगजू । इन दो इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में दोनों सरकारों में मतभेद है ।

## मध्य सेक्टर :

कोलम्बो सम्मेलन की यह इच्छा है कि इस सेक्टर में पूर्व स्थिति कायम रखी जाये और दोनों में से कोई पक्ष इस स्थिति को अंग न करे ।